बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 174

सुधार का एजेंडा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने गत सप्ताह अप्रत्यक्ष कर ढांचे में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए। परिषद ने सैद्धांतिक रूप से 5 और 18 फीसदी की दो दरों को अपनाने की घोषणा की जबकि नुकसानदेह और विलासितापूर्ण वस्तुओं के लिए 40 फीसदी की ऊंची कर दर रखी गई है। परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दे पर भी विचार किया। उपकर केवल कुछ नुकसानदेह वस्तुओं से वसूल किया जाएगा, वह भी तब तक जब तक कि महामारी के समय राज्यों की राजस्व कमी की भरपाई की खातिर लिए गए कर्ज को चुकता नहीं कर लिया जाता। माना जा रहा है कि यह कर्ज अगले कुछ महीनों में चुकता हो जाएगा। दोनों बातों को एक साथ देखा जाए तो ये उपाय जीएसटी व्यवस्था को विगत आठ वर्षों की तुलना में कहीं अधिक सरल बनाएंगे। दरों में बदलाव आगामी 22 सितंबर से लागू होगा।

बहरहाल, जीएसटी ढांचे को सरल बनाना ही सरकार का इकलौता सुधार एजेंडा नहीं है। इस समाचार पत्र में सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का साक्षात्कार प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने सुधार संबंधी कुछ क्षेत्रों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में अगली पीढ़ी के सुधारों का जिक्र किया। सरकार ने ऐसे सुधारों के लिए एक नई समिति की घोषणा की है। जैसा कि सीतारमण ने कहा, अगर हर माह रिपोर्ट के जरिये कदम उठाए जाने लायक बिंदु सामने रखे जाएं तो सरकार उनका क्रियान्वयन करेगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय के भीतर अन्य बातों के अलावा विनिवेश पर भी जोर देने की आवश्यकता है। यह कोई नया नहीं बल्कि पुराना एजेंडा है जिसमें कई कारणों से ढिलाई बरती जाने लगी थी। विनिवेश पर नए सिरे से जोर देना स्वागतयोग्य है। यह बात ध्यान देने लायक है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान एक नई रणनीतिक विनिवेश नीति की घोषणा की थी। उसे 2021-22 के आम बजट में प्रस्तुत किया गया था।

इस नीति के मुताबिक सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी सीपीएसई में अपनी मौजूदगी न्यूनतम करेगी। इस बारे में कुछ रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान की गई- जैसे परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, परिवहन और दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज तथा बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवा आदि। गैर रणनीतिक क्षेत्रों के सीपीएसई का निजीकरण किया जाना है या उन्हें बंद किया जाना है। बहरहाल, इस मोर्चे पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर इस नीति को सही ढंग से लागू किया गया तो सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा।

अब सरकार ने बजट में सालाना विनिवेश लक्ष्य देना बंद कर दिया है जो एक तरह से अच्छा निर्णय है। सालाना लक्ष्य से विनिवेश की प्रक्रिया केवल राजस्व बढ़ाने की कवायद में बदलकर रह जाती है। इसका लक्ष्य राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करना रह जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्व तो इस कवायद का केवल एक पहलू है। इसके साथ निजी क्षेत्र के लिए जगह बनाने और व्यवस्था को बेहतर बनाने का व्यापक लक्ष्य जुड़ा होना चाहिए। इससे राज्य की क्षमता में भी सुधार होगा। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि प्राप्तियां महत्त्वपूर्ण नहीं हैं।

रणनीतिक विनिवेश से काफी मूल्य निकल कर सामने आ सकता है और प्राप्तियों का इस्तेमाल आने वाले वर्षों में सरकार के पूंजीगत व्यय कार्यक्रम की भरपाई के लिए किया जा सकता है। इससे मध्यम अवधि में वृद्धि को गति देने में मदद मिलेगी। प्राप्त राशि का एक हिस्सा सार्वजनिक ऋण की अदायगी में भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे ब्याज भुगतान का बोझ कम होगा और राजकोषीय गुंजाइश बढ़ेगी। लेकिन वार्षिक प्रवाह समान नहीं होते और यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की और कितनी कंपनियों का विनिवेश किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वह राजकोषीय घाटे का आंकड़ा विनिवेश सहित और उसके बिना दोनों रूपों में प्रस्तुत करे, ताकि वित्तीय स्थिति की अधिक स्पष्ट और तुलनात्मक तस्वीर सामने आ सके। कुल मिलाकर, विनिवेश की घोषित नीति को लागू करने के पक्ष में पर्याप्त तर्क मौजूद हैं, लेकिन इसे राजनीतिक रूप से संभालना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। उम्मीद है कि इस बार सरकार इन बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर पाएगी।

ट्रंप के झटके और भारत पर इसका असर

उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रंप द्वारा दिए गए भू-आर्थिक झटके देश में दूसरी पीढ़ी के अत्यधिक जरूरी सुधारों को गति देंगे। विस्तार से बता रहे हैं अजय छिब्बर

भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में जो चरणबद्ध सुधार आरंभ हुए थे और जिन्हें उनके बाद हर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा और गहरा किया गया, वह सिलसिला अब बाधित हो गया है। डॉनल्ड ट्रंप अब भारत को चीन के साथ भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में नहीं देखते। ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 फीसदी दंडात्मक शुल्क और बार-बार किए गए अपमानों ने भारत को चीन के करीब ला दिया है। इस सप्ताह भारतीय प्रधानमंत्री ने सात वर्षों के अंतराल के बाद शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भाग लिया, जहां उनका स्वागत चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने किया। कुछ सप्ताह पहले तक ऐसा होना असंभव नजर आता।

अमेरिका को आखिरकार यह एहसास होगा कि भारत पर जोर-आजमाइश नहीं की जा सकती है लेकि तब तक शायद हालात बहुत बिगड़ जाएं। ट्रंप यूरोपीय संघ से कह रहे हैं कि वह भारत पर प्रतिबंध लगाए। एच-1बी वीजा और छात्र वीजा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और ट्रंप ने उस क्वाड बैठक को रद्द कर दिया है जो इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाली थी। ध्यान रहे कि ट्रंप ने ही अपने पहले कार्यकाल में क्वाड का गठन किया था ताकि चीन पर लगाम कसी जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में चीन ही विजेता के रूप में उभरा है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसंट का मानना है कि भारत के साथ अभी भी द्विपक्षीय व्यापार समझौता संभव है। हालांकि ट्रंप शायद इसकी इजाजत न दें। उनके मुताबिक तो भारत ने कुछ उत्पादों पर शुल्क दर शून्य करने की भी पेशकश की है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रिश्ते बिगड़ने के पीछे व्यक्तिगत संबंधों में टूटन को भी वजह बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ युद्धविराम में उनकी भूमिका स्वीकार न करने के कारण भारत से नाराज हैं। वह मानते हैं कि उनका यह कदम उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार तक दिला सकता है।

ट्रंप अमेरिका के साथ भारत के व्यापार अधिशेष की बात करते रहते हैं लेकिन जब हम यह देखते हैं कि भारतीय अमेरिकी विश्वविद्यालयों में शिक्षा पर सालाना करीब 25 अरब डॉलर खर्च करते हैं, रॉयल्टी चुकाते हैं, रक्षा खरीद करते हैं और ई-कॉमर्स राजस्व में योगदान करते हैं तो वास्तव में पता चलता है कि भारत भुगतान संतुलन के घाटे का शिकार है। अमेरिका में एक अपीलीय अदालत ने ट्रंप द्वारा लगाए शुल्कों को अवैध बताया है लेकिन लगता नहीं कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में टिक सकेगा क्योंकि वह आमतौर पर ट्रंप के पक्ष में निर्णय देता है।

द्विपक्षीय समझौते में देरी के लिए तेल और दूध को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर शुल्क बढ़ाया है जो अपने आप में समझ से परे है। खासतौर पर यह देखते हुए कि उन्होंने अलास्का में पुतिन का स्वागत किया था तथा अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों रूस से गैस, उर्वरक, यूरेनियम और पैलेडियम खरीदते हैं। भारत, चीन और तुर्किये ने रूस से ज्यादातर वह कच्चा तेल खरीदना शुरू किया है जो अमेरिका और यूरोपीय संघ ने बंद किया है। ऐसा नहीं होता तो वैश्विक तेल कीमतों में इजाफा होता। तो भारत पर निशाना क्यों?

अमेरिका को कृषि उत्पादों पर भी व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए- खासतौर पर दूध को लेकर। अगर अमेरिका उत्पादन पर भारी सब्सिडी देता है जिसके बाद उसके दूध उत्पादक विश्व बाजारों में अपना दूध उतारने पर विवश होते हैं तो भारत से ऐसे आयात को इजाजत देने की उम्मीद करना उचित नहीं है। ऐसा करने से देश के 8-10 करोड़ ऐसे लोगों की आजीविका पर असर होगा जो पशुपालन पर निर्भर हैं। ट्रंप के कदमों ने ब्रिक्स में नई जान फूंक दी है। इन कदमो में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका पर भारी टैरिफ लगाना शामिल है। अब भारत और चीन इस समूह को मजबूत बनाने में लगे हैं। वर्ष 2026 और 2027 में ब्रिक्स प्लस की अध्यक्षता इन्हीं दोनों देशों के पास रहनी है। देखना होगा कि यह सौहार्द कितने समय तक बना रहेगा। खासकर सीमा विवाद और एशिया का चौधरी बनने की चीन की इच्छा को देखते हुए। प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक जॉन मियरशाइमर का कहना है कि पिछली अमेरिका सरकारों की नीतियों ने रूस और चीन को एक-दूसरे के करीब ला दिया, और अब ट्रंप की नीतियां भारत को उनके करीब धकेल रही हैं।

ब्रिक्स भारत को कुछ भू-राजनीतिक लाभ दिला सकता है लेकिन फिलहाल इसके आर्थिक लाभ सीमित हैं। ब्रिक्स प्लस समूह का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) करीब 32 लाख करोड़ डॉलर है जो वैश्विक जीडीपी का 27 फीसदी है। इसका बाजार जी7 जैसा नहीं है जिसकी कुल जीडीपी 50 लाख करोड़ डॉलर से अधिक है और वह वैश्विक जीडीपी के 45 फीसदी योगदान करता है। इतना ही नहीं ब्रिक्स प्लस के कुल जीडीपी में 20 लाख करोड़ डॉलर से अधिक का योगदान अकेले चीन का है। भारत चीन को बहुत कम निर्यात करता है और वहां उसके निर्यात में इजाफा होने की संभावना नहीं है। भारत की समृद्धि की राह निर्यात बढ़ाने और जी7 देशों से तकनीक जुटाने में है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता इस लक्ष्य के लिए जरूरी है। बिना इसके भारत न केवल अपना सबसे बड़ा निर्यात बाजार खो देगा बल्कि वह चीन प्लस 1 दुनिया में आने वाले नए निवेश से भी वंचित रह जाएगा। वह निवेश अब मेक्सिको, वियतनाम और अन्य उन देशों में जाएगा जहां अमेरिकी टैरिफ कम है।

भारत 50 फीसदी शुल्क के कारण निर्यातकों पर पड़ने वाले तत्काल प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकता है, यदि वह रुपये को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अवमूल्यित होने दे। विशेष रूप से यह देखते हुए कि मुद्रास्फीति कम स्तर पर है। अमेरिका को निर्यात करने वाले निर्यातकों को टैक्स रिफंड और ऋण रियायत प्रदान करना, साथ ही उनके आवश्यक इनपुट्स पर शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को समाप्त करना भी इस प्रभाव को कम करने में मददगार होगा। हमें घरेलू सुधारों की आवश्यकता है ताकि कारोबारी सुगमता बेहतर हो सके। इनमें से बहुप्रतीक्षित जीएसटी सुधारों को अंजाम देते हुए उसे दो दरों में समेट दिया गया है। अब जरूरत है ईंधन कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने की। हमारे यहां ईंधन कीमतें अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक हैं। बिजली और रेल किराये की क्रॉस सब्सिडी के कारण भी कारोबार की लागत बढ़ती है जिसे कम करना जरूरी है। श्रम बाजार में सुधार की आवश्यकता है और जमीन के उपयोग की नीति को अधिक सहज बनाने की आवश्यकता है। बैंकिंग मार्जिन में कमी करना भी एक प्राथमिकता होनी चाहिए। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता और अन्य व्यापार समझौतों मसलन व्यापक एवं प्रगतिशील प्रशांत पार साझेदारी समझौते (सीपीटीपीपी) में शामिल होना, पर्यटन को बढ़ावा देना आदि भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे।

अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, 'हर संकट के बीच एक महान अवसर छिपा होता है।' भारत को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं को खुला रखना चाहिए किंतु अपने महत्त्वपूर्ण हितों से समझौता किए बिना। अमेरिका में समृद्ध और प्रभावशाली मानी जाने वाली भारतीय-अमेरिकी लॉबी को भी सक्रिय किया जाना चाहिए ताकि अमेरिका की भारत नीति में अधिक समझदारी लाई जा सके। ट्रंप की भू-आर्थिक हलचल वह झटका साबित हो सकती है, जिसने भारत को उसके लंबे समय से प्रतीक्षित और अत्यंत आवश्यक दूसरे चरण के सुधारों की ओर धकेला। जो उसे आगे बढ़ाने में सहायक बने। यदि भारत घरेलू स्तर पर मजबूत होता है, तो भू-आर्थिक समीकरण भी भारत के पक्ष में झुकेंगे।

(लेखक जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनैशनल इकनॉमिक पॉलिसी में विशिष्ट विजिटिंग स्कॉलर हैं)

व्यापक समूह तक पहुंच वाले बाजार की अपार संभावनाएं

हाल की विदेशी चुनौतियों के कारण हमारा ध्यान अब घरेलू खपत पर गया है ताकि यह अंदाजा लगाया जा सके कि क्या यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को बरकरार रख सकता है। सभी की नजरें और उम्मीदें मांग बढ़ाने वाली पारंपरिक नीतियों पर टिकी हैं। आयकर दरों में पहले की गई कटौती से, भारत के उपभोक्ताओं के एक छोटे लेकिन ज्यादा खर्च करने वाले वर्ग को मदद मिली। साथ ही, अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में होने वाली कटौती से कई उपभोक्ता वस्तुओं के दाम कम होंगे, जिससे उपभोक्ता खर्च में एक जरूरी लेकिन एकबारगी बढ़ोतरी होगी।

हालांकि, भारत के व्यापक जनसमूह वाले बाजार को विकसित करने के लिए और भी रचनात्मक और रणनीतिक नीतियों की जरूरत है ताकि हम उसकी खपत की पूरी क्षमता का लाभ उठा सकें। इससे एक ऐसे भविष्य के लिए तैयारी होगी जहां घरेलू खपत वास्तव में आर्थिक विकास का बड़ा सूत्रधार बन सकती है। बड़ी कंपनियों और अमीर उपभोक्ताओं के लिए बनी बाजार नीतियां, बड़े जनसमूह वाले बाजार तक नहीं पहुंच पातीं हैं। कुछ कंपनियों को छोड़कर, बड़ी भारतीय कंपनियां इन उपभोक्ताओं पर ध्यान नहीं देतीं क्योंकि इनसे जुड़े उत्पाद, कम दाम लेकिन बहुत अधिक मात्रा में बिकने वाले और कम मुनाफा देने वाले होते हैं। अपनी कम आय और कम आत्मविश्वास के कारण ही ये उपभोक्ता छोटी स्थानीय कंपनियों और चीन से आयातित सामान पर निर्भर रहते हैं।

ऐसी उम्मीद कम ही है कि बड़ी कंपनियां अचानक अपना मन बदलेंगी और चीन की तरह बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता में निवेश करेंगी ताकि व्यापक जनसमूह के बाजार की जरूरतें पूरी की जा सकें। अमीर जैसे-जैसे और अमीर होते जा रहे हैं, बड़ी कंपनियों के लिए एक ऐसे बाजार में लगातार निवेश करने का आर्थिक तर्क कम आकर्षक होता जा रहा है जो लंबे समय तक तो पैसा कमा सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना मुश्किल है। वे वास्तव में किसी 'बदसूरत बत्तख' के एक 'अमीर हंस' में बदलने का इंतजार करेंगे, जिनके लिए सेवाएं देना उनके लिए फायदेमंद होगा लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा।

भारत के सबसे अमीर 20 फीसदी परिवार ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा कमाने वाले, अधिक खर्च करने वाले, बचत करने वाले (और निवेशक) रहे हैं। उनकी आमदनी झटकों को झेलने में सक्षम है और वे बेहतर गुणवत्ता वाली चीजें ढूंढ़ने और उनके लिए अधिक पैसे देने को तैयार रहते हैं। अपनी शिक्षा और व्यवसाय के स्तर के कारण वे ऐसा करते रहेंगे। वे नीतिगत बदलाव के बिना भी खपत करेंगे, हालांकि वे खर्च में तुरंत बढ़ोतरी का भी एक स्रोत हैं। अगर आईफोन या लैपटॉप की कीमतें कम होती हैं तब वे उन्हें जल्द ही बदलना चाहेंगे या ज्यादा गैजेट खरीदेंगे। अगर स्टांप ड्यूटी कम होती है, तब वे अधिक कीमत वाले घर खरीदेंगे। वे बड़ी कंपनियों के तरजीही ग्राहक हैं जो उन्हें विविधतापूर्ण सामान उपलब्ध कराकर उनका ध्यान रखती हैं।

रमा बीजापुरकर

अगले सबसे अमीर 20 फीसदी परिवार, जो शीर्ष 20 फीसदी का ही एक हल्का स्वरूप हैं, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है लेकिन वे बड़ी उपभोक्ता-केंद्रित कंपनियों की नजर में हैं क्योंकि वे उनकी मौजूदा रणनीतियों के लिए वृद्धि का अगला तार्किक स्रोत हैं। भले ही उनकी खपत में वृद्धि उतनी स्थिर न हो, लेकिन आर्थिक रूप से मुश्किल समय में भी उनकी खपत की रफ्तार बनी रहती है। सबसे खराब स्थिति में भी वे कम कीमत पर कम गुणवत्ता वाली चीजें ही सही, लेकिन खरीदते जरूर हैं। यह समूह अधिक या सस्ते ऋण और टिकाऊ सामान, कारों और घरों की कीमतों में कमी को देखते हुए अपनी सक्रियता दिखाता है बशर्ते कि इस माहौल ने उनकी भविष्य की आमदनी को लेकर उनके आत्मविश्वास को कम न किया हो, जो शीर्ष अमीर 20 फीसदी वर्ग की तुलना में ज्यादा नाजुक है।

हालांकि, अब हमें भारत के मध्य वर्ग के 40 फीसदी परिवारों की खपत से जुड़ी अपनी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जो देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर एकसमान जनसमूह वाला बाजार है। दीर्घकालिक लक्ष्य इसे एक अधिक उत्पादकता, उच्च-दक्षता वाले मांग और आपूर्ति (उपभोक्ता एवं उत्पादक) वाले पारिस्थितिकी तंत्र में बदलना होना चाहिए जो अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग कर सके। इसे भविष्य में होने वाली अनुमानित वृद्धि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर मापा जा सकता है।

यह उपभोक्ता वर्ग कम आय वाला है, जिसमें ज्यादातर स्वरोजगार करने वाले किसान, अनौपचारिक रोजगार में लगे लोग, या अलग-अलग कौशल वाले 'अपना काम करने वाले' लोग शामिल हैं। वे जानते हैं कि बाजार में क्या उपलब्ध है और वे एक उत्सुक उपभोक्ता की भूमिका में जरूर होते हैं लेकिन वास्तव में वे कीमतों का आकलन करने वाले एक समझदार विश्लेषक भी हैं। हालांकि, लंबी अवधि के रुझान के आधार पर यह वृद्धि के लिए एक पक्का दांव है लेकिन वे छोटी-मोटी परेशानियों के दौर में बहुत अधिक अस्थिरता दिखाते हैं।

अच्छी बात यह है कि हमारे लिए नई अर्थव्यवस्था ने अपने डिजिटल व्यापार मॉडल के साथ इस बदलाव को लाने का तरीका दिखाया है और यह एक ऐसा तरीका है जिसे अब नीतियों को और प्रोत्साहित करना चाहिए। यह छोटे उपभोक्ताओं और छोटे आपूर्तिकर्ताओं के जुटने और वर्चुअल बाजार के आधार पर बनाया गया है जो ऐसी मूल्य-वर्धित सेवाएं देता है जो किसी अकेले के लिए संभव नहीं है। इसकी खूबी यह है कि यह मौजूदा ढांचों के आसपास ही बदलाव लाता है। यह छोटे आपूर्तिकर्ताओं को एक मंच के माध्यम से बढ़ावा देकर रोजगार के अधिक मौके तैयार कर सकता है और छोटे ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को जोड़कर बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ दे सकता है। यह विभिन्न तरह के छोटे आपूर्तिकर्ताओं को एक साथ लाकर, बड़ी कंपनियों की तुलना में कम लागत और अधिक दक्षता के साथ कम मूल्य वाली, अधिक विविधता वाली जरूरतें पूरी कर सकता है। क्लाउड किचन, छोटे होटल, या विभिन्न घरेलू सेवाओं को एक साथ देने वाले फर्म इसके उदाहरण हैं।

छोटे-छोटे काम करने वालों को एक साथ जोड़ने वाला यह वर्चुअल बाजार अब आगे बढ़ रहा है। यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह कम कीमतों वाले बाजार और दूर-दराज के इलाकों से जुड़ी उन कमियों को दूर कर सकता है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर खपत को रोक रखा है। यह दूरदराज के इलाकों में मौजूद छोटे दुकानदारों को भी एक बड़े और प्रभावशाली वितरण प्रणाली से जोड़ सकता है। इस तंत्र के जरिए बहुत कम खर्च में अधिक से अधिक सामान और सेवाएं लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसके अलावा, यह छोटे ग्राहकों को चीजें साझा करने की सुविधा देकर महंगी चीजों तक पहुंचने में मदद करता है, जिन्हें वे खरीदना तो चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पाते। उदाहरण के लिए, ट्रैक्टर, कार या शादी का महंगा सामान।

सेवा बाजार खुद काम करने वाले लोगों को एक साथ लाकर एक तरह के औपचारीकरण को बढ़ावा देता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है, कौशल में सुधार होता है और चीजों की सही कीमत तय करने में मदद मिलती है। साथ ही लागत कम होती है और मंचों के जरिये ऋण लेना आसान हो जाता है जिससे वित्तीय पारदर्शिता भी बढ़ती है। यह सबकुछ महज एक विचार भर नहीं है। कई स्टार्टअप ने इसे जमीन पर सच करके दिखाया है। छोटे-छोटे काम करने वालों को एक साथ जोड़ने वाला यह वर्चुअल बाजार अब आगे बढ़ रहा है। इसलिए, बाजार के छोटे खिलाड़ियों के इस नए तंत्र को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाना बहुत जरूरी है। ये नीतियां उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की तरह ही महत्त्वपूर्ण हैं।

(लेखिका ग्राहक आधारित कारोबार रणनीति के क्षेत्र में कारोबारी सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस और देश में शिक्षा की हालत

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस सोमवार, 8 सितंबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने यह दिवस मनाने का फैसला किया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को साक्षरता के प्रति जागरूक करना है। देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए बेटियों को भी बेटों के बराबर शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। किसी भी देश के विकास में पढ़े लिखे लोगों का बहुत योगदान होता है। शिक्षा की अलख जगाने के लिए देश में बच्चों के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा अभियान की भी शुरुआत की गई थी जो काफी सफल भी रहा। हालांकि देश की साक्षरता दर वैश्विक स्तर पर कम है। ऐसे में सरकार को झुग्गी-झोपड़ी, गांवों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। देश और समाज की हर समस्या का हल निकालने के लिए शिक्षित लोगों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब लोग किताबी शिक्षा के साथ नैतिकता और इंसानियत का सबक भी सीखें। शिक्षा संस्थानों का मकसद विद्यार्थियों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या अन्य स्पेशलिस्ट बनाने के साथ- साथ आदर्श और मर्यादित विद्यार्थी बनाना भी होना चाहिए। आदर्श और मर्यादित बच्चे ही सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कूली बच्चों ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया

चीन से टूटे संवाद का सिलसिला फिर से कायम

एससीओ बैठक से भारत-चीन में व्यापक संवाद-संपर्क का टूटा सिलसिला फिर से कायम हो गया। कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद रूस और चीन के बीच मजबूत संबंध बने रहे हैं। दूसरी ओर तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था और एक विशाल बाजार के रूप में भारत की स्थिति इसे व्यापार वार्ताओं और अन्य आर्थिक मंचों पर महत्त्वपूर्ण सौदेबाजी शक्ति प्रदान कर सकती है। भारत इसका उपयोग अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। हालांकि प्रतिद्वंद्विता के ऊपर साझेदारी को प्राथमिकता देना, सीमा तनाव कम होने पर संतोष जताना, सीमा विवाद समाधान के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करना तथा एससीओ और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों के प्रति दोनों देशों का समर्थन जैसे उपाय भारत-चीन संबंधों को पुनः संतुलित एवं मजबूत करने की साझा रणनीति के परिचायक हैं। फिर भी चीन से सावधानी बेहद जरूरी है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

भारत-चीन तनाव के बाद सहयोग की ओर मुड़े रिश्ते

एससीओ बैठक ने भारत-चीन संबंधों को तनाव से सहयोग की ओर मोड़ने का अवसर दिया है। चीन का पहलगाम हमले का उल्लेख स्वीकार करना भारत की कूटनीति की सफलता और उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव का संकेत है। सीमा पर शांति और स्थिरता पर सहमति, दोनों देशों की सामूहिक आवश्यकता को दर्शाती है। हालांकि अविश्वास की परतें खत्म नहीं हुई हैं। फिर भी यह संवाद बताता है कि प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर साझेदारी ही एशिया के भविष्य की कुंजी है। भारत का संतुलित रुख सराहनीय है।

कृति जैन, बड़वानी

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

अनुपर्णा रॉय ने इटली के वेनिस में आयोजित 82वें 'वेनिस फिल्म फेस्टिवल' में 'सॉन्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार हासिल किया।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

ट्रैफिक सुधार के समग्र प्रयासों को देनी होगी गति

बढ़ते सड़क हादसों के बड़े कारणों में यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए वाहन चलाना सबसे ऊपर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के महानगरों से लेकर छोटे-बड़े शहरों में यातायात नियमों के उल्लंघन के बढ़ते मामलों के साथ-साथ दंडात्मक कार्रवाई भी बढ़ी है। संतोष इस बात पर भी जरूर किया जा सकता है कि तकनीक के इस्तेमाल से अब 'बड़े लोगों' का भी चालान होने लगा है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) के कैमरों के इस्तेमाल से यह संभव होने लगा है क्योंकि मशीन आम और खास में भेद नहीं करती। पिछले दिनों कर्नाटक के सीएम से सात बार यातायात नियमों की अनदेखी के कारण वसूला गया जुर्माना इसका उदाहरण है।

यातायात नियमों की अवहेलना के लिए जब रसूखदारों पर कार्रवाई होती है तो आम आदमी के मन में संतोष का भाव जरूर आता है। लेकिन चिंता की बात यह भी है कि बेतरतीब यातायात के कारणों की तरफ जिम्मेदारों का कभी ध्यान जाता ही नहीं। ध्यान जाता भी है तो कोई बड़ा हादसा होने पर जांच अभियान के नाम पर खानापूर्ति बनकर रह जाता है। बेतरतीब यातायात देश की प्रमुख समस्याओं में शामिल है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलूरु और जयपुर ही नहीं, कोई छोटा-बड़ा शहर-कस्बा इससे अछूता नहीं है। वाहन सवारों का बहुत अधिक समय आए दिन यातायात अवरोध में बीत जाता है। दुर्घटना का खतरा और प्रदूषण की मार है सो अलग। सड़कों पर वाहनों की भरमार की बड़ी वजह यह भी है कि महानगरों व शहरों में सार्वजनिक परिवहन के साधन नाकाफी हैं। इसलिए सड़कों पर निजी वाहनों की भरमार हो गई है। वाहनों की संख्या के मुकाबले बेहतर सड़कों की पहले से ही कमी है। यही कारण है कि जाम लगने पर आम आदमी रेंगते वाहनों में ही सफर करने को विवश है। दूसरा पहलू यह भी है कि यातायात के नियमों का पालना कठोरता से हो, इस दिशा में भी काम नहीं हो रहा। अकेले बेंगलूरु में पिछले एक साल में यातायात नियमों के उल्लंघन के 52 लाख मामले बने जबकि दिल्ली में यह संख्या 30 लाख रही। बड़ी चिंता यह भी है कि कोई राज्य या शहर इस दृष्टि से आदर्श नहीं है कि कहा जा सके कि अमुक स्थान के बाशिंदे यातायात नियमों की पालना के प्रति सजग हैं। जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली भी जब सिर्फ जुर्माना वसूलने पर केंद्रित होती दिखे तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर यातायात संकेतकों, बत्तियां आदि की पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं होती?

अधिकांश शहरों में बहुत से स्थानों पर जरूरत के बावजूद सिग्नल पॉइंट ही नहीं हैं। जहां हैं वे भी एक-दूसरे से तकनीकी तौर पर जुड़े हुए नहीं हैं। वाहन चालक हर सिग्नल पॉइंट पर रुकने के लिए बाध्य होते हैं। ट्रैफिक सुधार के समग्र प्रयासों को गति देनी होगी। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों से बिना किसी भेदभाव के सख्ती से पेश आना होगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: जब वैश्विक मंचों पर सब भारत को सुन रहे हैं, तो निर्णय की कुर्सी पर अब तक मौन क्यों?

भारत की बढ़ती शक्ति, पर स्थायी सदस्यता से वंचित

विनय कौड़ा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
@patrika.com

यूरोप के देश, जो मंच पर सुधार का मुखौटा पहनते हैं, पर बंद कमरों में सुधार की हर संभावना को नेस्तनाबूद कर देते हैं। उनकी नीति स्पष्ट है- सत्ता साझा नहीं होगी। यह वही औपनिवेशिक मानसिकता है, जो गोरों को अब भी वैश्विक नेतृत्व का एकाधिकार सौंपे हुए है।

दिन-ब-दिन की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत का नाम अब संयोग नहीं, बल्कि एक अपरिहार्य स्थिरता बन चुका है। अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप हों या वर्तमान वैश्विक मंचों के अन्य संचालक, भारत का उल्लेख उनकी वाणी में जितनी बार आता है, उतनी बार यह स्पष्ट होता है कि भारत अब कोई क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि विश्व राजनीति का एक केंद्रीय पात्र बन चुका है। वह पात्र, जिसके विचार, निर्णय और नीतियां विश्व पटल को प्रभावित करते हैं।

ट्रंप जब भारत पर 'उच्च टैरिफ' की चर्चा करते हैं या रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारत के रुख पर टिप्पणी करते हैं, तो दबे स्वर में वह दरअसल भारत की उस संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय-शक्ति को स्वीकार करते हैं, जो आज के भू-राजनीतिक जगत में बहुत कम देशों के पास है। जब चीन, जो बरसों से पाकिस्तान को भारत-विरोधी नीति का औजार बनाता रहा है और सीमा विवाद में भारत को उलझाकर रखना अपना कर्तव्य समझता रहा है, वही चीन भारत के साथ मैत्री की कालीन बिछाने को उत्सुक दिख रहा है। यह भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत का नहीं, बल्कि उसकी अपरिहार्यता का घोष है।

परंतु प्रश्न वही- जब वैश्विक मंचों पर सब भारत को सुन रहे हैं, तो निर्णय की कुर्सी पर अब तक मौन क्यों? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व की सबसे ताकतवर राजनीतिक संस्था है, जहां वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति केवल पांच देशों के पास केंद्रित है। अमरीका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास वह पांचजन्य सत्ता है, जो 1945 की युद्धोत्तर परिस्थितियों की उपज थी। उस वक्त न तो भारत स्वतंत्र था और न ही उसकी सामरिक और आर्थिक शक्ति का विश्व में कोई औपचारिक मूल्यांकन हुआ था। परंतु आज भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी है। वह देश, जो लोकतंत्र की वास्तविक प्रयोगशाला है, जो आतंकवाद के विरुद्ध अग्रिम पंक्ति में है और जिसकी सैन्य शक्ति किसी भी स्थायी सदस्य से कम नहीं। उस भारत को आज भी सुरक्षा परिषद के दरवाजे पर प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। यह केवल त्रासद विडंबना नहीं है, यह इतिहास का क्रूर व्यंग्य है।

1993 से आज तक सुरक्षा परिषद में सुधारों की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हर बार नतीजा वही ढाक के तीन पात। यूरोप के देश, जो मंच पर तो सुधार का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन बंद कमरों में सुधार की हर संभावना को नेस्तनाबूद कर देते हैं। उनकी नीति स्पष्ट है- सत्ता साझा नहीं होगी। यह वही औपनिवेशिक मानसिकता है, जो गोरों को अब भी वैश्विक नेतृत्व का एकाधिकार सौंपे हुए है। ऐसे में पिछले दिनों एक भाषण में सिंगापुर के प्रख्यात पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी ने सीधा, सहज और यथार्थवादी विचार दिया है- ब्रिटेन अपनी स्थायी सीट भारत को सौंप दे। एक दशक तक संयुक्त राष्ट्र में सिंगापुर के स्थायी प्रतिनिधि और 2001 में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रह चुके महबूबानी की गिनती दुनिया के सर्वोच्च भू-राजनीतिक विशेषज्ञों में होती है। उनके तर्क का पहला आधार है ऐतिहासिक नैतिकता। ब्रिटेन ने भारत को 200 वर्षों तक उपनिवेश बनाकर लूट-खसोट की। यदि वह उस ऐतिहासिक पाप के प्रायश्चित स्वरूप में यह सीट भारत को दे, तो यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक क्षतिपूर्ति होगी।

दूसरा तर्क है आर्थिक यथार्थ- भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से न केवल बड़ी है, बल्कि भविष्य में चार गुना बड़ी होने जा रही है। ऐसे में ब्रिटेन को भारत की सीट पर बैठे रहना, मानो कोई भूतकाल का राजा आज के जनतंत्र में सिंहासन पर विराजमान हो। तीसरा बिंदु है वैश्विक आवश्यकता- जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, युद्ध और शांति जैसे विषय आज पुराने यूरोपीय मॉडलों के नियंत्रण से बाहर हैं। इन समस्याओं का हल वे शक्तियां ही निकाल सकती हैं, जो न केवल सैन्य दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक, जनसंख्या और जनमत के प्रतिनिधित्व में भी सशक्त हों। भारत इसी श्रेणी का सबसे प्रतिनिधि राष्ट्र है। यूरोप आज केवल 17 प्रतिशत वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु सुरक्षा परिषद में 40 प्रतिशत सीटें उसके पास हैं। यह अनुपात न्याय का नहीं, बल्कि छल का द्योतक है। ब्रिटेन और फ्रांस आज वैश्विक निर्णयों में निरंतर प्रभावहीन होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वे उस परिषद में बैठे हैं, जहां भारत जैसे राष्ट्र को बाहर रखा गया है। अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस सार्वजनिक रूप से भारत का समर्थन तो करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसी शर्तें भी जोड़ते हैं, जिससे सुधार असंभव बन जाए। इसे कहते हैं राजनीतिक आडंबर- जहां मित्रता की मुस्कान के पीछे प्रतिस्पर्धा की तलवार छिपी होती है। परंपरागत रूप से चीन, भारत का विरोध करता रहा है। लेकिन महबूबानी का विश्लेषण है कि चीन को भी यह समझ में आने लगा है कि यदि सुरक्षा परिषद को वैश्विक प्रतिनिधित्व और प्रासंगिकता बनाए रखनी है, तो भारत जैसे देशों को अंदर लाना अपरिहार्य है। हालांकि चीन की वास्तविक नीयत को लेकर मतभेद की संभावना बनी रहेगी।

लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि भारत को सुरक्षा परिषद में क्यों होना चाहिए। सवाल तो यह है कि भारत अब तक क्यों नहीं है? अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शक्ति का मंच है, तो भारत की अनुपस्थिति उस मंच की प्रामाणिकता को खोखला करती है। यदि यह मंच न्याय व शांति की अभिव्यक्ति है, तो भारत को वंचित रखना अनैतिकता की पराकाष्ठा है। महबूबानी का प्रस्ताव सिर्फ कूटनीतिक संकेत नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक संकेतक है। यदि ब्रिटेन अपनी स्थायी सीट भारत को सौंपता है, तो यह न केवल एक भूतकाल से मुक्ति होगी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की लगातार कम हो रही साख का पुनर्निर्माण भी होगा। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी उपस्थिति केवल एक राष्ट्र की आकांक्षा नहीं, बल्कि इस सदी के संतुलन की मांग है।

प्रसंगवश

नाइट शिफ्ट में महिलाओं को काम की छूट कागजी सुधार बनकर न रह जाए

महिलाओं से ली गई सहमति किसी दबाव या नौकरी खोने के भय से न हो

नए कानूनी प्रावधानों के बाद राजस्थान में अब महिलाओं को कारखानों में रात्रि पारी (नाइट शिफ्ट) में काम करने की अनुमति मिल गई है। यह बात जरूर है कि ड्यूटी लगाने से पहले महिलाओं की सहमति जरूरी होगी। यह निर्णय पहली दृष्टि में महिलाओं को बराबरी का अवसर देने वाला प्रगतिशील कदम प्रतीत होता है। यह तर्क दिया जाता रहा है कि बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में महिलाओं को रोजगार के हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने का अधिकार मिलना चाहिए। कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 के पारित होने के बाद इसके सकारात्मक पहलुओं को देखा जाए तो निश्चित ही महिलाओं को इस प्रावधान से रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तो एक तरह से परिवार की आय में योगदान भी मजबूत होगा। लैंगिक समानता की दिशा में भी यह सकारात्मक पहलू कहा जा सकता है। दूसरी ओर इस फैसले से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों और सामाजिक चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिला संगठनों की ओर से व्यक्त आशंकाएं भी वाजिब हैं। यह भी संदेह जताया जा रहा है कि अधिकांश महिलाएं रात्रि पारी को प्राथमिकता से नहीं चुनेंगी, बल्कि आर्थिक दबाव उन्हें इसके लिए मजबूर करेगा।

सबसे अहम मुद्दा सुरक्षा का है। रात्रि के समय कार्यस्थल से घर तक महिलाओं के सुरक्षित आवागमन की गारंटी न हो तो यह उनके लिए खतरा भी बन सकता है। केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं होंगे। कार्यस्थल पर और उसके बाहर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। रात्रि पारी में काम करने की महिलाओं की सहमति किसी दबाव या रोजगार खोने के भय से न हो। सुरक्षित परिवहन व कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा भी मुहैया कराना होगा। महिलाओं के रात्रि पारी में काम को लेकर समाज और परिवार को भी मानसिकता बदलनी होगी। महिलाओं को रात्रि पारी में सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाया तो यह कागजी सुधार बनकर रह जाएगा।

- संजय कौशिक
sanjay.kaushik@in.patrika.com

बुक इनसाइट

द वैनिशिंग प्लेस: रोमाचंक थ्रिलर

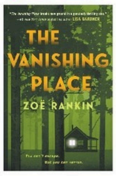

जोई रैनकिन का उपन्यास द वैनिशिंग प्लेस एक रोमांचक थ्रिलर है, जो पाठक को शुरुआत से अंत तक बांधे रखता है। किताब का वातावरण रहस्यमयी है और इसमें ऐसे मोड़ हैं, जो लगातार कहानी को अप्रत्याशित दिशा में ले जाते हैं। कहानी एक ऐसी जगह के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां पहुंचना तो आसान है, लेकिन वहां से निकलना लगभग असंभव। उपन्यास की नायिका धीरे-धीरे इस जगह के रहस्यों से जूझती है। यह जगह सिर्फ भौगोलिक रहस्य नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक डर का भी प्रतीक बन जाती है। रैनकिन ने कहानी में भय और असुरक्षा की भावना को बखूबी पिरोया है। लेखन शैली तेज, सजीव और फिल्मी अंदाज लिए हुए है। जंगल, अंधेरे और एकांत में स्थित घर का चित्रण इतना प्रभावशाली है कि पाठक को लगता है मानो वह खुद वहां मौजूद हो। लेखक ने डर व सस्पेंस को बिना किसी अतिश्योक्ति के इस तरह रचा है कि किताब को बीच में छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यह केवल एक थ्रिलर नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं और रिश्तों की जटिलताओं को भी सामने लाती है।

फैक्ट फ्रंट

क्वेट्ज़ल: कैद में नहीं रह सकता

क्वेट्ज़ल पक्षी जिसे दुनिया के खूबसूरत पक्षियों में गिना जाता है। मध्य अमरीका के बादलों से ढके घने जंगलों में पाया जाने वाला यह पक्षी अपने चमचमाते रंगों और अनोखी विशेषताओं के कारण आकर्षक है। इसका विशेष महत्व माया और अज्टेक संस्कृतियों में रहा है। क्वेट्ज़ल का आकार मध्यम होता है लगभग 33 से 40 सेंटीमीटर लंबा और नर पक्षी की पूंछ के पंख और भी लंबे हो सकते हैं जो 90 सेंटीमीटर तक पहुंच सकते हैं। नर का रंग चमकदार हरा-नीला होता है, जिसमें लाल छाती और पेट व सुनहरे-हरे पंख होते हैं। मादा थोड़ी फीकी होती है, जिसमें भूरे और ग्रे रंग के पंख होते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता कम नहीं होती। इनके पंखों का चमकदार रंग जंगली वातावरण में छिपने में मदद करता है। खास बात यह है कि इसके पंखों का रंग प्रकाश के अनुसार बदलता है। कभी यह नीला दिखाई देता है, कभी हरा और कभी सुनहरा। यही वजह है कि इसे रेस्प्लेंडेंट क्वेट्ज़ल यानी चमकदार क्वेट्ज़ल कहा जाता है। यह कभी कैद में नहीं रह सकता।

भू-राजनीति बुनियादी खाइयों को पाटना ही होगा

भारत-चीन सुलह: प्रतीकात्मक पहल या वास्तविक बदलाव

प्रो. रेणु राणा
इंटरनेशनल स्टडीज
फ्लेम यूनिवर्सिटी, पुणे
@patrika.com

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को द्विपक्षीय संबंधों में प्रतीकात्मक पिघलाव और अमरीका की टैरिफ धौंस के विरुद्ध संयुक्त रुख के रूप में देखा गया। चूंकि यह बैठक द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और रणनीतिक नैरेटिव पर असर डालने वाली थी, इसलिए भारत, चीन और रूस के अलावा अमरीकी रणनीतिकारों की भी इस पर गहरी नजर थी। दोनों नेताओं ने एक स्वर में कहा कि भारत-चीन को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि भागीदार बनकर काम करना चाहिए, पर इस कूटनीतिक परिदृश्य के परे, प्रश्न यह है कि क्या यह पहल वास्तव में कोई ठोस परिवर्तन लेकर आएगी या मात्र प्रतीकात्मक सुलह बनकर रह जाएगी?

भारत-चीन संबंधों की दिशा अब भी अनिश्चितताओं से भरी हुई है। दशकों से सीमा विवाद और कई झड़पों ने इस रिश्ते को क्षेत्रीय संघर्षों से रंग दिया है। सीमा-वार्ता द्विपक्षीय संबंधों का केंद्रीय स्तंभ रही है, पर डोकलाम और गलवान जैसी झड़पों ने इसे 1962 के बाद से सबसे खराब दौर में धकेल दिया। कूटनीति की कठिन चुनौती बातचीत शुरू करने की नहीं, बल्कि उसे निभाने की होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा सुलह और सहयोग की पहल द्विपक्षीय गर्मजोशी की बजाय बाहरी दबावों से अधिक प्रेरित है। इस रणनीतिक समीकरण ने संवाद के नए आयाम गढ़े हैं। भारत और चीन के बीच विवादित सीमा ही नहीं, बल्कि बीजिंग के पाकिस्तान से गहरे रिश्ते और असंतुलित व्यापार घाटा भी मतभेदों का कारण है। यदि चीन भारत के रुख को लेकर प्रतिबद्ध व सहयोगी होता तो एससीओ या ब्रिक्स में भारत के पक्ष में अधिक सक्रिय रुख अपनाता।

ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाजें होने के नाते भारत और चीन को अपने रिश्तों में बिछी बुनियादी खाइयों को पाटना ही होगा, तभी स्थायी- यदि और मजबूत नहीं तो कम से कम स्थिर-संबंध संभव हो पाएंगे। हाल की घटनाएं बताती हैं कि बीजिंग भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रुख अपना रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा-वार्ताओं को अधिक परिणामोन्मुख और गहन होना पड़ेगा तभी द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो पाएंगे।

अब समय ही बताएगा कि भारत चीन के 'खुलेपन' पर अधिक भरोसा करेगा या फिर अमरीका की उस नीति पर ध्यान देगा, जिसे कई लोग उपेक्षापूर्ण मानते हैं। यह भी संभव है कि अमरीका अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन कर भारत के साथ संबंधों को नई सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाने का प्रयास करे।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

कलात्मक प्रतिमाओं वाली येलांग वैली

चीन के गुइझोउ प्रांत की सुरम्य वादियों में बसी येलांग वैली अपनी अनोखी कलात्मकता के कारण दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। नदी के दोनों किनारों पर खड़ी विशालकाय मूर्तियां यहां की पहचान बन चुकी हैं। इन मूर्तियों के चेहरे किसी प्राचीन पौराणिक गाथा से निकले प्रतीत होते हैं। अतिरंजित भाव-भंगिमाएं और गहरी आंखें इन्हें और भी रहस्यमयी बनाती हैं। इन मानवाकृति प्रतिमाओं को किसी महंगे या दुर्लभ पत्थर से नहीं, बल्कि पुराने मिट्टी के बर्तनों, टाइलों, पत्थरों और अन्य परित्यक्त सामग्रियों से गढ़ा गया है। ये सृजनशीलता का संदेश भी देते हैं।

समाज दर्पण परस्पर स्नेह को प्राथमिकता देनी चाहिए

पैसों की चमक के कारण खो गई रिश्तों की ऊष्मा

डॉ. गौरव बिस्सा
प्रोफेसर और लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर
@patrika.com

एक या डेढ़ दशक पहले की सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होते थे। आपसी रिश्तों में गर्माहट दिखती थी क्योंकि परस्पर निर्भरता थी, लोगों को एक दूसरे की परवाह थी। जैसे मेहमान आने पर एक पड़ोसी दूसरे से चारपाई लेने आए, यह निर्भरता थी। अब सभी धनाढ्य हैं। निर्भरता को या परवाह करने को अब कमजोरी माना जाने लगा है। इस परवाह में स्नेह छिपा होता था, जुड़ाव बढ़ता था और अहंकार नहीं होता था। अब हर सुविधा के लिए पैसा तैयार है। 'पैसा फेंको, तमाशा देखो' - इस समाज का नया गुरुमंत्र प्रतीत होता है।

पैसे से उपलब्ध होने वाले संसाधनों ने आपसी प्रेम को मानो पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। व्यक्ति अपने मित्र, भाई, और यहां तक कि माता-पिता पर भी निर्भरता नहीं चाहता। उसे लगता है कि पैसा फेंककर कुछ भी मिल सकता है। इसी सोच के चलते वर्तमान युवा येन केन प्रकारेण सिर्फ धन कमाने में व्यस्त है। यहां यह सोचने योग्य बात है कि क्या पैसे से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है? रिश्तों की संवेदना और उसमें बसने वाला प्रेम अब समाप्ति की ओर है। हर रिश्ते को बनाए रखने के लिए पैसा हाजिर है। माता-पिता की सेवा हो या नवजात शिशु का पालन-पोषण, घर पर भोजन निर्माण हो या छोटे-मोटे घरेलू कार्य, इन्हें संपादित करने के लिए पैसे देकर सेवक रख लेना नया शगल है। आपत्ति सेवक रखने से नहीं, अपितु समस्या रिश्तों के तारों के ढीले पड़ने की है। इस वजह से व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क में आपसी स्नेह भाव में कमी तथा मन के रिश्तों में खटास आ रही है। वर्तमान में व्यक्ति पैसा खर्च करने को तो तैयार है परंतु समय देने में उसे आपत्ति है। बस यही प्रवृत्ति समाज को खोखला किए जा रही है।

आपसी परवाह के कारण पहले लोग एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते थे। अब कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। रिश्ते बनने का अब सिर्फ एक ही कारण है और वह है स्वार्थ। स्वार्थ न रहा तो रिश्ता खत्म होने में देर नहीं लगाई जा रही क्योंकि अब निर्भरता और परवाह तो है ही नहीं। हर व्यक्ति स्वच्छंद है। रिश्तों की ऊष्मा को बचाने के लिए 'पैसों' की जगह 'परस्पर स्नेह' को प्राथमिकता देना ही उत्तम जीवन का आधार होना चाहिए। जीवन दूसरों की परवाह करने और संबंधों पर टिका है। पेशा चाहे कोई भी हो, व्यक्ति की असली ताकत है परवाह करना और प्रेमपूर्ण संबंध बनाना। काम सिर्फ संबंध ही आते हैं। संबंध अच्छे तभी बन सकते हैं, जब आपमें समानुभूति का भाव हो।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

आपकी बात

फर्जी दस्तावेज रोकने में कारगर

जन्म के साथ आधार कार्ड फर्जी दस्तावेज को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। इससे न केवल वास्तविक भारतीय नागरिक की पहचान होगी, अपितु कई योजनाओं का फायदा डीबीटी के माध्यम से लेना सरल होगा।

- **कृष्णकांत शर्मा,** हिंडौन सिटी

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'जन्म के साथ आधार कार्ड बनने से आपकी नजर में क्या-क्या फायदे होंगे?' अन्य प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें। https://shorturl.at/ongsX

आज का सवाल

प्राचीन शिक्षा परंपरा को पुनर्जीवित करने को लेकर आपके क्या विचार हैं?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

विसंगति 25 करोड़ से अधिक बीमाधारक अब भी जीएसटी के बोझ तले, पुनर्विचार की आवश्यकता

व्यक्तिगत बीमा पर जीएसटी छूट, लेकिन समूह पॉलिसी बाहर क्यों?

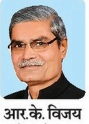

आर.के. विजय
लेखक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में उप महाप्रबंधक रहे हैं

वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यधिक महंगे स्वास्थ्य बीमा में तो 18 प्रतिशत की राहत बहुत मायने रखती है। लेकिन यह आंशिक इसलिए है क्योंकि इसी श्रेणी के समूह बीमा पर यह राहत नहीं दी गई है। क्योंकि बीमा प्रीमियम तथा इस पर लागू जीएसटी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से व्यक्तिगत तौर पर ही चुकाया जाता है।

जीवन बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाने की मांग वर्षों से चली आ रही थी। जीएसटी परिषद के माध्यम से जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत सरकार ने यह मांग आंशिक तौर पर मानते हुए सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा (पॉलिसियों) तथा इनके पुर्नबीमा (रिइंश्योरेंस) को जीएसटी से पूर्णतया मुक्त कर दिया है। सरकार का यह फैसला निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। स्वास्थ्य बीमा की विशेष प्रकृति के कारण वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यधिक महंगे स्वास्थ्य बीमा में तो 18% की यह राहत बहुत मायने रखती है। जीवन तथा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर यह राहत आंशिक इसलिए है क्योंकि इसी श्रेणी के समूह बीमा (बीमाधारक तथा बीमित के बीच किसी विशेष संबंध के चलते बहुत से लोगों का एक ही पॉलिसी के तहत बीमा) पर यह राहत नहीं दी गई है।

समूह बीमा पॉलिसियां एक ऐसी व्यवस्था है, जिसका आमतौर पर आधार सुविधा तथा मितव्ययिता होता है। इन पॉलिसियों में एक साथ बड़ी संख्या में बीमित व्यक्तियों के मद्देनजर बीमा प्रीमियम की दरें भी अपेक्षाकृत कम होती हैं। इसलिए आमतौर पर इन पॉलिसियों का इस्तेमाल होता है लेकिन बीमा प्रीमियम तथा इस पर लागू जीएसटी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से व्यक्तिगत तौर पर ही चुकाया जाता है। भारत में सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कर्मचारियों का ही उदाहरण लें। इन कर्मचारियों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी तो नियोक्ता कंपनी लेती है, लेकिन व्यक्तिगत कर्मचारी का प्रीमियम तथा जीएसटी उसके वेतन से तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों से सीधे लिया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों का एक बड़ा समूह, जिन्हें इस राहत की सबसे अधिक आवश्यकता थी, वह भी इससे वंचित रह गया है। सुविधा तथा मितव्ययिता की दृष्टि से बहुत से सरकारी तथा निजी क्षेत्र के नियोक्ता अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तथा बहुत से कर्मचारी संगठन व वरिष्ठ नागरिकों के अन्य सामाजिक संगठन अपने सेवानिवृत सदस्यों को समूह स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन इन पॉलिसियों में भी प्रीमियम तथा इस पर लागू जीएसटी व्यक्तिगत तौर पर ऐसे समूहों के सदस्यों से लेकर ही चुकाया जाता है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की नई वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में देश में कुल 2.68 करोड़ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां जारी की गई थी। इनमें 57.28 करोड़ लोगों को बीमित किया गया था, जिनका कुल प्रीमियम 1,07,680 करोड़ रुपए था। इनमें सरकारों की ओर से प्रायोजित पॉलिसियों के अलावा 25.59 करोड़ व्यक्ति समूह बीमा पॉलिसियों के तहत बीमित थे, जिन्होंने 55,666 करोड़ रुपए प्रीमियम चुकाया था जबकि 5.58 करोड़ लोग व्यक्तिगत पॉलिसियों के तहत बीमित थे, जिन्होंने 41,501 करोड़ रुपए प्रीमियम चुकाया था यानी जीएसटी 2.0 सुधारों के बावजूद 25.59 करोड़ स्वास्थ्य बीमाधारक जीएसटी में राहत के हकदार नहीं होंगे तथा 18% जीएसटी का भार ढोते रहेंगे।

इनमें कई ऐसे बुजुर्ग भी शामिल हैं जिन्हें मूल प्रीमियम ही वहन करने में मशक्कत करनी पड़ती है, 18% जीएसटी तो एक अतिरिक्त बड़ा भार है। जीवन बीमा की जीएसटी मुक्त श्रेणी के उन व्यक्तियों की बड़ी संख्या अलग है, जो समूह बीमा पॉलिसियों के तहत बीमित होते हैं। इतने बड़े समूह को जीएसटी राहत से वंचित रखना अनुचित है। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए तथा इस बड़े नागरिक-समूह को भी समूह बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी हटाकर इस भार से मुक्त करना चाहिए।

प्रेरणा

जहां पहली कोशिश नाकाम हो जाए, वहां दूसरी कोशिश नए उत्साह के साथ कीजिए। - **नारायण मूर्ति, उद्यमी**

संपादकीय

कागज का टुकड़ा बनकर न रह जाए आयुष्मान कार्ड

कई उत्तर भारतीय राज्यों में निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए सेवा देना बंद करने की बात कही है। उनका कहना है इलाज के बाद सरकार बिल का भुगतान देर से करती है। देश में 41 करोड़ आयुष्मान कार्डधारक हैं और 40% परिवारों को आयुष्मान मुफ्त स्वास्थ्य सेवा में कवर करने का दावा है। लेकिन क्या कभी सरकार ने सोचा है कि कार्ड धारण करने भर से गांव/ब्लाक-जिले के चिकित्सा केंद्र या अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल जाते या दवाएं नहीं उपलब्ध हो जातीं? 2018 में सबको स्वास्थ्य की लोकप्रिय अवधारणा के तहत आयुष्मान योजना शुरू की गई थी। संसद में बताया गया कि अगले चार साल में जीडीपी का 2.5% प्रतिशत स्वास्थ्य के मद में खर्च किया जाएगा। लेकिन सात साल बाद भी अभी तक यह प्रतिशत 1.20 से बढ़कर 1.90 ही हो सका है। इसमें भी खास बात यह है कि राज्यों ने तो अपना स्वास्थ्य बजट का प्रतिशत बढ़ाया लेकिन केंद्र ने नहीं। चूंकि स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होती गईं, लिहाजा डब्ल्यूएचओ के अनुसार लोगों का अपनी जेब से इस मद में खर्च बेतहाशा बढ़ा है। 70% सरकारी अस्पताल शहरों में हैं, इसलिए ग्रामीण भारत के लोग इस सेवा से महरूम हैं और कार्ड मात्र एक कागज का टुकड़ा बनकर रहा गया है। आयुष्मान योजना की सफलता के लिए गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूत करना अनिवार्य है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

ध्यान का ही एक और प्रयोग है पितरों का स्मरण करना

जब चेतना अकेली होती है, तब ध्यान लगता है। और यदि चेतना माया से जुड़ गई, तो हम उलझ जाते हैं। रामकथा में पक्षीराज गरुड़ ऐसे ही उलझ गए थे। उन्होंने रामजी का बंधन काटा युद्ध के दौरान, तो उन्हें लगा मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन परेशान हो गए। तो देवर्षि नारद के पास गए और अपना संदेह बताया- ब्याकुल गयउ देवरिषि पाहीं। कहेसि जो संसय निज मन माहीं।। तब नारद ने कहा था कि गरुड़, श्रीराम की माया बड़ी बलवती है। मुझे भी कई बार इस माया ने नचाया है। सावधान हो जाओ और ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। अब इसमें यह संकेत मिलता है कि हम संसार में रहते हैं तो कहीं ना कहीं उलझेंगे जरूर। तो संत के पास जाने से, सत्संग करने से, गुरु का सान्निध्य प्राप्त करने से हम ध्यान की तरफ जा सकते हैं और माया से मुक्त होंगे। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। ध्यान लगाने का एक और प्रयोग है कि हम अपने पितरों का स्मरण करें। उनके निमित्त शुभकार्य करें, तब भी हम ध्यान की तरफ चल पड़ते हैं। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

दूरदृष्टि • भारत का चीन से सुरक्षा संबंध जटिल है

चीन अब ज्यादा जरूरी, पर अमेरिका-विरोध जल्दबाजी

भू-राजनीति

आशुतोष वार्ष्णेय
ब्राउन यूनिवर्सिटी, अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर

जब मैं यह कॉलम बोस्टन से लिख रहा था, तब अमेरिका के बड़े अखबारों में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तियानजिन बैठक की तस्वीरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई थीं। तस्वीरों में तीनों नेता मुस्करा रहे थे और गर्मजोशी से मिल रहे थे। कहा गया कि ट्रम्प की नीतियां इन्हें करीब ला रही हैं और भू-राजनीति में अमेरिका-विरोधी एकता का रास्ता खोल रही हैं।

अमेरिका-विरोधी एकता की बात जल्दबाजी होगी। चीन व भारत के अमेरिका से अहम संबंध हैं, जिन्हें तोड़ना एक बड़ी कीमत पर ही संभव होगा। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2024 के अंत तक उसकी जीडीपी 29.18 ट्रिलियन डॉलर थी, जो विश्व अर्थव्यवस्था (111.33 ट्रिलियन) की 26.2% है। इतना बड़ा बाजार नकारा नहीं जा सकता।

लेकिन इसमें शक नहीं कि अमेरिका की शीतयुद्धोत्तर विदेश नीति से बिल्कुल अलग ट्रम्प की नीतियां नए भू-राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य बना रही हैं। देशों को अपनी विदेश नीतियों में बदलाव करते समय इन तब्दीलियों को ध्यान में रखना होगा। हालांकि, तीन चीजें स्थिर रहेंगी : व्यापार शुल्क का इस्तेमाल, इमिग्रेशन का विरोध और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में अमेरिकी निवेश घटना। बड़े बदलाव केवल तभी हो सकते हैं, जब इन नीतियों का असर ट्रम्प के समर्थकों के लिए विनाशकारी हों। ट्रम्प के व्यापार शुल्क से बुरी तरह झटका खाने के बाद भारत को अपने आगे का रास्ता कैसे सोचना चाहिए? मेरा मानना है कि चीन भारत की विदेश नीति में हाल के वर्षों से भी अधिक केंद्रीय भूमिका निभाएगा। लेकिन भारत अपने हितों को चीन के साथ कैसे आगे बढ़ाएगा?

पहली जटिलता यह है कि अब भारत चीन के सामने काफी कमजोर स्थिति से काम करेगा। जब अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ मजबूत किला मानता था- कम से कम इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में- तो अमेरिकी समर्थन ने दिल्ली की ताकत बढ़ाई थी। अगर हम मान लें कि अगले कुछ साल के लिए इंडो-पैसिफिक में शक्ति-संतुलन का असर नहीं रहेगा, तो भारत चीन से केवल एक अकेली ताकत के रूप में निपटेगा, न कि अमेरिका के समर्थन वाली ताकत के रूप में।

फिर भी, चीन के साथ संबंध बनाने में भारत का हित है। यह आज दुनिया की दूसरी महाशक्ति है, जो आर्थिक और रणनीतिक शक्ति दोनों रखती है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था पिछले तीस साल में सालाना 8-9% की दर से बढ़ती, तो यह कुछ हद तक चीन के बराबर हो सकता था। भारत की आर्थिक वृद्धि 1991 के बाद बढ़ी, लेकिन यह चीन के स्तर तक नहीं पहुंची।

कहा जाता है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन यह भारत और चीन के बीच के अंतर के बारे में कुछ नहीं बताता। 2024 के अंत तक भारत की जीडीपी 3.9 ट्रिलियन डॉलर थी (हाल ही में यह 4 ट्रिलियन को पार कर गई)। यह यूके (3.6 ट्रिलियन) और फ्रांस (3.2 ट्रिलियन) से अधिक है, लेकिन यह चीन की जीडीपी (18.7 ट्रिलियन) का लगभग पांचवां हिस्सा था। कुल अर्थव्यवस्था का आकार देखें, तो जर्मनी (4.7 ट्रिलियन) और जापान (4 ट्रिलियन) भी उस समय चीन से काफी पीछे थे।

यह अंतर भारत के लिए गंभीर नतीजे रखता है। ट्रम्प के टैरिफ के बाद अमेरिकी बाजारों में लगभग 65-70% भारतीय निर्यात के खरीदार खो गए हैं। बाजार विविधीकरण रणनीति जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अवसर तलाशना भी समझदारी होगी। जहां भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का केवल 3.5% है, चीन का आंकड़ा 16.8% है। चीन का भारत के मुकाबले व्यापार में ज्यादा फायदा है। अमेरिकी बाजारों

अमेरिका-विरोधी एकता की बात जल्दबाजी होगी। चीन व भारत के अमेरिका से अहम संबंध हैं, जिन्हें तोड़ना बड़ी कीमत पर ही संभव होगा। अमेरिका आज भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतने बड़े बाजार को नकारा नहीं जा सकता।

के कम होने के कारण भारत को इस घाटे को कम करने के लिए चीनी बाजारों की तलाश करनी होगी।

चाइना प्लस वन रणनीति का मूल विचार यह था कि अमेरिका-चीन तनाव से बचने के लिए अमेरिकी निवेशक धीरे-धीरे चीन से बाहर आएंगे और वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और भारत में निवेश करेंगे। एपल ने भारत को चुना, जबकि कई अन्य कंपनियों ने वियतनाम में निवेश किया। एपल का भारत से निर्यात फिलहाल अमेरिकी टैरिफ से बच गया है, लेकिन अन्य निवेशकों के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए, भारत में अमेरिकी निवेश लगभग निश्चित रूप से घटेगा। चीन इस अंतर को पाट सकता है। एक और गैर-अमेरिकी बाजार है, जो चीन के बराबर है। अगर ईयू को एक आर्थिक इकाई के रूप में देखें, तो इसकी जीडीपी 19.4 ट्रिलियन है। लेकिन भारत का चीन से सुरक्षा संबंध कठिन है। आर्थिक संबंध के तर्क से सुरक्षा तर्क कैसे प्रभावित होंगे, इस प्रश्न का समाधान करना चीन नीति के लिए बड़ी चुनौती होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नजरिया • पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है यूएस

अतीत बताता है कि 2025 की पटकथा नई नहीं है

इतिहास

अर्घ्य सेनगुप्ता
विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के रिसर्च डायरेक्टर

इतिहास बताता है कि ये पहली बार नहीं है, जब अमेरिका ने भारत को दुनिया में उसकी हैसियत बताने की कोशिश की है। ट्रम्प का रवैया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के एक घटनाक्रम की याद दिलाता है। इतिहास का यह सबक विदेश नीति के लिए उपयोगी है।

टोक्यो ट्रायल्स नवंबर 1948 में समाप्त हुए थे। इनमें जापान के 7 'क्लास-ए युद्ध अपराधियों' को फांसी और 16 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ट्रिब्यूनल में शामिल भारतीय जज राधाबिनोद पाल ने कानूनी तर्कों के आधार पर असहमति दर्ज करते हुए सभी जापानी प्रतिवादियों को बरी कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे अमेरिकी नाराज हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका जापान में अमेरिकी शैली का लोकतंत्र स्थापित करना चाहता था। पाल की असहमति ने दिखाया कि ट्रिब्यूनल स्वतंत्र है। मुकदमे में निष्पक्षता है और कानून ही सर्वोपरि है। अमेरिकियों के लिए यह पूरी तरह उपयुक्त था।

दूसरी ओर, भारत सरकार पाल के मत को लेकर संशय में थी। प्रधानमंत्री नेहरू ने इसकी आलोचना की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि फैसले में जापान में भारत की दृश्यता बढ़ाने की संभावना है तो अपने रुख को सुधार लिया। यही कारण था कि जापान में भारतीय राजदूत बेनेगल रामा राव ने नई दिल्ली में अपने समकक्षों को इस निर्णय की खुली निंदा नहीं करने की सलाह दी। 1952 में भारतीय राजदूत रहे एमए रऊफ ने ऑन-रिकॉर्ड लिखा कि पाल के विचारों ने भारत के लिए सद्भावना बटोरी थी। नेहरू ने भी 14 मई 1954 को संसद में एक सवाल के जवाब में पाल के मत को विद्वत्तापूर्ण असहमति वाला फैसला करार दे दिया।

इस समय तक अमेरिकियों ने भी जापान में अपनी रणनीति बदल दी थी। जापान अमेरिकी लोकतंत्र की प्रयोगशाला नहीं रह गया था। इसे रूस और चीनी साम्यवाद के खिलाफ मजबूत गढ़ बनाना था। सैन फ्रांसिस्को संधि 1951 के अंत में हस्ताक्षरित और 1952 की शुरुआत में अनुमोदित हुई, ताकि जापान पर मित्र देशों का कब्जा समाप्त हो सके। टोक्यो ट्रायल के मूल भागीदारों में से चीन, सोवियत संघ और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, ना इसे अनुमोदित किया। भारत का विरोध सैद्धांतिक था कि एशिया का भविष्य अमेरिका द्वारा निर्धारित नहीं होना चाहिए, जो अपने सैन्य हितों के लिए क्षेत्र में ठिकाने बनाए रखना चाहता है। विचारों की विविधता को स्वीकारने वाले किसी भी देश के लिए सैद्धांतिक असहमति बड़े महत्व की बात नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बदली अमेरिकी नीति के तहत तय हुआ कि जापान के सभी 'क्लास-ए' युद्ध अपराधियों को जेल से रिहा किया जाएगा। संधि के अनुसार, यह निर्णय उन सरकारों के बहुमत द्वारा किया जाएगा, जिनके जजों ने ट्रायल में भाग लिया था। नतीजतन, नवंबर 1952 में जापान ने कैदियों को रिहा करने के लिए भारत से सहमति मांगी। भारत ने देखा कि यह पाल के मत के अनुरूप है तो सहमति दे दी।

लेकिन मार्च 1953 में जापान ने शर्मिंदगी भरे लहजे में भारत को बताया कि उसकी सहमति मायने नहीं रखती, क्योंकि अमेरिका का मत है कि भारत ने सैन फ्रांसिस्को संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए उसको इस निर्णय से बाहर रखा जाएगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि भारत तो वैसे भी कैदियों की रिहाई के लिए सहमति दे चुका था। फिर भी अमेरिका एक बड़ा संदेश देना चाहता था। उसने जानबूझकर भारत को अलग-थलग किया और यह सुनिश्चित किया कि अन्य सभी मित्र देश किसी तोते

2025 में ट्रम्प उसी पटकथा का अनुसरण कर रहे हैं, जिसे 1953 में अपनाया गया था। ट्रम्प का रवैया अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन भारत पर टैरिफ थोपना और पाकिस्तान की ओर उनका झुकाव अप्रत्याशित नहीं है।

की तरह अमेरिकी रुख को दोहराएं।

बात यहीं नहीं रुकी। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने प्रस्ताव रखा कि पाकिस्तान को मताधिकार देना चाहिए। यह बेहद अजीब था, क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रायल में भाग ही नहीं लिया था। लेकिन अमेरिकी वकीलों ने कपटपूर्ण तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल में ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व था, इसलिए पाकिस्तान को भी इसमें भाग लेने का अधिकार है। जैसा कि मैनचेस्टर गार्डियन उस वक्त लिखा कि भारत की जगह पाकिस्तान को मताधिकार देना भारत को उकसाने की कोशिश थी।

2025 में ट्रम्प भी उसी पटकथा का अनुसरण कर रहे हैं। ट्रम्प का रवैया अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन भारत पर टैरिफ थोपना और पाकिस्तान की ओर उनका झुकाव अप्रत्याशित नहीं है। अमेरिकी विदेश नीति में यह आम है। भारत ने पहले 1953 और अब 2025 में इसे झेला है। हमें इससे सबक सीखने चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दैनिक भास्कर
अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

इस हफ्ते चर्चा में...

करोड़पतियों को भी किराए के मकानों में रहना पसंद

13,992
हो गई है अमेरिका में किराए के मकानों में रहने वाले करोड़पतियों की संख्या। संपत्ति के मूल्यों में उछाल के कारण यह ट्रेंड बढ़ा है।

2 लाख करोड़ रुपए
आय हुई है अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग को पिछले साल।

30,805 करोड़ रुपए
जुर्माना किया है, यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर एकाधिकार विरोधी कानून तोड़ने के लिए।

कार्रवाई

इमिग्रेशन छापों की चपेट में कोरियाई कंपनियां

विदेशी आप्रवासियों के खिलाफ अभियान के घेरे में अमेरिका के मित्र देश दक्षिण कोरिया की कंपनियों भी आ गई हैं। पिछले सप्ताह अधिकारियों ने जार्जिया राज्य में एक बैटरी कंपनी के प्लांट पर छापा मारकर 500 कामगारों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी दक्षिण कोरियाई हैं। यह प्लांट एलजी एनर्जी सॉल्यूशंस और ह्युंडई मोटर ग्रुप का साझा उपक्रम है। हालांकि, कोरियाई कामगारों को छोड़ने का समझौता हो गया है। इन्हें दक्षिण कोरिया वापस भेजा जाएगा। अधिकारियों ने इसे होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की किसी एक स्थान पर सबसे बड़ी कार्रवाई बताया है। यह प्लांट अमेरिकी मार्केट में होड़ के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनियों की महत्वाकांक्षा की झलक दिखाता था। इमिग्रेशन अधिकारियों के अभियान से इस अभियान को धक्का लगा है। दक्षिण कोरिया ने गिरफ्तारियों पर निराशा जताई है। 2023 में अमेरिका में नए प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा निवेश दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने किया है। © The New York Times

टेक्नोलॉजी • दुनियाभर में घोटालेबाज एआई की मदद से सोशल मीडिया पर डॉक्टरों को हेल्थ प्रोडक्ट्स का प्रचार करते दिखा रहे

एआई से डॉक्टरों के फर्जी पोस्ट बना बेची जा रहीं नकली दवाएं

स्टीवन मायर्स, एलिस कैलहन, टेडी रोसेनब्लथ

असली डॉक्टरों के नाम से फर्जी नुस्खों और प्रोडक्ट का कारोबार बढ़ता जा रहा है। दुनियाभर में सोशल मीडिया पर संदिग्ध हेल्थ केयर प्रोडक्ट बिक रहे हैं। एआई के इस्तेमाल से विशेषज्ञों के वीडियो बनाए जाते हैं। नामी डॉक्टर के चेहरे और आवाज की नकल से धोखाधड़ी होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार एआई टूल्स ने घोटालेबाजों का काम आसान बना दिया है।

लंबे समय से धोखेबाज स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में फर्जी कारोबार चला रहे हैं। इंटरनेट से उनकी पहुंच करोड़ों लोगों तक हो गई है। इससे चिकित्सा पेशे में लोगों का भरोसा कम हो रहा है। मरीजों की जान के लिए खतरा अलग है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर डॉ. रॉबर्ट लस्टिग को फेसबुक पोस्ट में इंजेक्शन, सर्जरी के बिना वजन घटाने की दवाई का प्रमोशन करते दिखाया गया है। जबकि डॉ. लस्टिग ने ऐसा नहीं किया है।

डायबिटीज, मोटापे के संबंध में बहुत ज्यादा नकली प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। फर्जी मार्केटिंग अभियान में मैक्सिको, नार्वे, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड सहित कई देशों की रेगुलेशन एजेंसियों के लोगो लगाए जा रहे हैं। इससे प्रोडक्ट को सरकारी मंजूरी की झूठी तस्वीर पेश की जाती है।

फर्जी तरीके से बेचे गए प्रोडक्ट खतरनाक नहीं हो तब भी लोगों में झूठी उम्मीदें जगाते हैं। अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अन्य सरकारी एजेंसियों, निजी संगठनों ने ऑनलाइन नकली या फर्जी हेल्थ प्रोडक्ट्स के खिलाफ लोगों को आगाह करने का अभियान तेज कर दिया है। एआई के फर्जी उपयोग पर नजर रखने वाली पिनड्रॉप के प्रमुख विजय बालसुब्रमण्यम कहते हैं, किसी की हूबहू इमेज और आवाज बनाने के टूल से घोटालेबाज असली जैसा प्रभाव पैदा करते हैं।

एआई टूल्स ने कंटेंट बनाना और फैलाना आसान कर दिया है। ये प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी के खिलाफ अपनी ही नीतियों को लागू नहीं करते हैं। ब्रिटेन में डॉक्टर गेमा न्यूमैन ने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स को टिकटॉक पर चल रहे एक वीडियो के बारे में आगाह किया था। इसमें वे विटामिन बी 12 और 9000 मिलीग्राम पोषण से भरपूर गाजर के कैप्सूल की खूबियां बताते दिखाई गई हैं।

मेडिकल विशेषज्ञों की नकल सप्लीमेंट्स तक सीमित नहीं है। स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट सैन डिएगो में कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉ. एरिक टोपोल की नई किताब के एआई अवतार अमेजन पर हैं। उनके एक मरीज ने कवर पर डॉ. टोपोल की एआई से बनाई गई तस्वीर वाली किताब अनजाने में खरीद ली। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशन साइंटिस्ट क्रिस्टोफर गार्डनर सैकड़ों वीडियो में बुजुर्गों को हड्डियों व जोड़ों के दर्द के संबंध में सलाह देते हैं। © The New York Times

सही जानकारी मिलना मुश्किल

कैंसर विशेषज्ञ डॉ. एलिओनोरा टेपिलिंस्की का कहना है, सेहत के बारे में ऑनलाइन सही जानकारी हासिल करना मुश्किल है। उनके नकली पोस्ट सोशल मीडिया पर हैं। वे कहती हैं, लोग कैसे जानेंगे कि ये पोस्ट मेरे नहीं हैं।

सही बड़े ब्रांड्स के लिए खतरा

फेसबुक पर डॉ लस्टिग के नाम से प्रसारित एक सप्लीमेंट पर नकली पोस्ट अन्य देशों में भी बनाई गई हैं। इनमें कुछ ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के असली डॉक्टरों की हैं। इजराइल में साइबर सिक्योरिटी कंपनी ब्रांड शील्ड के प्रमुख योआव केरेन का कहना है, इस अभियान से दुनिया में बड़े ब्रांड्स के लिए खतरा खड़ा हो गया है।

जीएलपी-1 की बिक्री बढ़ी

डायबिटीज, मोटापे और संबंधित बीमारियों के इलाज में बहुत अच्छे नतीजे देने वाली दवाइयों जीएलपी-1 की लोकप्रियता से घोटालेबाजों ने फायदा उठाया है। इस लिक्विड कैप्सूल की शक्ल में पीएका नाम से पेश की गई है। वैसे जीएलपी-1 इंजेक्शन के रुप में ही उपलब्ध है। हॉन्गकॉन्ग में रजिस्टर्ड वेबसाइट पर इन्हें बेचा गया है।

ओपिनियन • चीन कई मामलों में अमेरिका से आगे

अमेरिका सहयोगी देशों के बिना चीन का मुकाबला नहीं कर सकता

कुर्ट कैम्पबेल, रश दोषी (कैम्पबेल और दोषी पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की सरकार में रह चुके हैं)

आधुनिक इतिहास में पहली बार अमेरिका के सामने एक प्रतिद्वंद्वी चीन है। उसके पास विश्व में दबदबा बनाए रखने के लिए जरूरी क्षमता है। चीन की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका की राष्ट्रीय क्षमता नाकाफी है। उसकी सर्वोच्चता सहयोगियों की एकजुटता पर निर्भर करेगी। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उल्टी दिशा में जा रहे हैं। उनकी टैरिफ कूटनीति ने सहयोगियों को अलग कर दिया है और बीजिंग के लिए अपने गठबंधन बनाने के दरवाजे खोल दिए हैं।

सहयोगियों को दूर करने का नया उदाहरण भारत पर लगाया गया भारी टैरिफ है। अमेरिका ने चीन के सामने भारत को खड़ा करने के लिए तीन दशक तक प्रयास किए हैं। टैरिफ लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात साल में पहली बार चीन यात्रा की। वहां मोदी और राष्ट्रपति शी जिन पिंग ने तनावपूर्ण रिश्तों के इतिहास को पीछे छोड़ते हुए सहयोगियों के बतौर काम करने का इरादा जताया है। बीसवीं सदी में अमेरिका ने अर्थव्यवस्था और इनोवेशन में जर्मनी, जापान और सोवियत संघ को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन चीन अलग है। सामरिक होड़ के कई मामलों में वह अमेरिका से आगे निकल चुका है। अर्थव्यवस्था की गति धीमी है लेकिन उसके पास मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता दोगुनी है। चीन के सामने बुजुर्ग होती आबादी, बहुत बड़ी औद्योगिक उत्पादन क्षमता और भारी कर्ज जैसी समस्याएं हैं।

औद्योगिक क्रांति का फायदा ब्रिटेन को मिला था पर अमेरिका, सोवियत संघ जैसे बड़े देश उससे आगे निकल गए। आज यह स्थिति अमेरिका की है। वह गठबंधनों के जरिये अपनी ताकत बढ़ाकर चीन का मुकाबला कर सकता है।

अमेरिका कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीन की तुलना में छोटा है। लेकिन यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा, मैक्सिको, ताइवान को मिलाकर उसका कोई मुकाबला नहीं है। इस गठजोड़ की जीडीपी चीन से दोगुनी है। दुनिया की आधी मैन्युफैक्चरिंग यहां है। टैलेंट और बाजार की ताकत भी चीन के दबाव को झेल सकती है। अमेरिका और सहयोगी देश भविष्य के विजेता होंगे। भागीदारी के जरिये अमेरिका और सहयोगी बढ़त बनाए रख सकते हैं। अगर ट्रम्प चीन की विराट क्षमता के सामने संतुलन की स्थिति नहीं बनाते हैं तो वे अमेरिका को छोटा व अलग-थलग ही करेंगे। © The New York Times

कॉपीराइट

एंथ्रोपिक लेखकों को 13 हजार करोड़ रुपए देगी

केड मेट्ज

प्रमुख एआई कंपनी एंथ्रोपिक एक समझौते के तहत लेखकों और प्रकाशकों को 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक देने के लिए तैयार हो गई है। एक अदालत ने फैसला दिया कि कंपनी ने अवैध रूप से लाखों कॉपीराइट किताबों को डाउनलोड और स्टोर किया है। अमेरिका में कॉपीराइट मामलों में यह सबसे बड़ा भुगतान है। एंथ्रोपिक 5 लाख लेखकों को 2 लाख 60 हजार रुपए प्रति रचना के हिसाब से देगी। यह समझौता एआई कंपनियों और कॉपीराइट धारकों के बीच चल रही लड़ाई में निर्णायक मोड़ है। अमेरिकी अदालतों में इस तरह के 40 मुकदमे दायर किए गए हैं। इस समझौते से और अधिक टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा कॉपीराइट धारकों को पैसा देने का रास्ता खुलेगा। कैलिफोर्निया में नार्दर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज विलियम एलसप ने जून में फैसला दिया था कि ऑनलाइन चैटबॉट क्लॉड की कंपनी एंथ्रोपिक ने कॉपीराइट किताबों को कानूनी तरीके से हासिल किया है। कानून के अनुसार कंपनी किताबों से एआई की ट्रेनिंग कर सकती है। लेकिन जज ने यह भी पाया कि एंथ्रोपिक ने ऑनलाइन लायब्रेरियों से लाखों किताबें ली हैं। © The New York Times

युद्ध • 90 प्रतिशत आबादी बेघर हो चुकी है

गाजा में क्षतिग्रस्त घरों को नए सिरे से बनाने में 80 साल लग जाएंगे

राजा अब्दुलरहीम

इन दिनों गाजा में कई बुजुर्ग अतीत के भयावह दौर की याद करते हैं। उस वक्त लाखों फिलिस्तीनियों को बेघर होना पड़ा था। वे इसे नकबा यानी महासंकट कहते हैं। 1948 में दस साल के रहे अबू सामरा अकसर अपने परिवार के लोगों को वह वाकया सुनाते हैं। अब उन्हें फिर नकबा का डर सता रहा है। कुछ समय पहले इजराइल ने गाजा की अधिकतर आबादी को गाजा-मिस्र की सीमा पर एक इलाके में खदेड़ने की योजना पेश की है। उस पर अमल के लिए इजराइली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है, लाखों लोगों को अनिश्चित काल के लिए बेघर करना अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। गाजा में लगभग 80 प्रतिशत बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं। इजराइली सैन्य अभियान तेज होने से बची-खुची इमारतें भी नष्ट हो रही हैं। विश्व बैंक का अनुमान है, क्षतिग्रस्त घरों को फिर से बनाने में 80 साल लगेंगे।

रिटायर्ड शिक्षक सामरा कहते हैं, अब हमारे सामने बड़े नकबा की नौबत है। गाजा में युद्ध छिड़ने के बाद अब तक 90 प्रतिशत लोग अपने घर से बाहर किए जा चुके हैं। वे गाजा में भी विस्थापित हैं। कई लोगों को तो बार-बार अपना ठिकाना छोड़ना पड़ा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार का कहना है, गाजा में हमास की जड़ें गहरी हैं। इसलिए लोगों को असैनिक इलाकों से भी हटना पड़ेगा।

संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क कहते हैं, इजराइल स्थायी तौर पर फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाना चाहता है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। नस्लीय सफाये के समान है। इजराइल चाहता है कि लोग खुद गाजा छोड़ दें। मानव अधिकार विशेषज्ञों का कहना है, तथाकथित स्वैच्छिक पलायन भी एक नस्ल के खात्मे जैसा है। गाजा में स्थितियां इतनी खराब हो चुके हैं कि कई लोगों के लिए वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं है।

इजराइल के कुछ मंत्रियों के बयानों से भी फिलिस्तीनियों की आशंका बढ़ी है। वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच का कहना है, गाजा पट्टी में जो कुछ बचा है, उसे इजराइली सेना नष्ट कर रही है। हमास के तबाह होने तक बाकी गाजा की सफाई जारी रहेगी। कई फिलिस्तीनियों के लिए नकबा एक पीड़ादायक स्मृति है। गाजा की 22 लाख आबादी में 17 लाख लोग 1948 में इजराइल की स्थापना के समय हुए युद्ध के शरणार्थी हैं या उनके वंशज हैं।

© The New York Times

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

"कूटनीति जैज संगीत की तरह है, जिसमें एक ही थीम पर अंतहीन विविधताएं समाहित होती हैं।
-रिचर्ड होलब्रूक

नेपाल में सोशल मीडिया पर लगाए गए हालिया प्रतिबंधों और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पड़ोसी मुल्क में लोकतंत्र की सेहत और क्षेत्रीय स्थिरता की दृष्टि से भी चिंताजनक है। पड़ोसी देशों में अस्थिरता के हालिया अनुभवों के बरक्स भारत को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।

असंतोष की चिंगारी

नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए हालिया प्रतिबंधों और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हजारों युवाओं के संसद पर धावा बोलते वक्त हुई हिंसा, देश के इतिहास में इस तरह का पहला मामला तो है ही, पड़ोसी मुल्क में लोकतंत्र की सेहत के साथ क्षेत्रीय स्थिरता की दृष्टि से भी चिंताजनक है। नेपाल की करीब तीन करोड़ की आबादी में तकरीबन 90 फीसदी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। नहीं भूलना चाहिए कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन या संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जनता की आवाज, सूचना के प्रवाह और राजनीतिक विमर्श का भी अहम मंच बन चुका है। ऐसे में, इस पर प्रतिबंधों को युवा अनावश्यक दखलंदाजी की तरह तो देखते ही हैं, इससे यह संदेश भी जाता है कि सरकार नहीं चाहती कि उसकी नीतियों के खिलाफ किसी भी तरह के विमर्श को हवा मिले। आंकड़े इसकी पुष्टि भी करते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2024 के अनुसार, वहां 20 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सरकार हो या समाज, भ्रष्टाचार ने सभी स्तरों पर घुसपैठ कर ली है। कुल मिलाकर, 2008 में राजशाही की बर्खास्तगी के बाद नेपाल के लोगों ने जो स्वप्न देखा था, उसके पूरा न होने से लोगों में नाराजगी है, जो युवाओं के आंदोलन के रूप में प्रतिबिंबित हो रही है। चूंकि दक्षिण एशिया का भूगोल और राजनीति एक-दूसरे से गहरे से जुड़े हैं, लिहाजा इस घटनाक्रम पर भारत की भी नजर होगी। भारत के संदर्भ में यह स्थिति अधिक चिंताजनक इसलिए भी है, क्योंकि उसके तकरीबन सभी पड़ोसी मुल्कों में किसी न किसी स्तर पर संकट बना ही हुआ है। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद हो, बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल, म्यांमार का गृहयुद्ध हो या फिर राजनीतिक व आर्थिक अस्थिरता से उबरता श्रीलंका, ये सभी भारत की कूटनीतिक चिंताओं के विषय लगातार बने हुए हैं। नेपाल की स्थिति, जहां मुख्य लड़ाई राजशाही समर्थकों व विरोधियों के बीच है, हालांकि एक वर्ष पूर्व के बांग्लादेश से अलग है, फिर भी भारत को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि, नेपाल जैसे संवेदनशील राजनीतिक इतिहास वाले देश में, जहां राजशाही के खात्मे के बाद से अब तक करीब 17 वर्षों में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, असंतोष की चिंगारी कब आग में बदल जाए और अवांछित शक्तियों को अस्थिर स्थितियों का फायदा उठाने का मौका मिल जाए, कहा नहीं जा सकता। हालांकि, इसके कसूरवार वहां के राजनीतिक दल ही हैं, जिनकी अवसरवादिता और वैचारिक भटकाव का खामियाजा नेपाल की जनता अब तक भुगत रही है। समय रहते नेपाल को समझना होगा कि जनता की आवाज को दबाने की कोशिश अंततः शासन को ही अस्थिर करती है।

संगीत और संस्कृति के सेतु

भारत भूपेन हजारिका जैसे रत्न से धन्य है। जब हम उनके शताब्दी वर्ष का आरंभ कर रहे हैं, तो आइए यह संकल्प लें कि उनके संदेश को दूर-दूर तक पहुंचाएंगे। यह संकल्प हमें संगीत, कला और संस्कृति के लिए और काम करने की प्रेरणा दे, नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करे, भारत में सृजनात्मकता और कलात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा दे।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

भारतीय संस्कृति और संगीत से लगाव रखने वालों के लिए 8 सितंबर का दिन बहुत खास था। विशेषकर इस दिन के साथ असम के मेरे भाइयों व बहनों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती। वे भारत की सबसे असाधारण और सबसे भावुक आवाजों में से एक थे। यह बहुत सुखद है कि इस वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष का आरंभ हो रहा। यह भारतीय कला-जगत और जन-चेतना की दिशा में उनके महान योगदानों को फिर से याद करने का समय है। भूपेन दा ने हमें संगीत से कहीं अधिक दिया। वे केवल एक गायक नहीं थे, वे लोगों की धड़कन थे। कई पीढ़ियां उनके गीत सुनते हुए बड़ी हुईं। उनके गीतों में हमेशा करुणा, सामाजिक न्याय, एकता और गहरी आत्मीयता की गूंज है।

भूपेन दा के रूप में असम से एक ऐसी आवाज निकली, जो किसी कालजयी नदी की तरह बहती रही। वे सशरीर हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी आवाज आज भी हमारे बीच है। वह आवाज सीमाओं और संस्कृतियों से परे है। उसमें मानवता का स्पर्श है।

भूपेन दा ने दुनिया का भ्रमण किया, समाज के हर वर्ग के लोगों से मिले, लेकिन असम में अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे। असम की समृद्ध मौखिक परंपराएं, लोकधुनें और सामुदायिक कहानी कहने के तरीकों ने उनके बचपन को गढ़ा। यही अनुभव उनकी कलात्मक भाषा की नींव बने। वे असम की आदिवासी पहचान और लोगों के सरोकार को हर समय साथ लेकर चले। केवल पांच वर्ष की उम्र में उन्होंने सार्वजनिक मंच पर गाया। वहां लक्ष्मीनाथ बेझबरुआ जैसे असमिया साहित्य के अग्रदूत ने उनके कौशल को पहचाना। किशोरावस्था तक उन्होंने अपना पहला गीत रिकॉर्ड कर लिया। संगीत उनके व्यक्तित्व का सिर्फ एक पहलू था। वे भीतर से बौद्धिक व्यक्तित्व थे। जिज्ञासु, साफ बोलने वाले, दुनिया को समझने की अटूट चाह रखने वाले।

ज्योति प्रसाद अग्रवाला और विष्णु प्रसाद रभा जैसे सांस्कृतिक दिग्गजों ने उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया। सीखने की यही लगन उन्हें कॉटन कॉलेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तक ले गई। वे बीएचयू में राजनीति शास्त्र के छात्र थे, लेकिन उनका अधिकतर समय संगीत साधना में बीतता था। बनारस ने उन्हें पूरी तरह संगीत की तरफ मोड़ दिया। काशी का सांसद होने के नाते मैं उनकी जीवन यात्रा से एक जुड़ाव महसूस करता हूं, और मुझे बहुत गर्व होता है। उन्होंने अमेरिका में भी कुछ समय बिताया। वहां नामचीन विद्वानों, विचारकों और संगीतकारों से संवाद किया। वे पॉल रोबसन से मिले, जो दिग्गज कलाकार और सिविल राइट्स नेता थे। रोबसन का गीत *Ol' Man River* उनके कालजयी गीत *बिस्टीरनो परोरे* की प्रेरणा बना। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला एलेनॉर रूजवेल्ट ने भारतीय लोकसंगीत प्रस्तुतियों के लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया। भूपेन हजारिका संगीत के साथ ही मां भारती के भी सच्चे उपासक थे। उनके पास अमेरिका में रहने का विकल्प था, पर भारत लौट आए और संगीत साधना में डूब गए। रेडियो से लेकर रंगमंच तक, फिल्मों से लेकर एजुकेशनल डॉक्यूमेंटरी तक, हर माध्यम में वे पारंगत थे। जहां भी गए, नई प्रतिभाओं को समर्थन दिया।

उनकी रचनाएं काव्यात्मक सौंदर्य से भरी रहीं, और उन्होंने सामाजिक संदेश भी दिए। गरीबों को न्याय, ग्रामीण विकास, आम नागरिक की ताकत, ऐसे अनेक विषय उन्होंने उठाए। उनके गीतों ने नाविकों, चाय बागान के मजदूरों, महिलाओं, किसानों की आकांक्षाओं को आवाज दी। उनकी रचनाएं लोगों को पुरानी स्मृतियों में ले जाती थीं, साथ ही, उन्होंने आधुनिकता को देखने का एक सशक्त नजरिया भी दिया। बहुत से लोग, खासकर सामाजिक रूप से वंचित तबकों के लोग, उनके संगीत से शक्ति और आशा पाते रहे...और आज भी पा रहे हैं। उनकी जीवन यात्रा में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। उनकी रचनाओं ने भाषा और क्षेत्र की सीमाएं तोड़कर एकजुट किया। उन्होंने असमिया, बांग्ला और हिंदी फिल्मों के लिए संगीत रचा। उनकी आवाज में जो पीड़ा थी, वह बरबस हम सभी का ध्यान खींच लेती थी। *दिल हूम हूम करे* में जो पीड़ा बहती है, वह सीधे दिल की गहराइयों को छू लेती है। और जब वे पूछते हैं, *गंगा बहती है क्यूं*, तो ऐसा लगता है, मानो हर आत्मा को झकझोर कर जवाब मांग रहे हों।

उन्होंने पूरे भारत के सामने असम को सुनाया, दिखाया, महसूस कराया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आधुनिक असम की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ने में उनका बड़ा योगदान रहा। भूपेन दा राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी जनसेवा से जुड़े रहे। 1967 में वे असम के नौबोइचा से निर्दलीय विधायक चुने गए। उन्होंने राजनीति को अपना कॅरिअर नहीं बनाया, लेकिन हमेशा लोगों की सेवा में जुटे रहे। भारत की जनता और भारत सरकार ने उनके योगदान का सम्मान किया। उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड समेत कई सम्मान मिले। 2019 में हमारे कार्यकाल के दौरान उन्हें भारत रत्न मिला। यह मेरे लिए और एनडीए सरकार के लिए भी सम्मान की बात थी। वह कहते थे कि सच्चाई से निकला संगीत किसी एक दायरे में सिमट कर नहीं रहता। एक गीत लोगों के सपनों को पंख लगा सकता है, और दुनिया भर के दिलों को छू सकता है।

मुझे 2011 का वह समय याद है, जब भूपेन दा का निधन हुआ। मैंने टीवी पर देखा, उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग पहुंचे। हर आंख नम थी। जीवन की तरह, मृत्यु में भी उन्होंने लोगों को साथ ला दिया। इसलिए उन्हें जलुकबाड़ी की पहाड़ी पर ब्रह्मपुत्र की ओर देखते हुए अंतिम विदाई दी गई, वही नदी, जो उनके संगीत, उनके प्रतीकों और उनकी स्मृतियों की जीवनरेखा रही है। यह देखना सुखद है कि असम सरकार भूपेन हजारिका कल्चरल ट्रस्ट के कार्यों को बढ़ावा दे रही है। यह ट्रस्ट युवा पीढ़ी को भूपेन दा की जीवन यात्रा से जोड़ने में जुटा है।

भूपेन दा की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के लिए देश के सबसे बड़े पुल को भूपेन हजारिका सेतु नाम दिया गया। 2017 में जब मुझे इस सेतु के उद्घाटन का अवसर मिला, तो मैंने महसूस किया कि असम और अरुणाचल को जोड़ने वाले इस सेतु के लिए भूपेन दा का नाम सबसे उपयुक्त है। उनका जीवन हमें करुणा की शक्ति का एहसास कराता है। लोगों को सुनने और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की सीख देता है। उनके गीत आज भी बच्चों और बुजुर्गों, दोनों की जुबान पर हैं। उनका संगीत हमें मानवीय और साहसी बनना सिखाता है। वह हमें अपनी नदियों, अपने मजदूरों, अपने चाय बागान के कामगारों, अपनी नारी शक्ति और अपनी युवा शक्ति को याद रखने को कहता है। वह हमें विविधता में एकता पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। भारत भूपेन हजारिका जैसे रत्न से धन्य है। जब हम उनके शताब्दी वर्ष का आरंभ कर रहे हैं, तो आइए यह संकल्प लें कि उनके संदेश को दूर-दूर तक पहुंचाएंगे। यह संकल्प हमें संगीत, कला और संस्कृति के लिए और काम करने की प्रेरणा दे, नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करे, भारत में सृजनात्मकता और कलात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा दे। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

जीवन धारा

एल. रॉन हबर्ड

जब कभी कोई मनुष्य अपने जीवन में महसूस करता हो कि सब कुछ उलझ गया है और इसे सहन नहीं किया जा सकता, जब उसका दिमाग चकराने लगे, तो उससे कहें कि वह पीछे हटकर अपनी समस्या को ध्यान से देखे।

अपनी नजर से दुनिया को देखें

__वही__ देखें, जो आपको दिखाई देता है, न कि जो कोई आपको देखने के लिए कहता है। आपका अवलोकन वही है, जो आपने स्वयं किया है। जीवन को साफ नजर से देखें, न कि पक्षपातपूर्ण रंगीन चश्मे, भय के पर्दों में, या किसी दूसरे के द्वारा निकाले गए अर्थों के आधार पर। दूसरों के साथ वाद-विवाद करने के बजाय उनसे कहें कि वे ध्यान से देखें। यदि किसी को ध्यान से देखने के लिए हल्का-सा अनुरोध किया जाता है, तो झूठ के बड़े-बड़े गुब्बारे फुस्स हो सकते हैं, बड़े-बड़े आडंबरों का राजफाश हो सकता है, अत्यंत जटिल गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है, और अद्भुत विचार सूझ सकते हैं।

जब कभी कोई मनुष्य अपने जीवन में महसूस करता हो कि सब कुछ उलझ गया है और इसे सहन नहीं किया जा सकता, जब उसका दिमाग चकराने लगे, तो उससे कहें कि वह पीछे हटकर अपनी समस्या को ध्यान से देखे। देखने के बाद जो कुछ उसे पता लगता है, वह साधारणतया बहुत स्पष्ट होता है। वह अब आगे बढ़कर इससे निपट सकता है, लेकिन यदि वह स्वयं अवलोकन नहीं करता, तो हो सकता है उसके लिए इसमें कोई वास्तविकता न हो और दुनिया भर के आदेश-निर्देश उसकी उलझी गुत्थी नहीं सुलझा सकते। हालांकि, कोई दूसरा व्यक्ति उसे संकेत कर सकता है कि किस दिशा में देखा जाए और सुझाव दे सकता है कि वह जरूर देखे, लेकिन इस बारे में निष्कर्ष निकालना उसके अपने हाथ में है। कोई व्यक्ति वही देखता है, जो उसे स्वयं दिखाई देता है और उसके लिए वही वास्तविकता होती है। सच्ची कार्यकुशलता का आधार मनुष्य की अपनी अवलोकन करने की योग्यता होती है। इस तथ्य की वास्तविकता को मानकर ही मनुष्य दक्ष और निश्चयवान हो सकता है।

जीवन के हर पहलू को ध्यान से देखने का अभ्यास करें। शिक्षा का फल तभी मिलता है, जब इसे प्रयोग में लाया जाता है। मनुष्य को वास्तव में तब तक पता नहीं चलता कि वह बुद्धिमान है, जब तक कि वह उसका प्रयोग करके परिणाम देख नहीं लेता। किसी भी गतिविधि, हुनर या व्यवसाय या ज्ञान को अंत में इसी कसौटी पर परखा जाता है कि वह जमीनी स्तर पर काम कर सकता है या नहीं।

मनुष्य की निपुणता और दक्षता को उस युग की रफ्तार के स्तर पर लाया जाए, जिसमें वह रहता है। और यह अभ्यास से ही किया जा सकता है। अपने आसपास ध्यान से देखें, अध्ययन करें और कार्यक्षेत्र में स्वयं खोज करें, इसके बाद ही कार्य शुरू करें। और जब सब चीजें पटरी पर आ जाएं, तो तब तक अभ्यास करें, जब तक कि अपने कार्य में निपुण न हो जाएं। निपुणता, दक्षता तथा तेजी से काम करने में बड़ा आनंद मिलता है। केवल ध्यान और अभ्यास से ही इसे सुरक्षित किया जा सकता है।

हर पल सीखें

सूत्र

हम जल्दबाजी में रहते हैं और अपने जीवन को ध्यान से देख नहीं पाते। इसी का परिणाम है कि हम अक्सर तनाव में होते हैं, इससे न तो वर्तमान में होते हैं, न ही भविष्य में। आप अपने जीवन में चाहे जितनी ज्यादा किताबें पढ़ लें, लेकिन बगैर ध्यान और अभ्यास के जीवन सुंदर नहीं होगा। अपने आसपास देखें और सीखते रहें।

दूसरा पहलू

दुनिया की सबसे पुरानी नाट्य शैलियों में से एक 'नोह' को बचाने के लिए जापान के सादो द्वीप वासी अब भी प्रयासरत हैं।

जापान का सादो द्वीप और सबसे पुरानी नाट्य शैली

मार्टिन फैकलर

शिनोबू कामियामा पेशेवर अभिनेत्री नहीं हैं, लेकिन वह दुनिया के सबसे पुराने और अलौकिक रंगमंच (थिएटर) के प्रति बेहद जुनूनी हैं।

विलियम शेक्सपियर से करीब दो सदी पहले नोह के कई नाटकों को मोतोकिया जियामी ने लिखा था। विद्वान मानते हैं कि इसकी शुरुआत करीब आठवीं शताब्दी में हुई थी। लेकिन, अब नोह पर संकट है।

शिनोबू कामियामा पेशेवर अभिनेत्री नहीं हैं। वह दो बच्चों की मां हैं और दिन में एक केंद्र में बुजुर्गों की देखभाल करती हैं। लेकिन, वह जापान के उत्तर-पश्चिम स्थित सादो द्वीप के कई निवासियों में से एक हैं, जो दुनिया के सबसे पुराने और अलौकिक रंगमंच (थिएटर) के प्रति बेहद जुनूनी हैं। ग्रीष्म की एक रात्रि को कामियामा ने जापान की प्राचीन नाट्य शैली 'नोह' में भूतों से संबंधित कहानी में प्रमुख किरदार निभाया। उन्होंने जब एक छोटा अंडाकार मास्क और सुंदर किमोनो पहनकर शिंटो मंदिर के लकड़ी के पुराने मंच पर कदम रखा, तो संगतकार बांसुरी और ढोल के साथ गीत गाने लगे। वह अपनी शैलीगत नृत्य मुद्राओं में थिरक रही थीं। उन्होंने भी गीत गाया। 43 वर्षीय कामियामा कहती हैं, 'मैं नोह गीतों की सुंदरता के बीच पली-बढ़ी हूं और बचपन से ही इसे गा रही हूं।' उस दिन कामियामा ने शाही दरबार की प्रसिद्ध महिला तमकाजुरा की भूमिका निभाई, जो अपनी सुंदरता से इतनी परेशान है कि मृत्यु के बाद आत्मा के रूप में लौट आती है। नोह नाटक अक्सर भूतों के आगमन पर केंद्रित और प्रसिद्ध पराजित योद्धाओं या दरबार के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। द्वीप के नोह एसोसिएशन के प्रमुख तोशिहीरो कोंडो कहते हैं, 'नोह भगवान को अर्पित की जाने वाली भेंट है।' 45 हजार की आबादी वाले इस द्वीप में नोह के 34 मंच हैं, जिनमें से ज्यादातर बौद्ध धर्म या देश के मूल शिंटो धर्म के मंदिरों में स्थित हैं। जापान के ज्यादातर हिस्सो में नोह का अभ्यास पेशेवर रूप से किया जाता है, लेकिन सादो में हर साल दर्जनों प्रदर्शन शौकिया तौर पर होते हैं, जैसे कामियामा ने किया। 80 वर्षीय प्रशिक्षक इचिजी कहते हैं, 'नोह यहां अब भी जीवंत संस्कृति बनी हुई है, पर यह इसका अंतिम स्थान है।' विलियम शेक्सपियर से करीब दो सदी पहले नोह के कई नाटकों को मोतोकिया जियामी ने लिखा था। विद्वान मानते हैं कि इसकी शुरुआत करीब आठवीं शताब्दी में हुई थी। लेकिन, जापान की बुजुर्ग होती आबादी के बीच सदियों पुराने नोह पर भी संकट है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद नोह मंचों की संख्या आधी घटकर करीब 200 ही रह गई है। दो सदी पुराने नोह मंच वाले शिंटो मंदिर की 30वीं पीढ़ी के पुजारी यशियो हिनो कहते हैं कि इस कला को संरक्षित करने का मतलब है ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करना, जिन्होंने हाल के वर्षों में सादो द्वीप की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। कामियामा के प्रदर्शन को देखने के लिए स्थानीय और विदेशी पर्यटकों समेत करीब 200 दर्शक आए थे, जिनमें उनका पांच वर्षीय बेटा भी था।

आंकड़े

महंगे देश

यूरोपीय संघ में शामिल कुछ देश अन्य देशों की तुलना में 50 फीसदी तक महंगे हैं, इनमें लक्जमबर्ग सबसे महंगा है।

लक्जमबर्ग	52%
आयरलैंड	45%
डेनमार्क	43%
फिनलैंड	28%
नीदरलैंड	22%

आंकड़े यूरोपीय संघ में शामिल सबसे महंगे देशों के, प्रतिशत में | स्रोत : Eurostat

खुले ज्ञानचक्षु

जो वाचिक ज्ञानी संत भास्करराय से ईर्ष्या करते थे, वे शास्त्रार्थ करने पहुंचे, तो उनकी आभा व आध्यात्मिक प्रभाव से मोहित हो गए और प्रश्न तक न पूछ सके।

अंतर्यात्रा
संकलित

सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण में भास्करराय नाम के प्रसिद्ध चमत्कारी संत हुए। पांच वर्ष की अवस्था में काशी में उनका उपनयन संस्कार किया गया। इसके बाद उन्होंने गुरु नरसिंहाध्वरि से वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया। वह भगवती महात्रिपुरसुंदरी के अनन्य भक्त थे। वह भगवती की उपासना को मुख्य मानते थे। मां की कृपा से उन्हें ब्रह्म का ज्ञान हो गया था, लेकिन काशी के कुछ वाचिक ज्ञानी उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्हें तंग भी करते थे।

एक दिन उनके बीच शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें वाचिक मंडली एक तरफ और दूसरी तरफ अकेले भास्करराय थे। लेकिन, उन्हें शास्त्रार्थ में नीचा दिखाने के लिए आई विद्वानमंडली संत भास्करराय की आभा और उनके आध्यात्मिक प्रभाव से मोहित हो गई और सवाल तक नहीं पूछ सकी। फिर भी उनमें से एक व्यक्ति जैसे-तैसे खड़ा हुआ व मंत्रशास्त्र संबंधी प्रश्न करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि मां भगवती की कृपा से सभी के बीच से कुंकुमानंद स्वामी नाम के परमसिद्ध महात्मा प्रकट हो गए। उन्होंने प्रश्नकर्ता को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। इसके बाद कुंकुमानंद स्वामी ने वहां मौजूद विद्वानों के ऊपर जल के छींटे मारे, तो सभी की आंखों पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हट गया और सभी ने लज्जित होकर भास्करराय से क्षमा प्रार्थना कर उन्हें कंधे पर उठा लिया तथा ज्ञानचक्षु खोलने के लिए आभार माना।

आज का इतिहास

एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को विवि का दर्जा, बना अलीगढ़ मुस्लिम विवि

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देश के प्रमुख केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। वर्तमान में जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम विवि के तौर पर जानते हैं, उस आवासीय शैक्षणिक संस्थान की स्थापना समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी, जिसे मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा गया और फिर 1920 में नौ सितंबर के दिन इसे केन्द्रीय विवि का दर्जा दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विवि कैंब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनाया गया पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। 1974 : कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म। कारगिल युद्ध में शहीद भारत मां के इस वीर सपूत को मरणोपरान्त परमवीर चक्र से नवाजा गया। 1968 : भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, क्रान्तिकारी और पत्रकार रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन। 1850 : प्रसिद्ध हिन्दी लेखक और नाटककार भारतेन्दु हरिश्चंद्र का जन्म। 1943 : भारतीय सेना में विद्रोह की आग भड़काने के आरोप में चार युवकों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटकाया। 1776 : अमेरिकी कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर देश का नाम यूनाइटेड कॉलोनीज से बदलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रखा।

हिमालय नहीं बचा तो कौन बचेगा

हिमालय पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सवा करोड़ लोग निर्भर हैं। इसे बचाने के लिए अविवेकपूर्ण विकास को रोकने के साथ ही आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना बेहद जरूरी है।

अवधेश कुमार गुप्त, सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा समिति | हिमालय दिवस

पहाड़ पर जल प्रलय से मैदानी इलाकों में हाहाकार है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की विनाशलीला बहुतों ने अपने जीवनकाल में पहली दफा देखी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सभी नदियां अपने तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस आई हैं। हिमाचल में 5,600 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और 1,300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड में 2,600 से अधिक सड़कें ध्वस्त हुई हैं। जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 3,100 से अधिक सड़कें बह गई हैं।

मौसम विज्ञान की भाषा में, 100 मिलीमीटर प्रति घंटो की बारिश को बादल फटना कहते हैं। हिमालय में बादल फटने के मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप हैं। हिमालय पर पहले भी बारिश होती थी और बादल फटते थे, पर बादल फटने की इतनी ज्यादा घटनाएं और तबाही आम तौर पर नहीं दिखती थी। चाहे 2013 की केदारनाथ आपदा रही हो या फिर बाद की अनेक घटनाएं। इनके पीछे बड़ी वजह पहाड़ों, विशेषकर जल धाराओं के निकट बढ़ती मानवीय गतिविधियां हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण, वनों की कटाई और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों में अवरोध इन घटनाओं को भयावह बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में आपदाओं के लिए पेड़ों की अवैध कटाई को जिम्मेदार ठहराया है। पहाड़ क्या, धरती का हर कोना वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अति मानवीय गतिविधियों व अनियंत्रित विकास से विनाश की ओर बढ़ रहा है। हिमालय दुनिया के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक व अहम पारिस्थितिकी भंडार है। यहां की वनस्पति और जंतु जगत को न बचाया गया, तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र अस्थिर हो जाएगा। एशिया के सवा सौ करोड़ लोग भोजन, पानी व दवाओं के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिमालय पर पर निर्भर हैं। दशकों से विकास के बहाने अविवेकपूर्ण खनन व निर्माण के कारण न सिर्फ आपदाएं बढ़ीं हैं, बल्कि उनसे होने वाला नुकसान भीषण हुआ है। इसका सबसे बड़ा अपराधी चीन है। चीन तिब्बत में सैन्य और बुनियादी ढांचा, सड़कें व बांध बनाकर पारिस्थितिकी को नष्ट कर चुका है। वह ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा जलविद्युत बांध बनाने जा रहा है। हिमालय को ड्रैगन के विस्तारवाद की भूख से बचाना होगा। अन्यथा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यातायात सुगम होने व जीवन शैली बदलने से पहाड़ों पर पर्यटक तेजी से बढ़ हैं। हिमाचल प्रदेश में 2003 में करीब 55 लाख पर्यटक आए थे, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 2.63 करोड़ हो गया। उत्तराखंड में 2018 में 3.68 करोड़ पर्यटक आए थे, जबकि पिछले साल यह संख्या 5.96 करोड़ हो गई। बढ़ते पर्यटकों की सुविधा और आकर्षण के लिए शहर बढ़ रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण पीछे छूट गया। इसे रोकने के लिए पर्यटन को नियंत्रित करना ही होगा। भूटान जैसे देशों ने इसे कर दिखाया है। उसने पर्यावरण की कीमत पर पर्यटन को बढ़ने नहीं दिया। भूटान ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त नीतियां अपनाई हैं। विकास योजनाओं और पर्यटन उद्योग के विकास में पर्यावरण को केंद्र में रखा है। इसलिए वहां अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है। वर्ष 1961 से 2011 तक 50 साल में हिमालय की आबादी 250 फीसदी बढ़ी है। भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2011 से 2021 के बीच शहरी विकास की दर 40 फीसदी से अधिक थी। इसका दुष्परिणाम यह है कि हाल के कुछ वर्षों में वन क्षेत्र एक हजार वर्ग किलोमीटर घट गया है। पहाड़ पर वाहनों की धमाचौकड़ी का सीधा असर ग्लेशियर व नदियों पर पड़ रहा है। मंडी और हर्षिल जैसी घटनाएं सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं। ये हमारी तैयारियों की कमी, इन्सानी लालच और जलवायु परिवर्तन की अनदेखी के गंभीर परिणामों की दुखद तस्वीरें हैं।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 106 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

योगी सरकार का ऐलान वाकई सराहनीय

उत्तर प्रदेश में हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करने वालों के लिए योगी सरकार का ऐलान वाकई सराहनीय है। योगी आदित्यनाथ की सरकार 1 अगस्त से 'हेलमेट नहीं, पेट्रोल नहीं का विशेष अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की है। यह विशेष सड़क सुरक्षा अभियान 30 सितम्बर तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। दरअसल, देशभर में बिना हेलमेट लगाए बाइक चालकों की मौत का आंकड़ा व्यापक है। देश में साल 2021 में हेलमेट न पहनने के कारण लगभग 47,000 लोगों की मौत हुई, जो कि हर घंटे चार लोगों की मौत के बराबर है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और हेलमेट न पहनने के खतरनाक परिणामों को दर्शाते हैं, खासकर दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए, जहां मौतें अक्सर हेलमेट के इस्तेमाल से रोकी जा सकती है। राज्य सरकार के इस अभियान में परिवहन, पुलिस, राजस्व और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, मगर सड़कों पर कुछ दिनों के अभियान के बाद हालात पहले की तरह लापरवाही भरे दिखने लगते हैं। कई बार तो जुर्माने से बचने के लिए युवा तबका बाइक को ज्यादा तेज गति से भगाने लगता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। शायद इसी बात को देखते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि इसका लक्ष्य नागरिकों को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें कानून के अनुरूप सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईंधन तभी, जब हेलमेट सिर पर हो। बहरहाल, सरकार को इस नियम को कायदे से लागू करवाने के लिए जरूरत से ज्यादा मशक्कत करने की कवायद करनी पड़ेगी। काफी अरसा पहले दूरदर्शन में हेलमेट की महत्ता और लोगों की जान की कीमत को लेकर एक विज्ञापन दिखाया जाता था। वैसे भी एक बात सभी को समझनी चाहिए कि बिना सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल किए कोई भी अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए कार सवार के लिए सीट बेल्ट और बाइक सवार के लिए हेलमेट का इस्तेमाल जीवन रक्षा की गारंटी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला निःसंदेह प्रशंसनीय है। हालांकि ऐसे अभियान की सफलता तभी कारगर है जब पब्लिक नियम-कायदे का पालन करे और अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए बाकी लोगों को भी जागरूक करे।

बढ़ता जनसंख्या असंतुलन : राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास पर असर

आरती कुमारी

जनसंख्या देश की सबसे बड़ी पूंजी हैं क्योंकि यही राज्य का तत्व श्रम शक्ति, प्रतिभा एवं विकास की नींव होती है। जब जनसंख्या असंतुलन की स्थिति में पहुंच जाती है तो यह जनशक्ति देश के लिए अभिशाप एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष संकट का आकार धारण कर लेती है। समकालीन में वैश्विक स्तर के अनेक नवोदित राष्ट्र- राज्य ,विकासशील राष्ट्र – राज्य एवं विकास की प्रक्रिया में शामिल राष्ट्र- राज्य जनसंख्या के संतुलन से बोझिल है। जनसंख्या का संतुलित होना राष्ट्र के बहुआयामी विकास की अवधारणा को सार्थक,अर्थपाय, एवं निश्चित दिशा का सार्थक आशय देता है। हिंदू समाज अपने विवेकी प्रज्ञा एवं बौद्धिक परंपरा से सहिष्णु होता है। वह तनाव, भू – भागी तनाव, मानसिक विक्षोभ ,दंगों एवं आक्रामक व्यवहारों से असुरक्षित महसूस करता हैं ,तो इन भयावह स्थान से पलायन कर जाता है। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा पर जांच प्रतिवेदन ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालता हैं। संभल जिले में 1947 से सन् 2025 तक 25 बार दंगे हुए हैं। इन दंगों की भयावहता के कारण अधिकांश हिंदुओं ने पलायित कर अपना दूसरा सुरक्षित स्थान बनाया है। भारत का लोकतंत्र वैश्विक स्तर का वृहद लोकतंत्र एवं शांतिमय लोकतंत्र है। इसके राजनीतिक संस्कृति और प्रशासनिक संस्कृति में हिंदुओं का बाहुल्य है एवं हिंदुओं ने लोकतांत्रिक संस्कृति की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए सकारात्मक पहल की हैं। भारत में लोकतंत्र का जीवन हिंदुओं की सहिष्णुता एवं सहयोग से संभव है। करीब 3 दशकों से भारत में घुसपैठ, मतांतरण एवं अन्य दूसरी सामयिक कारणों से देश के करीब 210 जनपदों की जनसांख्यिकीय संरचना में बड़ा बदलाव आया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता, एवं राष्ट्रीय एकता के लिए चिंता का विचार एवं समाज के लिए कष्टकारी है। स्वतंत्रता के पश्चात तत्कालीन कांग्रेस सरकार की उपेक्षा से देश में तनाव जनित शक्तियां उभर रही थी जो देश की एकता, अखंडता एवं राष्ट्रीयता की भावना को तितर – बितर करना चाहती थी। सवाल यह है कि क्या संभल से हिंदुओं का खामोश पलायन देशव्यापी चलन का हिस्सा है ? संभल हिंसा पर आए एक जांच आयोग के प्रतिवेदन में रेखांकित है कि हिंदुओं की जनसंख्या में 30% की गिरावट दर्ज की गई है। संभल से हिंदुओं का खामोश पलायन स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या के असंतुलन के खतरों को उजागर कर रहा है। बंटवारे के पश्चात भारत की प्रथम जनगणना में देश में मुस्लिम आबादी 3 करोड़ थी जो वर्तमान में बढ़कर 21 करोड़ हो चुकी है। यह पाकिस्तान की वर्तमान आबादी 24 करोड़ के समतुल्य हो चुकी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के संभल में 30% तक हिंदू आबादी घटी है । संभल हिंसा के लिए जांच 3 सदस्य न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट के अनुसार, आजादी के समय संभल में लगभग 45 प्रतिशत हिंदू आबादी थी जो इस शहर में लगातार दंगों की आग में झुलसने से 15 प्रतिशत रह गई है । इस जन सांख्यिकी बदलाव के कारण संभल में आबादी से लेकर हुए 15 दंगों एवं हिंसा में हिंदू आबादी को निशाना बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के कैराना कस्बे में मुस्लिम आबादी 78% एवं हिंदू आबादी 22% थी। 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी चार प्रतिशत से बढ़कर 82 प्रतिशत हो गई है, वहीं हिंदू आबादी घटकर 18% रह गई है। स्थानीय स्तर के राजनीतिक दलों के चुनावी आंकड़ों के अनुसार 2015 में मुस्लिम जनसंख्या 90% हो गई एवं हिंदू आबादी 10% रह गई है। उत्तर – प्रदेश के नेपाल से सटे जिलों बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर में तेजी से जनसंख्या बदलाव हो रहे हैं। यहां पर पिछले 10 वर्षों में बड़ी संख्या में अवैध मदरसों एवं दरगाहे बनी हैं जो जनसांख्यिकीय असंतुलन के लिए प्रबल रूप से जिम्मेदार हैं। क्या देश में जनसांख्यिकीय असंतुलन का खतरा गंभीर एवं खतरनाक रूप ले रहा है ? किसी देश या राज्य – क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर असामान्य रूप से बढ़ जाती है एवं उसके संसाधन अवसर एवं आधारभूत संरचना उसके अनुरूप विकसित नहीं हो पाते हैं, तब वहां सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण आर्थिक संकट अर्थात बेरोजगारी एवं गरीबी बढ़ती है। संसाधनों पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न हो जाता हैं ,जिससे जल, भोजन , ऊर्जा एवं भूमि की कमी होने लगती है। पर्यावरणीय संकट अर्थात जंगलों की कटाई, प्रदूषण एवं जलवायु संकट उत्पन्न हो जाते हैं। सामाजिक असंतुलन अर्थात अपराधों में वृद्धि एवं अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं ।

जनसांख्यिकीय असंतुलन के तीन रूप हैं।

मुस्लिम जनसंख्या में औसत राष्ट्रीय वृद्धि।

2. देश के सीमावर्ती क्षेत्रों खास तौर से असम,बंगाल एवं बिहार में बांग्लादेश, म्यांमार एवं नेपाल से आए अवैध मुस्लिमों और रोहिंग्या घुसपैठियों का बढ़ता जमावड़ा; एवं

3.लगभग प्रत्येक शहरों एवं कस्बों में बढ़ते मुसलमानों की बेतहाशा संख्या।

1971 के पश्चात भारत में बांग्लादेशियों का पलायन दो कारणों से तेज हुआ । पहला कारण राजनीतिक था एवं दूसरा आर्थिक था। राजनीतिक कारण के अंतर्गत बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का उत्पीड़न शुरू हुआ और वहां से बहुसंख्यक स्तर पर हिंदुओं का पलायन हुआ । तत्कालीन समय में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति दयनीय स्थिति में थी. आर्थिक स्थिति को बेहतर एवं जीविका की सुरक्षा के लिए मुसलमान भी भारत में पलायन करके आए जिससे भारत में जनसंख्या असंतुलन उत्पन्न हो गया। दुर्भाग्य से तत्कालीन सरकार ने इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या के तौर पर नहीं देखा और न हीं इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान दिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का कहना था कि बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर भारत में पलायन हुआ है।(विदेश मंत्रालय, 20 जनवरी 1972)। तत्कालीन समय में सीमा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माधव गोडबोले थे. उन्होंने बांग्लादेश की सीमा को लेकर अपने प्रतिवेदन में लिखा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या पर कुछ नहीं किया था। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में तत्कालीन भारत सरकार की कटु आलोचना की थी । 2001 में उनका आकलन था कि प्रत्येक महीने लगभग 25000 व्यक्ति भारत में पलायन कर रहे हैं एवं प्रतिवर्ष 3 लाख बांग्लादेशी भारत में आ रहे हैं। उस समय उनका गणितीय आकलन था कि करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। सन् 2001 में भारत सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के समूह ने प्रतिवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है, उससे भारत के सामाजिक सौहार्द को खतरा, राजनीतिक स्थिरता को चुनौती, सुरक्षा को खतरा एवं आर्थिक प्रगति पर दबाव है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा था कि, असम एवं पूर्वी- राज्यों के रास्ते बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, वह बाहरी आक्रामकता है। इसका आशय है कि भारत में विदेशी आक्रमण का माहौल हो चुका है। इसमें भारत सरकार को अनुच्छेद 355 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक स्वार्थों , सत्तालोलुपता एवं लोक भावनाओं के उभार के लिए तुष्टिकरण की राजनीति की जाती है। अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़ती मुस्लिम आबादी राजनीतिक विजय या पराजय में निर्णायक भूमिका निभाती है। असम पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार , कछार, करीमगंज, धुबरी एवं दक्षिण सलमार में बांग्लादेश की सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर आबादी की दशकीय – वृद्धि दर 31.45 प्रतिशत है जो राज्य की संभावित वृद्धि दर 13.5 प्रतिशत से बहुत अधिक है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में मस्जिदों एवं मदरसों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई हैं जिसका प्रयोग अनेक संदिग्ध गतिविधियों में किया जाता है। राजनीतिक संरक्षण, पुलिस की संलिप्तता एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। उत्तर- प्रदेश पुलिस के प्रतिवेदन के अनुसार, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर ,बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत एवं लखीमपुर खीरी के जनपदों में 1047 गांवों में मुस्लिम आबादी 30 से 40% एवं 116 गांवों में मुस्लिम आबादी 50% से अधिक हो गई है। ऐसे जनसांख्यिकीय असंतुलन का राजनीतिक प्रक्रिया एवं लोकतंत्र पर सीधा असर पड़ेगा। यह हिंदू – मुस्लिम सौहार्द के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ के लिए राजनीतिक नेतृत्व भी संरक्षण देते रहते हैं, जिससे हिंदू समाज में गलत संदेश जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(RSS) इस दिशा में प्रयास कर रहा है कि हिंदू एवं मुस्लिम एक मंच पर आए एवं राष्ट्रीय हितों के विषय पर परस्पर संवाद कर सके। समाज से कट्टरपंथ ,उग्रवाद, उन्माद एवं नफरत को दूर कर सकें। दोनों समुदाय आपसी मतभेदों,तनावों, एवं समस्याओं को बातचीत से सुलझाएं।दोनों समुदाय अपने- अपने समाज में परस्पर सौहार्द कायम कर सकें एवं समाज को सशक्त संदेश दें कि किसी भी वाह्य शक्ति को भारत की धार्मिक विविधता को खंडित करके दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। हिंदुओं एवं मुसलमानों को भी सामाजिक स्तर पर प्रत्येक गांवों ,शहरों, एवं मोहल्ले स्तर पर काम करना होगा।

जनसांख्यिकीय असंतुलन को दूर करने हेतु निम्न सुझाव हैं : 1.समाज में शिक्षा एवं जागरूकता का उन्नयन किया जाए; 2. महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक एवं शासकीय प्रयास किया जाए ; 3 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन का शक्ति से क्रियान्वयन हो ; 4.विधि एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को जमीनी स्तर पर लाया जाए; 5. आर्थिक एवं सामाजिक संतुलन का समीकरण बढ़ाया जाए; 6. नैतिक एवं सांस्कृतिक पहल की धारणा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए; 7.जनसांख्यिकीय असंतुलन के लिए वर्तमान में "आयोग" की आवश्यकता है; एवं 8. हिंदू एवं मुसलमानों को धार्मिक समन्वय के साथ अंतर्जातीय संबंधों पर केंद्रीकरण की आवश्यकता है।

पूरे देश में होगा वोटर सत्यापन - 10 सितंबर को होगी सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हर नागरिक का वोट बेहद कीमती है, क्योंकि यह न केवल सरकारें बनाता है बल्कि देश के भविष्य की दिशा तय करता है। परंतु हाल के वर्षों में यह सवाल उठने लगा था कि क्या मतदाता सूची वास्तव में इतनी पारदर्शी और अद्यतन है कि हर योग्य नागरिक को वोट देने का मौका मिले और कोई भी फर्जी नाम शामिल न हो? इसी पृष्ठभूमि में निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है "विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR)" को पूरे देश में लागू करने का फैसला। विशेष गहन पुनरीक्षण का अर्थ है 'मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन', जिसमें किए जाते हैं मृत मतदाताओं के नाम हटाना, फर्जी या दोहराए गए नामों को चिन्हित कर उन्हें डिलीट करना, ऐसे नागरिकों के नाम जोड़ना जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, प्रवासी या स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी अपडेट करना, महिला मतदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों का विशेष सत्यापन। SIR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची बिल्कुल साफ-सुथरी और अद्यतन हो, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न बचे। इस अभियान की शुरुआत बिहार से हुई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पद संभालने के बाद सबसे पहले बिहार में इस प्रयोग को शुरू करने का फैसला किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले SIR को लागू किया गया ताकि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी न रह जाए। विपक्षी दलों ने इस कदम पर कई सवाल उठाए। उनका आरोप था कि यह प्रक्रिया उनके वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। इसके बावजूद आयोग ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की तैयारी है। बिहार में SIR के अनुभव ने आयोग को यह भरोसा दिलाया है कि इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। देशभर में इस मुहिम को लागू करने के लिए 10 सितंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक होगी क्योंकि यह तय किया जाएगा कि SIR को चरणबद्ध तरीके से कब और कैसे लागू किया जाए। राज्यों को तकनीकी और मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सत्यापन की व्यवस्था बनाई जाएगी। ज्ञानेश कुमार की यह तीसरी बड़ी बैठक होगी, जिसमें उनका फोकस चुनाव सुधार को तेज गति देने पर रहेगा। आज के समय में SIR केवल कागजी कार्यवाही नहीं रह गई है। निर्वाचन आयोग ने कई तकनीकी नवाचार किए हैं। NVSP पोर्टल (National Voter Service Portal) के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन, Voter Helpline App से घर बैठे विवरण अपडेट करने की सुविधा, आधार लिंकिंग के माध्यम से डुप्लीकेट एंट्री रोकना, AI आधारित डाटा एनालिटिक्स से फर्जी वोटर पहचानना, ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीकों पर भी भविष्य में विचार किया जा सकता है। तकनीकी हस्तक्षेप से यह प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो रही है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। SIR के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से कई राजनीतिक दलों में हलचल है। विपक्ष के कुछ दल इसे सत्ताधारी दल का वोटर सूची में हेरफेर का प्रयास मानते हैं। सत्तापक्ष का तर्क है कि यह कदम निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देगा और लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। जबकि आम मतदाता इसे स्वागत योग्य कदम मानते हैं क्योंकि इससे उनका वोट सुरक्षित रहेगा। लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस तरह की कवायद को राजनीतिक हथियार न बनाया जाए। SIR को पूरे देश में लागू करना आसान नहीं है। भारत के विशाल आकार और विविधता को देखते हुए हर घर तक पहुंचना कठिन होगा। बड़ी संख्या में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की आवश्यकता होगी। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी जागरूकता कम होने से ऑनलाइन सत्यापन मुश्किल हो सकता है। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दल प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्वाचन आयोग को कठोर दिशा-निर्देश और पारदर्शी मॉनिटरिंग व्यवस्था बनानी होगी। किसी भी सुधार की सफलता का सबसे बड़ा आधार होता है जन भागीदारी। आयोग को व्यापक SVEEP (Systematic Voters' Education and Electoral Participation) अभियान चलाना होगा। सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, मोबाइल मैसेजिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा। कॉलेज, पंचायत, स्वयंसेवी संगठनों को जोड़कर युवा मतदाताओं को प्रेरित करना होगा। जब नागरिक खुद अपने नाम की जांच करेंगे, तभी मतदाता सूची वास्तव में सही और त्रुटिहीन बन पाएगी। भारत में महिला मतदाता और युवा वोटर लोकतंत्र की धुरी हैं। महिलाएं जिनका विवाह के बाद नाम पुराने पते पर ही रह जाता है। SIR इस समस्या को हल कर सकती है। 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही उनका नाम जोड़ा जाना चाहिए। शहरों में काम करने वाले मजदूरों का नाम सही जगह दर्ज होना बेहद जरूरी है। इन वर्गों के सटीक पंजीकरण से वास्तविक मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। कई लोकतांत्रिक देशों में मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण सामान्य प्रक्रिया है। अमेरिका में 'Voter Registration Drive' अभियान चलता है। यूनाइटेड किंगडम में हर साल 'Annual Canvass' होता है। ऑस्ट्रेलिया में अनिवार्य पंजीकरण और वोटिंग है। भारत में इस तरह का राष्ट्रीय स्तर पर SIR कदम इसे वैश्विक मानकों के और करीब ले जाएगा। SIR केवल तकनीकी कवायद नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र में विश्वास को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। इससे फर्जी वोटिंग, डुप्लीकेट नाम और मृत व्यक्तियों के नाम से होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। आम नागरिक को भरोसा होगा कि उसका वोट गिने जाने योग्य है। राजनीतिक दलों के लिए भी यह एक पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी होगी। यदि यह प्रक्रिया सफल रही, तो भारत का चुनाव आयोग दुनिया के सबसे भरोसेमंद और आधुनिक चुनाव संस्थानों में गिना जाएगा।

मेष राशि- आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपको बिजनेस में बड़ा धन लाभ होगा, नए क्लाइंट भी आपसे जुड़ेंगे भविष्य में जो आपके लिए फायेदेमंद साबित होंगे। भूमि तथा वाहन से संबंधित व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। आज नौकरी में लक्ष्य व टारगेट को पूरा करने का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा।

वृष राशि- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप रोजगार के मामलों में कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और आप दोनों को बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज अनुभवी तथा जिम्मेदार व्यक्तियों का मार्गदर्शन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा।

मिथुन राशि- आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज आप किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले घर के बड़ों से जानकारी अवश्य ले – लें, इससे आपको अपने कामों को उचित तरीके से करने में सहायता मिलेगी। आज किसी करीबी के साथ चल रही अनबन में सुधार होगा, जिससे आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे।

कर्क राशि- आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करने पर उसके आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आज आप किसी फैमली फंक्शन में जायेंगे, जहां करीबियों से मुलाकात होगी। आज आप किसी समस्या को नए दृष्टिकोण के साथ हल करेंगे, तो आपको अवश्य उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

सिंह राशि- आज का दिन आपके लिए ठीक – ठाक रहने वाला है। आज आप अपने ऑफिस में सहकर्मियों का साथ देंगे और उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे, जिससे काम की गुणवत्ता बेहतर होगी। आज राजनीतिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता और वर्चस्व बढ़ेगा साथ ही आप अपनी फिटनेस पर भी समय देंगे। आज लम्बे समय बाद किसी दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे मिलकर आपको ख़ुशी होगी।

कन्या राशि- आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देंगे, आपकी मेहनत और लगन देखकर संस्था आपको सम्मानित भी करेगी। इस राशि के सरकारी कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों को आज ट्रान्सफर से जुड़ी सूचना प्राप्त हो सकती है। आज जीवनसाथी व परिवार जनों का सहयोग आपके आत्म बल व आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा।

तुला राशि- आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज आपको कारोबार में दोगना धन लाभ होगा, जिससे आप उसे और बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरुरत है, जिससे वे अपने सपनों को जल्द ही पूरा कर सकें।

वृश्चिक राशि- आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको नौकरी के लिए किसी बड़ी कम्पनी से ऑफर लेटर मिलने की सम्भावना हैं। आज आपको पारिवारिक उलझनों से राहत मिलेगी और आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। आज बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व स्नेह से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आज आप मार्केटिंग और नए क्लाइंट से बात करके अपने बिजनेस को बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे।

धनु राशि- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको किसी अपने के माध्यम से धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगें , आप ज्यादा सोच – विचार करने में समय न गवाएं। आज आप जीवनसाथी के साथ शॉपिंग करने जायेंगे और बच्चों के लिए भी कुछ गिफ्ट लेकर आयेंगे, जिससे उन्हें ख़ुशी मिलेगी। आज घर की देखरेख अथवा मरम्मत संबंधी कोई योजना बन रही है, तो अभी उस पर और अधिक विचार करने की जरुरत है।

मकर राशि- आज का दिन आपके लिए मिला – जुला रहने वाला है। आज आप कार्यों को अपने तरीके से करने की कोशिश करें और अपनी कार्य क्षमता व योग्यता पर विश्वास रखें। आज आपकी किसी योजना को साकार रूप मिलने वाला है। इसलिए अपने प्रयासों में कमी ना आने दे।

कुम्भ राशि- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी के साथ मिलकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, भविष्य में आपको बढ़िया लाभ होगा। आज आपके ऑफिस का माहौल ठीक रहेगा, इसलिए आज अधिकतर काम समय से पूरे हो जायेंगे। आज जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी से सलाह लेना भी आपके लिए उचित रहेगा। आज आपको किसी दोस्त से उपहार की प्राप्ति होगी, जिसे देखकर आप भावुक हो जायेंगें।

मीन राशि- आज का दिन आपके लिए रोज की अपेक्षा बेहतर रहेगा। आज आपको प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर मिलने के योग हैं। आज आपकी व्यावसायिक गतिविधियां सुचारु रूप से चलती रहेंगी, साथ ही पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा का भी समाधान निकलेगा। आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, जिससे उसके जीवन में सकारत्मक परिवर्तन आएगा। आज आप किसी काम में अपने बड़े भाई से मदद ले सकते हैं, उनका अनुभव आपके काम आएगा।

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 : जीत एनडीए की तय, पर असली जंग विपक्ष की एकजुटता तोड़ने की

अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

भारतीय राजनीति में उपराष्ट्रपति चुनाव हमेशा औपचारिकता भर लगते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ पक्ष आम तौर पर आंकड़ों के बल पर बाजी मार लेता है। लेकिन इस बार 9 सितंबर 2025 को होने जा रहा चुनाव महज जीत-हार तक सीमित नहीं है। असली लड़ाई जीत के अंतर को बढ़ाने और विपक्ष की एकजुटता को कमजोर करने की है। यही कारण है कि सत्ता और विपक्ष, दोनों खेमों ने अपनी-अपनी रणनीतियों को आक्रामक बनाया है। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है और चुनाव को वैचारिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरे माहौल में सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई फोन कॉल को लेकर है, जिसने क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं पर नई बहस छेड़ दी है। 6 सितंबर को राजीव राय का जन्मदिन था। इस मौके पर अमित शाह ने उन्हें फोन कर बधाई दी। यह कॉल सतह पर तो शिष्टाचार लग रही थी, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे। वीडियो में राजीव राय हल्के-फुल्के अंदाज में अपनी उम्र को लेकर मजाक करते नजर आए, जिसे यूपी-बिहार की राजनीति में नेताओं की उम्र पर चलने वाली चुटकियों से जोड़कर देखा गया। पर असली महत्व इस कॉल की टाइमिंग और संदर्भ का था। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले हुई इस बातचीत ने विपक्षी खेमे की बेचैनी बढ़ा दी। राय ने सफाई दी कि यह रिकॉर्डिंग उनके किसी कार्यकर्ता ने की और अनजाने में व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी। बावजूद इसके, यह सवाल बना रहा कि क्या अमित शाह का यह कदम केवल शिष्टाचार था या फिर किसी गहरी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा। राजीव राय का राजनीतिक सफर भी इस बहस को और दिलचस्प बनाता है। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने घोसी सीट से एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर को हराया और सपा के लिए महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। उन्हें अखिलेश यादव का करीबी और रणनीतिकार माना जाता है। दिलचस्प यह भी है कि उनकी जीत में बीजेपी के परंपरागत वोटरों का योगदान माना गया था। ऐसे में सत्ता पक्ष से तालमेल बनाए रखना उनके लिए व्यावहारिक राजनीति हो सकती है। यही कारण है कि यूपी-बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि सपा के कुछ सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि सपा के 3 से 5 सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, खासकर वे जिनके क्षेत्र में बीजेपी का प्रभाव मजबूत है उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 सांसदों को वोट डालना है, लेकिन 6 सीटें खाली हैं, इसलिए निर्वाचक मंडल में 775 वोट होंगे। जीत के लिए 388 वोट की जरूरत है। एनडीए के पास पहले से ही 439 वोटों का मजबूत आधार है। इसमें बीजेपी के 240 लोकसभा और 95 राज्यसभा सांसदों के अलावा जेडीयू के 12, टीडीपी के 16, शिवसेना के 7 और अन्य सहयोगियों के वोट शामिल हैं। यानी राधाकृष्णन की जीत तय है। इसके विपरीत इंडिया गठबंधन के पास 324 वोट का अनुमान है। इसमें कांग्रेस के 99 लोकसभा और 26 राज्यसभा सांसद, सपा के 37, टीएमसी के 29, डीएमके के 22 और आम आदमी पार्टी के 10 सांसद शामिल हैं। हालांकि 18 सांसद ऐसे हैं, जिनका रुख अब तक साफ नहीं है। इनमें बीजेडी के 7, बीआरएस के 4, अकाली दल का 1, जेडपीएम का 1, वीओटीटीपी का 1 और 3 निर्दलीय सांसद शामिल हैं। चुनाव गुप्त मतदान और एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली से होता है। इसमें सांसदों को प्राथमिकता अंकित करनी होती है और गलत वोटिंग से मतपत्र रद्द हो सकता है। यही कारण है कि क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इस बार भी यही स्थिति है। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए प्रशिक्षण सत्र कराए हैं ताकि कोई वोट अमान्य न हो और 100 प्रतिशत मतदान सुनिश्चित किया जा सके। एनडीए की रणनीति साफ है सिर्फ जीतना नहीं बल्कि भारी अंतर से जीतकर विपक्ष को यह संदेश देना कि उसकी एकजुटता महज कागजी है।एनडीए के वरिष्ठ नेता विपक्षी सांसदों और निर्दलीयों से सीधे संपर्क साध रहे हैं। अमित शाह और राजनाथ सिंह व्यक्तिगत तौर पर कई सांसदों से बातचीत कर चुके हैं। वाईएसआरसीपी, जिसके पास 11 सांसद हैं, पहले ही संकेत दे चुकी है कि वह विपक्ष का साथ नहीं देगी। 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वाईएसआरसीपी ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया था। बीजेडी भी अतीत में एनडीए को समर्थन देती रही है और इस बार भी संभावना इसी की है। बीआरएस के 4 सांसद और कुछ निर्दलीय भी एनडीए के खेमे में जा सकते हैं। इन हालात में विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन इस चुनाव को वैचारिक लड़ाई के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि यह संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का सवाल है। उन्होंने बी. सुदर्शन रेड्डी को इस रूप में पेश किया है कि वे संविधान की आत्मा की रक्षा करेंगे। कांग्रेस ने अपने सांसदों को एकजुट रखने के लिए रणनीतिक बैठकें और मॉक पोल कराए हैं। हर 15 सांसदों पर एक समन्वयक नियुक्त किया गया है। लेकिन गठबंधन की एकजुटता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का डिनर कार्यक्रम बाढ़ की वजह से रद्द हो गया, जिससे असंतोष की खबरें आईं। राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, जिससे विपक्षी खेमे का मनोबल प्रभावित हुआ है।कांग्रेस के कुछ सांसदों पर भी क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में जहां बीजेपी का दबदबा है। हालांकि 2022 में कांग्रेस के सांसदों ने ऐसा नहीं किया था और विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को एकजुट होकर वोट दिया था। लेकिन इस बार माहौल अलग है। समाजवादी पार्टी पर नजरें सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि उसके कुछ सांसदों के क्रॉस वोटिंग करने की चर्चा जोरों पर है। राजीव राय जैसे नेता, जिनका व्यवसाय भी फैला हुआ है, सत्ता पक्ष से संबंध बनाए रखना चाहेंगे। क्रॉस वोटिंग भारतीय संसदीय राजनीति में नई बात नहीं है। 2017 में वेंकैया नायडू को 516 वोट मिले थे, जबकि एनडीए की आधिकारिक संख्या इससे कम थी। 2022 में जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जो एनडीए की ताकत से कहीं ज्यादा था। इसमें बीजेडी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस की भूमिका रही। लोकसभा स्पीकर चुनाव 2019 में भी ओम बिरला को ऐसे ही अतिरिक्त वोट मिले थे। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि गुप्त मतदान में व्यक्तिगत समीकरण और सत्ता पक्ष की लॉबिंग अहम होती है।अमित शाह का राजीव राय को फोन कॉल इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सत्ता पक्ष ने यह साफ कर दिया है कि वह विपक्षी सांसदों से भी व्यक्तिगत संपर्क साधने से पीछे नहीं हटेगा। भले ही जीत पहले से तय हो, लेकिन इस जीत का अंतर विपक्ष की साख को कमजोर करेगा। अगर सपा या अन्य विपक्षी दलों से क्रॉस वोटिंग होती है, तो इंडिया गठबंधन की संगठनात्मक कमजोरी उजागर होगी। बीजेपी इसे अपनी रणनीतिक क्षमता और विपक्ष को तोड़ने की ताकत के रूप में प्रचारित करेगी। यह उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का असली संदेश भी है। आंकड़ों की बाजीगरी से परे यह चुनाव सत्ता और विपक्ष की ताकत, संगठन और रणनीति की परीक्षा है। एनडीए भारी बहुमत से जीतकर यह दिखाना चाहता है कि विपक्ष की एकजुटता खोखली है। वहीं, विपक्ष इस चुनाव को वैचारिक रंग देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। लेकिन अब तक के हालात बताते हैं कि विपक्ष न सिर्फ हार की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि उसकी एकजुटता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।अमित शाह और राजीव राय की बातचीत छोटी सी घटना लग सकती है, पर इसके पीछे छिपा संदेश गहरा है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

विकास और पर्यावरण

सर्वोच्च न्यायालय ने हिमालयी राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन पर टिप्पणी करते हुए पेड़ों की अवैध कटाई को जिस तरह इसका एक कारण बताया है, वह बहुत चिंताजनक है. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के पानी में लकड़ियों के बह जाने की मीडिया फुटेज का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि यह एक गंभीर मामला है और प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ियों पर पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है.

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वनों की अवैध कटाई को हिमालयी राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ का एक कारण बताया है, जो बेहद चिंताजनक है और मामले की गंभीरता को उजागर करता है.

अदालत का कहना था कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाये रखा जाना चाहिए. शीर्ष अदालत दरअसल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बताया गया है कि मॉनसून की वर्षा के बमुश्किल एक सप्ताह के भीतर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में व्यापक रूप से और घातक भूस्खलन हुए हैं. याचिका में अनियमित विकास, वनों की अवैध कटाई तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हिमालयी क्षेत्र की बढ़ती संवेदनशीलता के बीच के संबंधों को उजागर करते हुए इस पर भी जोर दिया गया कि समर्पित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए योजनाएं बनाने में विफल रही हैं, जिस कारण हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं. इसमें इस तरह की आपदाओं तथा विनाश के पैमाने को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कई कारणों को रेखांकित भी किया गया है, जैसे- पहाड़ों में सड़क नियमावली की अनदेखी, जल निकायों पर अतिक्रमण तथा पर्यावरण सुरक्षा उपायों का पालन न करना. साथ ही, याचिका में यह भी कहा गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय हिमालयी क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी तथा नदियों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर की सरकारों को नोटिस जारी कर दो सप्ताहों के भीतर जवाब मांगा है. पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए कहा है और उन्होंने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया है. चूंकि यह बेहद गंभीर मामला है, ऐसे में, संबंधित सरकारें तथा प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते. लगातार आपदाओं को देखते हुए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने ही होंगे.

भविष्य की राजनीति तय करेगा बिहार चुनाव

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
prabhuchawla@newindianexpress.com

बेशक विस्थापन पर केंद्रित कांग्रेस का अभियान जोर पकड़ रहा है, पर इंडिया गठबंधन में अंदरूनी खींचातानी इसे बाधित कर सकती है. बिहार का चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. राज्य के मतदाता सिर्फ अगले मुख्यमंत्री का ही चयन नहीं करेंगे, वे भारत के राजनीतिक भविष्य की भी नींव रखेंगे.

बिहार में होने वाला चुनाव सिर्फ एक लोकतांत्रिक कवायद नहीं है, इसमें तीन दिग्गजों- नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की राजनीति दांव पर लगी है. दो दल- जदयू और लोजपा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि शक्तिशाली भाजपा और इंडिया का भंगुर गठबंधन सबसे कठिन लड़ाई में जूझने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पांच बार चुनाव जीता है, परंतु यह उनका निर्णायक चुनाव होगा. उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत 2010 के 22.6 फीसदी से घटकर 2020 में 15.7 प्रतिशत रह गया. ढांचागत सुधार, विद्युतीकरण में वृद्धि तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने जैसी उनकी उपलब्धियां निर्विवाद हैं, लेकिन अब उन पर थकान भारी पड़ रही है. बेरोजगारी बिहार की आत्मा से जुड़ी है, और 75 लाख लोग बिहार से बाहर मेहनत कर जीविका चला रहे हैं. विस्थापन एक ऐसा घाव है, जो भरना ही नहीं चाहता. नीतीश कुमार को अपने दम पर बहुमत लाना होगा, ताकि एनडीए में अपनी पार्टी की प्रासंगिकता बनाये रखें, जिसने उन्हें मुख्यमंत्री प्रस्तावित किया है. इससे कुछ स्थानीय भाजपा नेता परेशान हैं, जो बड़ी भूमिका चाहते हैं.

बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका इन दिनों तेजस्वी यादव निभा रहे हैं. इस चुनाव में उन्हें लालू के बेटे से अलग पहचान साबित करनी होगी. इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी अपने मुस्लिम-यादव जनाधार पर निर्भर हैं, जिसके बूते 2020 के चुनाव में 75 सीटें जीत राजद राज्य का सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है. एनडीए के मजबूत जातिगत समीकरण को चुनौती देने के लिए तेजस्वी को अब ओबीसी, दलितों और कमजोर तबकों तक पहुंच बनानी होगी. तेजस्वी के तेज, युवा केंद्रित और तकनीकी दक्षता से लैस चुनाव अभियान का दायरा बढ़ रहा है. एक ओपिनियन पोल के मुताबिक, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी 36.9 प्रतिशत रेटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 18.4 फीसदी रेटिंग से बहुत आगे है. इसके बावजूद तेजस्वी पर लालू यादव के दौर के जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ है. लालटेन चुनाव चिह्न के आधार पर विपक्ष राजद को प्रगति विरोधी भी कहता है. बिहार के रण में राहुल गांधी भी अपनी योग्यता साबित करना चाहते हैं. वर्ष 2020 में 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस गठबंधन में जूनियर पार्टनर है, फिर भी चुनाव में कांग्रेस की भूमिका बड़ी है. यह चुनाव न केवल इस प्रांत में कांग्रेस की संभावनाओं की परीक्षा है, इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के संभावित प्रधानमंत्री के रूप में राहुल की नियति भी तय करेगा. तेजस्वी और कन्हैया कुमार के साथ राज्य पदयात्रा में उन्होंने उन मुद्दों को उभारा, जो युवाओं के मुद्दे हैं. यानी बेरोजगारी, विस्थापन और आर्थिक महत्वाकांक्षा. ऐसे ही, प्रियंका के साथ राहुल की साझा रैलियों का उद्देश्य कभी कांग्रेस के गढ़ रहे इलाकों में पार्टी को फिर से मजबूत बनाना था. राहुल गांधी के 'वोट चोरी' तथा चुनाव आयोग के पक्षपात के आरोप सार्वजनिक झगड़े में बदल गये हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सावधानी से जांच करने को कहा है. कांग्रेस के 'पलायन रोको, नौकरी दो' का नारा बिहार की हकीकत से जुड़ गया है, जहां के 51.2 फीसदी मतदाताओं ने रोजगार को अपनी प्रमुख प्राथमिकता बतायी है. नेहरू के वैज्ञानिक समाजवाद के नजरिये को मौजूदा समय संदर्भ में ढालकर राहुल गांधी कांग्रेस की परंपरागत धर्मनिरपेक्ष सोच को समसामयिक आर्थिक लोकप्रियतावाद से जोड़ते दिखाई देते हैं.

भाजपा के एजेंडे में आदर्शवाद कहीं नहीं है. एनडीए की चुनावी गाड़ी बिहार में एक असामान्य बाधा का सामना कर रही है : राज्य में एक भी करिश्माई स्थानीय नेता नहीं है. ऐसे में, भाजपा नरेंद्र मोदी की व्यापक लोकप्रियता व चुंबकीय व्यक्तित्व तथा अमित शाह के रणनीतिक कौशल के सहारे आगे बढ़ेगी. वर्ष 2020 के 74 सीटों से आगे बढ़ने के लिए पार्टी मोदी के विकासवादी विमर्श के साथ राजद के दौर में कानून-व्यवस्था की विफलता को याद दिलायेगी.

चुनाव विश्लेषक एनडीए के पक्ष में 48.9 प्रतिशत तथा इंडिया गठबंधन के पक्ष में 35.8 फीसदी समर्थन का आंकड़ा दे रहे हैं. परंतु एनडीए सहयोगियों में सब कुछ ठीक नहीं दिखता. सीटों के मामले में चिराग पासवान की लोजपा और जदयू के बीच मतभेद हैं. चिराग पासवान 20-25 सीट मांग रहे हैं, पर जदयू इतनी सीटें देना नहीं चाहता. चिराग पासवान बिहार चुनाव में सबसे अप्रत्याशित चेहरे के रूप में सामने हैं. पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में पांच सीटों पर शानदार जीत बिहार में पासवान मतदाताओं के बीच, जिनकी आबादी राज्य में अच्छी-खासी है, चिराग की लोकप्रियता का सबूत था. अगर चुनाव में भाजपा और जदयू में से किसी को निर्णायक बहुमत नहीं मिलता, तो मुख्यमंत्री के चयन में चिराग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. उनके द्वारा नीतीश कुमार के राज में कानून-व्यवस्था की आलोचना एनडीए में अंदरूनी दरार के बारे में बताती है. एनडीए के मजबूत जातिगत समीकरण को मोदी की रैलियों ने मजबूती प्रदान की है, जिनमें कल्याणकारी योजनाओं तथा ढांचागत सुधारों के बारे में बताया जाता है. एआइ की मदद से बनाये गये मीम्स तथा प्रभावी संदेशों से भरपूर राजद का डिजिटल अभियान एनडीए के व्हाट्सएप संदेशों तथा डोर-टू-डोर कैंपेन से बिल्कुल अलग है.

बिहार की राजनीति अब भी जातिगत समीकरणों पर निर्भर है. एक सर्वे बताता है, 51.2 फीसदी मतदाताओं ने बेरोजगारी को, 45.7 प्रतिशत वोटरों ने मुद्रास्फीति को और 41 फीसदी वोटरों ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बताया है. पर जातिगत समीकरणों को, नीतीश द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों तथा चिराग द्वारा पासवान मतदाताओं, साधने के कौशल के कारण एनडीए अपने प्रतिद्वंद्वी पर भारी है. दूसरी ओर, मुस्लिम, यादव, बहुजन, आदिवासी और गरीब मतदाताओं के अपने जनाधार को राजद और व्यापक करने की कोशिश में है. सभी 243 सीटों पर लड़ रही जन सुराज पार्टी जातिगत समीकरणों को महत्व नहीं दे रही. पर इसके नेता प्रशांत किशोर की मुख्यमंत्री के रूप में रेटिंग मात्र 16.4 फीसदी है. बेशक विस्थापन पर केंद्रित कांग्रेस का अभियान जोर पकड़ रहा है, पर इंडिया गठबंधन में अंदरूनी खींचातानी इसे बाधित कर सकती है. बिहार का चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. राज्य के मतदाता सिर्फ अगले मुख्यमंत्री का ही चयन नहीं करेंगे, वे भारत के राजनीतिक भविष्य की भी नींव रखेंगे.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

हॉकी में फिर एशिया का सरताज बना भारत

सत्येन्द्र पाल सिंह
वरिष्ठ खेल पत्रकार
satyendrapalsingh0507@gmail.com

भारत ने राजगीर में हुए पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 चैंपियनशिप चौथी बार जीत ली है. इस जीत के साथ ही उसने एफआइएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए सीधे क्वालिफाई कर एक बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है. भारतीय हॉकी टीम की इस खिताबी जीत का कारण 'स्ट्रक्चर' पर काबिज रहना और प्रोसेस पर भरोसा करना रहा.

भारत ने राजगीर में हुए पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 चैंपियनशिप चौथी बार जीत ली है. इस जीत के साथ ही उसने एफआइएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए सीधे क्वालिफाई कर एक बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है. हालांकि भारतीय हॉकी टीम के लिए यह जीत ही काफी नहीं है, उसे अभी और चुनौतियों का सामना करना है. विदित हो कि भारत ने पूल ए में अपना तीनों मैच जीता और सुपर चार में पांच बार की चैंपियन रही दक्षिण कोरिया के खिलाफ पहला मैच ड्रॉ खेला. इसके बाद मलेशिया और चीन को हरा वह सुपर चार में शीर्ष पर पहुंचा और एशिया कप के फाइनल में स्थान बनाया. फाइनल मैच में भारत ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के लंबे एरियल पास स्कूप के जरिये दक्षिण कोरिया की मजबूत किलेबंदी को भेद 4-1 की प्रभावी जीत दर्ज की.

भारतीय हॉकी टीम का एशिया कप में खिताबी जीत का कारण 'स्ट्रक्चर' पर काबिज रहना और प्रोसेस पर भरोसा करना रहा. भारत ने शुरुआत के दोनों पूल मैचों में चीन और जापान के खिलाफ जिस तरह कड़े संघर्ष के बाद जीत दर्ज की और फिर दक्षिण कोरिया के खिलाफ पहले सुपर चार में बढ़त लेने के बावजूद जब ड्रॉ खेला, तब आलोचकों ने चीफ कोच क्रेग फुल्टन पर उनकी रणनीति को लेकर सवाल उठाये. पर फुल्टन ने बार-बार यही दोहराया कि भारतीय टीम हारे या जीते, वह अपने स्ट्रक्चर पर काबिज रहने के साथ ही गलतियों से बहुत जल्दी सीखती है. ऐसा हुआ भी. शुरुआती संघर्षों से उबरकर वह न केवल फाइनल में पहुंची, बल्कि चैंपियनशिप भी अपने नाम की. विदित हो कि भारत 2023 में भुवनेश्वर और राउरकेला में हुए हॉकी विश्व कप में संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर रहा था. इस जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और चीफ कोच फुल्टन की निगाहें 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप में पदक जीतने पर टिक गयी हैं.

भारत के नौजवान स्ट्राइकर अभिषेक नैन ने एशिया कप में छह गोल दागे और 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट' बने. सुखजीत सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भी टूर्नामेंट में छह-छह गोल किये. अभिषेक ने तो शुरुआती मैचों में रिवर्स हिट से गोल करने में नाकाम रहने के बाद गोल करने के जो मौके बनाये और पेनल्टी कॉर्नर बनाने पर जिस तरह ध्यान केंद्रित किया, वह भारतीय टीम के बहुत काम आया. इस टूर्नामेंट के बाद अभिषेक, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह के साथ शिलानंद लाकड़ा भी भारत की अग्रिम पंक्ति में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. वहीं मध्य पंक्ति में अनुभवी मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, राज कुमार पाल की भी टीम में जगह पक्की हो गयी है. रक्षा पंक्ति में बतौर ड्रैग फ्लिकर कप्तान हरमनप्रीत सिंह, बतौर रशर अमित रोहिदास और फ्रीमैन के रूप में सुमित व संजय की जगह भी पक्की है. हालांकि जुगराज सिंह ड्रैग फ्लिकर के रूप में विकल्प तो देते हैं, पर रक्षा पंक्ति में गोलरक्षक कृष्ण बहादुर पाठक के साथ वह भारत की ऐसी कमजोर कड़ी हैं, जिन्हें लेकर चीफ कोच फुल्टन और चयनकर्ता कुछ सोच सकते हैं.

आगामी मैचों की बात करें, तो भारत को अगले वर्ष (14 से 30 अगस्त, 2026 तक) होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप और उसके बाद जापान में होने वाले एशियाई खेलों (19 सितंबर से चार अक्तूबर, 2026 तक) में शिरकत करना है. भारत के लिए विश्व कप में पदक जीतना तो जरूरी है ही, जापान में होने वाले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना भी आवश्यक है. इन जीतों के साथ ही उसे 2028 के लॉस एंजिल्स ओलिंपिक का टिकट मिल जायेगा. इन दोनों मैचों की तैयारी के लिए भारत के पास लगभग एक वर्ष का समय बाकी है. अभी इस वर्ष भारत को अजलान शाह कप खेलने मलेशिया जाना है और उसके बाद एचआइएल होना है. ऑस्ट्रेलिया के भी भारत आने का कार्यक्रम है. इन सबके बीच एफआइएच प्रो लीग 2025-26 भी शुरू होगा.

भारतीय टीम के लिए एशिया कप जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले वह एफआइएच प्रो लीग 2024-25 के यूरोपीय चरण में आठ में से सात मैच में हार के साथ आठवें स्थान पर रही थी. हालांकि इनमें से ज्यादातर मैचों में भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत कलाई में चोट के चलते नहीं खेल पाये थे. एशिया कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गयी भारतीय टीम ने चार मैत्री मैचों में भी बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया था. इसे देखते हुए कई हॉकी समीक्षकों और आलोचकों ने भारत के चीफ कोच फुल्टन को हटाने की मांग शुरू कर दी थी. पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने एशिया कप के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे न तो फुल्टन को हटाने की सोच रहे हैं, न ही टीम में किसी बड़े बदलाव की. उन्होंने यह भी साफ किया है कि वे चीफ कोच और चयनकर्ताओं से चर्चा कर विश्व कप और एशियाई खेलों के लिए एक ही भारतीय टीम चुनेंगे. दिलीप की मानें, तो चयनकर्ता भारतीय टीम के चयन में सुझाव दे सकते हैं, परंतु भारतीय टीम चुनने का अंतिम निर्णय चीफ कोच फुल्टन ही करेंगे.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से गुस्से में युवा

नेपाल का युवा गुस्से में है. फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसी सोशल मीडिया साइटों पर नये प्रतिबंध ने युवाओं की दुखती रग को छेड़ दिया है. युवा इन प्लेटफार्मों का उपयोग अपनी कुंठाओं को बाहर निकालने, दोस्तों और बाकी दुनिया से जुड़े रहने के लिए करते हैं. वे पहले से ही परेशान हैं, देश की दयनीय स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था, व्याप्त भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से तंग आ चुके हैं- इतना कि उनमें से कइयों को तो देश में कोई भविष्य ही नजर नहीं आता है. ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध, जो उनकी जीवनशैली का अभिन्न अंग बन चुके हैं, उनकी निराशा और बेचैनी को बढ़ा रहे हैं. वे सड़कों पर उतर आये हैं और यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बस अब बहुत हो चुका. अपने साथ एक के बाद एक हो रहे अन्याय को अब वे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करने वाले. सरकार द्वारा उन्हें हल्के में लेना नासमझी होगी. ऐसे आंदोलनों की अपनी अलग गति होती है और उनके परिणाम का अनुमान लगाना असंभव होता है. नेपाल की कानूनी और सामाजिक वास्तविकताओं को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने का निर्णय सही है. पर उसे जिस तरह से लागू किया गया, वह बिल्कुल गलत है. सबसे पहले, इन प्लेटफॉर्मों को एक व्यापक कानून के जरिये विनियमित किया जाना चाहिए था, न कि कैबिनेट के निर्णय से. सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से यही कहा था, पर सत्तारूढ़ दलों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए उसके निर्णय को तोड़-मरोड़कर पेश किया है. ऐसे में यह संदेह होना स्वाभाविक है कि सरकार इन प्लेटफॉर्मों के जरिये कुछ संदिग्ध प्रावधान थोपना चाहती है. देश के नियमों का पालन करने से इनकार करने वाले विदेशी एपों को कानूनी दायरे में लाना उचित है. पर इससे भी अधिक जरूरी है अपने लोगों, विशेषकर युवाओं की भावनाओं का सम्मान करना.

THE KATHMANDU POST
WITHOUT FEAR OR FAVOUR

बोधि वृक्ष

संबंधों की मिठास

कहते हैं कि सुख यदि अपने स्नेहियों के साथ मिलकर बांटा जाता है, तो उसका आनंद दोगुना हो जाता है और दुख के समय यदि अपने स्नेहियों का साथ मिल जाता है, तो दुख आधा हो जाता है. किंतु अफसोस कि शिक्षा के वर्तमान स्वरूप ने लोगों की मानसिकता एवं मान्यताओं को इस कदर बदल दिया है कि रिश्तों की अहमियत पर आज प्रश्नचिह्न लग गया है. पांच दशक पूर्व के सामाजिक वातावरण में जो अपनत्व दिखाई देता था, उस ऊष्मा का वर्तमान में अभाव-सा है. बदलाव के इस भागमभाग भरे दौर में संबंधों में शिथिलता आ गयी है. आज की पीढ़ी सामाजिक परंपराओं को रूढ़िवादिता मान उन्हें नजरअंदाज करने लगी है. संयुक्त परिवार की 'हम' की भावना अब एकल परिवार के 'मैं' में बदल चुकी है. जहां पहले परिवार में पांच-छह बच्चे हुआ करते थे, समय की पुकार पर बच्चे केवल एक या दो होने लगे और अब तो दंपत्ति या तो संतान चाहते ही नहीं, अथवा एक ही संतान का सूत्र अपनाने लगे हैं. ऐसे माहौल में लगता है कि संबंधों की डोर शनैःशनैः कटती जा रही है. ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आयेगा जब भाई-बहन, चाचा-मामा, मौसी-बुआ जैसे संबंध देखने और सुनने में भी नहीं आयेंगे. आज की प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा के दौर में माता-पिता एवं शिक्षकों का यह दायित्व बनता है कि वे अपने बालकों को उच्च शिक्षित करने से पहले संस्कारों का पाठ पढ़ायें और उनमें नैतिकता का बीजारोपण करें. आने वाला समय अनेक प्रतिकूलताओं से भरा होगा, ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि युवाओं को दृढ़ता से खड़े होने, मुसीबतों का सामना करने, परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए हिम्मत का पाठ पढ़ाया जाए और अध्यात्म के महत्व को उनके जीवन में बढ़ाया जाए. स्मरण रहे! यदि समाज से संबंधों की मिठास को समाप्त कर दिया गया, तो संपूर्ण समाज विषैला बन जायेगा. अतः समझदारी इसी में है कि हम आने वाली पीढ़ी को परस्पर स्नेह संबंध रखना सिखायें, ताकि वे सुखमय एवं शांतिमय जीवन जी सकें.

-ब्रह्माकुमार निकुंज जी

कुछ अलग

एआइ के कमाल से विस्मित है दुनिया

सरस्वती रमेश
टिप्पणीकार
saramesh17@gmail.com

कुछ रोज पहले ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखी. किसी महिला ने लिखा था, 'मैं चाहती हूं कि एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मेरे बर्तन, कपड़े धोए, सफाई करे और मैं पेंटिंग या लेखन कर सकूं.' एआइ से ऐसी अपेक्षा देख थोड़ा विस्मय हुआ. तभी बेंगलुरु वाले मित्र की याद आयी. उनके घर रोबोट ही सफाई करता है. यह अलग बात है कि ऐसे रोबोट तक मेरे जैसी देश की अधिकांश महिलाओं की पहुंच बनने में काफी समय लग सकता है. परंतु लेखक, कलाकार, चित्रकार का काम तो एआइ बड़ी आसानी से कर रहा है. एआइ के बनाये चित्र, वीडियो, लेख आदि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में तो दिखने भी लगे हैं. अभी तक लोग शॉर्ट फिल्म के जरिये रचनात्मकता दिखा रहे थे. अब एआइ से शॉर्ट फिल्में बनायी जाने लगी हैं.

हाल ही में खबर आयी कि शेखर कपूर ने वारलॉर्ड का टीजर रिलीज कर दिया है. एआइ से बनी उनकी यह पहली फिल्म है. जानकार बता रहे हैं कि एआइ फिल्मों का बजट काफी कम कर देगी. मामूली खर्चे पर हर कोई फिल्म बना सकेगा. मतलब ओटीटी पर फिल्मों की भरमार होगी. ठीक वैसी ही जैसी अभी रील्स की भरमार है. अखबारों को लेख के लिए लेखकों की जरूरत नहीं पड़ेगी. कहानी, कविता के लिए कहानीकार और कवियों की खुशामद नहीं करनी होगी. सब कुछ झटपट मिल जायेगा. एआइ के झटपट कमाल से लेखक, कलाकार बिरादरी वाले सदमे में हैं. इन सब को डर सता रहा है कि कलाकारों, रचनाकारों का हौसला टूटेगा. निराशा पैदा होगी. यदि एआइ ही अभिनय करेगा, तो अभिनय की कला सीखने के लिए वर्षों साधना करने वालों का क्या होगा. फिल्म इंडस्ट्री ने अब तक इतने लीजेंड्स पैदा किये हैं. क्या अब लोग छोटा भीम, डोरेमॉन या शिनचैन जैसे किसी काल्पनिक अभिनेता को लीजेंड्स का दर्जा देंगे? धर्मवीर भारती, अमृता प्रीतम, गुलजार, मनोहर श्याम जोशी सब एआइ से ही जन्म ले लेंगे?

उपरोक्त सारी बातों से गुजरते हुए मैं भी जरा सोच में पड़ गयी हूं. क्या सचमुच ऐसा होगा कि साहित्य, जो समाज का दर्पण होता रहा है, वह दर्पण अब एआइ हो जायेगा. अब तक जो फिल्में हमारा मनोरंजन करने के साथ ही समाज का आईना भी होती रही हैं, वही फिल्में अब किसी दूसरी दुनिया की कहानी कहने लगेंगी. मानवीय भावनाओं का कोई मतलब नहीं रहेगा? ब्रेन इंटेलिजेंस (बीआइ) बेकार हो जायेगा, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से ही होगा? सचमुच एआइ और बीआइ की जबरदस्त टक्कर है. आने वाला समय बतायेगा, जीत किसकी होती है. तो परिणाम आने तक प्रतीक्षा करते हैं.

आपके पत्र

ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के उपाय

शहरों की तरह गांवों में भी जगह-जगह दो खंभों के भरोसे बिजली के ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं. इससे गांव प्रकाशित तो होते हैं, पर बारिश और तूफान सहते-सहते ये कम समय में ही जर्जर हो जाते हैं. पेड़ों की डालियां टूटकर गिरने से भी ट्रांसफॉर्मर को नुकसान पहुंचता है. नया ट्रांसफॉर्मर लगाने में समय और पैसे दोनों ही लगते हैं और कई दिनों तक बिजली भी गुल रहती है. बिजली विभाग को चाहिए कि वह ट्रॉसफॉर्मर के लिए पक्की गुमटी का इंतजाम करे. इससे ट्रांसफॉर्मर बार-बार खराब नहीं होंगे.

श्रीमय घोष, जमशेदपुर

जीएसटी दर में सुधार सराहनीय

जीएसटी की दरों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार को धन्यवाद. अधिकांश घरेलू वस्तुओं पर 18 प्रतिशत और पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लेकर सरकार ने जनता को अच्छा संदेश दिया है. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत टैक्स भी उचित निर्णय है. इस बदलाव के बाद हम सब यह उम्मीद कर सकते हैं कि अधिकांश वस्तुओं पर, जिसमें रोजमर्रा की चीजें शामिल हैं, उनके मूल्य घटेंगे. हालांकि इससे सरकार को टैक्स का नुकसान तो होगा, पर मांग में वृद्धि भी होगी.

वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें** : 0651-2544006 ■ **मेल करें** : eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 09-09-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMA12 User: dilip.lal Time: 09-08-2025 21:09 Color:

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 9 सितंबर 2025

युवाओं का आक्रोश

नेपाल में सड़कों पर उतरा युवाओं का गुस्सा अचानक आई प्रतिक्रिया नहीं और न ही सरकार के किसी एक फैसले से उपजा आक्रोश है। यह लंबे वक्त की हताशा है, जो सब्र का बांध टूटने के बाद जाहिर हो रही। नेपाल में गृहमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, सरकार ने हिंसा की जांच कराने का एलान भी किया है, लेकिन देखना होगा कि इन सबका युवाओं के गुस्से पर कैसा और कितना असर होता है।

अभिव्यक्ति पर बैन । नेपाल सरकार ने स्थानीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के कारण बीते हफ्ते 26 सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर बैन लगा दिया। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (पूर्व में ट्विटर), वट्सऐप जैसे बड़े प्लैटफॉर्म भी हैं। सरकार भले सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नियमों का हवाला दे रही हो, लेकिन उसके इस कदम ने जनता खासकर युवाओं में दबे आक्रोश को उभार दिया। युवा वर्ग का कहना है कि यह प्रतिबंध सीधे उनके काम और अभिव्यक्ति पर है।

नेपाल में प्रदर्शन

करप्शन से परेशान । जो सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म अभी उपलब्ध हैं, उन्हीं के जरिये युवा एक-दूसरे से जुड़े और इस आंदोलन को खड़ा किया। इस दौरान 'नेपो बेबी' ट्रेंड करना बताता है कि भाई-भतीजावाद और करप्शन से लोग किस कदर परेशान हैं। इस साल की शुरुआत में भी ऐसा ही एक आंदोलन हो चुका है, जब देशभर में मांग उठी कि राजशाही की वापसी हो। उस समय भी जनता ने भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा जताया था।

राजनीतिक अस्थिरता । नेपाल के अंदरूनी हालात लंबे समय से नाजुक बने हुए हैं। यह देश राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों से जूझ रहा है। विडंबना है कि 2008 में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर व्यापक जन आंदोलन छिड़ा था, जिसने राजशाही का अंत कर गणतांत्रिक व्यवस्था कायम की। लेकिन, दो दशक भी नहीं बीते और उस सिस्टम से जनता का मोहभंग हो चुका है। चुने हुए नेताओं ने लोगों को किस कदर निराश किया है, समझने के लिए यह बताना काफी है कि 17 बरसों में यहां 14 सरकारें बन चुकी हैं। और, पूर्व प्रधानमंत्रियों शेर बहादुर देउबा से लेकर बाबूराम भट्टराई, प्रचंड और मौजूदा पीएम केपी शर्मा ओली तक - तमाम राजनेता किसी न किसी तरह के करप्शन के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

भरोसे की कमी । नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन और प्रवासी नागरिकों की ओर से भेजी गई रकम पर निर्भर है, पर हाल में दोनों में कमी आई है। युवाओं में बेरोजगारी दर 19.2% है और 82% आबादी informal employment में है। देश की GDP में मामूली तेजी का अनुमान है, लेकिन इन प्रदर्शनों से लगता है कि सरकार युवाओं में उम्मीद और भरोसा जगाने में नाकाम रही है।

धूप-छांव

ये कहां आ गए हम!

प्रणव प्रियदर्शी

दिलचस्प बात है कि जो चीजें जीवन को चलाने वाली, मनुष्य को आगे बढ़ाने वाली वाली होती हैं, उन्हीं को धार्मिक-आध्यात्मिक दृष्टि खारिज करती दिखती है। जैसे मोह को ही लें तो हम पूरी शिद्दत से जीते रहें, इसके लिए हमारा अपने घर-परिवार, दोस्त-मित्र, समाज वगैरह में मोहासिक्त होना जरूरी है। नवजात बच्चे का मुंह देखकर मां बड़ी से बड़ी पीड़ा झेलने के लिए तैयार हो जाती है। पिता हर कष्ट उठाकर भी उसका भविष्य संवारना चाहता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न गुरु महाराज कहते हैं कि मोह बड़ी घातक चीज है। इसे जितनी जल्दी संभव हो, छोड़ देना चाहिए।

ऐसे ही अपने अंदर का ईगो हो या महत्वाकांक्षा या फिर लालच- इन सबने मनुष्य को अपनी क्षमता की सीमा का निरंतर विस्तार करने को प्रेरित किया है। अपने आसपास भी ऐसे दर्जनों उदाहरण मिल जाते हैं, जिनमें लोग इन्हीं भावनाओं के वशीभूत तमाम प्रतिकूलताओं को चुनौती दे रहे होते हैं। एक बूढ़े नानाजी असाध्य बीमारियों से ग्रस्त अस्पताल के बिस्तर पर पड़े डॉक्टर से गुजारिश कर रहे थे, 'बस तीन दिन और जिला लीजिए मुझे। मेरी नातिन की शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहता उससे पहले मुझे कुछ हो और उसकी शादी में विघ्न पड़ जाए।' झूठी तसल्ली से बचने की कोशिश में डॉक्टर भी कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन अपनी संकल्प शक्ति से उन नानाजी ने तीन दिन निकाले, नातिन की शादी संपन्न हुई, यह खबर उन तक पहुंची और फिर कुछ घंटों के अंदर ही उन्होंने आंखें मूंद लीं।

वर्क प्लेस पर खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ सबको निरंतर मांजते रहने का कारण बनती है। इसके पीछे महत्वाकांक्षा और ईगो जैसी भावनाएं ही तो होती हैं। लालच को भी हमने बदनाम बहुत कर रखा है, लेकिन खुद की जरूरत से आगे बढ़कर सोचने, चाहने और उसे हासिल करने की प्रवृत्ति तथा क्षमता ही इंसान को इस मुकाम तक ले आई है। फिर इनसे परहेज बरतने की शिक्षाओं का भला मतलब क्या है? जवाब शायद इसी मुकाम में छुपा है जहां तक ये भावनाएं हमें ले आई हैं, और जहां आकर हवा, पानी, मिट्टी - सब हम इंसानों का साथ छोड़ते दिखने लगे हैं...।

बोल वचन

म्हारी गैल चल

राहुल पाण्डेय

इधर वेस्ट यूपी में बोली जाने वाली बोली में एक शब्द अक्सर कान में पड़ता है- गैल। उनकी गैल चले जाना। हमारी बहू फलाने की गैल आएगी। यहां गैल का अर्थ होता है साथ। यानी फलाने के साथ चले जाना। दिल्ली और वेस्ट यूपी की पुरानी बोली है कौरवी, जो कि एक मध्य हिंद-आर्य भाषा है। इसका नाम कौरवी रखा था महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। इसी कौरवी से तब उर्दू और आधुनिक हिंदी का विकास हुआ माना जाता है। लेकिन गैल का अर्थ साथ होता है, यह हिंदी के किसी शब्दकोश में नहीं मिलता। अलबत्ता यह शब्द अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कन्नौजी और मैथिली में खूब मिलता है। मैथिली में गेल भी चलता है और गैल भी। गेल का आशय जाने से है, जबकि गैल का अर्थ होता है ऐसा कोना, जो उपेक्षित हो। वहीं अवधी में गैल होता है रास्ता। अवधी कविता में यह अक्सर प्रेम-मार्ग के लिए प्रयोग होता रहा है। कन्नौजी में भी इसे गली या गलियारा के अर्थों में प्रयोग करते हैं। गढ़वाली में भी, कौरवी की ही तरह, गैल का अर्थ साथ ही होता है। बुंदेली और ब्रज में भी इसका मतलब गली, गलियारा या रास्ता ही होता है। कभी साथ, कभी गली, कभी रास्ता तो कभी एक उपेक्षित कोने के अर्थ रखने वाले इस गैल के लिए जाहिर है कि इंग्लिश में कोई एक शब्द तो हो नहीं सकता। गैल की गैल आने के लिए इंग्लिश को अपना रास्ता अभी थोड़ा और चौड़ा करना होगा!

AI Image

यूक्रेन को लेकर US की नीतियों में आए बदलाव की वजह से यूरोप का भरोसा डगमगाया

भारत को क्यों याद कर रहे ग्लोबल लीडर्स

अल्पयू सिंह

'मैंने उस दौरान पीएम मोदी को अलास्का की बैठक के बारे में बताया था।' चीन के थ्येनचिन में प्रोटोकॉल से इतर जब भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन के बीच लिमोजिन डिप्लोमेसी हुई, तो पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिक गईं। कार में बिताए उन 45 मिनटों में क्या बात हुई? पूतिन से यही सवाल किया गया था। दोनों नेताओं का पूतिन की कार में एक साथ सफर करना उसी वक्त लिया गया फैसला था। थ्येनचिन से ठीक 15 दिन पहले पूतिन ने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ उनकी कार 'बिग बीस्ट' में सवारी की थी।

जेलेंस्की का दावा । अलास्का से थ्येनचिन तक, इन दो यात्राओं के दरम्यान यूक्रेन संकट के हल को लेकर मामला काफी बदल चुका है। ऐसा लग रहा है कि शांति की राह निकालने की कोशिशों का स्टेयरिंग अब एक हाथ में नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पूतिन के बीच हुई बातों का पूरा ब्योरा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन, इस मुलाकात से एक दिन पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की थी। जेलेंस्की ने दावा किया था कि पूतिन और दूसरे नेताओं को जरूरी सिग्नल देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री तैयार हैं। जिस वक्त जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन मिलाया, उसी दौरान फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वोल्टोनेन और विदेश मंत्री जयशंकर ने भी यूक्रेन पर चर्चा की थी।

फोन का सिलसिला । थ्येनचिन में पूतिन के साथ बैठक से चार दिन पहले पीएम मोदी के पास हेलसिंकी से भी एक कॉल आई थी - ट्रंप के करीबी और फिलहाल अमेरिका और यूरोप के बीच पुल माने जाने वाले फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की। वह पिछले महीने वाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान भी मौजूद थे। मोदी के साथ बातचीत के बाद स्टब ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा - भारत की बात न सिर्फ दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में सुनी जाती है बल्कि मानी भी जाती है। स्टब के इन शब्दों के मायने अमेरिका से लेकर यूरोप तक की डिप्लोमेसी समझने वाले जानते हैं। इसके बाद से ही पीएमओ और साउथ ब्लॉक में कई देशों से फोन आ चुके हैं।

यूरोप की उम्मीद । शनिवार शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी से बात की। इससे दो दिन पहले यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने संयुक्त कॉल की थी। उर्सुला से लेकर बीते दिनों भारत दौरे पर आए जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल तक, यूरोप के कई नेता मान रहे हैं कि शांति कायम कराने में भारत की अहम भूमिका है। खास बात यह भी है कि यूरोपीय नेताओं ने पेरिस में अहम बैठक के बाद भारतीय पीएम को फोन किया था।

बदलते हालात
- पूतिन-ट्रंप मुलाकात से बाहर होने पर यूरोप असहज
- मल्टीपल पावर सेंटर्स की रणनीति अपनाई जा रही है
- जेलेंस्की, यूरोप के कई नेता नई दिल्ली से बात कर चुके

बदली डिप्लोमेसी । ट्रंप ने चुनाव जीतने से पहले ही दावा किया था कि रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करा देंगे। लेकिन वाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ जिस तरह की तनातनी दुनिया ने लाइव टीवी पर देखी, उसने यूएस डिप्लोमेसी की पूरी परिभाषा को ही उलट दिया। यूरोप में अलास्का समिट के आलोचकों ने कहा कि पूतिन के लिए रेड कारपेट बिछाने के बाद ट्रंप जब वॉशिंगटन लौटे, तो उनके हाथ खाली थे - पूतिन से न कोई वादा मिला, न कोई कमिटमेंट। यूरोपीय नेता पहले से ही ऐसी किसी मीटिंग के हक में नहीं थे, जिसमें जेलेंस्की मौजूद न हों। यहां मसला भरोसे और विश्वसनीयता का भी है।

एक पर भरोसा नहीं । अलास्का की बैठक से ठीक पहले फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों ने यूरोप को इस वार्ता से पूरी तरह हटाने को लेकर चिंता जाहिर की थी। वह भी तब, जबकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यूरोप ने यूक्रेन के लिए फंडिंग का ज्यादा बोझ खुद उठाने की कोशिश की है। ऐसे में स्थायी शांति की तलाश कर रहे यूरोप के कई देश अब मल्टीपल पावर सेंटर्स को एंगेज करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज भारत ऐसे ही एक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आता है।

संतुलित रुख । यूक्रेन युद्ध भारतीय डिप्लोमेसी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह रहा। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधते हुए निष्पक्षता की एक महीन रस्सी पर चलता दिखा। रूस की आलोचना करने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों से हमेशा दूरी बनाते हुए भी नई दिल्ली ने कहा कि यह युद्ध का दौर नहीं है। जेलेंस्की और पूतिन बीते साल ही युद्ध के हल को लेकर भारत की भूमिका पर भरोसा जता चुके हैं।

इमेज का असर । स्विट्जरलैंड में यूरोप की ओर से बुलाई गई शांति वार्ता में चीन के रुख से अलग भारत ने हिस्सा तो लिया था, लेकिन रूस की गैर मौजूदगी में इसके साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सभी पक्षों की उपस्थिति ही स्थायी शांति की पहली शर्त है। डायलॉग और डिप्लोमेसी को लेकर नई दिल्ली के स्टैंड को यूक्रेन अच्छी तरह समझता है। साल 2023 में जी-20 समिट के घोषणापत्र पर आम सहमति को भारत की कूटनीतिक कामयाबी माना गया। भारत की शांति के पक्षकार देश की छवि की वजह से ही ऐसा हो पाया। ऐसे में भारत से अब उम्मीदें लगी हैं, तो हैरानी कैसी।

पतियों से इतनी नाराज़गी क्यों, कोई तो बताए?

अखिलेश प्रताप सिंह

सहकार टैक्सी सेवा की भारत टैक्सी लेने वाले यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिन ड्राइवरों पर क्रिमिनल या नशाखोरी का केस होगा, वे भारत टैक्सी नहीं चला सकेंगे। अपनी कॉलोनी वाले भाई साहब ज्यों ही दिखे, मैंने उन्हें नई स्कीम की खबर सुनाई। रात पूर्ण चंद्रग्रहण का नजारा देखकर मूड फ्रेश हो गया था। अब सोचा सबेरे-सबेरे भाई साहब का चेहरा भी खिला दूं।

उनका चेहरा खिला तो जरूर, लेकिन मुस्कान जरा तिरछी लगी मुझे। बोले, यह बिल्कुल सही कदम होगा। एक-एक टैक्सी सही चलनी चाहिए। लेकिन क्रिमिनल केस वाले लोग माननीय बन जाएं, देश-दुनिया का गियर अपनी जांघ तले दबाए रखें, इसका हिसाब कौन करेगा?

मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई साहब इस कदर भरे पड़े हैं। बदमाश लोग सुनसान इलाके की ओर गाड़ी मोड़ देते हैं। कई तो कम किराये का झांसा देकर सवारी बैठा लेते हैं और फिर लूटपाट करते हैं। इसलिए जांच-परख का सिस्टम बनेगा, यह तो अच्छा ही है भाई साहब, मैंने उन्हें समझाने की एक और कोशिश की।

तो झांसे में आते ही क्यों हैं लोग? वोट देने लायक समझ आ गई 18 साल में, झांसेबाजों के चक्कर में न पड़ें, यह समझ में नहीं आता? भाई साहब का यह तेवर देख मैं समझ गया कि आज वह समझाने के मूड में हैं। कोई तो पेच कहीं उलझा है।

AI Image

गुस्ताख़ी माफ़

क्या हुआ, दिल्ली में तो चुनाव है नहीं, आपके जीवन में कोई तनाव है क्या? मैंने हालचाल पूछ लेना मुनासिब समझा। अब जरा उनका मूड बदला। मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, यार आप ही बताओ, हम पतियों की क्या गलती है? नौकरी-चाकरी करो, दुकान-धंधा संभालो, बीवी-बच्चों का ध्यान रखो। हमें एक मिनट की भी फुरसत नहीं कि आदमी अपने मन का कुछ कर सके।

मामला डोमेस्टिक था। क्या कर लिया भाई साहब आपने अपने मन का? क्या बवाल हो गया? मन की बात कहने-सुनने का मौका तो सबको मिलना चाहिए। नेता तो यूपी-बिहार और तमाम जगहों पर पब्लिक को सुनाने के बाद अपने मन की बात सुनने के लिए सिंगापुर, मलेशिया और न जाने कहां-कहां जाते हैं। इसमें गलत क्या है? मैंने भाई साहब की मिजाजपुर्सी की।

सही-गलत का फैसला तो तब होगा, जब आप मेरी बात सुनेंगे। भाई साहब फट पड़े। आपकी भाभीजी कॉलोनी की महिला संघ की चेयरपर्सन बनी हैं, आपको तो पता ही होगा। उन्होंने सबको धन्यवाद देने के लिए एक पार्टी का न्योता दे डाला। अब घर में जलसा हो तो पति दूर रह सकता है? क्या लाना है, क्या खिलाना है, किसे कहां बैठाना है, हर चीज का इंतजाम मुझे ही तो करना था। सब किया, जैसे पहले भी करता ही रहता था।

जी, यह तो घर का काम है, तो इसमें पीछे क्या रहना भाई साहब। पत्नी को तो अर्द्धांगिनी कहा ही गया है। उनकी हर जिम्मेदारी में पति को हाथ बंटाना ही चाहिए। जो नहीं करते, उन्हें भी करना चाहिए। यही तो संस्कार हैं हमारे। मैंने टुकड़ा जोड़ा।

लेकिन संस्कार पर ही तो बवाल है। भाई साहब बिफर पड़े। मैं पार्टी में जरा देर को क्या चला गया, तूफान खड़ा कर दिया बाकी महिलाओं ने। कहने लगीं कि मैं पत्नी के काम में टांग अड़ा रहा हूं। आप ही बताओ, मुझे देखकर बताओ, क्या मुझमें इतनी हिम्मत है? मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं तो यह देखने गया था कि सबको चाय-समोसे मिले या नहीं। इसमें क्या गलत कर दिया? पतियों से इतनी नाराजगी क्यों है, कोई तो बताए?

क्या ट्रैक बदल रही BJP की सियासत

नरेन्द्र नाथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल लाल किले से 15 अगस्त के मौके पर GST रिफॉर्म का एलान किया। इस एलान के चलते अब 22 सितंबर से कई चीजें सस्ती होंगी। इस साल आर्थिक और आम लोगों से जुड़ी चीजों पर यह दूसरा बड़ा रिफॉर्म है। पहला रिफॉर्म साल के शुरू में बजट में हुआ, जब 12 लाख तक की कमाई पर इनकम टैक्स को समाप्त किया गया। जाहिर है, ऐसे फैसलों को राजनीति के चश्मे से भी देखा जाएगा। क्या केंद्र सरकार अपने तीसरे टर्म में अपने कोर वोटर को खुश करना चाहती है, जिनमें कहीं न कहीं थकान दिखने लगी थी? क्या राष्ट्रवाद या हिंदुत्व जैसे भावनात्मक मुद्दे अब उतने प्रभावी नहीं रहे, और लोग भी कहीं न कहीं असल मुद्दों की ओर जाने लगे हैं? इन दो बड़े रिफॉर्म के बीच राजनीति की इस धारा को समझने की कोशिश की जा रही है।

मिलने लगे थे संकेत

हालांकि GST रिफॉर्म को कई और मुद्दों से जोड़कर देखा गया। मसलन, अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के अलावा इसे इकॉनमी में सुस्त डिमांड को ठीक करने की दिशा में भी उठाया गया कदम बताया गया। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार और BJP को भी अंदाजा लगने लगा है कि अब असल मुद्दों की ओर लौटने का टाइम आ गया है। इसका पहला बड़ा संकेत 2024 आम चुनाव में मिला, जब राम मंदिर निर्माण और इसके लिए चुनाव से पहले हुए बहुत बड़े आयोजन के बावजूद BJP को उम्मीद के अनुरूप सफलता नहीं मिली। एक हालिया सर्वे में बताया गया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर का सरकार और BJP को उतना राजनीतिक लाभ नहीं मिलता दिखा, जितना पहले के सर्जिकल या एयर स्ट्राइक के बाद मिला था। उसी सर्वे में यह बताया गया कि अब लोग हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से इतर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से अधिक जुड़ते दिखने लगे हैं। ऐसे में सरकार के इन कदमों को इस बदलते ट्रेंड से भी जोड़ा जा सकता है। जानकारों के अनुसार सरकार के सामने यही चुनौती और चिंता है। पिछले 11 साल से अधिक के शासन में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की यह खासियत रही है कि जब भी कोर्स करेक्शन की जरूरत दिखती है, वह कर लेती है। दूसरी ओर विपक्ष को शुरू से लग रहा था कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे उसके लिए कठिन हैं। पूर्व में तमाम मौकों पर वह इन सवालों पर पिटता भी दिखा है। लेकिन अब विपक्षी दलों को भी लगता है कि जब ये दोनों मुद्दे समय के साथ कमजोर पड़ते दिख रहे हैं तब 'असल मुद्दों' पर सरकार को राजनीतिक रूप से घेरने का यह सही मौका है।

विशुद्ध राजनीति

कसौटी

दरअसल 2014 से BJP के चुनावी गणित में 20 फीसदी लाभार्थी वर्ग और 20 फीसदी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कोर वोटर बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसमें पार्टी काफी हद तक सफल भी रही। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मिश्रण से बने भावनात्मक मुद्दे और इसके बीच गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के मेल ने चुनावी मैदान में BJP को अजेय सा बना दिया। लेकिन पिछले कुछ सालों में विपक्ष ने BJP की इस घेराबंदी को भेदने का नुस्खा तलाशा। विपक्षी दलों ने हिंदुत्व या राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों से पूरी तरह किनारा किया और महंगाई-बेरोजगारी और इससे जुड़े वादों तक अपनी राजनीति सीमित कर ली। नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग की और खासकर वंचित लोगों तक संदेश दिया कि भावनात्मक मुद्दों से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इधर सरकार के सबसे कोर सपोर्टर मिडिल क्लास वोटर में भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मसलों पर ठहराव और थकान का ट्रेंड साफ दिखने लगा। इससे सरकार और BJP को लगने लगा है कि अगर उनके इस बीस फीसदी वोटर बेस में कहीं असर होता है तो आगे की राह इनके लिए कठिन हो सकती है। इसीलिए अभी से BJP डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है।

गरीब तबकों की बेचैनी पर नजर

BJP को पता है कि यह उतना आसान नहीं होगा। हालांकि उसे लगता है कि इनकम टैक्स में कटौती और GST रिफॉर्म जैसे कदम से उसके इस कोर वोटर को बड़ी राहत मिली और फिलहाल उसकी नाराजगी दूर हो गई है। लिहाजा पार्टी के अंदर माना जा रहा है कि यह आजमाया फार्म्युला काम आता रहेगा। वहीं विपक्ष को लग रहा है कि अब खासकर गरीब और लोअर मिडिल क्लास में दिख रही बेचैनी का लाभ उसे मिलेगा। इसलिए विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक संदेश को उसी के इर्द-गिर्द रख रही हैं। चाहे संविधान बचाओ कैंपेन हो या वोट चोरी का अभियान, विपक्ष इसे कमजोर लोगों के हित-अधिकार से ही जोड़ रहा है। यानी आने वाले समय में हम राजनीति की पिच को बदलते हुए देख सकते हैं।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

भारत की रणनीति

8 सितंबर का संपादकीय 'मिट रहीं दूरियां' पढ़ा। भारत पर 50% का टैरिफ लगने के बाद भारत अड़ा रहा और अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की आलोचना होने लगी, जिससे उनके तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। उनका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान पीएम, शानदार दोस्त बताना और दोनों देशों के विस्तृत, रणनीतिक संबंधों का महत्व बताना वास्तव में आगे बढ़ने का रास्ता खोल गया। पीएम मोदी ने भी देर किए बगैर उनके बयान पर अपना पॉजिटिव रुख दर्शा दिया। अब भारत की तरफ से नियुक्त राजनीतिक लॉबीस्ट भी ट्रंप प्रशासन में सक्रिय हो गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि भविष्य में टैरिफ कुछ कम भी हो जाए। भारत ने धैर्य और स्वायत्तता से अमेरिका को समझा दिया है। उम्मीद है कि यह बात डॉनल्ड ट्रंप और अमेरिका आगे भी याद रखेंगे।

लीलाम्बर पंत, केशवपुरम

सभी जिम्मेदारी समझें

सोशल मीडया और ऑनलाइन गेम्स से फैल रही बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार के आईटी सेल को और मजबूत करने की जरूरत है। इनसे बैंकिंग फ्रॉड भी हो रहे हैं और कई लोग अपनी जमा पूंजी भी गंवा चुके हैं। वैसे तो बैंक और सरकार की ओर से जन जागरूकता के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन समाज और परिवार के स्तर पर भी सावधानी दिखानी होगी। सोशल मीडिया (इंटरनेट) की अनर्गल साइट्स को भी हटाने के लिए कानून बनना चाहिए।सरकार को इस पर सख्त होने की जरूरत है ताकि समाज में फैलती बुराइयों पर अंकुश लग सके।

शकुंतला महेश नेनावा, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

अमेरिका ने कहा, रूस से तेल खरीद पर और टैरिफ – एक खबर – लगता है अमेरिका के पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, टैरिफ!

कपिल यादव

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

आत्मशांति और वैश्विक सद्भाव का संदेश है क्षमावाणी

भागचंद जैन

क्षमावाणी केवल जैन धर्म तक सीमित नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्षमावाणी पर्व या क्षमा दिवस मना सकता है। इसका मूल संदेश है- बैर-भाव, क्रोध और मतभेद छोड़कर आपसी समझ और सद्भावना से जीवन जीना। यही भाव यदि वैश्विक स्तर पर अपनाया जाए तो सीमा विवाद, संघर्ष और युद्ध भी समाप्त हो सकते हैं। रूस-यूक्रेन, चीन-ताइवान, इस्राइल-फिलिस्तीन और भारत-पाकिस्तान जैसे देशों के बीच भी युद्धविराम संभव हो सकता है। हाल के आर्थिक 'टैरिफ वॉर' जैसे विवाद भी इसी मार्ग से हल हो सकते हैं। सचमुच क्षमावाणी पर्व हमें संघर्षों को सुलझाने का अनोखा पाठ पढ़ाता है।

हर धर्म का अंतिम लक्ष्य है आत्मकल्याण, मानव कल्याण और जीवमात्र का कल्याण। यह तभी संभव है जब हम धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करें। लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारे विचार, काम, आय और जीवनशैली अलग-अलग हैं। इन्हीं भिन्नताओं से मतभेद और मनभेद जन्म लेते हैं, जो क्रोध और अशांति का कारण बनते हैं। जीवन का यह स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इनसे पार पाने के लिए हमारे पास क्षमा का अद्भुत साधन है। क्षमा मांगना और क्षमा करना, दोनों ही अत्यंत प्रभावशाली हैं। जो गलती करता है, उसके पास क्षमा मांगने का अवसर रहता है। जान-बूझकर की गई गलती अहंकार से जुड़ी होती है और क्षम्य नहीं होती, परंतु अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगना आत्मा को हल्का करता है और संबंधों में सुधार लाता है।

जैन धर्म में दशलक्षण पर्व का विशेष महत्व है। ये दस लक्षण आत्मा के स्वाभाविक गुण माने गए हैं। पर्व की शुरुआत उत्तम क्षमा से होती है और समापन होता है अश्विन कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को सामूहिक क्षमा याचना के साथ। जैन परंपरा में प्रतिक्रमण के माध्यम से प्रतिदिन क्षमा मांगी और दी जाती है। अपनी भूलों का प्रायश्चित करना और उन्हें दोहराने का संकल्प न लेना आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। क्षमा करना वीरों का आभूषण है। कायर प्रतिकार करते हैं, लेकिन क्षमा करना साहस और महानता का प्रतीक है। जब हम क्षमा मांगते हैं, तो वास्तव में अपने ही ऊपर उपकार करते हैं, आत्मा का बोझ हल्का होता है और दूसरे के मन में भी सकारात्मक भाव जगते हैं।

प्राकृत भाषा की सूक्ति कहती है - मित्ती मा सव्वे भुयेसु, वैर मज्झंण ण केणवि - यानी सभी जीवों में मैत्रीभाव रहे, कोई किसी से बैर न रखे। भगवान महावीर ने कहा - कोधा पिये यपणा सई, यानी क्रोध प्रेम को नष्ट कर देता है और इसे जीतने का एकमात्र उपाय क्षमा है। क्षमा वाणी पर्व हमें यह सिखाता है कि गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें स्वीकार कर क्षमा मांगना और क्षमा करना ही सच्चा साहस है। यही आत्मशांति, सामाजिक समरसता और विश्व शांति की कुंजी है।

आर.एन.आई. नं. 510/57 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन: 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय: दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क: 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य: सोमवार से शनिवार: नेपाली 5 रु.; रविवार: नेपाली 6 रु. संपादक (दिल्ली मार्केट): आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

रैंकिंग संबंधी नुकसान

एनआईआरएफ को उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और समानता दोनों को बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए

मैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) पर आधारित इंडिया रैंकिंग (आईआर) 2025 में कुछ आश्चर्यजनक बातें सामने आईं। पिछले वर्षों की तरह, शैक्षणिक उत्कृष्टता के इतिहास वाले पुराने सार्वजनिक संस्थान शीर्ष स्थानों पर छाए रहे।

2016 में इसकी स्थापना के बाद से, भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, 3,565 से 14,163 तक, और इसका दायरा चार श्रेणियों से बढ़कर 17 हो गया है, जो उच्च शिक्षा के व्यापक क्षेत्रों को कवर करता है। हालाँकि, रैंकिंग पैरामीटर अभी भी सही नहीं हैं। संस्थानों का मूल्यांकन पाँच प्रमुख मापदंडों के आधार पर किया जाता है: शिक्षण, सीखना और संसाधन (30%), शोध और पेशेवर अभ्यास (30%), स्नातक परिणाम (20%), आउटरीच और समावेशिता या ओआई (10%), और सहकर्मी धारणा (10%)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहकर्मी धारणा पैरामीटर के बारे में अपने संदेह में सही हैं क्योंकि यह विषय के विशेषज्ञों और नियोक्ताओं से एकत्रित फीडबैक है। यह व्यक्तिपरक हो सकता है और प्रभाव और पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकता है, क्योंकि यह किसी संस्थान की प्रतिष्ठा पर उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा से अधिक निर्भर करता है चूँकि यह कुल भार का 10% है, इसलिए यह रैंकिंग को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसकी समीक्षा आवश्यक है।

किसी भी वैश्विक रैंकिंग की तरह, एनआईआरएफ के अपने स्वयं के एडब्ल्यू हैं। हालांकि यह सत्यापित मेट्रिक्स और शोध के तीसरे पक्ष के ऑडिट पर निर्भर होने का दावा करता है, यह संस्थानों से ग्रंथसूची डेटा और स्व-घोषित इनपुट पर बहुत अधिक निर्भर करता है। चिंता का विषय ओआई पैरामीटर का उपचार है। आईआर पर एनआईआरएफ पुस्तिका केवल क्षेत्रीय और लैंगिक विविधता से संबंधित परिणामों पर केंद्रित है। यह स्पष्ट रूप से उन छात्रों के डेटा को छोड़ देता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित हैं और विकलांग हैं, इन कारकों में से प्रत्येक का ओआई घटक के भीतर 20% भारांक है। तथ्य यह है कि ओआई को पर्याप्त रूप से प्राथमिकता नहीं दी गई है: केवल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, 70 से अधिक ओआई स्कोर वाले शीर्ष 10 संस्थानों में शामिल हैं। यह परेशान करने वाला है क्योंकि हाशिए के समुदायों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रतिबंधित है केंद्रीय संस्थान ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणियों के लिए रिक्तियों को भरने में लगातार पीछे रह रहे हैं। एक समतावादी राष्ट्र के रूप में भारत की प्रगति के लिए इस तरह की सक्रिय कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को केवल एक वार्षिक, औपचारिक आयोजन से कहीं अधिक होना चाहिए। इसकी अंतर्दृष्टि का उपयोग भारत के क्षेत्रीय असंतुलन; शीर्ष 100 संस्थानों के बाहर डॉक्टरेट योग्यता वाले संकाय की कमी; 58% से अधिक प्रबंधन संस्थानों द्वारा शून्य शोध प्रकाशनों की रिपोर्ट, और उभरते संस्थानों को मार्गदर्शन देने के लिए विरासत संस्थानों की आवश्यकता जैसे गहरे मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जाना चाहिए। सबसे बढ़कर, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाठ्यक्रम सुधार के बिना, एनआईआरएफ केवल एक रैंकिंग मंच बनकर रह जाने का जोखिम उठाता है जो निजी संस्थानों को खुद को ब्रांड के रूप में विकसित करने की अनुमति देता है, जिससे उच्च शिक्षा में समग्र गुणवत्ता और समानता में सुधार करने में कोई खास मदद नहीं मिलती।

हॉकी की महिमा

एशिया में भारत को हराना मुश्किल है, लेकिन असली चुनौतियां कहीं और हैं

हरमनप्रीत सिंह ने एशिया कप जीता पुनः प्रकाशित राजगीर राष्ट्र आकाश के नीचे, यह भारत का महाद्वीपीय प्रभुत्व का पुनः दावा था-

हॉकी में वित्त। भारत अब तीनों महाद्वीपीय खिताब - एशियाई खेल, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) और एशिया कप - पर कब्जा कर चुका है और यह हासिल करने वाली पहली पुरुष टीम बन गई है। यह भारत का चौथा एशिया कप खिताब था, जो कोरिया से दूर था, जिसे उन्होंने फाइनल में बड़े अंतर से हराया था। रविवार की जीत ने भारत को अगले साल होने वाले विश्व कप में भी जगह पक्की कर ली है, जिसकी मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारत ने टूर्नामेंट में प्रगति की है, उससे यूरोप में उसके हालिया प्रदर्शनों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जगी है। शुरुआत बहुत प्रभावशाली नहीं रही और भारतीयों ने बिहार की तपती गर्मी में संकीर्ण जीत हासिल की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह टूर्नामेंट एक शोस्टॉपर था। लेकिन जैसे-जैसे वे परिस्थितियों के अभ्यस्त हुए और अपनी लय पाई, भारतीय बेहतर होते गए।

विश्व की सातवें नंबर की टीम और शीर्ष 10 में एकमात्र एशियाई टीम होने के नाते उनसे खिताब जीतने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन खेल में सफलता का निर्धारण खेल के मैदान पर होता है, एक्सेल शीट पर रैंकिंग पर नहीं।

यही वजह है कि 22वीं रैंकिंग और चौथे स्थान पर रहने के बावजूद, चीन को एक गंभीर चुनौती और लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों का दावेदार माना जा रहा है। या फिर कोरिया ने, हाल के दिनों में कोई खास नतीजे न मिलने के बावजूद, भारत के साथ तालमेल बिठाया, उसे पूरी तरह से परखा और परखा। यूरोप में एशिया कप से ठीक पहले, जहाँ भारत अपने आठ एफआईएच प्रो लीग मैचों में से सात हार गया था, और ऑस्ट्रेलिया के औसत दौरे का मतलब था कि खिलाड़ी राजगीर में तैयारी के लिए तो बहुत उत्साहित थे, लेकिन नतीजे कम। इस खिताब के साथ अब भारत को भारतीय हॉकी के सबसे व्यस्त लेकिन अहम दौर में से एक की योजना बनाने और तैयारी करने के लिए पूरा एक साल मिल गया है।

अगले साल होने वाले विश्व कप और एशियाई खेलों के बीच एक महीने से भी कम का अंतर है। कोच क्रेग फुल्टन चुनौतियों से वाकिफ हैं। इस जीत से वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे; बल्कि, उन्होंने टीम का आकलन सोच-समझकर किया था, और लगातार इस बात पर ज़ोर देते रहे कि बड़ी चुनौती यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ होगी। 28 महीनों से कोच के रूप में काम कर रहे फुल्टन ने एक प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है - दो एसीटी, एशियाड, एक ओलंपिक कांस्य और अब एशिया कप।

आगे की राह कठिन होगी लेकिन टीम ने अपना जादू बरकरार रखा है।

नए भारत में 'घरेलू क्षेत्र'

बृंदा करात

सीपीआई(एम) के एक वरिष्ठ नेता हैं

में वर्तमान शासन व्यवस्था में, जब भारत के लोगों के सामने अनगिनत सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियाँ हैं, तो प्रतिरोध के एजेंडे में अक्सर "घरेलू क्षेत्र" के विकास को पीछे धकेल दिया जाता है। इससे सत्ता में बैठे लोगों को "नारी शक्ति" की अवधारणा का अपहरण करने और "महिला-नेतृत्व वाले विकास" का दावा करने का मौका मिल जाता है, जबकि वे "घरेलू क्षेत्र" में महिलाओं के प्रति पूरी तरह से प्रतिगामी दृष्टिकोण को बरकरार रखते हैं।

इसका ताज़ा उदाहरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख का अगस्त 2025 में दिया गया एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि "सभ्यता के अस्तित्व" को सुनिश्चित करने के लिए, परिवारों को कम से कम तीन बच्चे पैदा करने होंगे—मानो महिलाएँ प्रजनन मशीन हों जिनके पास बहुत कम या कोई विकल्प ही न हो। मोहन भागवत के लिए परिवारों और ख़ास तौर पर घर के भीतर महिलाओं के अस्तित्व के बारे में बोलना ज़्यादा उचित होता।

एक अकथनीय चुप्पी 2017 से 2022 तक हर साल
औसतन 7,000 महिलाओं की मौत भयावह मामलों में हुई है, जहां उन्हें जला दिया जाता है - कानूनी तौर पर इसे दहेज हत्या के रूप में जाना जाता है।

तो, 35,000 महिलाएं मर चुकी हैं - यह सिर्फ उनका सिंदूर नहीं मिटाया गया है; एक महिला का जीवन समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 ने नोट किया कि सर्वेक्षण में शामिल 30% महिलाओं ने अपने अंतरंग साथी द्वारा हिंसा की सूचना दी, लेकिन केवल 14% ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों के 4.45 लाख से अधिक मामलों में से एक तिहाई घरेलू हिंसा के हैं। लेकिन क्या आपने आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक भी नेता, पुरुष या महिला, को घर के भीतर हिंसा के खिलाफ एक शब्द भी बोलते सुना है? ये वे लोग हैं जो सहमति से बने अंतर-सामुदायिक संबंधों के खिलाफ मुखर और स्पष्ट रूप से बोलते हैं - जिसे वे लव जिहाद कहते हैं - लेकिन घर या समुदाय के भीतर हिंसा के किसी भी उदाहरण के बारे में कभी एक शब्द नहीं कहते क्योंकि यह मनुस्मृति पर आधारित बहुसंख्यकवादी विचारधारा के साथ नहीं होगा

उन दिनों से बहुत कम बदलाव आया है जब सत्ता में बैठे लोगों के मनुवादी पूर्वज बीआर अंबेडकर पर "हिंदू विचारधारा के विध्वंस" के लिए, हिंदू सुधार विधेयकों में महिलाओं को तलाक का अधिकार देने और वैध विवाह के लिए जाति प्रथा को समाप्त करने के उनके प्रस्तावों के लिए हमला करते थे। वे संस्कृतियाँ जो महिलाओं पर हिंसक विवाहों में बने रहने, विवाह की पवित्र प्रकृति के कारण "समायोजन" करने का दबाव डालती हैं, जो अपनी चुप्पी के माध्यम से, स्व-इच्छा से किए गए अंतर्जातीय विवाहों में तथाकथित सम्मान अपराधों को अनदेखा करती हैं, आज हिंदुत्व पारिस्थितिकी तंत्र के वैचारिक मंच का अभिन्न अंग हैं। हम इसे "दुरुपयोग" के नाम पर घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनों को कमजोर करने के प्रयासों में और वैवाहिक बलात्कार को "विवाह संस्था" और "भारतीय संस्कृति" के खिलाफ बताते हुए अपराध घोषित करने की मांग का विरोध करने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामले में सामाजिक तर्क में भी देख सकते हैं।

सरकार की नीतियों का 'घरेलू क्षेत्र' पर प्रभाव पड़ता है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि भारत में महिलाओं को घोर भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

"घरेलू क्षेत्र" का एक और पहलू -
घर के भीतर और बाहर महिलाएं जो काम करती हैं - उसे हाल ही में टाइम यूज सर्वे (टीयूएस) 2024 द्वारा उजागर किया गया है। विभिन्न गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत की गणना सर्वेक्षण किए गए सभी लोगों की औसत आयु का उपयोग करके की गई है।

सर्वेक्षण में शामिल सभी महिलाओं के आयु वर्ग (15-59 वर्ष) को लें तो, 25% महिलाएं "रोज़गार और संबंधित गतिविधियों" में लगी थीं और औसतन पाँच घंटे काम करती थीं। पारिवारिक उद्यमों में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 23% था; इस श्रेणी की महिलाएं दो घंटे से थोड़ा कम काम करती हैं। इन दोनों श्रेणियों में किए गए काम को आर्थिक रूप से उत्पादक माना जाता है और इसे राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (SNA) में शामिल किया जाता है। पुरुषों के लिए संबंधित आँकड़े बताते हैं कि पहली श्रेणी में औसतन 75% पुरुष प्रतिदिन औसतन आठ घंटे काम करते हैं। पारिवारिक उद्यमों में, 14% पुरुष प्रतिदिन औसतन दो घंटे काम करते हैं। अधिकांश पुरुषों के लिए कार्य दिवस का यही अंतिम समय होता है।

महिलाएँ और काम का बोझ टीयूएस ने काम से जुड़ी दो अन्य श्रेणियों
को सूचीबद्ध किया है - अवैतनिक घरेलू सेवाएँ (खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े धोना) और अवैतनिक देखभाल सेवाएँ। यहाँ, 93% महिलाएँ पहली श्रेणी में प्रतिदिन औसतन सात घंटे और 41% महिलाएँ अवैतनिक घरेलू देखभाल में ढाई घंटे काम करती हैं। पुरुषों के लिए इसी प्रकार का आंकड़ा यह है कि 70% पुरुष कोई घरेलू काम नहीं करते हैं।

घरेलू काम करने वाले 30% पुरुष दिन में डेढ़ घंटे से भी कम समय लगाते हैं। अवैतनिक देखभाल श्रेणी में, 79% पुरुष कोई "अवैतनिक देखभाल" नहीं करते हैं, जबकि 21% पुरुष जो करते हैं, वे औसतन एक घंटा 14 मिनट प्रतिदिन काम करते हैं। अगर सभी पुरुषों का औसत निकाला जाए, तो यह आँकड़ा मिलता है: "घरेलू क्षेत्र" में पुरुष दिन में 26 मिनट घरेलू काम करते हैं और 16 मिनट से भी कम अवैतनिक देखभाल करते हैं।

टीयूएस में अन्य श्रेणियां भी हैं लेकिन उन्हें लेना
कुल मिलाकर, निष्कर्ष यह है कि महिलाओं द्वारा लगाए गए कुल कार्य घंटे पुरुषों की तुलना में अधिक हैं, और महिलाएं पुरुषों की तुलना में खाने, सोने और आराम में कम समय बिताती हैं। ये मूल बातें हैं। आगे के विश्लेषण से विभिन्न आय समूहों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति के पुरुषों और महिलाओं के बीच कार्य विभाजन का पता चलेगा। इस तरह के अध्ययन से समय के उपयोग में वर्ग और जाति के अंतर का पता चलेगा, जहाँ श्रमिक वर्ग की महिलाओं को पुरुषों की तुलना में असमान रूप से अधिक काम का बोझ उठाना पड़ता है।

पुरुष.

सर्वेक्षण के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने में नरेंद्र मोदी सरकार के घोर पाखंड को देखना होगा। पूरी रिपोर्ट प्रकाशित होने के महीनों पहले, सामाजिक सरकारी एजेंसी, प्रेस सूचना ब्यूरो ने 25 फ़रवरी, 2025 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति (सर्वेक्षण के सारांश के साथ) में शीर्षक दिया: "भारतीय परिवारों में लिंग भेद के बिना देखभाल संबंधी गतिविधियों को अधिक मान्यता"। इसके अलावा, समय के उपयोग में असमानताओं को इस पंक्ति से महिमामंडित करने की कोशिश की गई,

"...यह भारतीय सामाजिक ताने-बाने की पुष्टि करता है, जिसमें घर के सदस्यों की देखभाल की अधिकांश ज़िम्मेदारियाँ घर की महिलाओं द्वारा वहन की जाती हैं।" जहाँ तक भाजपा सरकार के सामाजिक दृष्टिकोण का सवाल है, यह कि पुरुष देखभाल के लिए थोड़ा भी समय देते हैं, भले ही यह औसतन केवल 15 मिनट के लिए ही क्यों न हो, "भारतीय परिवार" की महानता को दर्शाता है, और यह कि महिलाएँ घरेलू और देखभाल के काम में पुरुषों की तुलना में तीन गुना अधिक काम करती हैं, यह गर्व की बात है - अर्थात, भारतीय सामाजिक ताने-बाने पर।

सार्वजनिक नीति के प्रति इसी दृष्टिकोण के विस्तार में, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन सेवाओं और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के रूप में बाल देखभाल सेवाओं की ज़िम्मेदारी संभालने वाली लाखों महिलाओं को "सामाजिक स्वयंसेवक" माना जाता है, न कि कार्यकर्ता। उन्हें न्यूनतम वेतन के बजाय मानदेय के रूप में एक मामूली राशि दी जाती है। अंततः, उन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। इस प्रकार, घरेलू क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो "स्वाभाविक" कार्य माना जाता है, वह सार्वजनिक क्षेत्र में देखभाल सेवाओं में कम वेतन वाले काम में तब्दील हो जाता है।

घोर अवमूल्यन। ऐसा दृष्टिकोण पूँजीपतियों के लिए
भी उपयुक्त है। भारतीय स्टेट बैंक ने 2023 में एक सर्वेक्षण में दिखाया कि यदि महिलाओं द्वारा किए गए अवैतनिक कार्य का मुद्रीकरण किया जाए, तो यह देश के सकल घरेलू उत्पाद के 7% से अधिक या ₹22.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष के बराबर होगा। यह श्रम के सामाजिक पुनरुत्पादन में महिलाओं के अवैतनिक घरेलू कार्य द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका के अवमूल्यन की ओर भी इशारा करता है। न्यूनतम मजदूरी तय करते समय उनके काम पर विचार नहीं किया जाता।

आमतौर पर, इस तरह की मजदूरी से श्रमिक और उसके परिवार की बुनियादी जीवन-निर्वाह संबंधी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तथा वह अगले दिन भी काम करने के लिए स्वस्थ रहता है।

यह "निर्वाह" स्तर वास्तव में महिला के बेहिसाब और अदृश्य घरेलू और देखभाल संबंधी कामों से पूरा होता है। महिला के घरेलू काम का यह अदृश्य घटक ही निर्वाह और मजदूरी की लागत को कम रखता है।

इस प्रकार, उचित न्यूनतम मजदूरी के लिए संघर्ष का सीधा संबंध महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अदृश्य कार्य की मान्यता से है।

सरकार की नीतियों का "घरेलू क्षेत्र" पर सीधा असर पड़ता है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। विकल्प इस प्रकार हैं: पहला, परिवारों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और खत्म करने के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और नीतिगत हस्तक्षेप; दूसरा, समान वेतन पर प्राथमिक श्रमिकों के रूप में पुरुषों और महिलाओं को समान काम करने का अधिकार; तीसरा, राज्य द्वारा बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के लिए आसानी से सुलभ सार्वभौमिक सुविधाओं का प्रावधान; चौथा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान; पाँचवाँ, दक्षिणपंथी ताकतों के "सामाजिक ताने-बाने" के तर्क के विपरीत, पुरुषों और महिलाओं के बीच घरेलू ज़िम्मेदारी साझा करने को प्रोत्साहित करने वाली संस्कृतियों को बढ़ावा देना, और अंत में, बाल देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं में सभी योजना कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों के समान न्यूनतम वेतन और लाभ के साथ न्याय प्रदान करना।

ईरान और भारत, प्राचीन सभ्यताएँ और नए क्षितिज

Iraj Elahi

भारत में इस्लामी गणराज्य ईरान के राजदूत हैं

टी दुनिया एक गहरे बदलाव के दौर से गुज़र रही है। कई लोग इसे "संक्रमण का समय" कहते हैं, जबकि अन्य इसे "पश्चिमी नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संकट" कहते हैं।

यह स्पष्ट है कि वैश्विक प्रणाली, जिस पर लंबे समय से पश्चिमी शक्तियों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व रहा है, अब गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।

हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन देखते हैं,
बल का अनियंत्रित प्रयोग, व्यापार युद्ध, वैश्विक संस्थाओं की अवहेलना, मीडिया से छेड़छाड़ और पर्यावरण का अपरिवर्तनीय विनाश। ये कोई छिटपुट घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि एक गहरे संकट के संकेत हैं। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम अब अपनी इच्छाशक्ति को नियंत्रित करने की पहले जैसी क्षमता नहीं रखता। प्रभुत्व के उसके पारंपरिक हथियार—वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एकाधिकार, तथाकथित मानवाधिकार मानकों का थोपना और वैश्विक मीडिया पर नियंत्रण—अपनी प्रभावशीलता खो रहे हैं।

वैश्विक दक्षिण एक नए रास्ते पर है। राष्ट्र जागृत हो रहे हैं। देश, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देश, प्रभुत्व और भेदभाव के अधीन रहने से इनकार करते हैं। स्थानीय मॉडलों पर भरोसा करके, स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करके, और अपनी रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करके, उन्होंने एक नया रास्ता शुरू किया है।

इस ऐतिहासिक परिवर्तन में, प्राचीन सभ्यताओं की एक अनूठी भूमिका है। दुनिया की दो सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं, ईरान और भारत, ने सदियों से वैश्विक संस्कृति को आकार दिया है। दोनों सभ्यताएँ शांति को महत्व देती थीं और युद्ध से बचती थीं, केवल आक्रमण के विरुद्ध रक्षा के लिए लड़ती थीं। सैन्य रूप से पराजित होने पर भी, उनका सांस्कृतिक प्रभाव इतना गहरा था कि उन्होंने विजेताओं को नया रूप दिया, उन्हें शासन-कला, साहित्य, दर्शन, कला और वास्तुकला का अपना ज्ञान प्रदान किया।

इस्लाम के आगमन के बाद, ईरान के सभ्यतागत मूल्य एक नए रूप में जारी रहे, जबकि भारत — जिसे सबसे प्राचीन सतत सभ्यता माना जाता है — इस्लामी प्रभाव से और समृद्ध हुआ। साझा प्राचीन मूल्य सदियों से कायम रहे हैं: जीवन को एक उपहार के रूप में देखना, बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय में विश्वास, विविधता के प्रति सम्मान,

अपनी सभ्यतागत बुद्धिमत्ता, रणनीतिक स्वतंत्रता और रचनात्मक साझेदारी के साथ, तेहरान और नई दिल्ली बदलती दुनिया को एक नई व्यवस्था दे सकती है

आंतरिक शुद्धि की खोज, और आध्यात्मिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता।

आधुनिक इतिहास भी यही लचीलापन दर्शाता है।
भारत ने अपने उपनिवेश-विरोधी संघर्ष और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के अधिकारों की रक्षा की। ईरान ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करके और इस्लामी क्रांति के माध्यम से पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध किया।

दोनों राष्ट्र एक साथ मिलकर उन मूल्यों को अपनाते हैं जिनकी आज तत्काल आवश्यकता है: शांति, आध्यात्मिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान - ऐसे मूल्य जो संरचनात्मक हिंसा, पर्यावरणीय संकटों और सामाजिक पतन का सामना करने में मानवता का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

बेशक, इस आज़ादी की एक कीमत चुकानी पड़ी है। दशकों से, ईरान ने आर्थिक आतंकवाद, संज्ञानात्मक युद्ध और लगातार बाहरी हस्तक्षेप सहा है, फिर भी, उसने कभी हार नहीं मानी।

भारत को भी अनुचित दबावों और शत्रुतापूर्ण उपायों का सामना करना पड़ा है। लेकिन किसी भी देश ने प्रभुत्वशाली शक्तियों की महत्वाकांक्षाओं के आगे अपनी पहचान या स्वतंत्रता का बलिदान नहीं दिया है।

अब समय आ गया है प्राचीन सभ्यताओं जैसे
ईरान और भारत वैश्विक दक्षिण के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मज़बूत करके, ब्रिक्स जैसे ढाँचों में सक्रिय भूमिका निभाकर, मानवीय और नैतिक सिद्धांतों को कायम रखकर, और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) जैसी परिवर्तनकारी परियोजनाओं को आगे बढ़ाकर, भारत और ईरान मिलकर एक न्यायसंगत और मानवीय व्यवस्था की नींव रख सकते हैं।

फ़िलिस्तीन मुद्दा इस व्यवस्था के केंद्र में
फ़िलिस्तीन के लिए संघर्ष है - जो वैश्विक दक्षिण की सबसे बड़ी चिंता है। पश्चिम का पाखंड, वर्चस्ववाद और क्रूरता कहीं और इतनी स्पष्ट नहीं है। फ़िलिस्तीनी लोग, जो कब्जे और विस्तारवाद के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, वास्तव में वैश्विक दक्षिण के सभी देशों के वर्चस्व का विरोध करने के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह, ईरान द्वारा शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अपने अधिकार की रक्षा, दक्षिण के विकास के अधिकार की रक्षा भी है। साथ ही, ईरान उन लोगों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीति और संवाद का गढ़ बन जाता है जो इसे बनाए रखने का दावा करते हैं।

मानवाधिकारों और लोकतंत्र का हनन करते हुए भी वे लगातार कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं।

ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय संगठन
पश्चिम के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने की अपार संभावनाएँ हैं। ऐसे समय में जब आर्थिक प्रतिबंधों और व्यापार युद्धों का इस्तेमाल विकास में बाधा डालने और डॉलरीकरण को रोकने के लिए किया जा रहा है, ब्रिक्स एक स्वतंत्र, सहभागी और लोकतांत्रिक भविष्य का वादा करता है। इसी तरह, आईएनएसटीसी कॉरिडोर एक आर्थिक मार्ग से कहीं बढ़कर है। यह एक सभ्यतागत सेतु है, जो यूरेशिया, काकेशस, भारत और अफ्रीका को जोड़ता है और पश्चिम एशिया में स्थिरता लाता है।

पश्चिम एशिया में अमेरिका और उसके सहयोगियों
ने ज़ायोनी शासन का समर्थन करके तथा फिलिस्तीन, लेबनान, इराक, सीरिया, यमन और ईरान में अस्थिरता को बढ़ावा देकर स्वदेशी क्षेत्रीय सुरक्षा के उदय को रोकने की लगातार कोशिश की है।

क्षेत्र की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में ईरान ने इस तरह के हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध किया है और पश्चिम एशिया क्षेत्र के संप्रभु देशों की क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालने के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है।

दक्षिण एशिया में भी, अमेरिका ने आतंकवादी समूहों को बनाने और उनके विस्तार में अहम भूमिका निभाई है। जब भी उसके हित सधने लगे, उसने आतंकवाद से लड़ने के बहाने हस्तक्षेप किया है। और जब भी उसका एजेंडा पूरा हुआ, उसने उन्हीं आतंकवादी समूहों को सत्ता वापस सौंप दी है।

आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं।
दुनिया बदल रही है। उभरती हुई शक्तियाँ और प्राचीन सभ्यताएँ अपनी भूमिकाएँ पुनः निर्धारित कर रही हैं।
ईरान और भारत सभ्यतागत बुद्धिमत्ता, रणनीतिक स्वतंत्रता और रचनात्मक साझेदारी के माध्यम से विश्व को एक नया मॉडल प्रदान कर सकते हैं: एक ऐसी व्यवस्था जो न्याय, साझा हितों और मानव सम्मान के प्रति सम्मान पर आधारित हो।

यह व्यवस्था प्रभुत्व पर नहीं, बल्कि भागीदारी पर आधारित है; श्रेष्ठता पर नहीं, बल्कि समानता पर आधारित है।
यह एक ऐसा भविष्य है जहाँ राष्ट्र शक्तिशाली लोगों के हथियार नहीं, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होंगे। और ऐसे भविष्य की ओर मानवता का नेतृत्व करने के लिए ईरान और भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं से बेहतर और कौन हो सकता है?

द टटर्सटूदएडिटर

कर सुधार जीएसटी
2.0 एक दूरदर्शी कदम है जो करों को सरल बनाकर और स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा जैसी प्रमुख अनिवार्यताओं को छूट देकर भारत को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह के सुधारों का अनुसरण करता है।

और यूनाइटेड किंगडम, जिससे युवा कल्याण और उपभोग को बढ़ावा मिला।
भारत की 60% से अधिक जीडीपी निजी व्यय से संचालित होती है, इसलिए जीएसटी 2.0 से युवा परिवारों को सीधे लाभ होगा।
यह सुधार न केवल भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करता है, बल्कि इसके लिए मंच भी तैयार करता है नवाचार-संचालित, समावेशी विकास।

शमंत पाइडीकोंडाला, हैदराबाद

अगले उपराष्ट्रपति
जैसे-जैसे भारत बढ़ते संस्थागत तनाव से जूझ रहा है, वैसे-वैसे भारत के उपराष्ट्रपति, विशेष रूप से राज्यसभा के सभापति के रूप में, यह पद प्रक्रियात्मक दक्षता से कहीं अधिक की मांग करता है। इसके लिए संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में, न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी पर गहन विचार किया जाना चाहिए। आशा है राजनीतिक स्वार्थ की बजाय सिद्धांत आधारित नेतृत्व की वापसी होगी।

सैयद रफ़ी,
हैदराबाद

At Rajgir
भारतीय हॉकी टीम के राजगीर में एशिया कप जीतना बहुत खुशी की बात थी हॉकी प्रेमियों का उत्साहवर्धन और मैदान पर मौजूद प्रशंसकों की तालियों की गड़गड़ाहट। उम्मीद है कि टीम आगे भी इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी और उसे संरक्षण मिलता रहेगा।

डॉ. वी. पुरुषोत्तमन, चेन्नई

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

अनमोल वचन

आदमी नकली पैसे बनाता है; पर कई मामलों में, पैसा नकली आदमियों को बनाता है

-सिडनी जे. हैरिस

सकारात्मक एकीकरण

सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने फिर सेना के एकीकरण की पैरवी की है। एक किताब के विमोचन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने थलसेना, वायुसेना व नौसेना की क्षमताओं के एकीकरण की बात करते हुए स्वीकारा कि इसमें कितना समय लगेगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। द्विवेदी ने कहा यदि कई एजेंसियों के साथ तालमेल बैठाना होगा तो एकीकरण ही समाधान है। देखना होगा इसमें कितना समय लगेगा। उन्होंने स्वीकारा इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे; जिसमें एकजुटता व तालमेल शामिल है। सेना प्रमुख का यह बयान वायुसेना प्रमुख के थियेटर कमांड्स बनाने की जल्दबाजी के खिलाफ दी गई चेतावनी के बाद आया है। सेनाधिकारियों द्वारा इस पर मतभेदों की बात विभिन्न मौकों पर स्वीकारी गई है। शायद इसीलिए सेना प्रमुख

ने खुली व स्पष्ट चर्चा के उपरांत राष्ट्रहित में अंतिम फैसला करने की बात स्वीकारी। बेशक यह एकीकरण आसान नहीं है। इसके लिए कई कड़े चरणों से गुजरना होगा। जिसमें संयुक्तीकरण, एकीकरण व विभिन्न अन्य मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी आवश्यक है। बेशक कोई भी जंग अकेले एक अंग नहीं लड़ सकती। देश की सीमाओं पर बीएसएफ व आईटीबीपी व इंडो-तिब्तन बॉर्डर पुलिस फोर्स मुस्तैद ही नहीं रहती। अब तो रक्षा साइबर एजेंसी, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी व कॉग्निटिव को भी शामिल करने की बात हो रही। इसरो, नागरिक सुरक्षा, नागरिक उड्डयन, रेलवे, राज्य व केंद्र की विभिन्न एजेंसियों के दरम्यान एकीकरण पर चर्चा हो रही है ताकि कार्यान्वयन में बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। लंबे समय से नौसेना पूर्वी व पश्चिमी समुद्री सीमाओं की देख-रेख करने की जिम्मेदारी दिए जाने की भी बात हो रही है। वायु सेना का भी इस बंटवारे में अहम हिस्सा होगा इसलिए अब तक कोई अहम समझौता नहीं हो सका है। जिन तीन थिएटर कमांड्स की चर्चा हो रही है, चीन पर केंद्रित नॉर्दर्न थिएटर कमान व पाकिस्तान पर केंद्रित वेस्टर्न थिएटर के अलावा नौसेना के लिए मैरिटाइम थिएटर कमांड पर रणनीति बन रही है। विभिन्न सुरक्षा बलों, आर्मी, वायु व नेवी के दरम्यान बेहरीन तालमेल के साथ कुशलतापूर्वक क्षमताओं का इस्तेमाल का मार्ग प्रश्रस्त किया जा सकेगा। जैसा कि द्विवेदी ने कहा, यह एकीकरण अमेरिका/चीन की तर्ज पर न होकर देश की जरूरतों व सुरक्षा के आधार पर होगा। चुनौतियों का सामना करने के साथ ही सैन्यबलों पर होने वाले खर्च को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा।

एशिया में बादशाहत

भारतीय हॉकी टीम का रंगत में खेलने के साथ त्रुटिहीन प्रदर्शन करना आम नहीं है। पर राजगीर (बिहार) में एशिया कप हॉकी के फाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ भारत ने कुछ ऐसा ही प्रदर्शन किया। उन्होंने सहज अंदाज में जीत पाकर एशिया में अपनी धाक ही नहीं जमाई बल्कि अगले साल अगस्त माह में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। पिछले कुछ समय में भारतीय टीम से टूटती उम्मीदों ने फिर से भरोसा बना दिया है। असल में एफआईएच प्रो लीग के पिछले सत्र में खराब प्रदर्शन से लगने लगा था कि पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जिताने वाले कोच क्रेग फुल्टोन टीम को अब प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। इस लीग में भारत ने नौ टीमों के बीच आठवां स्थान प्राप्त किया था और इसमें आखिरी स्थान पर रहने वाली टीम बाहर हो जाती है और उसका स्थान नीचे से ऊपर आने वाली टीम लेती है। इस खराब

प्रदर्शन के बाद भारत ने एशिया कप में जीत से तो अभियान शुरू किया पर चीन और जापान के खिलाफ जीतें इतनी संघर्षपूर्ण थीं कि टीम लोगों के मन में भरोसा नहीं भर सकी। इसके बाद सुपर फोर में दक्षिण कोरिया से ड्रा खेलने से टीम को और भद्द पिटती दिखी, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सुपर फोर में चीन पर शानदार जीत के बाद फाइनल में पांच बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया को जिस तरह से फतह किया, उससे टीम का डंका फिर से बजने लगा। यही नहीं फुल्टोन के 2028 के ओलंपिक तक बने रहने की संभावनाएं भी बनने लगी हैं। ऐसा यदि हो जाता है तो वह पिछले दो दशकों में सबसे लंबे समय तक कोच रहने वाले बन जाएंगे। टीम यदि इसी तरह खेलती रही तो एफआईएच प्रो लीग में वह पहले दो सत्रों की तरह अच्छा प्रदर्शन करने के साथ अगले ओलंपिक में पदक का रंग बदलने में भी कामयाब हो सकती है। पर इससे पहले तो विश्व कप में भारत पहली तीन टीमों में शुमार हो जाता है, तो टीम के साथ कोच का भी डंका बज जाना है। भारत के कदम आगे की तरफ बढ़ने में खिलाड़ियों और कोच की तो अहम भूमिका है ही, साथ ही हॉकी इंडिया की भी तारीफ करनी होगी, जिसने कोच पर भरोसा करके टीम को अपने हिसाब से ढालने का मौका दिया है। पहले एक खराब प्रदर्शन होते ही कोच को बलि का बकरा बना दिया जाता था। पर हॉकी इंडिया के इस व्यवहार का असर साफ तौर पर टीम पर दिख रहा है।

आपदा प्रबंधन/मुनीष भाटिया

तैयारी में पिछड़ गए हम

भारत ऐसा देश है जहां प्रकृति ने विविधता का अद्भुत उपहार दिया है, लेकिन इसी विविधता के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं की विभीषिका भी हमें बार-बार झकझोरती है। कभी बादल फटते हैं, तो कभी बाढ़ गांवों को निगल जाती हैं। कहीं धरती कांपती है, तो कहीं पहाड़ दरक जाते हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने हमें मौसम की भविष्यवाणी करने, वर्षा की तीव्रता और समय का अनुमान लगाने की क्षमता दी है, फिर भी हमारी तैयारी हर बार अधूरी साबित होती है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है।

आपदा प्रबंधन की विडंबना यह है कि हम हमेशा आपदा के आने के बाद ही सक्रिय होते हैं। राहत शिविरों की तैयारी, सड़क और पुलों की मजबूती, नालों की सफाई और आवश्यक दवाओं का भंडारण-ये सब बातें कागजों पर तो खूब दिखाई देती हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां अक्सर तब तक इंतजार करती हैं जब तक संकट सिर पर न आ जाए। कई बार तो तंत्र की लापरवाही और उदासीनता आपदा से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। आपदा प्रबंधन केवल राहत और बचाव तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे हमारी विकास नीतियों और जीवनशैली का हिस्सा बनाना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, यदि हम शहरी नियोजन को आपदा-रोधी दृष्टिकोण से करें, तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। भूकंप-रोधी निर्माण मानकों का पालन सख्ती से कराया जाए, नालों और नदियों की नियमित सफाई सुनिश्चित हो, अवैध निर्माण पर रोक लगे और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए-तो हमारी तैयारियां कहीं अधिक मजबूत हो सकती हैं। आम नागरिकों को यह समझना होगा कि आपदा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। स्कूलों और कॉलेजों में आपदा प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, मॉक ड्रिल कराई जाए और लोगों को यह बताया जाए कि संकट की घड़ी में किस तरह खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। यदि नागरिक स्तर पर तैयारी मजबूत होगी, तो प्रशासन का बोझ भी कम होगा और जान-माल का नुकसान भी घटेगा।

राहत देने की कवायद

जीएसटी दरों में कमी

प्रो. लल्लन प्रसाद

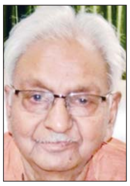

अगस्त 15 2025 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिवाली पर उपहार देने का वादा किया था, जो उनकी सरकार ने उसके पहले ही नवरात्र से जीएसटी की दरों में सुधार करके देने की घोषणा कर दी है। पहले जीएसटी की चार मुख्य दरें थीः 5 फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद। उनकी जगह अब केवल दो दरेंः 5 फीसद और 18 फीसद होंगी। अति विलासिता और हानिकारक उपभोग की वस्तुओं पर पहले भी भारी टैक्स था (जिसे 'पाप कर' की संज्ञा दी गई है) अब भी रहेगा 40 फीसद।

बहुत सी वस्तुएं जो पहले 12 फीसद के दायरे में थी अब 5 फीसद के दायरे में आ गई हैं। 18 फीसद की भी कुछ वस्तुएं 5 फीसद के दायरे में लादी गई है। 28 फीसद की अधिकांश वस्तुएं 18 फीसद के दायरे में रख दी गई है। रोटी, खाखरा दूध, दही, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, जीवन रक्षक 33 दवाएं, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी, स्टेशनरी के बहुत से आइटम्स पूरी तरह कर मुक्त होंगे। खाद्य पदार्थों, घी, पनीर, मक्खन, भुजिया, किराना के सामान, साबुन, तेल, शैंपू, शेविंग क्रीम टूथपेस्ट, स्टेशनरी, रोजमर्रा के कपड़े, बर्तन, सिलाई मशीन और पुर्जों आदि को पहले से कम टैक्स के दायरे में ला दिया गया है। खेती में उपयोग होने वाले आम उपकरण, मशीनें, डीजल, फर्टिलाइजर आदि पर करो में कमी की गई है। डायग्नोस्टिक किट्स, कम कीमत की कारों, मोटरसाइकिलों, तिपहिया और माल ढोने वाले वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लगने वाले टैक्स में भी कमी की गई है।

जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। इसके लिए संसद ने 2016 में संविधान में 101 वां संशोधन करके एक नया अनुच्छेद 279 ए जोड़ा था। आजादी के बाद से भारत में अप्रत्यक्ष करों के एकीकरण का यह सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार माना जाता है, जिसमें बिक्री कर, वैट, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे अनेक करो को एक ही यूनिफाइड टैक्स सिस्टम में ला दिया गया। जीएसटी की शुरुआत 1954 में फ्रांस से हुई थी, इस समय दुनिया के 140 देशों में जीएसटी लागू है। वित्त वर्ष 2025 में देश को जीएसटी से कुल 22.08 लाख करोड़ रुपये की उगाही हुई। अगस्त 2025 में 1.8 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ जो जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का आठवां सबसे बड़ा कलेक्शन था। करदाताओं की सहूलियत के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल कर दी गई है, ऑनलाइन सबमिशन की व्यवस्था कर दी गई है। प्रक्रिया की दुरुहता के कारण व्यापारियों में असंतोष था जो संभवत अब कम हो जाएगा, कर विभाग में भ्रष्टाचार पर

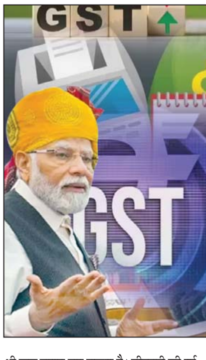

भी कुछ लगाम लग सकता है। जीएसटी की नई दरों से किसानों को राहत मिलेगी, पूंजीगत और उत्पादन खर्चों में कुछ कमी होगी। ट्रैक्टर के पिछले टायर ट्यूब्स और कल पुर्जे, ट्रैक्टरों के लिए 250 सीसी से अधिक सिलेंडर वाले कृषि डीजल इंजन, हाइड्रोलिक पंप, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया सहित प्रमुख उर्वरकों पर पहले 18 फीसद टैक्स था जो अब 5 फीसद के दायरे में ला दिए गए हैं।

ट्रैक्टर (1800 सीसी क्षमता को छोडकर), बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर, हैंड पम्प, मिट्टी तैयार करने, जोताई, बुवाई, कटाई और बागवानी के आम उपकरणों और मशीनों पर पहले 12 फीसद टैक्स लगता था अब मात्र 5 फीसद देय होगा। किसानों की आमदनी में वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाएगी। जीएसटी के दरों में कमी का प्रभाव कम समय और लंबे समय दोनों में होगा। खाने की थाली सस्ती होगी, किचन के खर्चे कम होंगे, होटल और रेस्टोरेंट के बिलों में भी कमी होगी। उपभोक्ताओं को कितना लाभ होगा यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उत्पादक करदाता करों में कमी का पूरा फायदा उपभोक्ताओं को कीमतों में कमी करके देते हैं या नहीं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों में करों में कमी बड़े पैमाने पर आम जनता को लाभ पहुंचाएगी। रोटी, खाखरा, दूध, दही, पनीर जीवन रक्षक दवाएं, आम इस्तेमाल के स्टेशनरी आदि को कर मुक्त करने और डेयरी पदार्थो-मक्खन, घी, पनीर, चीनी, पैक्ड नमकीन, भुजिया, तेल, साबुन, शैंपू, शेविंग क्रीम आदि पर करों की कमी स्वागत योग्य है। समाज के सभी वर्गो को कुछ ना कुछ लाभ होगाः शिशुओं के दूध की बोतल, घरवाली की साड़ी, किचन के समान, किराने की वस्तुएं, बर्तन, डिशवॉशर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नौजवानों के शेविंग क्रीम, शैंपू, टूथपेस्ट, बालों के तेल, सीनियर सिटीजन के चश्मा, बीमा, जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों मे कमी होगी।

विलासिता की वस्तु कहे जाने वाली चीजें, जो वास्तव में उच्च मध्यम वर्ग और धनी वर्ग के लिए आम उपभोग की वस्तुएं हैं-जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, महंगी कारें, मोटरसाइकिल, टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की कीमतें भी जीएसटी में कमी के कारण मांग बढ़ाएंगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, अधिक निवेश आएगा, पूंजी बाजार को बल मिलेगा, निर्यात में भी वृद्धि होगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट सब के लिए लाभप्रद होगी, माल ढुलाई और विभिन्न वाहनों के किराये कम होंगे। ये वस्तुएं अभी तक 28 फीसद कर के दायरे में थी, अब 18 फीसद के दायरे में आ जाएंगी।

कर मुक्ति और करों में रियायत का लाभ पूरी अर्थव्यवस्था को होता है, कीमतों में गिरावट होने से उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है जो उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, रोजगार के नये अवसर बनाती है, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ती है। आमदनी में वृद्धि बचत और निवेश के लिए नये द्वार खोलती है। जीएसटी की नई दरों से सरकार पर 48000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा जो उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं के मांग में वृद्धि से पूरा होगा, निवेश बढ़ेगा। भारत का उपभोक्ता बाजार विश्व के सबसे बड़े बाजारों में एक है, अर्थव्यवस्था मजबूत होने से विदेशी निवेश भी अधिक आएगा, जीडीपी बढ़ेगा। आर्थिक सुधारों की गति सरकार को बनाए रखनी है जिससे जीडीपी में और तेजी से वृद्धि हो और अर्थव्यवस्था में विकास का लाभ आम लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच सके।

(लेख में विचार निजी हैं)

कर मुक्ति और करों में रियायत का लाभ पूरी अर्थव्यवस्था को होता है, कीमतों में गिरावट होने से उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है जो उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, रोजगार के नये अवसर बनाती है, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ती है। आमदनी में वृद्धि बचत और निवेश के लिए नये द्वार खोलती है। जीएसटी की नई दरों से सरकार पर 48000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा जो उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं के मांग में वृद्धि से पूरा होगा, निवेश बढ़ेगा

दही पाचन तंत्र के लिए अत्यंत लाभकारी

- **अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, दही दूध को प्राकृतिक बैक्टीरिया की मदद से फर्मेंट करके बनाया जाता है, जिसमें लैक्टोबैसिलस जैसे प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन तंत्र के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं**
- **हालांकि, बाजार में मिलने वाली मीठी दही अक्सर ज्यादा चीनी के कारण स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए इसे सावधानी से ही लेना चाहिए। इसके अलावा, कुछ लोगों को रात में दही खाने से बलगम की समस्या हो सकती है, इसलिए इसे अपने स्वास्थ्य के अनुसार लेना चाहिए**

स्रोत : मीडिया इन्पुट्स

जीएसटी प्रतिशत घटने से पहले ही सीमेंट कंपनियों ने दाम इतना बढ़ा दिया कि कोई फर्क न पड़े! 'खेला' हो गया! आजकल के कॉरपोरेट 'ज्योतिषी' भी हो गए हैं! यानी सीमेंट के दामों में नये जीएसटी रेट से जितनी कमी होती, बड़ी सीमेंट कंपनियों ने दाम में उतनी बढ़ोत्तरी सप्ताह भर पहले ही कर ली थी!

उर्मिलेश, पत्रकार
@UrmileshJ

आधी आबादी | डॉ. नीलू तिवारी

लापरवाही पड़ सकती है भारी

हाल ही में एक 18 वर्षीय छात्रा की मौत की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया, जिसने धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीरियड्स रोकने की दवा खा ली थी। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी है कि मासिक धर्म को रोकने या बदलने वाली दवाएं कितनी घातक हो सकती हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या थोड़ी सुविधा या सामाजिक दबाव महिला की जान से अधिक महत्त्वपूर्ण है? यह विषय आज न केवल स्वास्थ्य के लिहाज से, बल्कि सामाजिक सोच और सरकारी नीतियों की दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक हो गया है।

बेंगलुरु में घटी इस दर्दनाक घटना ने समाज का ध्यान खींचा है, जहां छात्रा ने धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने मासिक धर्म को रोकने की गोलियां खाईं। लगातार तीन दिन तक दवा खाने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे पैरों में सूजन, तेज दर्द और फिर सांस लेने में तकलीफ हुई। जब तक परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने पाया कि उसकी नसों में खून का थक्का जम चुका था। गहन उपचार के बावजूद छात्रा की मौत हो गई। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर क्यों महिलाएं बिना सोचे-समझे या बिना चिकित्सकीय सलाह के ऐसी खतरनाक दवाओं का सेवन करती हैं। असल में यह केवल एक महिला के व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो इन हार्मोनल दवाओं का गलत या बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन करना बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे हार्मोनल असंतुलन, रक्त के थक्के, गर्भधारण में कठिनाई और यहां तक कि मौत जैसी स्थिति तक हो सकती है। महिलाओं के जीवन में मासिक धर्म एक प्राकृतिक और सामान्य प्रक्रिया है। यह न केवल उनके स्वास्थ्य का संकेत है, बल्कि शरीर की प्राकृतिक लय का हिस्सा भी है। सामाजिक दृष्टि से भारत जैसे देशों में अब भी धार्मिक अवसरों, शादी-ब्याह और परीक्षाओं के दौरान महिलाओं पर मासिक धर्म रोकने का दबाव डाला जाता है। यह दबाव उन्हें मजबूरी में दवा खाने पर मजबूर करता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो इन हार्मोनल दवाओं का गलत या बिना डॉक्टर की सलाह

के सेवन करना बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे कई दिक्कतें पैदा हो सकती है। चिकित्सकों के अनुसार, पीरियड्स रोकने वाली गोलियां सामान्य दर्द निवारक या सर्दी-जुकाम की दवा नहीं होतीं। इन दवाओं का अत्यधिक सेवन महिलाओं के शरीर में गंभीर बदलाव ला सकता है। इससे मोटापा बढ़ना, मुंहासे होना, चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल उगना, लगातार थकान रहना, मूड स्विंग और अवसाद जैसी मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में महिलाओं में गर्भधारण की क्षमता प्रभावित होती है और प्रजनन संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक लगातार इन दवाओं का सेवन करना दिल और लिवर से जुड़ी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। बेंगलुरु की इस घटना ने यह भी उजागर किया है कि हमारे समाज में मासिक धर्म से जुड़ी झिझक और दबाव अभी भी बहुत गहरे हैं। धार्मिक अवसरों, शादी-ब्याह या सामाजिक आयोजनों में लड़कियां और महिलाएं यह सोचकर दवा खा लेती हैं कि पीरियड्स को टालना आसान उपाय है। शुरुआत में यह उपाय आसान और प्रभावी लगता है, लेकिन लंबे समय में यह शरीर पर गंभीर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। ग्रामीण और कम शिक्षित महिलाएं अक्सर बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ले लेती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ जाता है।

कई बार उन्हें तुरंत राहत तो मिलती है, लेकिन बाद में यह निर्णय गंभीर बीमारी की जड़ बन सकता है। दूसरा सवाल यह भी है कि नकली और सस्ती दवाइयों का सेवन स्वास्थ्य को गहरी चोट पहुंचाता है, लेकिन यह आसान उपाय जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हमें यह समझना जरूरी है कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे रोकने या बदलने की कोशिश शरीर की प्राकृतिक घड़ी के साथ खिलवाड़ है। अगर किसी महिला को पीरियड्स में असामान्य दर्द, अधिक रक्तसाव या बार-बार पीरियड्स अनियमित होने जैसी समस्या है, तो उन्हें तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए बेहतर होगा कि महिलाएं अपने मासिक धर्म को प्राकृतिक रूप से स्वीकार करें और केवल आपात स्थिति में, वह भी डॉक्टर की सलाह पर ही दवा लें। जागरूकता अभियान इस समस्या के समाधान का सबसे अहम हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। वहीं सरकार और स्वास्थ्य संस्थानों को टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक या कार्यशालाओं के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। महिलाओं को इस बात को समझना ही होगा और सच को स्वीकार करना होगा।

ईश्वर है? | ओशो

शास्त्र से पढ़ लेते हैं आत्मा की बातें, सुन लेते हैं परंपराओं से परमात्मा के विचार। और उन्हें सीख लेते हैं, और इस भांति उनकी बातें करने लगते हैं जैसे हम जानते हों। जैसे हम जानते हों ऐसे उधार ज्ञान को हम

एहसास करने लगते हैं कि हमारा अपना है। यह अंतिम धोखा है जो कोई आदमी अपने को देता है। पंडित इसी भांति अपने को धोखा दे लेता है। जो उसने नहीं जाना है, जो उसने केवल सुना है और सीखा है, जो उसने पढ़ा है और स्मरण कर लिया है, उसे भी वह ज्ञान मान लेता है। हममें से कोई ईश्वर को मानता होगा, कोई आत्मा को मानता होगा, कोई मोक्ष को मानता होगा; और हममें से कोई भी नहीं जानता इन बातों की सच्चाई, लेकिन निरंतर इन बातों को दोहराते रहने से ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है जैसे कि हम जानते हैं। और जब हम दूसरों को ये बातें समझाने लगते हैं, और उनको ऐसा एहसास होता है, उनकी आंखों में हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि उनकी बातें समझ में आ रही हैं। तो उनकी आंखों में ये झलक देख कर हमको खुद यह विश्वास आ जाता है कि हम जो बातें कह रहे हैं वे जरूर सच होंगी और हमने जानी होंगी।

आज ही दोपहर में एक घटना कह रहा था।

अमेरिका में एक आदमी ने सबसे पहले बैंक डाला। बाद में कोई चालीस वर्षों बाद जब वह बूढ़ा हो गया, और उसकी कोई जयंती मनाई जा रही थी तो उसके एक मित्र ने उससे पूछा कि तुमने सबसे पहले बैंक किस तरह शुरू किया? उसने कहाः मैंने एक तख्ती बनवाई, जिस पर मैंने लिख दिया 'बैंक' और उसे घर के सामने टांग दिया और मैं एक पेटी और किताबें लेकर बैठ गया। पीछे, कोई घंटे भर बाद एक आदमी आया और उसने पचास रुपये जमा करवाए, फिर दो घंटे बाद एक आदमी आया उसने भी डेढ़ सौ रुपये जमा करवाए। उन दोनों को जमा करते देख कर मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मैंने भी अपने पचास रुपये उसमें जमा कर दिए। दो आदमियों को जमा करते देख कर मेरा भी विश्वास इतना बढ़ गया कि मैंने भी अपने पचास रुपये उसमें जमा कर दिए कि जरूर यह बैंक चल जाएगा। ऐसे बैंक शुरू हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, ईश्वर है? और अगर आप चुप रह जाएं और कहें: मुझे कुछ भी पता नहीं। तो मैं कहूंगा, आप धार्मिक आदमी हैं, आप अपने को धोखा नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें कि हां, ईश्वर है और इस रंग का है, तो मैं कहूंगा, आपने अपने को धोखा देना शुरू कर दिया।

रीडर्स मेल

भारतीय हॉकी टीम को बधाई

भारत की पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर में खेली जा रही एशिया हॉकी कप में दक्षिण कोरिया को हरा कर शानदार जीत हासिल की है। भारत की शानदार जीत पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को मैच में 4-1 से पराजित किया है। दक्षिण कोरिया पांच बार की एशिया कप विजेता टीम रही है। इसी के साथ भारत में 2026 में होने वाले विश्व हॉकी कप में पदार्पण किया है जो बड़ी उपलब्धि है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और इस खेल में सफलता अर्जित करना बेहद शानदार, रोमांचकारी और गौरवपूर्ण होता है। टूर्नामेंट में भारत के हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह 'सरपंच' की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही जिन्होंने न केवल अच्छा प्रदर्शन किया बल्कि टीम को हौसले के लिए प्रेरित करते रहे। सभी भारतीय देश की हॉकी टीम पर गर्व करते हैं और 2026 में होने वाले विश्व कप के लिए भी अग्रिम बधाई प्रेषित करते हैं।

वीरेंद्र कुमार जाटव, ई मेल से

सराहनीय कदम

सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के स्लैब में बदलाव करके आम जनता को राहत पहुंचाने का एक सराहनीय कार्य किया है। जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा नीतिगत बदलाव करते हुए 12 और 18 प्रतिशत वाले स्लैब हटा दिए है। अब सभी तरह की जरूरी चीजों पर टैक्स काफी घट जाएगा जैसे कि अब दूध और पनीर वगैरह पर जीएसटी जीरो कर दिया गया है इसके अलावा कई तरह की जिंदगी बचाने वाली जरूरी दवाओं पर से भी टैक्स हटा लिया गया है। पहले बहुत अधिक स्लैब होने और एक ही कैटेगरी की वस्तुओं पर अलग-अलग दरों से काफी उलझनें होती थी। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में घरेलू खपत को बढ़ावा देना जरूरी है। क्योंकि ऐसा करने से ही सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की जा सकती है। कुल मिलाकर इस सकारात्मक कदम का असर फेस्टिव सीजन में देखने को मिल सकता है।

हितेंद्र डेढ़ा, दिल्ली

शर्तों के साथ होगी बात

डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न इतना जल्दी होगा, इसकी संभावना नहीं थी। सोशल मीडिया पर अपने संदेश के माध्यम से भारत अमेरिका के रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने की कोशिश करते नजर आए और कहा की दोनों देशों के बीच विशेष रिश्ता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटिनक का बयान की भारत माफी मांगेगा और डील करेगा और इसके अतिरिक्त ट्रंप के और अधिकारियों ने भी ऐसे विवादस्पद बयान देकर रिश्तों को खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एक बात तो तय है कि अमेरिका को इस बात का अहसास हो गया है कि भारत को झुकाया नहीं जा सकता है और न ही दरकिनार करा जा सकता है। भारत ने अभी तक अपना स्टैंड दृढ़ रखा है और आगे भी ऐसा ही रखना चाहिए, अमेरिका के साथ डील भी हो और रिश्ता भी मधुर होना चाहिए, लेकिन हमारी शर्तों के अनुसार। ट्रंप का रवैया दूसरे कार्यकाल में अप्रत्याशित रहा है तो हमें उनके साथ बड़े सावधानी से आगे बढ़ना है।

बाल गोविंद, नोएडा

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-35, अंक 26
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय -011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

पंजाब केसरी संपादकीय

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

शहादत को नमन

जब भी मैं अपने परिवार का इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे स्वयं पर गर्व होता है। क्योंकि मैं उस परिवार का हिस्सा हूं जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया, बल्कि स्वतंत्र भारत में भी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। 9 सितम्बर 1981 के दिन मेरे परदादा अमर शहीद लाला जगत नारायण जी का बलिदान दिवस है। यद्यपि मेरे पिता श्री अश्विनी कुमार मुझे परिवार की पूरी दास्तां से अवगत कराते रहते थे। मेरे दादा जी रमेश चन्द्र जी ने भी अपने पिता लाला जी की तरह शहादत का मार्ग चुना था। इतिहास के अवलोकन के बाद जितना मैं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समझ पाया उन्हें मैं शब्दों में उतारने की कोशिश कर रहा हूं। लाला जी एक हुतात्मा थे जिन्होंने धर्म और सत्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वे वेदों और महर्षि दयानंद सरस्वती के मार्ग पर चलने वाले एक सच्चे आर्यसमाजी थे। वे अहिंसा में विश्वास करते थे और उन्होंने जीवन में कभी किसी हथियार को हाथ तक नहीं लगाया। उनका मानना था कि कलम हथियार से अधिक शक्तिशाली है। वे आलोचना के प्रति खुले थे और स्वस्थ तरीके से बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करते थे। वे सभ्य तरीके से तर्क और युक्ति का प्रयोग करते हुए समाज में व्याप्त बुराइयों की आलोचना करते थे।

> पहले आजादी की लड़ाई और देश के स्वतंत्र होने के बाद यानी पहले अंग्रेजी सत्ता और बाद में अपने ही लोगों द्वारा लाला जी को बार-बार प्रताड़ित किया गया, तकलीफें दी गईं। उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों से कभी पलायन नहीं किया। जहर पीकर भी अमृत पीने जैसी मुस्कान उनके चेहरे पर रहती थी। जीवन का अंतिम घूंट भी उन्होंने शहादत का ही पिया। जब पंजाब में सीमा पार के 'मित्रों' की काली करतूतों के कारण अलगाववाद की आग सुलगने लगी थी तो क्या इंटेलीजेंस, क्या सीबीआई, किस-किस ने नहीं कहा, "लाला जी आप स्वयं को सुरक्षित रखें, बाहर व्यर्थ न जाएं और अपनी फिक्र करें। विध्वंसक शक्तियां सत्य और असत्य की गरिमा को नहीं पहचानतीं"

पहले आजादी की लड़ाई और देश के स्वतंत्र होने के बाद यानी पहले अंग्रेजी सत्ता और बाद में अपने ही लोगों द्वारा लाला जी को बार-बार प्रताड़ित किया गया, तकलीफें दी गईं। उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों से कभी पलायन नहीं किया। जहर पीकर भी अमृत पीने जैसी मुस्कान उनके चेहरे पर रहती थी। जीवन का अंतिम घूंट भी उन्होंने शहादत का ही पिया। जब पंजाब में सीमा पार के 'मित्रों' की काली करतूतों के कारण अलगाववाद की आग सुलगने लगी थी तो क्या इंटेलीजेंस, क्या सीबीआई, किस-किस ने नहीं कहा, "लाला जी आप स्वयं को सुरक्षित रखें, बाहर व्यर्थ न जाएं और अपनी फिक्र करें। विध्वंसक शक्तियां सत्य और असत्य की गरिमा को नहीं पहचानतीं" लेकिन लाला जी ने कहा- समाज से अलग रहकर, भागकर, घर के कमरे में बंद रह कर कुछ नहीं हो सकता। अगर असत्य से लड़ना है तो समाज और राज्य में रहकर ही लड़ना होगा। अंततः राष्ट्र विरोधी ताकतों ने उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बना दिया। लाला जी ने लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में एक कोष की स्थापना कर अखबार निकालने का काम किया। अखबार का नाम रखा गया 'पंजाब केसरी'। लाला जी को अंग्रेजों के खिलाफ सम्पादकीय लिखने पर कई बार जेल जाना पड़ा, यातनाएं सहनी पड़ीं। जब भी वे जेल से बाहर आते ओजस्वी लेख लिखते तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। जेल में ही उनकी मुलाकात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से हुई थी। महात्मा गांधी के अनुयायी होने के बावजूद क्रांतिकारियों से उन्हें प्यार था और सम्पर्क भी, क्योंकि लक्ष्य केवल एक था- देश को आजाद कराना। आजादी से पूर्व भारत की आजादी के वास्ते 16 वर्ष तक जेल में काटे लेकिन आजादी के बाद भी सत्ता ने उन्हें बहुत कष्ट दिए।

एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में बार-बार उभरता रहता है कि आखिर आतंकवादियों ने ऐसे व्यक्ति की हत्या क्यों की जो अत्यंत प्रभावशाली होने के बावजूद वृद्ध था और जीवन के अंतिम दौर में था। उनकी हत्या नृशंस अपराध था। लाला जी ने आतंकवाद का खुला विरोध किया था लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाकर उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। मेरे परदादा पंजाब के मंत्री भी रहे और सांसद भी। स्पष्टवादी इतने कि उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियों का भी विरोध किया। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तो लाला जी के लिए यह लोकतंत्र की हत्या का आघात असहनीय था। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर देश में आपातकाल का विरोध किया। तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिन्होंने 16 वर्ष अंग्रेजों की जेल में काटे हों उन्हें आजाद भारत में जेल जाने की क्या परवाह। आपातकाल के बाद कांग्रेस शासन को उखाड़ फैंकने की जयप्रकाश नारायण जी की समग्र क्रांति में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। सोच रहा हूं आज की राजनीति में ऐसे लोग कहां चले गए हैं। वे सिद्धांत प्रियता और विशाल हृदय के प्रतीक थे। उनके अवसान के बाद मेरे दादा रमेश चन्द्र जी ने और उनके बाद मेरे पिता श्री अश्विनी कुमार जी ने कलम को संभाला। आज वही कलम मेरे हाथों में है। मेरी मां श्रीमती किरण चोपड़ा, मेरे अनुज आकाश और अर्जुन चोपड़ा भी मुझे सहयोग दे रहे हैं। मेरी मां वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के माध्यम से बुजुर्गों की सेवा कर लाला जी के दिखाये मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। हम सब अपने पूर्वजों के सपनों को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। निसंदेह पंजाब केसरी पर पूर्वजों का आशीर्वाद आज भी बना हुआ है। युग पुरुष लाला जी को हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें सत्य पथ पर चलने की शक्ति और ऊर्जा प्रदान करें। कलम के सिपाही को नमन।

जिए जब तक लिखे खबरनामे।
चल दिए हाथ में कलम थामे।।

प्रेमी जोड़े मौत के घाट उतार...

एक ओर सभी राधा और श्रीकृष्ण जी की जोड़ी के आगे शीश झुकाते हैं,
और विद्वान भी भूरि-भूरि सच्चे प्रेम की महिमा गाते हैं,
पर क्यों उसी समाज में 'आनर कीलिंग' के नाम पर,
प्रेमी जोड़े मौत के घाट उतार दिए जाते हैं,
वहीं वंशबेल चलाने के लिए दूसरे राज्यों से मोल की बहू ले आते हैं,
तब-तब झूठी प्रतिष्ठा और मर्यादा के दोहरे मापदंड सामने आते हैं...!!

गीता पाढा

राम और कृष्ण की कथा में है अमृत धारा

विजय दर्डा
संपादक : लोकमत समूह
पूर्व राज्यसभा सांसद

पौराणिक मान्यताओं में एक दिलचस्प संदर्भ आता है, एक दिन महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति है, जो सर्वगुण संपन्न हो और जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जा सके? नारद जी तीनों लोक में भ्रमण करते थे और दुनिया के पहले पत्रकार के रूप में जानकारियों से सदैव लैस रहते थे। उन्होंने पलक झपकते ही इक्ष्वाकु वंश के श्रीराम का नाम लिया। वही श्रीराम पिछले हजारों वर्षों से हमारे हृदय में न केवल भगवान के रूप में विराजमान हैं बल्कि हमारी प्रेरणा के प्रमुख स्रोत भी बने हुए हैं।

आप सोच रहे होंगे कि अचानक मुझे प्रभु श्रीराम के इस संदर्भ की याद क्यों आ गई और आपके साथ इसे क्यों साझा कर रहा हूं? दरअसल इस वक्त मेरे गृह नगर यवतमाल में प्रखर विद्वान कथाकार श्री मोरारी बापू राम कथा कह रहे हैं, जब मैं आयोजन की तैयारियों में व्यस्त था तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप तो जैन धर्म को मानने वाले हैं, फिर, आपके नेतृत्व में रामकथा का ये आयोजन क्यों? मैं ऐसे सवालों का कारण समझता हूं, धर्म इतने भागों में बंट चुका है कि धर्म के मूल्यों के एक होने की बात लोगों के दिमाग से उतर चुकी है। मैं बड़ी सहजता से जवाब देता हूं कि धर्म के मूल को समझिए तो ही बात समझ में आएगी कि जैन धर्म का कोई अनुयायी प्रभु श्रीराम की कथा से क्या अर्जित कर रहा है?

सबसे पहले मेरी मां वीणा देवी दर्डा और बाद में मेरी पत्नी ज्योत्सना ने धर्म के मूल तत्वों को समझते हुए मुझसे कहा था कि आराधना के मार्ग अलग हो सकते हैं लेकिन सभी धर्मों का उद्देश्य एक है, प्रभु श्रीराम और प्रभु श्रीकृष्ण का जीवन मानव जाति के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। हमें कथा करानी चाहिए, तब तक साध्वी प्रीति सुधा जी का चातुर्मास हम करा चुके थे और हमने महसूस किया था कि उनके प्रवचनों को सुनने के लिए जैनियों के साथ ही बड़ी संख्या में दूसरे धर्मों के लोग भी आए थे। जब हमने श्री रमेश भाई ओझा की श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया तब भी सभी धर्मों के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की।

अब यही बात मैं श्री मोरारी बापू की श्रीराम कथा में भी महसूस कर रहा हूं।

श्री मोरारी बापू हों, श्री रमेश भाई ओझा हों, जया किशोरी जी हों या इन जैसे अन्य संतों के प्रति समाज में एक अलग तरह की विश्वसनीय धारणा है कि ये संत समाज को बेहतर दिशा देने का काम कर रहे हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संतत्व का चोला पहन कर जादूगर की तरह चमत्कार दिखाते हैं और उसे दैवीय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कई बार राजनीति अपने फायदे के लिए इनका उपयोग भी करती है लेकिन इससे समाज का बहुत अहित होता है। चमत्कार की इस प्रवृत्ति से शायद ही कोई धर्म बचा हो।

धर्म में 'हम बेहतर' की प्रवृत्ति ने भी समाज और धर्म का बहुत अहित किया है। ऐसे आयोजन के पीछे मेरा उद्देश्य धार्मिक कतई नहीं है बल्कि उद्देश्य यह है कि समाज को संस्कारित करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए वास्तविक शक्ति उसकी संस्कृति में निहित होती है लेकिन आज क्या हो रहा है? हमारी युवा पीढ़ी को संस्कृति और संस्कारों का वह मार्ग दिखाया ही नहीं जा रहा है जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। सैकड़ों सालों की गुलामी के बावजूद यदि हमारा वजूद बचा रहा है तो उसका मुख्य तत्व हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार ही हैं। भारतीय संस्कृति इस धरती को एक परिवार मानती है और विश्व के हर जीव के कल्याण की बात करती है।

मैंने करीब-करीब सभी धर्मों को समझने की कोशिश की है, मनन और विश्लेषण किया है, इसलिए मैं धार्मिक और आध्यात्मिक समरसता की बात करता हूं। जब मैं श्री मोरारी बापू को सुनता हूं तो प्रभु श्रीराम के आदर्श आचरण मुझे प्रेरित करते हैं। आप रामचरितमानस पढ़िए तो प्रभु श्रीराम के अद्भुत व्यक्तित्व से रूबरू होंगे। विज्ञान की कसौटियों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं प्रभु श्रीराम, उनके भीतर पिता की आज्ञा का सम्मान तो है ही, जिसने वनवास दिलाया उस कैकेयी के प्रति भी अथाह आदर कितनी बड़ी बात है। सौम्य, विनम्र, मितभाषी, सत्यवादी, कुशाग्र, धैर्यवान और साथ में बेहद साहसी भी। आज समाज जाति-पांति की बेड़ियों और महिलाओं की प्रताड़ना से परेशान है लेकिन प्रभु श्रीराम ने सबरी के जूठे बेर खाकर समतामूलक समाज की रचना, महिलाओं के प्रति सम्मान और जाति-पांति के बंधनों को तोड़ने का कितना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। बगैर किसी साधन के ऐसी सेना तैयार कर ली जिसने रावण जैसे महारथी को परास्त कर दिया। युवाओं को प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता की ऐसी सीख और कहां मिलेगी?

यही बात मुझे भगवान श्रीकृष्ण में भी नजर आती है, रणक्षेत्र में जब वे अर्जुन के सारथी थे तो सामने कौरवों की विशाल सेना थी। इधर वे अकेले थे लेकिन पांडवों की विजय रच दी। प्रबंधन का यह कितना बड़ा उदाहरण है। मानव के रूप में अपनी पूरी जिंदगी में वे कठिनाइयों से जूझते रहे लेकिन श्रीकृष्ण का मुख कभी मलिन नहीं हुआ। हमारे युवा प्रभु श्रीकृष्ण से आंतरिक शक्ति को संयोजित करना सीख सकते हैं। खुद की क्षमताओं पर विश्वास करना सीख सकते हैं। श्रीमद्भागवत और रामचरितमानस में पूरी जिंदगी के सूत्र समाए हुए हैं। सच्चे संत हमें इन्हीं सूत्रों से अवगत कराते हैं। मुझे विश्वास है कि श्री मोरारी बापू के सान्निध्य में यह जो आयोजन हो रहा है वह जाति-पांति और धार्मिक विषमताओं से परे, समाज को एक सूत्र में बांधने में सफल होगा।

प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ता कहर

विनीत नारायण
www.vineetnarain.net

भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध भौगोलिक संरचना के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है लेकिन हर साल मानसून के आगमन के साथ यह देश प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ जाता है। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से हिमालयी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बादल फटने, भूस्खलन और भारी बारिश के कारण होने वाली तबाही ने न केवल जन-धन की हानि की है, बल्कि सरकारी तंत्र की नाकामी और भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है। भारत में मानसून का मौसम जून से सितंबर तक रहता है और इस दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं अब आम हैं। हाल के महीनों में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची, जिसमें कम से कम पांच लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग लापता हो गए। हिमाचल प्रदेश में भी अगस्त 2025 में भारी बारिश के कारण दर्जनों सड़कें बंद हो गईं और कई लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि सरकारी तंत्र इन आपदाओं को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने में क्यों असफल हो रहा है?

बादल फटने की घटनाएं, जिन्हें भारत मौसम विज्ञान विभाग 100 मिमी प्रति घंटे से अधिक बारिश के रूप में परिभाषित करता है, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में आम हैं। ये घटनाएं न केवल प्राकृतिक हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों जैसे अनियोजित निर्माण, जंगलों की कटाई और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप के कारण और भी घातक हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश की तीव्रता बढ़ रही है जिससे बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं अधिक बार और अधिक विनाशकारी हो रही हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में अपने बयान में कहा कि पहाड़ी राज्यों में होने वाले निर्माण और नुक्सान के लिए 'घर में बैठकर तैयार की गई फर्जी डीपीआर बनाने वाले दोषी (कल्प्रिट) हैं। ये लोग बिना ज़मीनी हकीकत जाने हुए डीपीआर बना देते हैं जिससे ऐसे हादसे होते हैं।' यह बयान न केवल सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी कितनी घातक हो सकती है। डीपीआर जो किसी भी योजना का बुनियादी ढांचा व आधार होती है, में अगर भ्रष्टाचार और लापरवाही बरती जाती है तो इसका परिणाम ऐसे हादसों व त्रासदियों के रूप में सामने आता है। इसे 'करप्शन ऑफ़ डिज़ाइन' कहा जाता है।

पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय भूगर्भीय और पर्यावरणीय कारकों को नजरअंदाज करना आम बात हो गई है। गडकरी का यह बयान इस ओर इशारा करता है कि कई परियोजनाओं के लिए डीपीआर बिना स्थानीय भूगोल और जलवायु की गहन जांच के तैयार की जाती हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में जहां भूस्खलन और बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है, सड़क निर्माण के लिए अक्सर पहाड़ों को अंधाधुंध काटा जाता है जिससे ढलान अस्थिर हो जाते हैं। यह न केवल भूस्खलन को बढ़ावा देता है, बल्कि नदियों में मलबे का प्रवाह भी बढ़ाता है जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो जाती है।

भारत में बाढ़ और जलभराव की स्थिति को नियंत्रित करने में सरकारी तंत्र की विफलता कई स्तरों पर दिखाई देती है। सबसे पहले तो हमारी आपदा प्रबंधन की तैयारी ही अपर्याप्त है। उत्तराखंड में 2013 की केदारनाथ त्रासदी, जिसमें 6,000 से अधिक लोग मारे गए थे। 2021 की चमोली आपदा, जिसमें 200 से अधिक लोग हिमस्खलन और बाढ़ की चपेट में आए। इन हादसों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार को पहले से चेतावनी और तैयारी की जरूरत है। फिर भी, हर साल न सिर्फ़ एक जैसी आपदाएं दोहराई जाती हैं बल्कि राहत और बचाव कार्यों में देरी और अव्यवस्था भी दिखाई देती है।

दूसरा, जल निकासी प्रणालियों की कमी और रखरखाव की अनदेखी भी एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरी क्षेत्रों में, जहां 2024 में 108 मिमी बारिश ने भारी जलभराव पैदा किया, नालों की सफाई और उचित जल निकासी की कमी साफ दिखाई दी। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के किनारे अनियोजित निर्माण और अतिक्रमण ने प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित किया है जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

तीसरा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में स्थानीय ज्ञान का उपयोग करके सड़क निर्माण हो तो शायद भूस्खलन में रोकथाम हो सके लेकिन वास्तव में स्थानीय लोगों की सलाह को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और परियोजनाएं केवल ठेकेदारों और अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब सरकार और समाज मिलकर एक समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। सबसे पहले, डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाना होगा। भूगर्भीय सर्वेक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और स्थानीय विशेषज्ञों की राय को शामिल करना अनिवार्य होना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्वतंत्र ऑडिट और निगरानी तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।

दूसरा, आपदा प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना होगा। इसमें न केवल राहत और बचाव की तैयारी शामिल होनी चाहिए, बल्कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, जैसे कि बादल फटने की निगरानी को भी मजबूत करना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भूस्खलन और जलभराव की संभावना वाले स्थानों की पहचान के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास को प्राथमिकता देनी होगी। जंगलों की कटाई को रोकना, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करना और अंधाधुंध निर्माण पर रोक लगाना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इको-सेंसिटिव जोन में निर्माण को सख्ती से विनियमित करना होगा।

भारत में बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की त्रासदियां केवल प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि मानवीय लापरवाही और भ्रष्टाचार का भी परिणाम हैं। नितिन गडकरी का बयान इस दिशा में एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। सरकारी तंत्र की नाकामी, चाहे वह जलभराव को नियंत्रित करने में हो या आपदा प्रबंधन में, ने आम लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है। अब समय है कि सरकार, समाज और विशेषज्ञ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो न केवल आपदाओं को रोके, बल्कि उनके प्रभाव को कम करने में भी सक्षम हो। टिकाऊ विकास, पारदर्शी प्रशासन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही इस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता है।

आज अमर शहीद लाला जी का शहीदी दिवस है

श्रीमती किरण चोपड़ा
डायरेक्टर- पंजाब केसरी दैनिक समाचार लि.
चेयरपर्सन- वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब
मुख्य संरक्षिका- चौपाल
सदस्या- राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल, एकल
संरक्षिका- भारतीय लोक विकास परिषद
f/kiranchopra01
kiranchopra@punjabkesari.com
kiranchopradesk@gmail.com

आज भी इस दिन को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी शादी को अभी 3 साल हुए थे, मैं पढ़ भी रही थी। उन्हीं 3 सालों में मैंने लाला जी यानी दादा ससुर जी से 3000 साल जितना स्नेह और आशीर्वाद पा लिया था। उनको सुबह 4 बजे मेरे हाथ की बनी चाय और शाम को मेरे हाथ के बने पकौड़े-समोसे पसंद थे। बहुत लाड़-प्यार करते थे, अपने अनुशासन और असूलों के पक्के थे। बड़े न्याय प्रिय निष्पक्ष, निडर, निर्भीक थे जो कहते थे वो खुद भी करके दिखाते थे, जब तक वे जीवित रहे 3 पीढ़ियां एक ही घर में एक ही रसोई, एक ही छत के नीचे रही। अगर घर के बड़े अच्छे और मजबूत हों तो ही संयुक्त परिवार वाले घर चलते हैं।

8 सितम्बर को शाम को मैं खुद कार चलाकर उन्हें घर वापस लाई क्योंकि उन्होंने सुबह-सुबह जाना था, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। 9 सितम्बर को सुबह मैंने अपने हाथों से उनको आलू-मटर की सब्जी और परांठे बनाकर दिये और वो पटियाला के लिए रवाना हो गए। शाम को जब मैं और अश्विनी जी किसी कार्यक्रम में जाने को तैयार हो रहे थे तो अचानक से तहलका मच गया। लाला जी को गोली मार दी...। अश्विनी जी और रोमेश जी तो फटाफट कार चलाकर रफ्तार से चले गए और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि लाला जी को किसने और क्यों गोली मार दी? क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से थी ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं था, हालांकि हमारा परिवार भी क्रांतिकारी परिवार था परंतु यह सब हमारे पैदा होने से पहले की बातें थीं, मैं इतना डर गई कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने कार चलानी भी छोड़ दी।

मैं लाला जी की इकलौती पौत्रवधू थी जिसको उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहते हैं मूल से ब्याज बहुत ज्यादा प्यारा होता है। यानी मैं लाला जी के सबसे बड़े और चहेते पौत्र अश्विनी जी की पत्नी थी। लाला जी के और भी तीन पौत्र थे जिन्हें वह प्यार करते थे परंतु अश्विनी जी के प्रति उनका लगाव व स्नेह कुछ अलग ही था। यही कारण था कि वह अश्विनी जी को अपने सारे शेयर देकर गए। वो बहुत दूरदर्शी थे। उन्हें मालूम था कि अश्विनी जी एक जन्मजात पत्रकार हैं।

लाला जी दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों की और अपने पौत्र अश्विनी, मेरी शादी मंदिर में एक रुपए से की। उनकी इसी परम्परा को कायम रखते हुए मैंने भी अपने तीनों पुत्रों की शादी आर्य समाज मंदिर में 1 रुपए से ही की। सचमुच लाला जी एक आदर्श, देशभक्त थे जिन्होंने सच्चाई पर चलते हुए देश की आजादी के लिए 16 साल जेल काटी फिर देश की एकता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लाला जी की बहुत इच्छा थी कि देश में बुजुर्गों के लिए कुछ होना चाहिए। उन्होंने अपने अंतिम समय में "जीवन की संध्या नामक" सीरीज लिखी क्योंकि वो अक्सर कहते थे जीवन की संध्या यानी बुढ़ापा बहुत ही मुश्किल है। इसमें अच्छे घरों के लोग अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार होते हैं और जो जरूरतमंद घरों के बुजुर्ग हैं उनको तो फिजीकल, (शरीर में तकलीफें शुरू हो जाती हैं) सामाजिक और आर्थिक रूप में सहायता की बहुत जरूरत है, खासकर जिनके बच्चे महंगाई के कारण उनसे मुंह मोड़ लेते हैं और उन्हें बोझ समझने लगते हैं।

इसलिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना लाला जगत नारायण जी और उनके पुत्र रमेश चंद्र जी की याद में वृद्ध केसरी रोमेश चंद्र ट्रस्ट के अंतर्गत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों में अकेलापन और अवहेलना जैसी भावनाओं को दूर करना, उन्हें आत्मविश्वास और सुरक्षा की अनुभूति दिलाना, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और जरूरतमंदों को आर्थिक या चिकित्सा सहायता प्रदान करना, यह क्लब एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां वे अपनत्व और सम्मान के साथ समय बिता सकें। बुजुर्गों के लिए सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रतियोगिताएं हास्य भाव, धार्मिक आयोजन, महामृत्युंजय पाठ आदि होते हैं।

उन्हीं की प्रेरणा से दुनिया में पहली बार एडोप्शन सिस्टम इसी क्लब द्वारा बनाया गया है जिसमें अब तक हजारों की संख्या में बुजुर्ग एडोप्ट किये जा चुके हैं। एडोप्ट किए गए बुजुर्ग को घर लेकर नहीं जाना होता है, बल्कि एडोप्ट किए गए सदस्य की दवाई और मूलभूत जरूरतों का खर्च वहन करना होता है ताकि वो अपने बच्चों और पौत्र-पौत्रियों के साथ रह कर अपने ही घर में सुकून के पल बिता सकें। वृद्ध आश्रम छत-रोटी तो दे सकते हैं अपनापन नहीं, सम्मान और मानसिक सुरक्षा भी नहीं मिल पाती है। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में उनकी जरूरत का सामान उनके मन पसंद खाने खिलाये जाते हैं। इस क्लब की शाखाएं पूरे देश में फैली हैं जिसका लाभ लाखों में वरिष्ठ नागरिक उठा रहे हैं। इसकी एक झलक अगर आप पाना चाहें तो 9 सितम्बर को आमंत्रित हैं। बड़ा सुकून मिलता है जब हम इनकी अंगुली पकड़ते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया। यह कदमों की धूल नहीं माथे की शान हैं। यही सच्ची सेवा और श्रद्धांजलि है। आज उनके शहीदी दिवस पर मेरे तीनों बेटे-बहुएं, पौत्र और सारे पंजाब केसरी के कर्मचारी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए बहुत याद करेंगे क्योंकि जब पिता का साया सिर से उठ जाता है तो बच्चे अपने दादा-परदादा के प्यार के सहारे को ढूंढते हैं।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस : 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग : 011-30712224
विज्ञापन विभाग : 011-30712229
सम्पादकीय विभाग : 011-30712292-93
मैगजीन विभाग : 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

कूटनीति जैज संगीत की तरह है, जिसमें एक ही थीम पर अंतहीन विविधताएं समाहित होती हैं। -रिचर्ड होलब्रूक

नेपाल में सोशल मीडिया पर लगाए गए हालिया प्रतिबंधों और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पड़ोसी मुल्क में लोकतंत्र की सेहत और क्षेत्रीय स्थिरता की दृष्टि से भी चिंताजनक है। पड़ोसी देशों में अस्थिरता के हालिया अनुभवों के बरक्स भारत को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।

असंतोष की चिंगारी

नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए हालिया प्रतिबंधों और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हजारों युवाओं के संसद पर धावा बोलते वक्त हुई हिंसा, देश के इतिहास में इस तरह का पहला मामला तो है ही, पड़ोसी मुल्क में लोकतंत्र की सेहत के साथ क्षेत्रीय स्थिरता की दृष्टि से भी चिंताजनक है। नेपाल की करीब तीन करोड़ की आबादी में तकरीबन 90 फीसदी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। नहीं भूलना चाहिए कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन या संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जनता की आवाज, सूचना के प्रवाह और राजनीतिक विमर्श का भी अहम मंच बन चुका है। ऐसे में, इस पर प्रतिबंधों को युवा अनावश्यक दखलंदाजी की तरह तो देखते ही हैं, इससे यह संदेश भी जाता है कि सरकार नहीं चाहती कि उसकी नीतियों के खिलाफ किसी भी तरह के विमर्श को हवा मिले। आंकड़े इसकी पुष्टि भी करते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2024 के अनुसार, वहां 20 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सरकार हो या समाज, भ्रष्टाचार ने सभी स्तरों पर घुसपैठ कर ली है। कुल मिलाकर, 2008 में राजशाही की बर्खास्तगी के बाद नेपाल के लोगों ने जो स्वप्न देखा था, उसके पूरा न होने से लोगों में नाराजगी है, जो युवाओं के आंदोलन के रूप में प्रतिबिंबित हो रही है।

चूंकि दक्षिण एशिया का भूगोल और राजनीति एक-दूसरे से गहरे से जुड़े हैं, लिहाजा इस घटनाक्रम पर भारत की भी नजर होगी। भारत के संदर्भ में यह स्थिति अधिक चिंताजनक इसलिए भी है, क्योंकि उसके तकरीबन सभी पड़ोसी मुल्कों में किसी न किसी स्तर पर संकट बना ही हुआ है। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद हो, बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल, म्यांमार का गृहयुद्ध हो या फिर राजनीतिक व आर्थिक अस्थिरता से उबरता श्रीलंका, ये सभी भारत की कूटनीतिक चिंताओं के विषय लगातार बने हुए हैं। नेपाल की स्थिति, जहां मुख्य लड़ाई राजशाही समर्थकों व विरोधियों के बीच है, हालांकि एक वर्ष पूर्व के बांग्लादेश से अलग है, फिर भी भारत

को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि, नेपाल जैसे संवेदनशील राजनीतिक इतिहास वाले देश में, जहां राजशाही के खात्मे के बाद से अब तक करीब 17 वर्षों में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, असंतोष की चिंगारी कब आग में बदल जाए और अवांछित शक्तियों को अस्थिर स्थितियों का फायदा उठाने का मौका मिल जाए, कहा नहीं जा सकता। हालांकि, इसके कसूरवार वहां के राजनीतिक दल ही हैं, जिनकी अवसरवादिता और वैचारिक भटकाव का खामियाजा नेपाल की जनता अब तक भुगत रही है। समय रहते नेपाल को समझना होगा कि जनता की आवाज को दबाने की कोशिश अंततः शासन को ही अस्थिर करती है।

क्या गोर इन पहलुओं पर गौर करेंगे

ट्रंप ने भारत के राष्ट्रीय गौरव और संकल्प को कम करके आंका है। भारत उनकी धौंस के आगे नहीं झुकेगा और उन शर्तों पर सहमत नहीं होगा, जो उसके राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हैं। नव मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर को भारत और भारतीय नेताओं की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि मायने नहीं रखती, बल्कि लेन-देन संबंधी व्यापार मायने रखता है, वह भी अमेरिकी हित में। शायद उन्हें यह देखकर अच्छा लगता है कि अमेरिका के दुश्मन और दोस्त, दोनों ही उनकी उच्च टैरिफ की धमकियों के बाद अमेरिकी हित में समझौते करने के लिए होड़ लगा रहे हैं। उनका दावा है कि उच्च टैरिफ से अमेरिकी खजाने में अरबों डॉलर आ रहे हैं। जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज भारत के साथ भी यही हुआ है। रूसी तेल आयात करने के कारण अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले भारतीय माल पर कुल 50 फीसदी का शुल्क लगाया गया है। इस मनमाने और गैर-दोस्ताना निर्णय ने उस रणनीतिक साझेदारी को नुकसान पहुंचाया है, जिसे पिछले 25 वर्षों से विभिन्न दलों की अमेरिकी और भारतीय सरकारों ने इतनी लगन से पोषित किया है।

सुरेंद्र कुमार
पूर्व राजदूत

फरीद जकारिया सहित कई विश्लेषकों का मानना है कि यह ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल मानी जाएगी। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के अनुसार, भारत पर टैरिफ लगाना कोई रणनीतिक समझदारी नहीं है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल पूछते हैं: इस बेतुकी बात को कैसे उचित समझा जा सकता है? इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए थी। फरवरी, 2025 की शुरुआत में ओवल ऑफिस में भारतीय प्रधानमंत्री के बगल में बैठे, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को व्यापार करने के लिए बहुत ही मुश्किल जगह बताया था। इससे पहले उन्होंने भारत को 'टैरिफ किंग' कहा था। द्विपक्षीय व्यापार समझौता उनके पहले कार्यकाल में साकार नहीं हो सका, क्योंकि मोदी कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और लघु उद्यम क्षेत्रों को खोलने पर सहमत नहीं हुए, जिन पर लाखों भारतीय निर्भर हैं। इन क्षेत्रों को अमेरिकी उत्पादों से भरने की अनुमति देने के भारी राजनीतिक परिणाम होंगे।

फिर भी, उनके दूसरे कार्यकाल में हुई पांच दौर की वार्ताओं में, दोनों देशों के व्यापार प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर काफी प्रगति की थी और राष्ट्रपति

के हस्ताक्षर के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य व्यापार समझौते का मसौदा तैयार किया था। पर पुतिन के साथ अलास्का शिखर सम्मेलन से पहले ट्रंप ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया और रूसी तेल आयात जारी रखने पर 25 फीसदी अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाने की घोषणा कर दी, जिससे यह ब्राजील के बराबर 50 फीसदी टैरिफ का शिकार हो गया! उपराष्ट्रपति वेंस ने एक टीवी शो में दावा किया कि यह रूस को सजा देने के लिए था!

व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार नवारो द्वारा भारत को रूसी तेल का धंधा करने वाला देश बताने से भारत भड़क गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने याद दिलाया कि चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक है और कई यूरोपीय देश अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी गैस खरीदते रहे। अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम, उर्वरक और कुछ अन्य उत्पाद खरीद रहा है। शायद, वर्तमान विवाद व्यापार असंतुलन को लेकर नहीं है; चीन के पास छह गुना बड़ा व्यापार अधिशेष है, लेकिन उसे ऐसी आलोचना का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास दुर्लभ पृथ्वी धातुएं और औद्योगिक चुंबक है। तो क्या भारत ने अनजाने में राष्ट्रपति ट्रंप के अहंकार को ठेस पहुंचा दी है, जो खुद को महान शांतिदूत और नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार मानते हैं? उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम करवाया है।

जाहिर है, ट्रंप ने भारत के राष्ट्रीय गौरव और संकल्प को कम करके आंका है। भारत उनकी धौंस के आगे नहीं झुकेगा और उन शर्तों पर सहमत नहीं होगा, जो उसके राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी था। यह एक प्रेरणादायक और एकजुट करने वाली सैन्य सफलता थी, जिसने सावधानीपूर्वक चुने गए आतंकवादी ठिकानों, पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों और पूरे पंजाब को तबाह कर दिया। कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ खड़े थे। ट्रंप का युद्धविराम कराने का दावा मोदी सरकार को रास नहीं आया। इसे भारतीय सशस्त्र बलों का अपमान माना गया, उनके शानदार अभियानों का श्रेय किसी और ने हड़प लिया!

पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी वहां अपने केंद्र और प्रशिक्षण शिविर चलाते रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का यह कहना कि उन्हें पाकिस्तान से प्यार है, जले पर नमक छिड़कने जैसा था। पाकिस्तान में, सत्ता पर सेना का नियंत्रण है और वही फैसले लेती है। भारत को आतंकवाद का निर्यात उनकी राजकीय नीति का अभिन्न अंग रहा है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख और आईएसआई महानिदेशक को आमंत्रित करना भारत के प्रति बेहद असंवेदनशील रवैया था। पिछले 25 वर्षों में भारत-अमेरिका संबंधों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, सबसे बड़ा निवेशक और उन्नत तकनीकों का सबसे बड़ा स्रोत है। वे वैश्विक रणनीतिक साझेदार और प्रमुख रक्षा साझेदार हैं और हिंद-प्रशांत, क्वाड, आई2यू2, आईएमईईसी और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रंप की लापरवाही के कारण ऐसे बहुआयामी और महत्वपूर्ण संबंध खतरे में हैं।

विदेश मंत्री ने भारत की तीन सीमाएं स्पष्ट कर दी हैं-किसानों और छोटे उद्यमों के हितों से कोई समझौता नहीं; रूसी तेल आयात पर रोक नहीं और भारत-पाक संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं। नई दिल्ली में नव मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर के सामने कठिन चुनौती है। उनके लिए सलाह है कि वे भारत की इन सीमा रेखाओं को अपने दिमाग में रखें। भारत-अमेरिका व्यापार परिषद के प्रमुख अतुल केशप की यह सलाह कि द्विपक्षीय मुद्दों पर निजी तौर पर चर्चा की जानी चाहिए, भी उनके लिए लाभदायक होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें भारत, भारतीय नेताओं और भारतीय लोगों के प्रति सम्मान दिखाना होगा तथा उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी तथा दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में अपनी भूमिका में भारत और पाकिस्तान को एकसाथ रखने से बचना होगा। यदि उन्हें भारत के बारे में तथा भारत के मौजूदा कद के बारे में समुचित जानकारी दी जाए और वह राष्ट्रपति ट्रंप के विश्वास और भरोसे के साथ संबंधों को सुधारने, उन्हें और विस्तारित करने और गहरा करने के उद्देश्य के साथ आएं, तो वह ट्रंप कार्यकाल के एक और केनेथ गैलब्रैथ हो सकते हैं। हालांकि, ट्रंप के हालिया बयान में भारत के प्रति सकारात्मकता दिखी है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

एल. रॉन हबर्ड

जब कभी कोई मनुष्य अपने जीवन में महसूस करता हो कि सब कुछ उलझ गया है और इसे सहन नहीं किया जा सकता, जब उसका दिमाग चकराने लगे, तो उससे कहें कि वह पीछे हटकर अपनी समस्या को ध्यान से देखे।

अपनी नजर से दुनिया को देखें

वही देखें, जो आपको दिखाई देता है, न कि जो कोई आपको देखने के लिए कहता है। आपका अवलोकन वही है, जो आपने स्वयं किया है। जीवन को साफ नजर से देखें, न कि पक्षपातपूर्ण रंगीन चश्मे, भय के पर्दों में, या किसी दूसरे के द्वारा निकाले गए अर्थों के आधार पर। दूसरों के साथ वाद-विवाद करने के बजाय उनसे कहें कि वे ध्यान से देखें। यदि किसी को ध्यान से देखने के लिए हल्का-सा अनुरोध किया जाता है, तो झूठ के बड़े-बड़े गुब्बारे फुस्स हो सकते हैं, बड़े-बड़े आडंबरों का राजफाश हो सकता है, अत्यंत जटिल गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है, और अद्भुत विचार सूझ सकते हैं।

जब कभी कोई मनुष्य अपने जीवन में महसूस करता हो कि सब कुछ उलझ गया है और इसे सहन नहीं किया जा सकता, जब उसका दिमाग चकराने लगे, तो उससे कहें कि वह पीछे हटकर अपनी समस्या को ध्यान से देखे। देखने के बाद जो कुछ उसे पता लगता है, वह साधारणतया बहुत स्पष्ट होता है। वह अब आगे बढ़कर इससे निपट सकता है, लेकिन यदि वह स्वयं अवलोकन नहीं करता, तो हो सकता है उसके लिए इसमें कोई वास्तविकता न हो और दुनिया भर के आदेश-निर्देश उसकी उलझी गुत्थी नहीं सुलझा सकते। हालांकि, कोई दूसरा व्यक्ति उसे संकेत कर सकता है कि किस दिशा में देखा जाए और सुझाव दे सकता है कि वह जरूर देखे, लेकिन इस बारे में निष्कर्ष निकालना उसके अपने हाथ में है। कोई व्यक्ति वही देखता है, जो उसे स्वयं दिखाई देता है और उसके लिए वही वास्तविकता होती है। सच्ची कार्यकुशलता का आधार मनुष्य की अपनी अवलोकन करने की योग्यता होती है। इस तथ्य की वास्तविकता को मानकर ही मनुष्य दक्ष और निश्चयवान हो सकता है।

जीवन के हर पहलू को ध्यान से देखने का अभ्यास करें। शिक्षा का फल तभी मिलता है, जब इसे प्रयोग में लाया जाता है। मनुष्य को वास्तव में तब तक पता नहीं चलता कि वह बुद्धिमान है, जब तक कि वह उसका प्रयोग करके परिणाम देख नहीं लेता। किसी भी गतिविधि, हुनर या व्यवसाय या ज्ञान को अंत में इसी कसौटी पर परखा जाता है कि वह जमीनी स्तर पर काम कर सकता है या नहीं।

मनुष्य की निपुणता और दक्षता को उस युग की रफ्तार के स्तर पर लाया जाए, जिसमें वह रहता है। और यह अभ्यास से ही किया जा सकता है। अपने आसपास ध्यान से देखें, अध्ययन करें और कार्यक्षेत्र में स्वयं खोज करें, इसके बाद ही कार्य शुरू करें। और जब सब चीजें पटरी पर आ जाएं, तो तब तक अभ्यास करें, जब तक कि अपने कार्य में निपुण न हो जाएं। निपुणता, दक्षता तथा तेजी से काम करने में बड़ा आनंद मिलता है। केवल ध्यान और अभ्यास से ही इसे सुरक्षित किया जा सकता है।

हर पल सीखें

सूत्र

हम जल्दबाजी में रहते हैं और अपने जीवन को ध्यान से देख नहीं पाते। इसी का परिणाम है कि हम अक्सर तनाव में होते हैं, इससे न तो वर्तमान में होते हैं, न ही भविष्य में। आप अपने जीवन में चाहे जितनी ज्यादा किताबें पढ़ लें, लेकिन बगैर ध्यान और अभ्यास के जीवन सुंदर नहीं होगा। अपने आसपास देखें और सीखते रहें।

दूसरा पहलू

दुनिया की सबसे पुरानी नाट्य शैलियों में से एक 'नोह' को बचाने के लिए जापान के सादो द्वीप वासी अब भी प्रयासरत हैं।

जापान का सादो द्वीप और सबसे पुरानी नाट्य शैली

शिनोबू कामियामा पेशेवर अभिनेत्री नहीं हैं। वह दो बच्चों की मां हैं और दिन में एक केंद्र में बुजुर्गों की देखभाल करती हैं। लेकिन, वह जापान के उत्तर-पश्चिम स्थित सादो द्वीप के कई निवासियों में से एक हैं, जो दुनिया के सबसे पुराने और अलौकिक रंगमंच (थिएटर) के प्रति बेहद जुनूनी हैं। ग्रीष्म की एक रात्रि को कामियामा ने जापान की प्राचीन नाट्य शैली 'नोह' में भूतों से संबंधित कहानी में प्रमुख किरदार निभाया। उन्होंने जब एक छोटा अंडाकार मास्क और सुंदर किमोनो पहनकर शिंटो मंदिर के लकड़ी के पुराने मंच पर कदम रखा, तो संगतकार बांसुरी और ढोल के साथ गीत गाने लगे। वह अपनी शैलीगत नृत्य मुद्राओं में थिरक रही थीं। उन्होंने भी गीत गाया। 43 वर्षीय कामियामा कहती हैं, 'मैं नोह गीतों की सुंदरता के बीच पली-बढ़ी हूं और बचपन से ही इसे गा रही हूं।'

मार्टिन फैकलर

शिनोबू कामियामा पेशेवर अभिनेत्री नहीं हैं, लेकिन वह दुनिया के सबसे पुराने और अलौकिक रंगमंच (थिएटर) के प्रति बेहद जुनूनी हैं।

विलियम शेक्सपियर से करीब दो सदी पहले नोह के कई नाटकों को मोतोकिया जियामी ने लिखा था। विद्वान मानते हैं कि इसकी शुरुआत करीब आठवीं शताब्दी में हुई थी। लेकिन, अब नोह पर संकट है।

उस दिन कामियामा ने शाही दरबार की प्रसिद्ध महिला तमकाजुरा की भूमिका निभाई, जो अपनी सुंदरता से इतनी परेशान है कि मृत्यु के बाद आत्मा के रूप में लौट आती है। नोह नाटक अक्सर भूतों के आगमन पर केंद्रित और प्रसिद्ध पराजित योद्धाओं या दरबार के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। द्वीप के नोह एसोसिएशन के प्रमुख तोशिहीरो कोंडो कहते हैं, 'नोह भगवान को अर्पित की जाने वाली भेंट है।' 45 हजार की आबादी वाले इस द्वीप में नोह के 34 मंच हैं, जिनमें से ज्यादातर बौद्ध धर्म या देश के मूल शिंटो धर्म के मंदिरों में स्थित हैं। जापान के ज्यादातर हिस्सो में नोह का अभ्यास पेशेवर रूप से किया जाता है, लेकिन सादो में हर साल दर्जनों प्रदर्शन शौकिया तौर पर होते हैं, जैसे कामियामा ने किया। 80 वर्षीय प्रशिक्षक इचिजी कहते हैं, 'नोह यहां अब भी जीवंत संस्कृति बनी हुई है, पर यह इसका अंतिम स्थान है।'

विलियम शेक्सपियर से करीब दो सदी पहले नोह के कई नाटकों को मोतोकिया जियामी ने लिखा था। विद्वान मानते हैं कि इसकी शुरुआत करीब आठवीं शताब्दी में हुई थी। लेकिन, जापान की बुजुर्ग होती आबादी के बीच सदियों पुराने नोह पर भी संकट है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद नोह मंचों की संख्या आधी घटकर करीब 200 ही रह गई है। दो सदी पुराने नोह मंच वाले शिंटो मंदिर की 30वीं पीढ़ी के पुजारी यशियो हिनो कहते हैं कि इस कला को संरक्षित करने का मतलब है ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करना, जिन्होंने हाल के वर्षों में सादो द्वीप की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। कामियामा के प्रदर्शन को देखने के लिए स्थानीय और विदेशी पर्यटकों समेत करीब 200 दर्शक आए थे, जिनमें उनका पांच वर्षीय बेटा भी था।

©The New York Times 2025

आंकड़े

महंगे देश

यूरोपीय संघ में शामिल कुछ देश अन्य देशों की तुलना में 50 फीसदी तक महंगे हैं, इनमें लक्जमबर्ग सबसे महंगा है।

लक्जमबर्ग	52%
आयरलैंड	45%
डेनमार्क	43%
फिनलैंड	28%
नीदरलैंड	22%

आंकड़े यूरोपीय संघ में शामिल सबसे महंगे देशों के, प्रतिशत में | स्रोत : Eurostat

जो वाचिक ज्ञानी संत भास्करराय से ईर्ष्या करते थे, वे शास्त्रार्थ करने पहुंचे, तो उनकी आभा व आध्यात्मिक प्रभाव से मोहित हो गए और प्रश्न तक न पूछ सके।

खुले ज्ञानचक्षु

सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण में भास्करराय नाम के प्रसिद्ध चमत्कारी संत हुए। पांच वर्ष की अवस्था में काशी में उनका उपनयन संस्कार किया गया। इसके बाद उन्होंने गुरु नरसिंहाध्वरि से वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया। वह भगवती महात्रिपुरसुंदरी के अनन्य भक्त थे। वह भगवती की उपासना को मुख्य मानते थे। मां की कृपा से उन्हें ब्रह्म का ज्ञान हो गया था, लेकिन काशी के कुछ वाचिक ज्ञानी उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्हें तंग भी करते थे।

एक दिन उनके बीच शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें वाचिक मंडली एक तरफ और दूसरी तरफ अकेले भास्करराय थे। लेकिन, उन्हें शास्त्रार्थ में नीचा दिखाने के लिए आई विद्वानमंडली संत भास्करराय की आभा और उनके आध्यात्मिक प्रभाव से मोहित हो गई और सवाल तक नहीं पूछ सकी। फिर भी उनमें से एक व्यक्ति जैसे-तैसे खड़ा हुआ व मंत्रशास्त्र संबंधी प्रश्न करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि मां भगवती की कृपा से सभी के बीच से कुंकुमानंद स्वामी नाम के परमसिद्ध महात्मा प्रकट हो गए। उन्होंने प्रश्नकर्ता को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। इसके बाद कुंकुमानंद स्वामी ने वहां मौजूद विद्वानों के ऊपर जल के छींटे मारे, तो सभी की आंखों पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हट गया और सभी ने लज्जित होकर भास्करराय से क्षमा प्रार्थना कर उन्हें कंधे पर उठा लिया तथा ज्ञानचक्षु खोलने के लिए आभार माना।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला पुराने पन्नों से — 09 सितंबर, 1950

पंजाब में वर्षा से हाहाकार

पंजाब में वर्षा से हाहाकार
अनेक पक्के मार्ग कट गये
नई दिल्ली, ६ सितम्बर। पूर्वीपंजाब हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू व कश्मीर के इलाकों में पिछले ४ दिन से घन घोर वर्षा होने के समाचार मिले हैं। धर्मशाला जिले की कुलू-क्वराइन रोड ६ स्थानों से कट गई है।

पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के इलाकों में पिछले चार दिनों से घनघोर बारिश हो रही है। शिमला-कालका रोड समेत कई जगहों पर यातायात रुक गया है। कई स्थानों पर चट्टानें गिर पड़ी हैं।

हिमालय नहीं बचा तो कौन बचेगा

हिमालय पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सवा करोड़ लोग निर्भर हैं। इसे बचाने के लिए अविवेकपूर्ण विकास को रोकने के साथ ही आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना बेहद जरूरी है।

अवधेश कुमार गुप्त, सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा समिति

हिमालय दिवस

पहाड़ पर जल प्रलय से मैदानी इलाकों में हाहाकार है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की विनाशलीला बहुतों ने अपने जीवनकाल में पहली दफा देखी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सभी नदियां अपने तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस आई हैं। हिमाचल में 5,600 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और 1,300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड में 2,600 से अधिक सड़कें ध्वस्त हुई हैं। जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 3,100 से अधिक सड़कें बह गई हैं।

मौसम विज्ञान की भाषा में, 100 मिलीमीटर प्रति घंटो की बारिश को बादल फटना कहते हैं। हिमालय में बादल फटने के मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप हैं। हिमालय पर पहले भी बारिश होती थी और बादल फटते थे, पर बादल फटने की इतनी ज्यादा घटनाएं और तबाही आम तौर पर नहीं दिखती थी। चाहे 2013 की केदारनाथ आपदा रही हो या फिर बाद की अनेक घटनाएं। इनके पीछे बड़ी वजह पहाड़ों, विशेषकर जल

धाराओं के निकट बढ़ती मानवीय गतिविधियां हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण, वनों की कटाई और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों में अवरोध इन घटनाओं को भयावह बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में आपदाओं के लिए पेड़ों की अवैध कटाई को जिम्मेदार ठहराया है।

पहाड़ क्या, धरती का हर कोना वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अति मानवीय गतिविधियों व अनियंत्रित विकास से विनाश की ओर बढ़ रहा है। हिमालय दुनिया के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक व अहम पारिस्थितिकी भंडार है। यहां की वनस्पति और जंतु जगत को न बचाया गया, तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र अस्थिर हो जाएगा। एशिया के सवा सौ करोड़ लोग भोजन, पानी व दवाओं के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिमालय पर पर निर्भर हैं। दशकों से विकास के बहाने अविवेकपूर्ण खनन व निर्माण के कारण न सिर्फ आपदाएं बढ़ीं हैं, बल्कि उनसे होने वाला नुकसान भीषण हुआ है। इसका सबसे बड़ा अपराधी चीन है। चीन तिब्बत में सैन्य और बुनियादी ढांचा, सड़कें व बांध बनाकर पारिस्थितिकी को नष्ट कर चुका है। वह ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा जलविद्युत बांध बनाने जा रहा है। हिमालय को ड्रैगन के विस्तारवाद की भूख से बचाना होगा। अन्यथा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

यातायात सुगम होने व जीवन शैली बदलने से पहाड़ों पर पर्यटक तेजी से बढ़ हैं। हिमाचल प्रदेश में 2003 में करीब 55 लाख पर्यटक आए थे, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 2.63 करोड़ हो गया। उत्तराखंड में 2018 में 3.68 करोड़ पर्यटक आए थे, जबकि पिछले साल यह संख्या 5.96 करोड़ हो गई। बढ़ते पर्यटकों की सुविधा और आकर्षण के लिए शहर बढ़ रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण पीछे छूट गया। इसे रोकने के लिए पर्यटन को नियंत्रित करना ही होगा। भूटान जैसे देशों ने इसे कर दिखाया है। उसने पर्यावरण की कीमत पर पर्यटन को बढ़ने नहीं दिया। भूटान ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त नीतियां अपनाई हैं। विकास योजनाओं और पर्यटन उद्योग के विकास में पर्यावरण को केंद्र में रखा है। इसलिए वहां अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है।

वर्ष 1961 से 2011 तक 50 साल में हिमालय की आबादी 250 फीसदी बढ़ी है। भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2011 से 2021 के बीच शहरी विकास की दर 40 फीसदी से अधिक थी। इसका दुष्परिणाम यह है कि हाल के कुछ वर्षों में वन क्षेत्र एक हजार वर्ग किलोमीटर घट गया है। पहाड़ पर वाहनों की धमाचौकड़ी का सीधा असर ग्लेशियर व नदियों पर पड़ रहा है। मंडी और हर्षिल जैसी घटनाएं सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं। ये हमारी तैयारियों की कमी, इन्सानी लालच और जलवायु परिवर्तन की अनदेखी के गंभीर परिणामों की दुखद तस्वीरें हैं।

आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाने की रणनीति पर काम करना होगा। यूरोप के जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन और ऑस्ट्रिया में पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन वहां नुकसान कम होता है। बादल फटने को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक मौसमी घटना है। इन देशों ने आपदा प्रबंधन तंत्र उन्नत बनाया है और आधारभूत ढांचा मजबूत किया है। डेनमार्क ने आधारभूत ढांचे को विकसित करने से पहले रिस्क असेसमेंट किया है, उसके अनुसार विकास योजनाएं बनाई हैं। पार्कों का डिजाइन इस तरह बनाया है कि बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जा सके। सरकार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जैसे कानून और कड़े तथा प्रभावी बनाने चाहिए। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाना ही समझदारी है। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका समझनी होगी। तभी हम इस प्रकार की आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

नेपाल में नाराजगी

नेपाल में युवाओं की नाराजगी का हिंसक विस्फोट दुखद और चिंताजनक है। वर्षों बाद इस पड़ोसी देश में इस तरह से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने में आया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में कई लोगों की मौत हुई है और अनेक घायल हुए हैं। हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए नेपाल में अनेक इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आखिर इस प्रदर्शन या उपद्रव की वजह क्या है? नेपाल सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब और एक्स सहित अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के खिलाफ ही वहां युवाओं में नाराजगी है। युवा मांग कर रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार को रोका जाए, सोशल मीडिया को नहीं। जाहिर है, युवाओं की मांग को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन विरोध का यह तरीका उचित नहीं है। काठमांडू में हजारों प्रदर्शनकारियों का सड़कों पर यूं हिंसक हो उठना और कंटीले तारों को तोड़कर देश की संसद को घेर लेना कतई प्रशंसनीय नहीं है। संसद व अन्य सरकारी कार्यालयों की रक्षा के लिए सेना को तैनात करना पड़ा है, क्योंकि उग्र प्रदर्शन को संभालना वहां की सामान्य पुलिस के वश की बात नहीं रह गई थी।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेपाल पुलिस बहुत संयम बरत रही है, तभी तो भीड़ ने दंगा पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वैसे, वहां प्रशासन को यह उम्मीद नहीं थी कि युवा सोशल मीडिया के पक्ष में ऐसे सड़कों पर उतर आएंगे। यह सच है कि नेपाल में सरकार सोशल मीडिया को व्यवस्थित करने में लगी है। सोशल मीडिया कंपनियों को देश और देश के कानूनों के प्रति जिम्मेदार बनाया जा रहा है। गौर करने की बात है कि उन्हीं सोशल मीडिया मंचों को प्रतिबंधित किया गया है, जिन्होंने नेपाल में विधिवत पंजीकरण नहीं कराया है। सरकार का यह दावा है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसने सोशल मीडिया कंपनियों के पंजीकरण को बाध्यकारी बनाया है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल के नियम-कायदे के हिसाब से चलना चाहिए। यह अक्सर देखा गया है कि सोशल मीडिया कंपनियां किसी भी जिम्मेदारी या नियम-कायदे में बंधने से बचना चाहती हैं। अब तक ये कंपनियां वहां आजादी का पूरा आनंद ले रही थीं और अब उन्हें आगे भी आजादी का आनंद लेने के लिए स्थानीय नियम-कायदों की पालना करनी चाहिए। अगर ये कंपनियां मनमानी करेंगी, तो स्वाभाविक है, स्थानीय सरकार के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

नेपाल में सरकार सोशल मीडिया को व्यवस्थित करने में लगी है। सोशल मीडिया कंपनियों को देश और देश के कानूनों के प्रति जिम्मेदार बनाया जा रहा है।

नेपाल के लोगों की डाटा गोपनीयता को लेकर भी चिंताएं हैं और इन चिंताओं को खारिज नहीं किया जा सकता। इस मोर्चे पर युवाओं को भी सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार को फर्जी आईडी को लेकर शिकायत है, तो इसे समझना चाहिए। लोगों और युवाओं को ज्यादा सभ्य बनते हुए समझदारी का परिचय देना चाहिए। बदलते दौर में सोशल मीडिया का महत्व बहुत बढ़ गया है। इसके जरिये आर्थिक गतिविधियों को बल मिलता है, तो राजनीति भी सोशल मीडिया पर निर्भर करने लगी है। यहां सरकार की शिकायत मायने रखती है कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके अभद्र भाषा और गलत सूचना फैला रहे हैं। नेपाल में धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए इन सोशल मंचों का दुरुपयोग बढ़ने लगा है। ऐसे में, यह जरूरी है कि सोशल मीडिया कंपनियों को शुचिता बरतने के लिए बाध्य किया जाए और युवाओं को विश्वास में लिया जाए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 09 सितंबर, 1950

डच न्यूगिनी का प्रश्न

इण्डोनेसिया और हालैण्ड के बीच डच न्यूगिनी का प्रश्न अभी तय होना बाकी है। इण्डोनेसिया को सत्ता हस्तान्तरित करने का जब समझौता हुआ था, तो डच न्यूगिनी को छोड़कर वह सारा प्रदेश इण्डोनेसिया को सौंप दिया गया था, जो पहले हालैण्ड की अधीनता में था। डच न्यूगिनी के बारे में यह तय पाया था कि इण्डोनेसिया और हालैण्ड दोनों देश आपसी बातचीत द्वारा उसका भविष्य तय कर लेंगे और ऐसा करने के लिए एक वर्ष की अवधि नियत कर दी गई थी। डच न्यूगिनी की स्थिति का अध्ययन करने के लिए डचों और इण्डोनेसियनों का एक संयुक्त जांच कमीशन नियुक्त किया गया था।

खेद का विषय है कि इस कमीशन के सदस्य एकमत नहीं हो पाये और इसलिए कमीशन के डच सदस्यों ने अलग रिपोर्ट दी है और इण्डोनेसियन सदस्यों ने अलग। डच रिपोर्ट में बताया गया है कि डच न्यूगिनी को क्यों इण्डोनेसिया के सुपुर्द नहीं किया जाना चाहिए। उसमें कहा गया है कि इसमें डच न्यूगिनी के आदिवासियों के आत्म-निर्णय के अधिकार की अवहेलना होगी। दूसरे, इण्डोनेसिया के आर्थिक साधन इतने स्वल्प हैं कि वह बहुत समय तक डच न्यूगिनी के लोगों के विकास के लिए कोई काम नहीं कर सकेगा। तीसरे, इण्डोनेसिया के पास डच न्यूगिनी का शासन चलाने के लिए योग्य कर्मचारियों का अभाव है। चौथे, डच न्यूगिनी के निवासी डचों के प्रभुत्व को पसन्द करते हैं और इस बात से सहमत नहीं कि उनके प्रदेश को इण्डोनेसिया के सुपुर्द कर दिया जाये।

इसके मुकाबले इण्डोनेसिया का कहना है कि डच न्यूगिनी उस प्रदेश का ही अंग है जो पहले पूर्वी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। जब पूर्वी द्वीप समूह में सर्वत्र डचों की औपनिवेशिक सत्ता समाप्त हो गई, तो वे केवल डच न्यूगिनी में औपनिवेशिक शोषण कैसे जारी रख सकते हैं? यहां से भी उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना चाहिए। यदि वे डच न्यूगिनी में बने रहते हैं, तो इण्डोनेसिया की स्वतंत्रता को हमेशा खतरा बना रहेगा तथा हालैण्ड और इण्डोनेसिया के बीच न तो विश्वास की भावना पैदा हो सकती है और न सच्चे अर्थों में सहयोग ही संभव हो सकता है। इण्डोनेसिया के विदेश विभाग ने ठीक ही कहा है कि हालैण्ड को दो चीजों में से एक का चुनाव कर लेना चाहिए।

उच्च शिक्षा पर अयोग्य शिक्षकों का बोझ

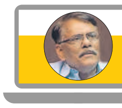

राय की राय
यहां स्कैन करें

विभूति नारायण राय | पूर्व कुलपति व साहित्यकार

प्राथमिक स्कूलों जैसी व्यवस्था उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी नहीं लागू होनी चाहिए? एक निश्चित अंतराल के बाद क्या अयोग्य प्राध्यापकों को बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया जाना चाहिए?

किसी भारतीय विश्वविद्यालय के कुलपति की कौन सी सलाह उसे अपने अध्यापकों के बीच अलोकप्रिय बना सकती है? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि किसी अध्यापक को नियमित कक्षाएं लेने की हिदायत उसे किसी गाली से कम नहीं लगती। यह बात आपको अजीब लग सकती है कि जिस दायित्व के लिए चयन हुआ है, उसी में किसी शिक्षक की सबसे अधिक अरुचि हो। दुनिया में किसी अन्य मुल्क के लिए यह सच नहीं हो सकता, पर भारतीय शिक्षा जगत की यह एक ऐसी सच्चाई है, जिसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का दुस्साहस कोई हितधारक नहीं करता। अध्यापकों के संगठन केवल वेतन-भत्तों में वृद्धि या किसी अध्यापक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न हो, इसके लिए आंदोलन करते हैं। आपने कभी उन्हें अध्यापकों के नियमित रूप से अपनी कक्षाएं लेने या उनके बौद्धिक विकास की जरूरत के लिए लड़ते नहीं देखा होगा।

मैं केवल संयोगवश एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति हो गया और शुरुआत में ही एक दिलचस्प संयोग से मेरा पाला पड़ा। अपने दफ्तर में मुझे एक ऐसे चीनी छात्र का मेल मिला, जो कुछ ही दिनों पहले मेरे विश्वविद्यालय से हिंदी का एक कोर्स करके निकला था। बड़े विनोद से उसने लिखा था, भारत आकर उसे पहली बार पता चला कि छात्रों का एक दायित्व यह भी है कि वे कक्षा शुरू होने के समय ढूंढ़कर अध्यापक को याद दिलाएं कि उनको कक्षा लेनी है।

हुआ कुछ ऐसा था कि सत्र के प्रारंभ में चीनी छात्रों का एक समूह कक्षा में समय से जाकर बैठ गया। वे काफी देर तक अपने अध्यापक की प्रतीक्षा करते रहे और फिर ऊबकर इधर-उधर मटरगश्ती करने लगे। अचानक एक छात्र की नजर उस अध्यापक पर पड़ी, जो एक कमरे में दूसरे अध्यापकों के साथ बैठे ठहाके लगा रहा था। वह उसके पास गया और क्लास की याद दिलाई। अध्यापक ने उल्टे उसी को डांट पिलाई कि छात्रों ने उनको बुलाया क्यों नहीं?

अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या शिक्षा मंत्रालय यह सर्वेक्षण कराए कि कितने प्रतिशत अध्यापक नियमित रूप से अपनी कक्षाएं ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसे निराशा ही हाथ लगेगी। विभिन्न हितधारकों, जिनमें छात्र, अभिभावक और अध्यापक, सभी शरीक हैं, से बात करके मैं निश्चय से कह सकता हूं कि राजधानी दिल्ली में भी अधिकांश अध्यापक नियमित कक्षाएं नहीं ले रहे हैं।

मुझे एक और प्रसंग ने कक्षाओं को लेकर भारतीय शिक्षकों की दिलचस्पी को समझने में मदद की है। हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा ने विदेश में हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए 'रिफ्रेशर कोर्स' आयोजित करने का फैसला किया और काफी बड़े बजट के साथ यह कार्यक्रम शुरू हुआ। दुनिया भर से आने वाले हर अध्यापक पर कई-कई हजार रुपये खर्च होते थे। मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य होता था कि संपर्क करने पर बहुत से अध्यापक यह कहते हुए माफी मांग लेते थे कि प्रस्तावित तिथियों में आने से उनके पहले से निर्धारित पठन-पाठन के कार्यक्रम में बाधा पहुंचेगी। ऐसे उदाहरण भारतीय परिदृश्य में बिरले ही दिखेंगे। हमारे यहां ज्यादातर सेमिनार, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम या अतिथि वक्तव्य तो होते ही हैं उन दिनों में, जब कक्षाएं अपने उरूज पर होती हैं। न किसी अध्यापक को इससे हिचकिचाहट होती है कि उसकी अनुपस्थिति से छात्रों की पढ़ाई-लिखाई पर बुरा असर पड़ेगा और न ही किसी विश्वविद्यालय के प्रशासन की जुर्रत कि वह सलाह दे सके कि ये सारी गतिविधियां उन्हीं दिनों भी हो सकती हैं, जब कक्षाएं न चल रही हों।

पठन-पाठन के प्रति इस उपेक्षा का सीधा असर शोध की गुणवत्ता पर भी दिखता है। अक्सर सुनने को मिलता है कि देश शोध पर उतना खर्च नहीं करता, जितना किसी विकासशील देश को करना चाहिए। मेरी समझ यह बनी है कि संसाधनों की कमी से अधिक गुणवत्ता निराश करती है। हमारे ज्यादातर शोध प्रबंध, खास तौर से मानविकी के क्षेत्र में, कूड़े से अधिक कुछ नहीं हैं। वे कट, कॉपी-पेस्ट के बेहतरीन नमूने तो हो सकते हैं, पर उनको ज्ञान के किसी भी अनुशासन को समृद्ध करने वाला नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति के लिए भी छात्रों की अयोग्यता से अधिक अध्यापकों की उदासीनता और तिकड़म करके हासिल की गई हैसियत जिम्मेदार है।

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके अनुसार, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने या किसी तरह की तरक्की हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को एक परीक्षा पास करनी होगी। जिन अध्यापकों के रिटायरमेंट में पांच से अधिक वर्ष बाकी हैं, उन्हें यह परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह प्रावधान संबंधित कानून में पहले से मौजूद था और राजनीतिक कारणों से सरकारें उदासीन बैठी थीं। अब भी कोशिश हो रही है कि इससे बचने के रास्ते निकाल लिए जाएं। यदि इसे ईमानदारी से लागू किया गया, तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में आजादी के बाद का यह सबसे क्रांतिकारी कदम होगा।

क्या इसी तरह की व्यवस्था उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी नहीं लागू होनी चाहिए? एक निश्चित अंतराल के बाद क्या अयोग्य शिक्षकों को बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया जाना चाहिए? यह एक दुखद यथार्थ है कि एक बार नौकरी हासिल करने के बाद अधिकांश शिक्षक पढ़ना-लिखना बंद कर देते हैं। अपने अनुशासन में दुनिया भर में जो कुछ नया घट रहा है, उससे पूरी तरह अनभिज्ञ अध्यापकों को बाबा आदम के जमाने के नोट्स से पढ़ाते देखना एक मनोरंजक अनुभव होता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों की समयबद्ध प्रोन्नति की व्यवस्था कर दी है और कहने के लिए पुस्तकें/ शोध आलेख प्रकाशन जैसी कुछ शर्तें भी लगा दी हैं, पर शायद ही कोई विश्वविद्यालय किसी अध्यापक की प्रोन्नति रोकता है। संभवतः यही कारण है कि विश्वविद्यालय में घुसते ही अध्यापक पढ़ने-लिखने से अपना रिश्ता खत्म कर लेता है। अपने छात्रों के साथ समय बिताने से बेहतर विकल्प उनके लिए जमीन-जायदाद जैसा कोई धंधा या कोचिंग संस्थाओं में जाकर मोटी कमाई करना है। यह ताज्जुब की बात नहीं है कि सोशल मीडिया के इस दौर में अधिकांश अध्यापकों के प्रोफाइल के नेपथ्य में कोई मंहगी कार दिखती है, किताबों को आप बिरले ही पाते हैं!

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सैलानी और सरकार साथ आएं, तभी बचेगा हिमालय

यहां स्कैन करें

गिरीश गुरुरानी | वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड में चंपावत जिले का गांव है कजीना। नौ साल पहले इसका एक हिस्सा सड़क से जुड़ा था। गांव बिखरा हुआ है, लिहाजा उसके कई हिस्से अब भी सड़क की मांग कर रहे थे। इसी दौरान कजीना मुख्य तोक के लिए अलग से करीब पौन किलोमीटर लिंक रोड बनाई गई। आठ साल पहले तीसरी रोड सालकांडे नामक जगह से केलानी तक साढ़े तीन किलोमीटर स्वीकृत हुई, लेकिन बनी सिर्फ 1,700 मीटर। उसका भी संरेखण, यानी अलाइनमेंट निर्माण के दौरान बदल दिया गया। नतीजतन, योजना का सीधा लाभ सिर्फ एक परिवार तक सिमट गया।

वंचित इलाके के लोगों ने फिर सड़क की मांग की। छह साल पहले तीसरे छोर से साढ़े चार किलोमीटर लंबी एक और सड़क जालछीना-गहत्वाड़ नाम से मंजूर हुई। यह अभी निर्माणाधीन है, लेकिन इसकी लंबाई भी गहत्वाड़ नामक बस्ती तक पहुंचने के लिए कम पड़ गई। पहाड़ों पर अनियंत्रित, अनियोजित और मनमाने विकास को बयां करते ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं। कठिन भौगोलिक क्षेत्र के कारण पहाड़ को विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन हिमालय को ग्लोबल वार्मिंग के अलावा प्रदूषण, प्लास्टिक और अनियोजित विकास के दुष्प्रभावों से बचाना भी जरूरी है।

विषम भूगोल के कारण पहाड़ों को विकास की अधिक जरूरत है, पर वह अनियोजित नहीं होना चाहिए। हिमालय दिवस पर विशेष :

निर्माण में मानकों का पालन नहीं होने और डंपिंग यार्ड के बजाय सीधे नदी-नालों में डाला जाने वाला मलबा भूस्खलन और बाढ़ को बढावा देता है। बड़े पैमाने पर भूस्खलन से हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अरबों रुपये की सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा। वैज्ञानिक और पर्यावरण कार्यकर्ता पिछले कई दशकों से हमें चेतावनी देते रहे हैं। चिपको आंदोलन ने करीब 52 साल पहले ही जंगलों का महत्व दुनिया को बता दिया था, मगर संसार को सजग करने वाली इस भूमि ने खुद उसे पूरी तरह आत्मसात नहीं किया। अगर हमने कुछ सीखा होता, तो चिपको की भूमि रैणी के इलाके में बिजली परियोजना डिजाइन करते समय आसन्न नुकसान का समग्र अध्ययन किया जाता। उस 'हैंगिंग ग्लेशियर' का भी समय रहते पता लगा लिया जाता, जो फरवरी 2021 में टूटकर तबाही का कारण बना था और 200 से ज्यादा लोग मलबे में दफन हो गए थे।

बीते 13 साल से हिन्दुस्तान हिमालय बचाओ अभियान के जरिये यही समझाने का प्रयास हो रहा है कि हिमालय के प्राकृतिक तंत्र को नहीं समझ पाने की गलती कितनी खतरनाक हो सकती है? धरती का तापमान बढ़ने समेत कई कारणों से हिमालय के ग्लेशियर प्रति वर्ष दो मीटर से 52 मीटर तक पिघल रहे हैं। इस प्रक्रिया को रोकना विश्व समुदाय की एकजुटता के बिना संभव नहीं, पर ग्लेशियरों के पिघलने से बन रही खतरनाक झीलों को वैज्ञानिकों की राय के अनुसार निष्क्रिय करके त्रासदी को शून्य या कम किया जा सकता है। इसी तरह, विकास में नियोजन और वैज्ञानिक सोच को शामिल करके आपदा का आकार घटाया जा सकता है। एक उदाहरण पर गौर कीजिए। दिल्ली से देहरादून फोर लेन सड़क बनाई जा रही है। मगर इससे पहाड़ियां दरक सकती हैं, इसलिए इसके विकल्प देखने होंगे। पहाड़ को ज्यादा काटे बिना एलिवेटेड रोड तैयार किया जा सकता है। मसूरी को जोड़ने वाली चार सड़कें चुनकर उनमें से दो आने और दो जाने के लिए आरक्षित करके यातायात को सुगम किया जा सकता है।

इसी तरह, आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को प्लास्टिक के प्रयोग को लेकर सचेत करना होगा, क्योंकि प्लास्टिक जंगल और जमीन के लिए खतरा बन रहा है। अकेले 2023 में चार धाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड 54.18 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड आए। पर्यटकों को प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें पहाड़ों से आवश्यक रूप से वापस लाने के लिए तैयार कर सकें, तो बड़ी कामयाबी होगी। पिछले दो दशकों से पर्यावरण प्रेमियों एवं सामाजिक संगठनों की ओर से समग्र हिमालय नीति बनाने की पैरवी की जाती रही है। कुछ राज्य सरकारों ने इस पर सहमति जताई, पर राष्ट्रीय स्तर पर इसे निर्णायक नेतृत्व नहीं मिल सका। हिमालय का कोई अकेला राज्य भी विकास में विज्ञान का प्रकृति-हितैषी समावेशन करके खुद को मॉडल के रूप में पेश कर सकता है। कुल मिलाकर, जनता, सैलानी और सरकार, सभी को साथ आना होगा, तभी हिमालय को आपदाओं से बचा सकेंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आया है, वह जाएगा

यह प्रश्न किसी के मन में उठ सकता है कि जब सब कुछ परमात्मा बनाते हैं, तो हर चीज नष्ट क्यों हो जाती है?

सृष्टि की मूल वस्तुएं परमात्मा से उत्पन्न होती हैं। किसी चीज की सृष्टि को हम 'संभूति' कहते हैं। जब मनुष्य मौलिक वस्तुओं की सहायता से नई वस्तुएं बनाता है, तो इसे संभूति नहीं कहा जाता। ऐसे मौलिक पदार्थ स्वयं उत्पन्न नहीं होते, लेकिन उनकी सहायता से अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी वस्तु है, वह परमात्मा की संभूति का परिणाम है।

ध्वंस या विनाश को समझना भी आवश्यक है। सामान्य अर्थ में ध्वंस यानी नाश, वह होता है, जब कोई वस्तु नष्ट हो जाती है। विनाश उस अवस्था को कहते हैं, जब वस्तु रूपांतरित हो जाए और उसे अपनी मूल अवस्था में वापस न पाया जा सके। 'प्रणाश' वह है, जब वस्तु का ध्वंस होने के बाद वही वस्तु नई रूपरेखा में तैयार हो जाए। संभूति परमात्मा की विशेष सृष्टि है। परमात्मा ने सृष्टि को इतना व्यापक रूप दिया है कि हम हर वस्तु में उनकी छाया देख सकते हैं। सृष्टि को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है- जड़ जगत और उद्भिद जगत। चेतन और अचेतन सभी वस्तुएं कालक्रम में विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो गई हैं। हर वस्तु, चाहे जड़ हो या चेतन, परमात्मा की सृष्टि का हिस्सा है। जब परम पुरुष स्वयं किसी जड़ वस्तु में विद्यमान होते हैं, तो उस वस्तु को परम पुरुष का अवतार कहा जाता है।

सृष्टि का वैचित्र्य अत्यंत अद्भुत है। जगत में एक जीव अत्यंत उन्नत होता है और कोई जीव कम उन्नत होता है। जीवकोटि की प्रगति सांस्कृतिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती है। ईश्वरकोटि का अर्थ है परमदेवत्व का प्रकाश। जीवकोटि गहन साधना और अभ्यास के माध्यम से ईश्वरकोटि में उन्नति कर सकता है। इस क्रम में साधक का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मत्व की प्राप्ति है, जिसमें पूर्ण आनन्द, ज्ञान और एकत्व का अनुभव होता है।

इस प्रकार, जीवन और सृष्टि का मार्ग चार मुख्य सत्य बताते हैं- प्रत्येक वस्तु परमात्मा की संभूति है। विनाश और प्रणाश, सृष्टि के परिवर्तन और रूपांतरण को दर्शाते हैं। जीवकोटि की उन्नति सीमित होती है, लेकिन यह अनुभव और साधना से लगातार बढ़ती है। अंतिम लक्ष्य ईश्वरकोटि और ब्रह्मत्व की प्राप्ति है, जिसमें सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य परम आनंद के स्वरूप में विलीन हो जाता है। इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि जीवन केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और आत्म-साक्षात्कार की यात्रा है। प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक साधना और प्रत्येक प्रगति परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य व साधना का मार्ग है।

जीवन केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और आत्म-साक्षात्कार की यात्रा है। प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक साधना और प्रत्येक प्रगति परमात्मा की कृपा का परिणाम है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

डोनाल्ड ट्रंप | अमेरिकी राष्ट्रपति

हर कोई बंधकों की रिहाई चाहता है। हर कोई चाहता है कि यह युद्ध खत्म हो। इजरायलियों ने मेरी शर्तें मान ली हैं। अब हमास की बारी है। अगर वे नहीं माने, तो उन्हें अंजाम भुगतने पड़ेंगे। यह आखिरी चेतावनी है, अब और नहीं!

अनुलोम-विलोम

जीएसटी 2.0

जीएसटी में यह बदलाव क्रांतिकारी

जीएसटी दरों में बदलाव की नई घोषणा से भारत की कर व्यवस्था को अभूतपूर्व दिशा मिलेगी। जीएसटी परिषद ने 12 और 28 प्रतिशत की पुरानी श्रेणियों को समाप्त कर 5 और 18 प्रतिशत की सुगम दरों पर सहमति जताई है। यह ऐतिहासिक बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होगा। इस फैसले से दैनिक उपयोग की वस्तुएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़े उत्पाद व सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। हालांकि, इसके कारण सरकार को 93,000 करोड़ रुपये की राजस्व-हानि का भी अनुमान है, लेकिन इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं और व्यवसायों को राहत मिलेगी, बल्कि भारत की आर्थिक नीतियों और संघीय संरचना को भी एक सशक्त दिशा मिलेगी। साल 2017 में लागू जीएसटी का लक्ष्य जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल एवं एकीकृत करना था, लेकिन चार स्लैब (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत) और विशेष दरों (शून्य प्रतिशत, 0.25 प्रतिशत, 3 प्रतिशत) ने इसे जटिल बनाए रखा। इसके पालन में कारोबारियों को मुश्किलें पेश आ रही थीं, तो उपभोक्ताओं को भी अधिक दाम चुकाने पड़ रहे थे। नई व्यवस्था इस दिशा में एक साहसिक और स्वागतयोग्य सुधार है। ये सुधार निम्न और मध्यम वर्ग के लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इस सुधार के फायदे स्पष्ट और दूरगामी हैं। रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं पर कर घटने से परिवारों का बजट हल्का होगा और खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगेगा। स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर जीएसटी शून्य होने से बीमा योजनाएं सस्ती होंगी और अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे। जीएसटी सुधार से शिक्षा भी सस्ती और समावेशी बनेगी, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर अवसर मिल सकेंगे। इससे किसानों की लागत भी घटेगी, क्योंकि टिकाऊ खेती और जल-संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर, यह एक दूरदर्शी कदम है।

आरके जैन 'अरिजीत', टिप्पणीकार

कहावत है- देर आए, दुरुस्त आए। आठ वर्षों से जीएसटी ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया था। खाने-पीने की चीजों से लेकर कॉपी-किताब और पेंसिल तक पर जीएसटी लगा दिया गया था। खेती-किसानी के उपकरणों पर भी इसकी मार पड़ रही थी। आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी एक भी वस्तु ऐसी नहीं बची थी, जिस पर जीएसटी की मार न पड़ी हो। ऐसे में, सरकार ने जीएसटी दरों को कम करके देश के लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। हालांकि, यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था।

सुदेश त्यागी, टिप्पणीकार

सुधार के साथ चुनौतियां भी नत्थी

मुख्य रूप से अमेरिकी टैरिफ से उपजे संकट से पार पाने के लिए केंद्र सरकार ने 'जीएसटी 2.0' नामक अस्त्र चलाया है, मगर सवाल यही है कि क्या यह कदम कामयाब होगा या फिर टांय-टांय फिस्स साबित हो जाएगा? जीएसटी सुधार के समर्थक मानते हैं कि नए प्रयास से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी। मगर यह राय बनाने से पहले संभवतः वे यह भूल जाते हैं कि मांग तब बढ़ती है, जब लोगों की आय में इजाफा होता है। कृषि कर्म में लगे लोग बमुश्किल अपने घर का बजट संभाल पा रहे हैं। इसी तरह, श्रमिकों, खास तौर से लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों में जुटे कामगार अपने रोजगार गंवा रहे हैं। नई नौकरियों का सृजन नहीं हो पा रहा। फिर, अपने देश में नीतियां भी इस कदर गढ़ी गई हैं कि अमीर इतना अमीर हो गया कि जीएसटी 18 प्रतिशत हो या 28 प्रतिशत, उसे फर्क नहीं पड़ता, जबकि गरीब की हालत इतनी खराब हो गई है कि वह जन-वितरण केंद्रों से मिल रहे पांच किलो अनाज से जैसे-तैसे दिन गुजार रहा है। रहा मध्यम वर्ग, तो महंगाई ने उसकी कमर इस कदर तोड़ दी है कि उसकी बचत खत्म हो गई है। ऐसी सूरत में कोई खर्च भला करेगा कैसे?

इतना ही नहीं, इस सुधार के बाद जीएसटी संग्रह में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। कहा भी जा रहा है कि 48,000 करोड़ रुपये का सकल राजस्व घाटा होगा। इसका अर्थ है कि हिमाचल जैसे वे सभी राज्य प्रभावित हो सकते हैं, जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री ने कहा भी है कि इस सुधार के बाद राज्य को एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इसकी भरपायी करने की मांग की है, पर क्या केंद्र सरकार मदद कर पाएगी? यह सवाल इसलिए भी है, क्योंकि कई केंद्रीय परियोजनाएं ऐसी हैं, जिनके लिए धन की अति-आवश्यकता है। चूंकि जीएसटी से केंद्र सरकार के खजाने में खूब पैसा आ रहा था, तो इन योजनाओं के संचालन में दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन अब आशंका है कि ये योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

जाहिर है, जीएसटी सुधार के साथ कई अन्य कदम उठाने की भी जरूरत है। अगर समग्रता में प्रयास नहीं किया गया, तो केंद्र सरकार के इस कदम से सुधार के बजाय अर्थव्यवस्था को नुकसान ही होगा। शेयर बाजार ने भी इस बाबत कोई खास उल्लास नहीं दिखाया है, जिसका मतलब है कि कई चुनौतियों का अब तक समाधान नहीं हो सका है। कुल मिलाकर, इस कथित कर सुधार के बाद भी हमारी राज्य सरकारों को खूब मशक्कत करनी पड़ सकती है।

नरेश पाराशर, बीमा अधिकारी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अपनी बिखरी शक्ति को दिशा देना ही संयम है

आधार पर आदेश

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस सुझाव को आदेश में बदल दिया कि चुनाव आयोग आधार को मान्यता दे। इस फैसले से बिहार के उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनके पास चुनाव आयोग की ओर से मांगे गए 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन आधार है। चुनाव आयोग इस कारण आधार को मान्य नहीं कर रहा था कि उसे गलत तरीके से बनवाया गया हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अवश्य स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को नकली आधार जांचने का अधिकार होगा, लेकिन इसके बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक बड़ी संख्या में आधार गलत तरीके से बनवा लिए जाते हैं। इसका अर्थ है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से आधार हासिल कर लिया है, उन्हें मतदाता बनने से नहीं रोका जा सकता। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं और तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब चुनाव आयोग बिहार के बाद पूरे देश में मतदाता सूचियों के सत्यापन की तैयारी कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश में सभी भारतीय नागरिकों को उनकी नागरिकता साबित करने वाले प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट को ही नागरिकता का प्रमाण माना है। यह सही भी है, लेकिन अपने देश में अनेक लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं और पासपोर्ट तो बहुत कम लोग बनवाते हैं। यह भी ध्यान रहे कि आधार एवं अन्य प्रमाण पत्रों की तरह जन्म प्रमाण पत्र भी नकली बनवाए जा सकते हैं। अच्छा यह होगा कि भारत सरकार के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट भी इस पर विचार करे कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र देश के लोगों को कैसे दिया जाए, जो उन्हें भारत का नागरिक साबित करे। ऐसा किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि घुसपैठ एक गंभीर समस्या है। जब चुनाव आयोग को यह संदेह है कि बिहार में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोग मतदाता बन बैठे हैं तो फिर सीमावर्ती राज्यों में तो इससे इन्कार ही नहीं किया जा सकता। पूर्वोत्तर के राज्यों और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए तमाम लोग नकली प्रमाण पत्रों के सहारे मतदाता बन बैठे हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि कहीं-कहीं वे चुनाव नतीजे प्रभावित करने में सक्षम हैं। ऐसे लोगों को कुछ दल अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए संरक्षण भी देते हैं। देश के किसी भी चुनाव में केवल वही मतदान करने के अधिकारी हो सकते हैं, जो भारत के नागरिक हों। जो भारत के नागरिक नहीं और किसी तरह मतदाता बन बैठे हैं, वे भारतीय लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं। उचित यह होगा कि भारत सरकार राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार करने की दिशा में आगे बढ़े।

सशक्तीकरण पर जोर

राज्य सरकार महिलाओं की स्थिति हरेक स्तर पर सुदृढ़ कर सशक्तीकरण का हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रविधान किया गया। अधिक से अधिक महिलाएं उच्च शिक्षा हासिल कर सकें, इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रविधान भी किए गए। उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाई गई। यही वजह है कि आज इन समूहों से एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं। शहरी क्षेत्रों में भी साढ़े तीन लाख से अधिक जीविका दीदियां जुड़ चुकी हैं। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उन्हें अपनी पसंद के रोजगार के लिए दो लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी यह एक निर्णायक कदम साबित होगा। बीते जुलाई माह में राज्य सरकार ने आशा व ममता कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाया और अब आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण तथा जीवन स्तर में सुधार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया। जाहिर है, ऐसी घोषणाओं से उनका मनोबल बढ़ेगा। दरअसल, सरकार का मानना है कि शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाएं ही सशक्त समाज का निर्माण करती हैं। अब यह संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जरूरतमंद महिलाओं तक योजनाओं का लाभ हर हाल में पहुंचे।

सशक्तीकरण से महिलाओं का मनोबल तो बढ़ेगा ही, वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर भी अधिक ध्यान देंगी।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या भारत चालू वित्त वर्ष के अंत तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है?

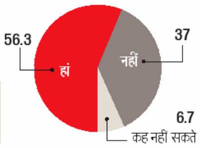

आज का सवाल
क्या नेपाल सरकार की ओर से डिजिटल मीडिया बैन करने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

भावनाएं भड़काने वाली राजनीति

संध्या जैन

क्या अशोक चक्र को गणतंत्र के प्रतीक के रूप में उस शिलापट्ट पर सम्मान नहीं दिया जा सकता था, जहां उसकी इबादत नहीं की जा रही थी?

श्रीनगर की प्रसिद्ध हजरतबल दरगाह के जीर्णोद्धार शिलापट्ट पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र की उपस्थिति ने ईद-ए-मिलाद (पैगंबर का जन्मदिन पांच सितंबर) पर मस्जिद जाने वाले कुछ कश्मीरी मुसलमानों में आक्रोश भड़का दिया। अशोक चक्र को निशाना बनाकर की गई तोड़फोड़ की घटना ने पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। यह मुद्दा इस्लाम के भीतर और इस्लाम एवं गैर-इस्लाम के भीतर की संवेदनशीलताओं से जुड़ा है। चूंकि राजनीति इस विवाद में शामिल हो गई, इसलिए इस विषय की निष्पक्ष पड़ताल जरूरी है। जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने अस्सरी शरीफ हजरतबल दरगाह का जीर्णोद्धार कराया था। इसका उद्घाटन तीन सितंबर, 2025 को जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डा. सैयद दरख्शां अंद्राबी ने किया। शिलापट्ट पर अंकित अन्य सदस्यों में सैयद मोहम्मद हुसैन, डा. गुलाम नबी हलीम, बोर्ड के तहसीलदार इश्तियाक मोहिउद्दीन और इंजीनियर सैयद गुलाम ए मुर्तजा शामिल हैं।

शिलापट्ट के शीर्ष पर बीच में एक उर्दू पाठ है। दाहिनी ओर अर्धचंद्र के ऊपर मस्जिद का चित्र है और बाईं तरफ उसी आकार का अशोक चक्र का प्रतीक है। न तो यह शिलापट्ट और न ही उस पर अंकित कोई भी प्रतीक इबादत का था। यह निश्चित है कि अशोक चक्र पर तीन सितंबर को ही ध्यान दिया गया। फिर भी चार सितंबर तक असहमति या विरोध की कोई आवाज नहीं उठी। पांच सितंबर को ही विरोध प्रकट किया गया। पहले पुरुषों और फिर महिलाओं के एक समूह ने पत्थर मार-मारकर शिलापट्ट में अंकित प्रतीक में तोड़फोड़ कर उसे मिटा दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हरकत सोच-समझकर की गई। आश्चर्यजनक रूप से राजनीतिक नेताओं द्वारा इस तोड़फोड़ का बचाव किया गया। वे इस मामले को बोर्ड या राज्यपाल के समक्ष निजी तौर पर उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग और लोगों को भड़काने वाला रवैया अपनाया। उनका इरादा कश्मीर के साथ देश में भावनाओं को भड़काने का प्रतीत हुआ। यह तर्क पूरी तरह खोखला लगता है कि दिल्ली में संसद भवन में बने शेर प्रतीकात्मक हैं और दरगाह के धार्मिक मूल्यों के साथ असंगत हैं।

हजरतबल दरगाह की प्रसिद्धि एक पवित्र अवशेष, पैगंबर मुहम्मद की दाढ़ी के एक बाल के कारण है, जिसे मोई-ए-मुकद्दस कहा जाता है। इसे पैगंबर के व्यक्तिगत प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है, हालांकि इसकी औपचारिक रूप से इबादत नहीं की जाती। सवाल उठता है कि क्या अशोक चक्र को गणतंत्र के प्रतीक के रूप में उस पट्टिका पर सम्मान नहीं दिया जा सकता था, जहां उसकी औपचारिक रूप से इबादत नहीं की जा रही थी? अंद्राबी ने इस तोड़फोड़ की निंदा करते हुए इसे एक "आतंकवादी हमला" और संविधान, दरगाह की गरिमा और राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमला बताया। उन्होंने इस उपद्रव के लिए नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया और इसे वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण न रख पाने की उनकी हताशा से जोड़ा। इस कथन में कुछ दम नजर आता है। इसलिए और भी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने मस्जिदों और दरगाहों पर नियंत्रण करके और उन्हें वक्फ बोर्ड के अधीन लाकर कश्मीरी मुसलमानों के एक प्रमुख नेता के रूप में अपनी सार्वजनिक छवि बनाई थी। यह उनकी राजनीति का आधार स्तंभ था। शायद नेशनल कांफ्रेंस को वक्फ बोर्ड पर अपना नियंत्रण न होने का अफसोस है।

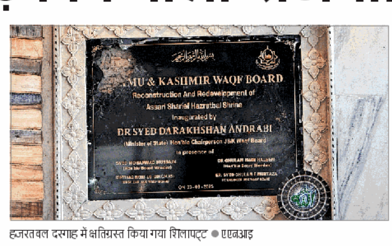

हजरतबल दरगाह में क्षतिग्रस्त किया गया शिलापट्ट ● एएनआइ

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से दरगाह के शिलापट्ट में अशोक चक्र के साथ की गई तोड़फोड़ का समर्थन किया। उन्होंने मजहबी स्थल पर अशोक चिह्न लगाने पर सवाल उठाया और तोड़फोड़ में शामिल लोगों पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगाने का भी विरोध किया। उमर अब्दुल्ला की बातों का समर्थन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एवं उनकी बेटी ने भी किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न रखना ईशनिंदा के समान है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विरोध प्रदर्शन "प्रतीक चिह्न के खिलाफ नहीं", बल्कि "मूर्ति पूजा" के खिलाफ था। माकपा नेता और विधायक एमवाई तारिगामी और मीरवाइज उमर फारूक ने भी प्रदर्शनकारियों का पक्ष लिया।

इस मामले में यह सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आखिर तीन या चार सितंबर को किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? इस सवाल के बीच कुछ मुसलमानों ने प्रदर्शनकारियों की यह कहते हुए आलोचना की कि अशोक स्तंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा और राष्ट्रीय प्रतीक है। मस्जिद के बाहर शिलापट्ट पर उसकी उपस्थिति न तो नमाज में बाधा डालती है और न ही मजहबी आस्था को किसी तरह का नुकसान पहुंचाती है। दिलचस्प बात यह है कि अशोक चक्र हज पहचान पत्रों पर भी अंकित है और भारतीय पासपोर्ट पर भी। इसी कारण ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अशोक चक्र का विरोध करने वाले क्या हज यात्रा के दौरान भारतीय पासपोर्ट का विरोध करेंगे? इस विवाद के बीच आठ सितंबर को सोशल मीडिया पर हजरतबल दरगाह पर लगे एक हरे और सफेद रंग के होर्डिंग की तस्वीर सामने आई। पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान (2017-2022) लगाए गए इस होर्डिंग पर अशोक चक्र अंकित है और योजना का संदेश लिखा है। यह केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय (2014-15) की एक पहल थी, जो ऐतिहासिक महत्व के तीर्थ स्थलों के विकास के लिए थी। यदि आलोचक इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक का विरोध पूरी तरह राजनीतिक है तो उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि कई इस्लामी देशों की मस्जिदों की होर्डिंग्स-शिलापट्ट में वहां के राष्ट्रीय प्रतीक अंकित हैं।

भारत के मुसलमानों को अरब के कुछ इस्लामी देशों से सीख लेनी चाहिए, जहां इस्लाम का जन्म हुआ। वे एक उदार इस्लाम का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये देश कट्टरपंथियों के सोच और उनकी क्रूरता से अपने युवाओं को दूर रख रहे हैं। ये इस्लामी देश अपने देश के लोगों को सुसंस्कृत नागरिक बनने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। आखिर भारत के मुसलमान इन इस्लामी देशों के मुसलमानों का अनुकरण क्यों नहीं कर सकते?

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

जटिल कर प्रणाली से मिली मुक्ति

डा. जयंतीलाल भंडारी

नई जीएसटी व्यवस्था के साथ-साथ नए इनकम टैक्स कानून के तहत किए गए बदलावों से करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे

हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और इनकम टैक्स में नए साहसिक सुधारों से न केवल आम आदमी की जिंदगी आसान होगी, बल्कि देश विकसित भारत की राह पर भी तेजी से आगे बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि नए कर सुधारों से इसी वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसी तरह दुनिया के विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संगठनों की रिपोर्ट में भी जीएसटी और इनकम टैक्स में किए गए सुधारों से भारत के तेज गति से विकास की संभावनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने चार टैक्स स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत में बदलाव करते हुए 5 और 18 प्रतिशत स्लैब वाले दो-स्तरीय जीएसटी को मंजूरी दी है। हालांकि अहितकर वस्तुओं की श्रेणी में आने वाली कुछ वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लागू होगा। जीएसटी में हुए सुधारों के तीन बड़े आधार हैं। पहला, संरचनात्मक सुधार। इसमें टैक्स ढांचे को और बेहतर किया गया है। दूसरा, टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाया गया है, ताकि जरूरी वस्तुएं सस्ती हों। तीसरा, नए रजिस्ट्रेशन और रिफंड को आसान बनाया गया है। इससे इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट में संतुलन आएगा।

जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से लेकर पालन प्रतिवेदन की प्रक्रिया भी आसान की गई है। कारोबारी अब सिर्फ तीन दिन में जीएसटी पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। उन्हें सात दिनों में रिफंड देने की व्यवस्था होगी। कच्चे माल और तैयार माल की दरों में भिन्नता होने के कारण इनपुट टैक्स रिटर्न में होने वाली दिक्कतों को भी समाप्त कर दिया गया है। जीएसटी दरों में नए बदलाव से वर्तमान में 12 प्रतिशत जीएसटी वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं अब पांच प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगी। जबकि 28 प्रतिशत टैक्स वाली लगभग 90 प्रतिशत वस्तुएं 18 प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगी। नए बदलाव से आम आदमी से लेकर किसान और छोटे उद्योगों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी।

जीएसटी में सुधार का ऐतिहासिक फैसला ● फाइल

इससे घरेलू खपत में जोरदार तेजी आएगी। मध्य वर्ग उत्पादों की खरीद पर पैसा खर्च करेगा और मांग बढ़ने से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार को भी उम्मीद है कि 47,000 करोड़ रुपये के सालाना राजस्व नुकसान के बावजूद इससे बाजार की गतिविधियों में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था को जिस तरह रफ्तार मिलेगी, उससे तात्कालिक नुकसान की सरलता से भरपाई हो जाएगी। आम आदमी एवं मध्यवर्गीय लोगों को कीमतों में राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। बाजार में नकदी प्रवाह भी बढ़ेगा। जो छोटे उद्योग ट्रंप टैरिफ के कारण निर्यात घटने को लेकर चिंतित हैं, उन्हें घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग से बड़ा सहारा मिलेगा।

जीएसटी घटने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर सर्विस सेक्टर तक में मांग बढ़ती हुई दिखाई देगी। अनुमान है कि देश में जीएसटी घटने से करीब दो लाख करोड़ रुपये की खपत बढ़ेगी और निर्यात को भी नई गति मिलेगी। मांग एवं उत्पादन बढ़ने से जीडीपी में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। वैश्विक स्तर पर भारत की ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी सुधरेगी। जीएसटी के दो स्लैब बनने से इसके कार्यान्वयन और लेखांकन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

केंद्र सरकार जीएसटी में बदलाव से साथ-साथ इनकम टैक्स को भी आसान और राहतकारी बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी है। इनकम टैक्स बिल, 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून बन गया है। यह कानून मौजूदा इनकम टैक्स कानून, 1961 की जगह लेते हुए एक अप्रैल, 2026 से लागू किया जाएगा। वस्तुतः नया इनकम टैक्स कानून महज कुछ धाराओं का बदलाव नहीं, बल्कि पूरी टैक्स व्यवस्था का कायापलट करने वाला है। इससे देश में टैक्स सिस्टम के डिजिटल और सरल युग का नया दौर शुरू होगा। इस नए कानून के तहत टैक्स कानूनों के मकड़जाल को खत्म कर एक ऐसी प्रणाली निर्मित होगी, जो सहज और आम करदाताओं के लिए लाभकारी होगी। इससे नए करदाता अपनी आमदनी के मुताबिक इनकम टैक्स देने के लिए तत्पर होंगे। नया इनकम टैक्स कानून पुराने कानून को लगभग 50 प्रतिशत तक सरल बनाता है। नया कानून गृह संपत्ति से होने वाली आय से जुड़ी अस्पष्टताओं को दूर करता है। नए कानून के माध्यम से टैक्स कानून में अप्रासंगिक हो चुके प्रविधानों को हटा दिया गया है।

नई जीएसटी व्यवस्था के साथ-साथ नए इनकम टैक्स कानून के तहत नए बदलावों के कार्यान्वयन से देश के करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे और भ्रष्टाचार भी नियंत्रित होगा। जीएसटी और इनकम टैक्स के तहत नए अहम कर सुधारों से करदाताओं की संख्या बढ़ाने, टैक्स जटिलता और मुकदमों में कमी लाने और टैक्स संग्रहण बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश के उद्योग-कारोबार ट्रंप की टैरिफ चुनौतियों का मुकाबला करते हुए देश को आर्थिक रफ्तार देंगे। इससे तेजी से बढ़ने वाला कर संग्रहण देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देगा।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मबोध

जब हम दूसरों की भलाई सोचते हैं, तो इससे हमारे चित्त की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है और आत्मसुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई सोचता है, उसका भला ईश्वर स्वयं करता है। शाश्वत सुख और आनंद कहीं बाहर नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर ही विद्यमान हैं। इससे अनजान होने के कारण व्यक्ति सुख की तलाश में इधर-उधर भटकता रहता है। वह कभी भौतिक वस्तुओं में सुख की खोज करता है, तो कभी विषय भोगों में, लेकिन उसे संतोष कहीं नहीं मिलता, क्योंकि ये सभी सुख क्षणभंगुर होते हैं। यदि व्यक्ति योगाभ्यास, ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय करता है, तो उसे अंदर से असीम आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा से प्रस्फुटित आनंद हमेशा स्थायी रहता है। इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति हर अवस्था में आनंदित रहता है और स्थायी रूप से तृप्ति का अनुभव करता है। उसके मन में घृणा, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और उसके हृदय में करुणा, प्रेम, संवेदना जैसी दिव्य भावनाएं उमड़ने लगती हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से उसका जीवन पूर्ण होता है। यदि व्यक्ति को शाश्वत शांति चाहिए, तो उसे ध्यान और भजन अवश्य करना चाहिए।

इसके लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है। इससे हमारी चेतना का परिष्कार होता है। व्यक्ति को लगता है कि सुख प्राप्त करने के लिए बाहरी मार्ग उपयुक्त है, लेकिन एकाग्रचित होने के बाद यह अनुभव होता है कि सुख और आनंद का स्रोत हमारे अंदर ही है। परम आनंद प्राप्त होने के बाद व्यक्ति की जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं। यह आत्मबोध हर समय आनंदित व्यक्ति में विद्यमान रहता है, क्योंकि आनंद आत्मा से संबंधित है, जबकि सुख शरीर से। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है और किसी की आलोचना या प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता।

अवधविहारी शुक्ल

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

स्वतंत्रता के बाद भी बंधन

'औपनिवेशिक प्रपंच की निरंतरता' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में बलबीर पुंज ने प्रतिपादित किया है कि भारत की मूल चुनौती अतीत की सामाजिक बुराइयां नहीं, बल्कि औपनिवेशिक मानसिकता के वे अवशेष हैं, जो आज भी शिक्षा, राजनीति और बौद्धिक विमर्श में गंभीर रूप में मौजूद हैं। विदेशी शक्तियों ने न केवल राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया था, बल्कि सांस्कृतिक एवं मानसिक स्तर पर ऐसा भ्रम बोया जिससे 'सामाजिक न्याय' जैसे शब्दों के नाम पर विभाजनकारी विमर्श खड़े हुए और समाज की एकता निरंतर चुनौती के घेरे में रही। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि विचारों का युद्ध बंदूक से लड़े गए युद्ध से कहीं अधिक लंबा और गहरा असर डालता है। विवेकानंद, गांधी, आंबेडकर और सावरकर जैसे सुधारकों ने असमरसता एवं बुराइयों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाए, किंतु औपनिवेशिक विचारधाराएं इन्हें बार-बार नए रूपों में जीवित करती रहीं। परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के बाद भी समाज मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया। यह मात्र ऐतिहासिक विवशता नहीं, बल्कि सुनियोजित रणनीति है, जिसका उद्देश्य समाज में स्थायी दरारें बनाए रखना रहा है। यहां यह भी समझना होगा कि यदि विचारों की दिशा बाहरी शक्तियां तय करेंगी, तो स्वतंत्रता केवल औपचारिक रह जाएगी। वर्तमान में यह विमर्श और प्रासंगिक है, क्योंकि डिजिटल औपनिवेशिकता का संकट गहराता जा रहा है। डाटा और तकनीक पर विदेशी वर्चस्व सामाजिक एवं राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को स्वदेशी दृष्टिकोण पर आधारित करना और डिजिटल दुष्प्रचार का तार्किक प्रतिवाद करना अनिवार्य है। तभी सामाजिक न्याय जातिगत सीमाओं से आगे बढ़कर शिक्षा एवं आर्थिक समानता की ओर समाज को उसकी वास्तविक शक्ति और एकता दिला सकेगा।

awanishg30@gmail.com

हाकी का प्रदर्शन उत्साहवर्द्धक

भारत के लिए गर्व की बात रही कि राजगीर के खेल मैदान में हाकी में भारत ने चौथी बार एशिया चैंपियन का खिताब प्राप्त किया। राष्ट्रीय खेल होने के नाते हाकी में बेहतरीन प्रदर्शन उत्साहवर्द्धक है। हाकी राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद क्रिकेट जैसे खेल के सामने अन्य खेलों की तरह उपेक्षित ही नजर आता है। ऐसे में यह चैंपियनशिप अन्य खेलों के प्रति भी युवाओं को आकृष्ट करेगा। आज गली, मोहल्ले, शहर, गांव हर जगह बैट, बाल व विकेट के साथ बच्चे मिल जाते हैं लेकिन अन्य खेलों के प्रति उतना आकर्षण नहीं दिखता। केंद्र व राज्य सरकार की खेल नीति में बदलाव के कारण अन्य खेलों के प्रति दिलचस्पी बढ़नी शुरू हुई है। बच्चे अन्य खेल भी खेल रहे हैं, यह क्रम जारी रखना होगा। आज आवश्यकता है कि हाकी में देश को चैंपियन बनाने वाले दिलप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, अभिषेक जैसे खिलाड़ियों को भी लोग जानें। इसमें मीडिया को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

मिथिलेश कुमार, भागलपुर, बिहार

फूट डालो, शासन करो की नीति

'औपनिवेशिक प्रपंच की निरंतरता' शीर्षक आलेख से स्पष्ट संकेत दिया गया है कि देश में कुशल एवं मजबूत सरकार कायम है, जो विदेशी ताकतों की कठपुतली कतई नहीं है। सरकार को अस्थिर करने वाली ताकतें घुटनों पर आ गई हैं। ऐसा सरकार के मजबूत इरादों एवं कुशल कूटनीति के कारण हो सका है। भारत सरकार के विरुद्ध चलाए जा रहे विदेशी आख्यान को लपकने वाले कतिपय राजनीतिक दलों की बोलती बंद है। ट्रंप सरकार में व्यापार मामलों के वरिष्ठ सलाहकार नवारो ने भारत में उस वक्त सुर्खियां बटोरीं, जब उन्होंने कहा कि 'ब्राह्मण' भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं और इसे रोकने की ज़रूरत है। नवारो ने यह भी कहा कि पीएम मोदी एक महान नेता हैं। ये समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं? जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नवारो ने यह भी सलाह दी कि भारतीय लोग कृपया समझें कि यहां क्या हो रहा है। नवारो का ब्राह्मणों की मुनाफाखोरी वाला बयान बिल्कुल वैसा है, जैसे ब्रिटिश ने यहां 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाई थी। नवारो इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भारत के खिलाफ झूठ फैलाने में लगे हैं, लेकिन 'एक्स' ने एक फैक्ट चेक करके नवारो की पोल खोल दी है।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार।

X पोस्ट

पहले पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अब नेपाल बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की चपेट में है। ये विरोध प्रदर्शन और सत्ता परिवर्तन दिखाते हैं कि पड़ोस में राजनीति की स्थिति कितनी नाजुक है। प्रयाग@theprayagtiwari

राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र किसी भी धर्म, आस्था या विश्वास से ऊपर होने चाहिए। धर्म के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनादर करना कभी उचित नहीं है, कभी नहीं। जय हिंद। अर्पित शर्मा@iArpitSpeaks

हाकी में हम विश्व में बेजोड़ थे। आम लोग गर्व करते थे। ध्यान हट क्रिकेट का मोह जगा, तो हाकी में पिछड़ गए। एशिया कप में चैंपियन बन विश्व कप खेलने की पात्रता मिली, तो देश का ध्यान फिर हाकी पर गया। कभी वर्ल्ड चैंपियन थे, आज पात्रता के लिए लड़ना पड़ रहा है। पुराना गौरव हासिल करना होगा। सुशील दोशी@RealSushilDoshi

भारत की ग्रेट निकोबार परियोजना मलक्का स्ट्रेट में देश की सैन्य, भू-राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाएगी, जहां से चीन का आधा समुद्री व्यापार गुजरता है। कांग्रेस इसके भी खिलाफ है। मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

जनपथ

ओली जी के राज में उबल रहा नेपाल,
युवा देश के एक हो करते खूब बवाल।
करते खूब बवाल न कोई उनका नेता,
बिखरेगा नेपाल अगर ना अब भी चेता।
बच्चों पर इस भांति चलाएंगे यदि गोली,
नहीं टिकेंगे चार दिवस भी पीएम ओली।
– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर. बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 149

****

कल्पमेधा

मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे हमेशा अपना अतीत याद करते रहना चाहिए।
- ईश्वर चंद्र विद्यासागर

राहत के बरक्स

सरकार की ओर से हाल में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती के एलान से माना जा रहा था कि इससे आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। उनके पास पैसों की बचत होगी, जिसे वे अन्य जरूरी वस्तुएं जुटाने पर खर्च कर सकेंगे। मगर इससे पहले कि जीएसटी की नई दरें लागू होतीं, लोगों की जेब पर एक और शुल्क का बोझ पड़ गया है। आनलाइन माध्यम से भोजन की आपूर्ति करने वाली कुछ कंपनियों ने अपने मंच शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। यानी आनलाइन भोजन मंगवाना अब महंगा हो जाएगा। इसका असर देशभर के लाखों लोगों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि 22 सितंबर से आपूर्ति शुल्क पर अठारह फीसद जीएसटी लागू होने पर आनलाइन भोजन मंगाने पर खर्च और बढ़ सकता है। ऐसे में यह सवाल भी अहम हो गया है कि सरकार ने जीएसटी सुधारों के तहत जो कदम उठाया है, क्या वास्तव में उसका लाभ उभोक्ताओं को मिल पाएगा या नहीं?

खबरों के मुताबिक, आनलाइन बुकिंग के माध्यम से भोजन परोसने वाली एक मुख्य कंपनी ने चुनिंदा बाजारों में अपना मंच शुल्क जीएसटी सहित पंद्रह रुपए कर दिया है। इसकी एक अन्य प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने भी अपना मंच शुल्क बढ़ाकर 12.50 रुपए (जीएसटी को छोड़कर) कर दिया है, जबकि एक अन्य कंपनी ने व्यापक उद्योग रुझानों के अनुरूप अपना मंच शुल्क संशोधित करके दस रुपए प्रति आर्डर कर दिया है। भोजन आपूर्ति कारोबार से जुड़े विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि 22 सितंबर से जब आपूर्ति शुल्क पर अठारह फीसद जीएसटी लागू हो जाएगा तो उपयोगकर्ताओं पर प्रति आर्डर लगभग दो रुपए से लेकर ढाई रुपए से ज्यादा तक अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि जीएसटी में बदलाव से भोजन तैयार करने की लागत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उपभोक्ताओं पर शुल्क का अतिरिक्त बोझ डालने का औचित्य समझ से परे है। ऐसे में इन कंपनियों द्वारा मंच शुल्क में एक साथ की गई बढ़ोतरी खाद्य वितरण क्षेत्र में महंगाई के बढ़ते रुझान को रेखांकित करती है, जिससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या लाखों ग्राहकों के लिए सामर्थ्य और सुविधा अब भी साथ-साथ चल सकती हैं?

सरकार का तर्क है कि जीएसटी दरों में कटौती और इनके सरलीकरण से न केवल आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि घरेलू मांग भी बढ़ेगी, छोटे और बड़े उद्यमों को ज्यादा अवसर मिलेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा लोगों की आय बढ़ेगी, जिससे उनके खर्च की क्षमता भी बढ़ेगी। सरकार के इस फैसले को अमेरिकी शुल्क की चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल, सरकार का जोर घरेलू मांग और खपत बढ़ाने पर है। कर में राहत से लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी और इसके परिणामस्वरूप खपत में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे अमेरिकी शुल्क का प्रभाव कम होगा। मगर यह तभी संभव होगा, जब जीएसटी दरों में कटौती का लाभ वास्तव में उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। अगर एक तरफ कर कम किया जाता है और दूसरी तरफ बढ़ा दिया जाता है तो जाहिर है कि मांग और खपत बढ़ने की उम्मीदों पर भी धुंधलका छाया रहेगा। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जीएसटी सुधारों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और जिन उत्पादों पर कर बढ़ा है, उसका बोझ सीधा उपभोक्ता पर न डाला जाए।

हौसले की जीत

अंतरराष्ट्रीय हाकी की दुनिया में भारत को जिस रूप में याद किया जाता है, उसमें इसकी टीम से किसी प्रतियोगिता में खिताबी जीत की उम्मीद स्वाभाविक है। ऐसे मौके भी आते रहे हैं, जिनमें भारतीय टीम ने किसी प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन पदक से थोड़ी दूरी रह गई। करीब आठ वर्ष के बाद बिहार के राजगीर में एशिया कप, 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस दमखम का प्रदर्शन किया, उससे एक बार फिर हाकी में अतीत की यादें ताजा हो गईं, जब भारतीय टीम को हर विश्वकप में सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था। गौरतलब है कि रविवार को एशिया कप का फाइनल मैच भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खेला गया। यों दक्षिण कोरिया को भी हाकी के मैदान में सबसे मजबूत टीमों में से एक माना जाता है और एशिया कप पर वह पांच बार कब्जा जमा चुका है। मगर भारत ने इस मैच में दक्षिण कोरिया को एक के मुकाबले चार गोल से हराया और एशिया कप के विजेता का खिताब अपने नाम किया। खास बात यह भी है कि न केवल अंतिम मुकाबले में, बल्कि इस पूरी प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने अपने सारे मैच जीते।

इस लिहाज से देखें तो भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप में अपनी टीम के सर्वश्रेष्ठ होने का दावा सामने रखा है और टीम की विश्व स्तर पर स्थिति और मजबूत हुई है। निश्चित रूप से इस वर्ष के एशिया कप में भारतीय टीम की जीत की अपनी अहमियत है, लेकिन यह भी सच है कि भारत यह खिताब इससे पहले चार बार अपने नाम करा चुका है। मैच में खास बात यह रही कि इस मुकाबले में शुरू से ही नियंत्रण भारत की टीम ने अपने हाथ में रखा। यही वजह रही कि पहले ही मिनट में सुखजीत सिंह के शानदार गोल के बाद दक्षिण कोरिया की टीम एक तरह के मानसिक दवाब में आई और इसका असर समूचे मैच में दिखा। दक्षिण कोरिया पर मिली जीत को इस लिहाज से भी अहम माना जा सकता है कि इसी वजह से भारत को अगले वर्ष होने वाले हाकी विश्व कप में सीधे प्रवेश मिल जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि विश्वकप और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय हाकी टीम की यही धार बनी रहेगी।

समावेशी शिक्षा के समांतर चुनौतियां

प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का अभाव लड़कियों को शैक्षिक लाभों, समान अवसरों और सर्वांगीण विकास से वंचित करता है। जिन लड़कियों को पढ़-लिख कर घर, समाज और देश में बदलाव का वाहक बनना था, उनका एक बड़ा हिस्सा घर की चौखट लांघ कर प्राथमिक विद्यालय तक भी नहीं पहुंच पा रहा है।

सुधीर कुमार

संयुक्त राष्ट्र के महिला संगठन की ताजा रपट बताती है कि दुनिया भर में आज भी बड़ी संख्या में लड़कियां प्राथमिक शिक्षा हासिल करने से कोसों दूर हैं। यह अत्यंत चिंताजनक है कि वर्ष 2015 में जहां शिक्षा से वंचित लड़कियों की संख्या 1.24 करोड़ थी, वहीं दस वर्ष बाद इसमें 26 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का अभाव लड़कियों के माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मार्ग को ही अवरुद्ध नहीं करता, बल्कि उन्हें शैक्षिक लाभों, समान अवसरों और सर्वांगीण विकास से भी दूर करता है। शिक्षा के सार्वभौमीकरण में लैंगिक विषमता ने बड़ी रुकावट पैदा की है। जिन लड़कियों को पढ़-लिख कर घर, समाज और देश में बदलाव का वाहक बनना था, उनका एक बड़ा हिस्सा घर की चौखट लांघ कर प्राथमिक विद्यालय तक भी नहीं पहुंच पा रहा है।

ऐसे परिदृश्य में वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र का शिक्षा में व्याप्त लैंगिक असमानताओं को समाप्त करने तथा सतत विकास लक्ष्य (2015-30) के अंतर्गत समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार का लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शिक्षा के प्रति व्याप्त सामाजिक रुढ़ियां न केवल स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर रही हैं, बल्कि उनके अधिकारों और अवसरों को भी सीमित कर रही है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि वैश्विक लक्ष्यों के निर्धारण के बावजूद शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में दुनिया की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए भारत में भी ठोस प्रयासों की जरूरत है। पिछली जनगणना (2011) के आंकड़ों की मानें, तो देश में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच बड़ी खाई है। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 फीसद के मुकाबले महिलाओं में यह आंकड़ा 65.46 फीसद है। इन दोनों समूहों के मध्य 17 फीसद का अंतर बताता है कि भारतीय परिवारों में बालिकाओं की शिक्षा को लेकर लैंगिक भेदभाव की मानसिकता अभी खत्म नहीं हुई है। शिक्षा मंत्रालय की 'यू-डाइस प्लस' की 2023-24 रपट भी इस अंतर और भेदभाव को उजागर करती है। रपट के अनुसार, देश के विद्यालयों में अध्ययनरत लड़कों की संख्या जहां 12.87 करोड़ है, वहीं लड़कियों की संख्या 11.93 करोड़ है। दोनों की उपस्थिति में 94 लाख का अंतर यह बताने के लिए काफी है कि लड़कियों की शिक्षा के प्रति समाज में अभी भी समान अवसर और जागरूकता की कमी बनी हुई है।

लड़कों के मुकाबले लड़कियों की शिक्षा तक कम पहुंच के पीछे कई कारक उत्तरदायी रहे हैं, जिनका निराकरण किए बगैर शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित नहीं की जा सकती है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, जो बच्चों को सुरक्षित भविष्य बनाने की नींव प्रदान करता है। शिक्षा के प्रसार में किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भेदभाव न केवल लड़कियों को शिक्षण अवसरों तक पहुंचने से रोकता है, बल्कि उनके जीवन और भविष्य को भी प्रभावित करता है।

शिक्षा में बालिकाओं की हिस्सेदारी कम होने की एक बड़ी वजह समाज में व्याप्त गरीबी की समस्या भी है। गरीब परिवार अक्सर शिक्षा

में निवेश करते समय लड़कों को प्राथमिकता देते हैं। पुरातन और पुरुष प्रधान सोच भी यही रही है कि बेटे ही भविष्य में घर की जिम्मेदारी उठाते हैं। आज भी कई घरों में लड़कियों को शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे घरों में विवाह कराने के लिए दिलाई

> **बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए भारत में भी ठोस प्रयासों की जरूरत है। पिछली जनगणना (2011) के आंकड़ों की मानें, तो देश में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच बड़ी खाई है। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 फीसद के मुकाबले महिलाओं में यह आंकड़ा 65.46 फीसद है। इन दोनों समूहों के मध्य 17 फीसद का अंतर बताता है कि भारतीय परिवारों में बालिकाओं की शिक्षा को लेकर लैंगिक भेदभाव की मानसिकता अभी खत्म नहीं हुई है। शिक्षा में बालिकाओं की हिस्सेदारी कम होने की एक बड़ी वजह समाज में व्याप्त गरीबी की समस्या भी है। गरीब परिवार अक्सर शिक्षा में निवेश करते समय लड़कों को प्राथमिकता देते हैं।**

जाती है। इस परंपरागत सोच को बदले बिना बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। बाल विवाह भी लड़कियों की शिक्षा की दिशा में बड़ा बाधक साबित हुआ है। कम उम्र में विवाह न सिर्फ उनके अधिकारों का हनन करता है, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ का असर पढ़ाई पर पड़ता है और इससे बचपन एवं भविष्य दोनों बर्बादी के मुहाने पर चले जाते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा के बाद हर वर्ष स्कूल में रहने से लड़कियों की अल्पायु में शादी होने की संभावना घट रही है। हालांकि दुनिया में बाल विवाह उन्मूलन की जो रफ्तार है, उसके हिसाब से इसे पूरी तरह समाप्त फिलहाल से पहले संभव नहीं है।

हिंसा भी लड़कियों की शिक्षा में एक बड़ी बाधा है, जो उन्हें स्कूल जाने, प्रभावी ढंग से सीखने और अपनी शिक्षा पूरी करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। स्कूलों में शारीरिक दंड, यौन दुर्व्यवहार, अपमानजनक टिप्पणियां, मारपीट और साथियों या वयस्कों द्वारा मनोवैज्ञानिक तरीके से परेशान करना भी इसके आम स्वरूप हैं। स्कूलों में आधारभूत संरचना का अभाव भी शिक्षा में लैंगिक भेदभाव के कायम रहने के लिए जिम्मेदार है। 'यू-डाइस प्लस' की रपट के अनुसार, देश में तीन फीसद सरकारी विद्यालयों में आज भी बालिका शौचालय की उपलब्धता नहीं है। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास का आकलन इस बात से भी किया जाता है कि वहां लड़कियों की शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच कितनी सुलभ और प्रभावी है।

शिक्षा लड़कियों के लिए आर्थिक अवसरों के दरवाजे खोलती है और उन्हें स्वावलंबी बनाती है। संयुक्त राष्ट्र के महिला संगठन का कहना है कि एक लड़की का स्कूल में बिताया गया प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष वयस्क होने पर उसकी आय में बीस फीसद तक की वृद्धि कर सकता है। हमें इस कथन पर गंभीरता से गौर करना चाहिए कि 'यदि एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं।' शिक्षा की उपलब्धता में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए परिवार स्तर पर ठोस प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जब तक बेटे-बेटियों में भेदभाव को बंद नहीं किया जाएगा, लड़कियों के लिए शिक्षा की राह आसान नहीं होगी।

हालांकि, शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करने के लिए देश में संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना जहां प्रखंड स्तर पर की गई है, वहीं जिले में स्थापित नवोदय विद्यालयों में लड़कियों के लिए 25 फीसद सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में निहित कोष शिक्षा में व्याप्त लैंगिक विषमता को खत्म करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस कोष का इस्तेमाल समान शिक्षा की राह में विद्यमान भेदभावों को समाप्त करने के लिए किया जाना है। इस कोष के जरिए जिन क्षेत्रों में काम किया जाएगा, उनमें स्कूलों में लड़कियों की सौ फीसद भागीदारी सुनिश्चित करना, शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक उपलब्धि में लैंगिक अंतर को कम करना, समाज में लैंगिक समानता के लिए वैचारिक बदलाव लाना, लड़कियों में नेतृत्व की क्षमता विकसित करना और नागरिक समाज के साथ संवाद में सुधार करना भी शामिल है। इसका उद्देश्य लैंगिक भेदभाव से मुक्त समाज का गठन करना है, जहां शिक्षा दिलाने और अवसरों की उपलब्धता के मामले में कोई भेदभाव न दिखाई दे। इसके लिए परिवार से लेकर सरकारी स्तर तक, सभी को संवेदनशील और गंभीर होने की जरूरत है।

विकास बनाम साक्षरता

राजेंद्र जोशी

साक्षरता के बिना किसी भी समाज और राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। यह सामाजिक सद्भावना को मजबूत करती है और आर्थिक प्रगति का द्वार खोलती है। वहीं निरक्षरता पिछड़ेपन और असमानता का मुख्य कारक है। आजादी के बाद साक्षर भारत की परिकल्पना भी की गई और उसके लिए सरकारों ने अलग-अलग नाम से निरक्षरता उन्मूलन के लिए अनेक अभियान और कार्यक्रमों का संचालन किया। उन कार्यक्रमों की बदौलत हमने प्रगति करने का भी प्रयास किया। 1951 से 2011 तक हमने साक्षरता में दशकीय प्रगति कभी धीमी और कभी तेज रखी। 1991 से 2001 का दौर हमारे लिए सुकून देने वाला था। दरअसल, 2001 में भारत की साक्षरता दर 64.83 फीसद से 74.04 फीसद पर आ गई। यह बढ़ोतरी पिछले दशकों के दौरान लगभग अच्छी मानी जानी चाहिए। इस दशक में अनेक राज्यों ने खासी उपलब्धि हासिल की।

वर्ष 2000 तक भारत में साक्षरता की दर तेजी से बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही थी। इसी क्रम में संपूर्ण साक्षरता अभियान मील का पत्थर साबित हुआ। मगर धीरे-धीरे यह अभियान कार्यक्रम में बदलता गया। कार्यक्रमों के दौरान निरक्षर लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। जबकि वर्ष 2000 के बाद इसे और बड़ा अभियान बनाने की जरूरत रही थी, क्योंकि शेष रह गए निरक्षर मुख्य और केंद्रीय समूह की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें साक्षर बनाने की जरूरत थी। यह वह समूह है, जिनकी साक्षरता से बहुत दूरी बनी हुई थी और वे दूरदराज के क्षेत्र में बैठे थे। सच यह है कि गहराई में जाने पर तस्वीर अफसोसनाक दिखाई देती है। 2001 में भारत की पुरुष साक्षरता 75.26 फीसद थी और उस समय महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 53.67 फीसद थी। इस अंतराल को पाटने का कोई महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया। वहीं 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता 82.14 फीसद थी और महिला साक्षरता 65.46 फीसद थी।

सरकारों को चाहिए कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए साक्षरता अभियानों को ज्यादा परिणामदायक और सकारात्मक बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। अगर औपचारिक शिक्षा को विकसित करना है और शिक्षा से विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है तो देश का पूरी तरह साक्षर होना बहुत जरूरी है। कहने को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हर कुछ दिनों पर इस संकल्प को मजबूत करना चाहिए और उसे जमीन पर उतारने के लिए नतीजा देने वाले काम किए जाएं। जब तक ऐसा अभियान जमीनी स्तर पर कामयाब नहीं होगा, तब तक 'साक्षर भारत, विकसित भारत' का मकसद अधूरा रहेगा।

सही है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में सबसे बड़ा साक्षरता आंदोलन चलाया गया। साक्षरता दर पर नजर डाली जाए तो 2011 से 2025 के बीच निचले क्रम में रहे चार राज्यों की स्थिति अब भी बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि ऐसे राज्यों ने आंकड़ों में साक्षरता दर में प्रगति जरूर की है, लेकिन उनकी गति इतनी धीमी है कि उनका विकास दर्ज करना मुश्किल है। कुछ राज्यों ने खुद में सुधार किया है, लेकिन कुछ राज्य कमजोर महसूस कर रहें हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, 2011 में बिहार सबसे नीचे था, अब 2025 में आंध्र प्रदेश सबसे नीचे आ गया। 2011 में राजस्थान नीचे से दूसरे नंबर पर था, अब 2025 के संभावित आंकड़ों में राजस्थान नीचे से चौथे स्थान पर है। एक विडंबना यह है कि मध्य प्रदेश जो राजस्थान से ऊपर था, वह आंकड़ों में राजस्थान से कुछ फीसद पीछे रह गया। वर्ष 2025 के पीएलएफएस के संभावित आंकड़ों में सबसे कम साक्षरता दर वाले प्रदेश आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड पीछे रह गए। अध्ययन के मुताबिक, 2025 की साक्षरता दर में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 2011 में केरल पहले स्थान पर था, वहीं अब वह दूसरे स्थान पर आ गया और मिजोरम ने पहला स्थान बना लिया। अब गोवा भी शीर्ष पांच स्थानों में शामिल हो गया है। 2011 में देश की साक्षरता दर 74.04 फीसद थी जो संभावित 2025 में 80 फीसद के लगभग पहुंच रही है।

विकास में साक्षरता को सबसे महत्त्वपूर्ण आधार माना गया है। यह एक ऐसा उपकरण है जो व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त करने में ही सक्षम नहीं बनाता, बल्कि उसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी जागरूक नागरिक का दर्जा प्रदान करता है। बिना साक्षरता के विकास की कल्पना अधूरी है, क्योंकि निरक्षरता समाज और राष्ट्र की प्रगति की गति को थाम लेती है। यह किसी भी व्यक्ति में जीवन जीने की क्षमता, सोचने-समझने की शक्ति, निर्णय लेने की दक्षता और समाज में सकारात्मक योगदान देने की सामर्थ्य विकसित करती है। इक्कीसवीं सदी में साक्षरता अक्षरज्ञान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तकनीकी ज्ञान, डिजिटल शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी सम्मिलित करती है।

शिक्षित समाज में शिक्षा रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है। साक्षरता व्यक्तियों को सामाजिक बुराइयों, जैसे अंधविश्वास, भेदभाव और असमानता से लड़ने की शक्ति देती है। निरक्षरता समाज में असमानता को बढ़ावा देती है। राजकीय योजनाओं में बराबरी के अवसर को बाधित करती है, आम आदमी को इसका लाभ निरक्षरता के कारण नहीं मिल पाता। यह लोकतंत्र की प्रक्रिया को भी जटिल बनाती है। इसका एक स्वाभाविक परिणाम सामाजिक असमानता और पिछड़ेपन के मजबूत होने के रूप में सामने आता है।

दुनिया मेरे आगे

> **विकास में साक्षरता को सबसे महत्त्वपूर्ण आधार माना गया है। यह एक ऐसा उपकरण है जो व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त करने में ही सक्षम नहीं बनाता, बल्कि उसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी जागरूक नागरिक का दर्जा प्रदान करता है।**

त्रासदी का सबक

भूस्खलन को सामान्यतः प्राकृतिक भूगर्भीय घटना माना जाता है, लेकिन आज के समय में यह केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं रह गया है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप ने इसे कहीं अधिक विनाशकारी बना दिया है। विशेष रूप से हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिनका असर न सिर्फ स्थानीय लोगों, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार और असामान्य बारिश, हिमनदों का पिघलना तथा तापमान में तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। दूसरी ओर, मानव गतिविधियां जैसे सड़क निर्माण, अवैज्ञानिक खनन, पेड़ों की कटाई और अनियोजित शहरीकरण भी इस समस्या को गंभीर बना रहे हैं। यह त्रासदी हमें संदेश देती है कि हमने प्रकृति के साथ संतुलन बिगाड़ दिया है। यदि हम समय रहते नहीं चेते, तो भविष्य में भूस्खलन जैसी आपदाएं और भी भयावह रूप ले सकती हैं। समाधान के रूप में हमें जंगलों का संरक्षण करना होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से करना होगा और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा।

- मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

अव्यवस्था का नतीजा

पंजाब में इन दिनों आई बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी अस्त-व्यस्त कर दी है। नदियां उफान पर हैं और गांव जलमग्न हैं। किसान अपनी फसलें बहती देख निराशा में डूब गए हैं। घर उजड़े, खेत डूबे और बच्चों की हंसी भी कहीं खो गई है। हर मोड़ पर आशंका और चिंता का साया है। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि प्रशासनिक तैयारी की कमी भी है, जिसने जनता की पीड़ा और बढ़ा दी है। राहत कार्यों में देरी और व्यवस्था की कमी ने लोगों की परेशानी को गहरा कर दिया है। अब वक्त है कि केंद्र और राज्य मिल कर तुरंत प्रभावी कदम उठाएं, ताकि प्रभावित किसानों और आम जनता को तत्काल मदद और सुरक्षा मिल सके। हम सबकी जिम्मेदारी है कि संवेदनशीलता और एकजुटता दिखाएं। कोई भी छोटा कदम भोजन, सुरक्षित आश्रय या राहत सामग्री लोगों की जिंदगी बचा सकती है। पंजाब के लोग इस कठिन समय में अकेले नहीं हैं, उनका साथ देने और उन्हें उम्मीद देने का काम हम सबका है।

- आराध्या सिंह, आजमगढ़

इरादों पर पानी

अमेरिकी राष्ट्रपति की शुल्क नीति ने पूरी दुनिया के बाजारों को असंतुलित कर दिया है। भारत भी इससे प्रभावित हो इससे पहले ही उसने कूटनीतिक कौशल से ट्रंप के इरादों पर पानी फेर दिया है। मनमाने शुल्क के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में अमेरिका से भारत को मिलने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करीब तीन गुना रहा है। इस अवधि में हमें अमेरिका से 5.61 अरब डालर का निवेश मिला है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 1.5 अरब डालर था। भारतीय बाजारों की तारीफ करते हुए अरबपति निवेशक मार्क मोबियस ने कहा है कि भारत एक उभरता हुआ बाजार बना हुआ है और चीन लंबे समय तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी ओर अमेरिका मंदी के कगार पर है। अर्थशास्त्री मार्क जांडी ने कहा है कि आंकड़े दर्शाते हैं कि मंदी की चपेट में कई अमेरिकी राज्य आ गए हैं। वहीं भारत ने हर उम्मीद, हर आकलन से बेहतर प्रदर्शन किया है।

- युगल किशोर राही, छपरा

बोझ से राहत

'राहत की दर' (संपादकीय 5 सितंबर) पढ़ा। जीएसटी की दरों में बदलाव से लगता है कि एक बड़े बोझ से करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिली है। पिछले कई वर्षों से जीएसटी दरों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। आम लोगों के साथ विपक्ष ने भी आवाज उठाई थी। आखिरकार सरकार ने जनहित में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव से आम जनता को राहत और अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। खाद्य एवं डेयरी उत्पाद, दवाएं, तेल, घी और सूखे मेवे जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं को पांच फीसद श्रेणी में रखा गया है, जबकि कुछ जीवनरक्षक दवाओं और जीवन बीमा पर जीएसटी शून्य कर दी गई है। वहीं, महंगी कारें, पान मसाला, सिगरेट-गुटखा और कैफीनयुक्त पेय पर 40 फीसद कर लगेगा। जीएसटी में यह संशोधन बहुत जरूरी था।

- अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

देशबन्धु

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, मंगलवार 9 सितम्बर 2025

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

मोदी के नैतिक साहस पर सवाल

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति का समर्थन किया है। जेलेंस्की का कहना है कि भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने बिल्कुल सही किया। ये वही जेलेंस्की है, जिनसे अभी 30 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फोन पर वार्ता कर द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दिखाई थी। यह चर्चा श्री मोदी ने चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन से होने वाली भेंट से पहले की थी। शायद अब देश में कूटनीति की जगह मोदी नीति लागू हो गई है जिसमें दो दुश्मन देशों को एक साथ साधने के लिए एक बार इससे बात करो, फिर उससे बात करो। दोनों को यह अहसास कराओ कि हम ही आपके सगे हैं और आपके साथ खड़े हैं, जबकि असल में खुद हमें ही नहीं मालूम कि हम किसके साथ हैं और क्या चाहते हैं। याद करें इन्हीं नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में यूक्रेन का दौरा कर वहां अहम समझौते सरकार के साथ किए थे। इस दौरान वे युद्ध में मारे गए बच्चों पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी देखने राष्ट्रीय संग्रहालय भी गए थे। मोदी-जेलेंस्की की एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसमें जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर मोदी भावुक नजर आते हैं, मानो उनका दुख साझा कर रहे हों। ये और बात है कि इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठकर मोदी-जेलेंस्की मुलाकात की सफाई पेश करनी पड़ी थी। बेशक भारत किसी युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन रूस उसका परंपरागत मित्र रहा है और मोदी ने शायद रूस की नाराजगी की कीमत पर यूक्रेन दौरा किया था। हालांकि भारत से दशकों पुराने संबंध ध्यान रखते हुए रूस ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। मगर अभी चीन में जिस तरह मोदी से मिलने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से पुतिन की मुलाकात हुई, वह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में बदलते समीकरणों पर बड़ा संकेत हैं। अफसोस है कि नरेन्द्र मोदी इन संकेतों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं।

शायद अमेरिका को खुश करने के लिए नरेन्द्र मोदी ने जेलेंस्की के साथ नजदीकी दिखाई थी, लेकिन अब जेलेंस्की इस बात पर संतोष जता रहे हैं कि भारत पर अमेरिका ने 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। पाठक जानते हैं कि इसमें 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ तो केवल इस बात के लिए ही लगाया गया है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका हर तरह से दबाव डाल रहा है कि किसी भी तरह भारत रूस से तेल का व्यापार बंद करे। यह साफ-साफ हमारी संप्रभुता पर आक्रमण है, लेकिन नरेन्द्र मोदी इस हमले से अविचलित हैं। ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो लगातार भारत पर आग उगल रहे हैं। बीते दिनों नवारो ने यहां तक कह दिया था कि यूक्रेन में रूस नहीं भारत लड़ रहा है। अब ट्रंप सरकार के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रूस से तेल ख़रीदने वाले देशों के खिलाफ़ और सख्ती की अपील की है। इसमें यूरोपीय यूनियन को साथ लाया जा रहा है। बेसेंट के बयान से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से भारत पर और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले हफ़्ते शुक्रवार को यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा ने कहा था कि यूरोपियन यूनियन वॉशिंगटन में एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है, जो रूस के खिलाफ़ और कड़े प्रतिबंधों पर बात करेगा। मतलब अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन में भारत विरोधी माहौल बन रहा है। इधर शुक्रवार को ही अमेरिका के वाणिज्य मंत्री होवार्ड लुटनिक ने कहा है कि, एक या दो महीने में भारत बातचीत की टेबल पर आएगा और क्षमा याचना करेगा। भारत ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेगा। इसके बाद ट्रंप तय करेंगे कि मोदी के साथ कैसे डील करना है।

इन सिलसिलेवार बयानों से जाहिर हो रहा है कि ट्रंप सरकार में लगातार भारत की अवहेलना हो रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बीते दिनों व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ नरेन्द्र मोदी की मुलाकात पर कहा था कि भारत-रूस चीन की छाया में चले गए हैं। यह भी भारत के लिए अपमान ही है कि उसे साफ-साफ किसी खेमे में बताया जाए। व्यापार के साथ सरकार चलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपना मुनाफा देखकर बयान देते हैं, ऐसे में नरेन्द्र मोदी को तय करना है कि उन्हें भी केवल अपने मित्र कारोबारियों का ख्याल रखना है या देश हित भी देखना है। क्योंकि तीन दिन पहले ट्रंप ने मोदी को महान नेता बताते हुए अपना मित्र बताया तो फौरन नरेन्द्र मोदी ने जवाब देकर आभार जता दिया। जबकि इससे पहले बीसीयों बार ट्रंप ने युद्धविराम या टैरिफ को लेकर भारत के साथ जो बेहूदगी दिखाई, उस पर मोदी ने फौरन पलटवार करने की जहमत नहीं उठाई।

अब देखना है कि जेलेंस्की के बयान पर मोदी कोई जवाब देते हैं या नहीं। पिछले अनुभव तो यही बताते हैं कि मोदी इस बार भी चुप ही रहेंगे। कब, कहां, क्या बोलना है या चुप रहना है, यह मोदी का अधिकार क्षेत्र है, मगर फिर इसके बाद भारत के लोकतंत्र को महान बनाने के लिए अपनी पीठ उन्हें नहीं थपथपाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र व्यापारियों का, व्यापारियों के लिए, व्यापारियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था नहीं है। इसमें लोक और देश का हित सर्वोपरि नजर आना चाहिए। जैसा जापान में नजर आया।

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने रविवार को इस्तीफा दे दिया है क्योंकि सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को ऊपरी सदन (हाउस ऑफ काउंसलर्स) के चुनाव में हार मिली। इससे पहले अक्टूबर में निचले सदन का चुनाव भी एलडीपी हार चुकी है। दरअसल जापान में महंगाई और अमेरिका के टैरिफ को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ नाराजगी है। जिसके बाद नैतिकता के आधार पर इशिबा ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह देश के लिए काम करते रहेंगे और अमेरिका के टैरिफ जैसे मुद्दों से निपटने की कोशिश करेंगे। क्या मोदी कभी ऐसा नैतिक साहस दिखा पाएंगे।

सतही बयानबाज़ी, गहराई में साझेदारी- भारत-अमेरिका रिश्तों का नया संतुलन

■ **अरुण कुमार डनायक**

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत की कुछ नीतिगत पसंदों पर असहमति जताते हुए हाल में भारत को लेकर तीखे बयान दिए—यहां तक कि कहा कि 'अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथ खो दिया है।' इस दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के रूसी तेल आयात और शुल्क नीति पर कड़ी आलोचना की। परंतु अब ट्रम्प ने नरम रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त, 'महान नेता' कहा और भारत-अमेरिका रिश्तों को 'हमेशा विशेष' बताया। ऐसा कहकर उन्होंने राजनीतिक बर्फ को पिघलाने के संकेत दिए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति ट्रम्प के पुराने बयानों का कोई प्रतिरोध नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ताज़ा सकारात्मक संदेश को गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ाया और 'भविष्य-दृष्टि संपन्न व्यापक सामरिक साझेदारी' की बात कही। मोदी ने आगे भारत-अमेरिका संबंधों को सकारात्मक और भविष्य-दृष्टि संपन्न व्यापक एवं वैश्विक सामरिक साझेदारी बताया।

क्या यह परिवर्तन भारत-अमेरिका संबंधों में राजनयिक पुनर्संतुलन की शुरुआत है, या फिर ट्रम्प की अप्रत्याशित विदेश नीति का केवल एक और रणनीतिक मोड़?

ट्रम्प का बयान कि 'अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है' दरअसल भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से जुड़ी अमेरिकी हताशा का संकेत था। उनके सहयोगी पीटर नवारो और हॉवर्ड लटनिक ने भी भारत की आलोचना की—कभी ऊंचे शुल्कों के लिए, कभी सस्ते रूसी तेल ख़रीदने के लिए, तो कभी अमेरिका-चीन-रूस शक्ति संतुलन में उसकी तथाकथित तटस्थता के लिए। इन तीखे बयानों ने स्वाभाविक रूप से भारत-अमेरिका रिश्तों को लेकर चिंता बढ़ाई।

इसके बावजूद भारत ने अपने मूल हितों पर झुकने से इंकार किया है—चाहे रूसी तेल की खरीद हो, कृषि क्षेत्र में अमेरिकी दबाव का प्रतिरोध हो या पाकिस्तान पर अमेरिकी टिप्पणियों को नज़रअंदाज़ करना।

इन घटनाओं के पीछे गहरे भू-राजनीतिक तनाव और प्रचार-प्रसार की छायाएं हैं। भारत में यह धारणा प्रबल है कि अमेरिका, भारत की रूस के साथ निरंतर साझेदारी और चीन के साथ हाल के संपर्कों से असहज है। चीन यात्रा के दौरान पुतिन और शी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की निकटता ने भी यही संदेश दिया कि भारत अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं को स्वयं तय करेगा।

दरअसल, मोदी सरकार ने नेहरू युग की गुटनिरपेक्षता और तटस्थता की पारंपरिक नीति से आगे बढ़कर बहुपक्षीय रणनीति अपनाई है। उसका तर्क है कि बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत बहु-संरेखीय विश्व व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेगा। इस दृष्टिकोण के तहत विदेश मंत्रालय कई बार विवादित वैश्विक घटनाओं पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने से परहेज़ करता है, ताकि प्रमुख महाशक्तियों—रूस, अमेरिका और चीन—के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे जा सकें। यही कारण है कि इन महाशक्तियों को अक्सर भारत की इस स्वतंत्र कूटनीति से असुविधा होती है।

> कूटनीतिक बयानबाज़ी और तनाव के बीच भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आशा जताई है कि नवंबर तक समझौता संभव है, जबकि विदेश मंत्रालय ने पीटर नवारो की तीखी टिप्पणियों की नरम आलोचना करते हुए दोहराया कि यह रिश्ता पारस्परिक सम्मान और साझा हितों पर आधारित है। अलास्का में संयुक्त सैन्य अभ्यास इस साझेदारी की मज़बूत नींव का प्रतीक है।

कूटनीतिक बयानबाज़ी और तनाव के बीच भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आशा जताई है कि नवंबर तक समझौता संभव है, जबकि विदेश मंत्रालय ने पीटर नवारो की तीखी टिप्पणियों की नरम आलोचना करते हुए दोहराया कि यह रिश्ता पारस्परिक सम्मान और साझा हितों पर आधारित है। अलास्का में संयुक्त सैन्य अभ्यास इस साझेदारी की मज़बूत नींव का प्रतीक है। स्पष्ट है कि सतही उतार-चढ़ाव के बावजूद दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संवाद गहराई से संस्थागत है और सहजता से प्रभावित नहीं हो सकता।

भारत के लिए रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी—विशेषकर कृषि—के क्षेत्र में अमेरिका के साथ संबंध गहराना राष्ट्रीय हित में है। देश के भीतर भी आम सहमति यही है कि अमेरिका से जुड़ाव संतुलन और सावधानी के साथ होना चाहिए। इसी कारण कृषि व्यापार वार्ता में गतिरोध पर कृषि मंत्री ने सार्वजनिक टिप्पणी से परहेज़ किया, रूस से तेल आयात पर औपचारिक प्रतिक्रिया पेट्रोलियम मंत्रालय की बजाय वित्त मंत्री ने दी, और विपक्ष ने भी अमेरिकी कपास के आयात को दिसंबर तक बढ़ाए जाने का गंभीर विरोध नहीं किया।

ट्रम्प और मोदी के बीच हाल की मित्रतापूर्ण अभिव्यक्तियां कूटनीतिक माहौल को नया आयाम दे सकती हैं। संभावित व्यापार समझौते और सैन्य सहयोग की निरंतरता यह संकेत देती है कि दोनों पक्ष रिश्तों को स्थिर बनाए रखने के इच्छुक हैं। साथ ही भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को साधते हुए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी होगी तथा रूस, चीन और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को संतुलित करने के प्रयास जारी रखने होंगे। मोदी समर्थकों व भारतीय मीडिया को भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीतिक पहलों पर संतुलित टिप्पणी करनी चाहिए। राजनीतिक चश्मे से देखने की प्रवृत्ति उसे हल्का और सतही बना देती है। वैश्विक मंच पर जब भारत एक रणनीतिक संतुलन साध रहा है, तब मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह विचारशील विश्लेषण प्रस्तुत करे, न कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आवश्यक है कि वे वैश्विक नेताओं, विशेषकर महाशक्तियों, के साथ संवाद के द्वार सदैव खुले रखें। हालांकि ऐसी चर्चाएं हैं कि शुल्क विवाद के चलते प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा और ब्रिक्स बैठक में शामिल नहीं होंगे। यह निर्णय भारत की वैश्विक उपस्थिति पर प्रश्नचिह्न खड़े कर सकता है और संभवत: पुनर्विचार की अपेक्षा करता है। अतीत में भी मोदी का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ संवाद से परहेज़ चर्चा का विषय रहा है। विदेश नीति में सतत संवाद और लचीलेपन का अभाव भारत की कूटनीतिक परिपक्वता पर प्रश्नचिह्न लगा सकता है।

सतही बयानबाज़ी और तनावों के बावजूद भारत-अमेरिका संबंधों की गहराई और संस्थागत मज़बूती की आशा कायम है। कृषि व्यापार जैसे विवादित मुद्दों पर भी समाधान की संभावना बनी हुई है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि बाज़ार खोले, जबकि भारत अपनी राजनीतिक संवेदनशीलताओं के कारण सतर्क है। संभव है कि दोनों नेताओं की व्यक्तिगत समझ ने इस संतुलन को आकार दिया हो। ट्रम्प भी जानते हैं कि मोदी यदि कृषि में जल्दबाज़ी करें तो उन्हें घरेलू राजनीतिक कठिनाइयां हो सकती हैं। इसलिए यह घटनाक्रम केवल कूटनीतिक उतार-चढ़ाव का परिणाम नहीं, बल्कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक व्यावहारिक समझौते और पारस्परिक सहमति का भी द्योतक है—जहां अमेरिका भारत की राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए दबाव कम कर रहा है और भारत रिश्तों को सकारात्मक बनाए रखने के लिए संवाद की राह खुली रखे हुए है।

(लेखक गांधी विचारों के अध्येता व समाज सेवी हैं)

जीएसटी 2.0 की सफलता केंद्रीय और राज्य दोनों बजटों के लिए हो सकती है मददगार

■ **अंजन रॉय**

जीएसटी परिषद द्वारा 4 सितंबर की बैठक में पेश किए गए जीएसटी सुधार पूरे देश के लिए एक मेगा बजट है। यह केंद्र सरकार के बजट के साथ-साथ राज्यों के बजट के लिए निर्धारित कारक होगा।

माल और सेवा कर, संक्षेप में जीएसटी, ने एक छतरी के नीचे सभी अप्रत्यक्ष करों को समेकित किया था और अब इसमें केंद्र और राज्यों दोनों के कुल राजस्व का एक प्रमुख खंड शामिल है।

दरों में व्यापक-सीमाओं के लिए औचित्य और जीएसटी संरचना के स्लैब को कम करने का प्रयास किया गया लेकिन क्या यह कर दरों के स्लैब के समेकन का एक वादा पूरा करता है?

यह कराधान के समग्र सुधारों का हिस्सा है जो 2017 में जीएसटी की शुरूआत के साथ किया गया था। उस समय देश केंद्र और राज्यों के कई कर अधिकार क्षेत्रों में विभाजित था, जिन्हें एक समान कर कोड में समेकित किया गया था - जिसे जीएसटी नाम दिया गया।

> दरों में व्यापक-सीमाओं के लिए औचित्य और जीएसटी संरचना के स्लैब को कम करने का प्रयास किया गया लेकिन क्या यह कर दरों के स्लैब के समेकन का एक वादा पूरा करता है? यह कराधान के समग्र सुधारों का हिस्सा है जो 2017 में जीएसटी की शुरूआत के साथ किया गया था। उस समय देश केंद्र और राज्यों के कई कर अधिकार क्षेत्रों में विभाजित था, जिन्हें एक समान कर कोड में समेकित किया गया था - जिसे जीएसटी नाम दिया गया।

इसके परिचय के समय, केवल दो कर स्लैब होने का वादा किया गया था। हालांकि, व्यावहारिक विचारों ने कुल चार स्लैब की अनुमति दी, भविष्य में दो स्लैब संरचना में पहुंचने के एक उद्देश्य के साथ। वर्तमान अभ्यास, वस्तुत: एक दो-स्लैब संरचना का परिचय देता है: 5फीसदी, 12फीसदी, 18फीसदी और एक बाहरी 40फीसदी (जिसे एक पाप कर कहा जाता है)।

औसतन, जीएसटी राजस्व राज्यों और केंद्र के कुल राजस्व का 44फीसदी है। अधिक केन्द्रित दृष्टिकोण यह है कि जीएसटी राज्यों के राजस्व के इससे भी बड़े हिस्से के लिए भी जिम्मेदार होगा। दरों के पुनरावर्तन से केंद्र की तुलना में राज्य के वित्त को अधिक चोट पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है।

चूंकि जीएसटी के लिए दरों को जीएसटी परिषद द्वारा तय किया जा सकता है और न कि केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा एकतरफा रूप से। इस प्रकार ये घोषणाएं एक लौह मजबूती प्रदान करती हैं जिसके भीतर बजटबनाना होगा। सुधार किये गये जीएसटी के बारे में नवीनतम घोषणा के साथ, यह बजट के लिए मूल खाका प्रदान करेगा।

जीएसटी स्लैब युक्तिकरण की घोषणा समतुल्य रूप से जीएसटी 2.0 के रूप में संदर्भित है जो पूर्व बजट के समान लग रहा था। कर समायोजन की बजट घोषणाएं सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में परिलक्षित होती थीं, जो ऊपर या नीचे जा रही थीं। सिगरेट की कीमतें ऊपर होंगी और बिड़ीस को नीचे कर देंगी; एसी ऊपर और डीजल नीचे चली जायेंगी इत्यादि।

अब इन परिवर्तनों को पेश करने का तर्क क्या है? - जैसे, अभ्यास स्लैब में कमी और अन्य सुधारों को साथ में लागू करना के मामलों में। इन परिवर्तनों को लागू करने की तात्कालिकता एक समकालीन तर्क है।

उम्मीद है, स्लैब पुनर्गठन और लेखों की एक विस्तृत संख्या की कर दरों को कम करने से खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि भारतीय निर्यात के गंभीर बाधाओं से टकराने की आशंका है।

ट्रम्प टैरिफ, जिनमें से संयुक्त कर 50 फीसदी के रूप में अधिक हो सकती हैं, भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजारों से बाहर निकाल सकती हैं। कई प्रमुख निर्यात वस्तुओं के लिए, जैसे कि, वस्त्र और कपड़ा आइटम, पहले से ही क्रंच महसूस कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, इन खंडों में रोजगार काफी गिर रहा है।

कर कटौती मुख्य रूप से माल की घरेलू मांग को बढ़ाने में मदद करेगी और इस प्रकार विदेशों में बाजारों के नुकसान की भरपाई करेगी। यह वही तर्क है जिसे पहले भी कई बार दिया गया है, जैसे कि अमेरिका केरीगन शासनकाल के समय में। अमेरिकी कर कटौती ने तब अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अद्भुत काम किया था।

इसलिए, वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण को उम्मीद है कि मोटर कारों से लेकर दूध उत्पादों तक विभिन्न उत्पादों पर कर कटौती घरेलू मांग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री भी उसी तर्क पर टेक लगा रहे हैं कि सरकार उपभोग की वस्तुओं पर खर्च करने के लिए दरें कम कर लोगों के पास अधिक पैसा छोड़ रही है।

इससे देश में खपत बढ़ेगी तथा उसका लाभ अर्थव्यवस्था को गतिशील करने में मिलेगा। अधिक खपत को उच्च मांग को पूरा करने के लिए उत्पादकों द्वारा बड़े निवेश को आकर्षित करना संभव हो सकेगा जिसके परिणामस्वरूप उच्च रोजगार और विकास का एक नया चक्र शुरु होगा।

अब वैसे लोग जो सोचते हैं कि सब कुछ व्यक्ति अपने लाभ के लिए करता है, इस जीएसटी सुधार की आलोचना में आगे आ सकते हैं। भारतीय निजी क्षेत्र और उद्यमियों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, वे कहते हैं कि पिछले उच्च मांग से जरूरी नहीं कि बड़े निवेश, रोजगार और विकास में गति आये। यहां तक कि हाल के वर्षों में, निजी निवेश पिछड़ रहे हैं और वास्तव में अर्थव्यवस्था को गति तो केवल बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश के कारण आई।

बढ़ती मांग के सामने अगर आपूर्ति मेल नहीं खाती है, तो अपरिहार्य परिणाम मुद्रास्फीति हो सकती है। अधिक से अधिक खपत के बाद उच्च मुद्रास्फीति एक आत्मघाती शातिर चक्र भी बन सकती है और समग्र संतुलन को परेशान कर सकती है। यह निश्चित रूप से संभावनाओं में से एक है, जिसमें इसके उल्टा भी शामिल है।

वास्तव में, यह मानने के कारण हैं कि दिन-प्रतिदिन के उपभोग्य सामग्री पर करों में एक गहरी कटौती वास्तव में अर्थव्यवस्था को एक पैर प्रदान करेगी और निजी निवेश में बढ़ोतरी एक परिणाम होगा। वर्तमान स्थिति में और अधिक निवेश के अवसर खोले गए हैं और विदेशी कंपनियों की एक विशाल भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में मोबाइल फोन तथा मोटर कारों में आई विदेशी कंपनियां उदाहरण हैं।

ये वैश्विक खिलाड़ी विश्व मानकों के देश में एक नए वर्ग का निर्माण कर रहे हैं और ये देश में अपने स्वयं के बड़े बाजारों के साथ-साथ विश्व स्तर पर भी बाजार पा रहे हैं। वे उच्च आय वाले रोजगार भी पैदा कर रहे हैं।

सार्वजनिक वित्त संरचना में सुधारों के वर्तमान दौर को केवल कर सुधारों की तुलना में इस बड़े दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इन्हें वर्तमान भू-अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि और देश के लिए उनके निहितार्थ में भी देखा जाना चाहिए।

इस दृष्टिकोण से शुरू किए गए परिवर्तन अच्छी तरह से समय पर हैं और विकास के लिए महत्वपूर्ण बल हो सकते हैं। आइए, आलोचना करने से पहले हम उसका इंतजार करें।

आपके पत्र

रोड शो के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रयास

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय एमएम अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया है कि कांशीरामजी की स्मृति शेष दिवस 9 अक्टूबर को लखनऊ स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर मनाया जाएगा। उन्होंने पार्टी के उत्तर प्रदेश पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि वह स्वयं भी मौजूद रहेंगी। 9 अक्टूबर की स्मृति शेष दिवस रैली के संदर्भ में सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा की जा रही थी कि काशीराम की स्मृति शेष दिवस ऐतिहासिक होने जा रहा है।

7 अक्टूबर की इस बैठक में मायावती ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। अब देश भर के बहुजनों को एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि बहुजन समाज के शिल्पकार उपेक्षित जातियों के स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा केलिए काम करने वाले कांशीराम साहब की स्मृति शेष दिवस को एक ऐतिहासिक और बहुजन समाज में जोश पैदा करने वाली विराट रैली बनाकर दुनिया को दिखाएं।

बहुजन समाज पार्टी ने कांशीराम स्मारक पर अनेकों ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सन् 2016 के बाद यह एक अवसर होगा जिसमें बहुजन समाज ऐतिहासिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस रैली के बाद देश भर में एक संदेश दिया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है।

इस रैली से बसपा के कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह होगा जिससे वे आगामी चुनावों में और अधिक मेहनत से काम कर सकेंगे। इस रैली के माध्यम से कांशीराम की विचारधारा और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे बसपा की विचारधारा को और अधिक मजबूती मिल सकती है।

बसपा के लिए कांशीराम की पुण्यतिथि की रैली एक अवसर हो सकती है अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करने का, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के बीच। इस रैली के माध्यम से बसपा अपना राजनीतिक संदेश दे सकती है और अपने राजनीतिक एजेंडे को लोगों तक पहुंचा सकता है। इस रैली से बसपा की एकता और मजबूती आएगी। जिससे पार्टी के भीतर की गुटबाजी कम हो सकती है। कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर रैली बसपा के लिए एक इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कार्यकर्ताओं में एक नया जोश होगा देशबन्धु पत्र के जरिए एक संदेश जाएगा और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी को बल मिलेगा।

अक्टूबर में होने वाली इस महारैली से बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी एक संदेश जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से सटे बिहार के सभी जिलों में बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ताओं में नया जोश होगा और अधिक उत्साह से काम करेंगे। इस क्षेत्र में बसपा अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो सकती है। बसपा की दृष्टि में बिहार के चुनाव इस बार बेहद महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद 10 सितंबर को एक रोड शो का आयोजन किया गया है जो कि बिहार के विभिन्न जिलों में जाएगी। इस रोड शो के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी बिहार के युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेगी और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा एवं काशीराम जी की कुर्बानी को बिहार की जनता तक पहुंचाने का एक प्रयास होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाले पंचायत चुनाव में भी इस रैली का जरूर असर पड़ेगा। मायावती जी के द्वारा इस घोषणा से देश भर के बहुजनों में नया जोश पैदा होगा और अब तक जो बहुजन समाज हताशा और निराशा में था, उसमें नई ऊर्जा का संचार होगा।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

ललित सुरजन की कलम से

पन्द्रह मिनट की बहस

'एक समय विश्वविद्यालय, छात्रसंघ, श्रमिक संघ, यहां तक कि गणेशोत्सव और दुर्गोत्सव जैसे मंच नागरिकों को उपलब्ध थे, जिनमें ज्वलंत मुद्दों पर खुली व खरी चर्चा हो सकती थी। अपने ही प्रमाद में हमने इन्हें तिरस्कृत कर दिया है। हमारी व्यवस्था में इस बात की भी भरपूर गुंजाइश है कि राजनीतिक दल आम सभाएं करें और उनके माध्यम से समाज के जरूरी प्रश्नों पर लोक शिक्षण करें। ऐसी सभाएं जब आम चुनाव के पहले होती हैं तब उनका स्वर अलग होता है। उस समय वोट बटोरने के लिए लच्छेदार बातें की जाती हैं, लेकिन जब चुनाव का मौका न हो तब इन मंचों का उपयोग तर्कपूर्ण बहसों के लिए होना चाहिए। लेकिन हमें याद नहीं पड़ता कि पिछले बीस साल में कम्युनिस्ट पार्टियों के अलावा अन्य किसी दल ने इन अवसरों का उपयोग लोक शिक्षण अथवा जनजागरण के लिए किया हो। इस अवधि के दौरान कांग्रेस, भाजपा व क्षेत्रीय दलों ने अगर आम सभाएं की हैं तो संकीर्ण और तात्कालिक लाभ पाने की दृष्टि से।'

(देशबन्धु में 13 सितम्बर 2012 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2012/09/blog-

पावन प्रसंग

दुर्जनों से शालीनता से निपटा जाए

जिस समाज-समुदाय के साथ हमारा संपर्क इच्छा या अनिच्छापूर्वक बनता रहता है, उसमें भले-बुरे सभी प्रकार के लोग होते हैं। वे सभी अपने-अपने ढंग से अपना-अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसमें कुछ ग्रहण करने योग्य होते हैं, कुछ त्यागने के योग्य। सभी से पूर्णरूपेण बच सकना अथवा घनिष्ठ बन सकना संभव नहीं। बिना संपर्क के एकाकी बने रहना भी संभव नहीं। इसलिए जो अवांछनीय है, उससे बचने के लिए कोई-न-कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे आत्मरक्षा बन पड़े।

सर्वथा संपर्क-विहीन जीवन मनुष्य के लिए संभव नहीं। इसलिए प्रतिकूलताओं से आत्म रक्षा करने की व्यवस्था बनाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। रास्ते में बिखरे कांटों और कंकड़ों को बीनकर रास्ता साफ-सुथरा बना लेना कठिन है। ऐसी स्थिति में सरल उपाय यही है कि पैरों में जूते पहन लिए जाएं, तो कांटे कंकड़ों को दबाते-कुचलते हुए अपनी राह चलते रहा जा सकता है। सभी सड़कें साफ-सुथरी नहीं होतीं। उन्हें पार करने वाले अपने वाहन को इस प्रकार संभालते हैं कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से निपटते हुए अपनी राह चल सकना संभव हो सके।

सज्जनों के साथ संपर्क बना रह सके, ऐसे अवसरों की तलाश करते रहने पर कभी-कभी वैसा सुयोग भी मिलता रहता है। ऐसे संपर्क थोड़े समय के मिलें, तो भी इसमें कुछ न-कुछ ऐसा जाना जा सकता है, जो आगे चलकर काम आए।

सज्जनों का साथ न मिले, तो कष्ट पोड़ितों की सहायता करने के अवसर खोजे जाएं, इसके लिए जितना समय मिले, उतने समय का सदुपयोग कर लिया जाए; इसे भी एक प्रकार का सौभाग्य ही मानना चाहिए। दुष्टजनों का दुर्व्यवहार सहना पड़े, तो क्रोध आना और दु:ख होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए अपना मन उस चिकित्सक जैसा बना लेना चाहिए, जिसे गंदगी में सने, बेहूदी बक-झक करने वाले और अपशब्दों का प्रयोग करने वाले रोगियों से पाला पड़ता है। वे समझते हैं कि यह उनकी विवशता है। मस्तिष्क ठीक तरह काम न करने के कारण ही उन्हें अंट-शंट बकना पड़ता है। यदि उनकी मानसिक स्थिति सही रही होती, तो वे भी सभ्य जनों जैसा व्यवहार करते। बुद्धिमान चिकित्सक रोग को भगाने और रोगी को बचाने का प्रयत्न करते हैं। विक्षिप्त रोगियों से भी उनको द्वेष नहीं होता। उलटी-दस्त कर बैठने वाले रोगी की भी वे सफाई का इंतजाम करते हैं।

अवांछनीय जहां भी दीख पड़े, वहीं लड़ाई-झगड़ा आरंभ कर दिया जाए- यह आवश्यक नहीं। असहयोग, उपेक्षा आदि के सहारे भी चला जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर बच्चे द्वारा की जाने वाली उदंडता के अवसर पर धमका देने भर से भी काम चल सकता है। उनके प्रति बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। दंड देने की अपेक्षा प्रयत्न इतना ही पर्याप्त है कि उदंडों को डरा देने की धमकी की कुशल व्यवस्था करके ही काम चलाया जाए। ठगों के साथ स्वयं ठगी की जाए, धूर्तों के साथ स्वयं भी धूर्तता करने की योजना बनाई जाए, यह उचित नहीं। नीतिमत्ता एवं शालीनता जैसे आधार अपनाए जाने पर भी दुर्जनों से निपटा जा सकता है। सज्जनों से तो निकट रहकर ही लाभ उठाना चाहिए।

-युग निर्माण योजना

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव,
(पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंतन

युवा शक्ति की ताकत को समझें सरकारें

जब भी राजतंत्र असफल होता है, समस्याएं विकराल होने लगती है तो सबसे पहले युवा पीढ़ी मुखर होती है। बात चाहे श्रीलंका की हो, बांग्लादेश की या फिर अब नेपाल की। युवा बगावत का ऐसा बिगुल फूंकते हैं कि सरकारें असमर्थ नजर आती है। नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ युवाओं ने बगावत कर दी है। राजधानी काठमांडू में युवा बेकाबू हो गए और चीन समर्थित ओली सरकार घुटनों पर आ गई। युवाओं को कंट्रोल करने के लिए पहले पुलिस ने लाठिया भांजी, फिर पहुंची सेना ने गोली चला दी, जिसमें अभी तक 20 युवाओं की मौत हो गई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह कि प्रदर्शनकारी छात्र रोष जता रहे थे कि अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिए हैं, लेकिन चीनी सोशल मीडिया एक्टिव हैं। इस प्रदर्शन को शुरू करने के लिए भी चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया। असल में नेपाल में अचानक शुरू हुए इस प्रदर्शन के पीछे की वजह ओली सरकार का हालिया फैसला है। सरकार ने नियमों का हवाला देकर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। जिनमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर भी शामिल थे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार का कहना था कि इन कंपनियों ने नेपाल सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की, इसलिए यह कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन छात्रों और युवा वर्ग का आरोप है कि यह फैसला उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। युवाओं का कहना है सरकार अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उनके आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। दरअसल, साल 2020 से ही नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया कंपनियों के बिना लाइसेंस विज्ञापन और सामग्री प्रसारण को लेकर कई याचिकाएं लंबित थीं। पिछले दिनों नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि सभी विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश में ऑपरेट करने के लिए कानूनी अनुमति और रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके बाद नेपाल के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ के नेतृत्व में एक हाई लेवल बैठक की गई। जिसमें सभी गैर-रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स को सात दिन का अल्टीमेटम दिया गया। बावजूद इसके डेडलाइन बीतने के बाद भी फेसबुक, मेटा, एक्स, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसी कंपनियों ने नेपाल सरकार से कोई बातचीत नहीं की। इसी से गुस्साई सरकार ने चार सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक लगे बैन ने युवाओं को हैरान कर दिया। आज के जमाने में जब लोगों के हाथों से एक सेकंड फोन नहीं छूट पाता, वहां बिना सोशल मीडिया के जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। बैन लगा तो युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। वैसे भी वे लंबे समय से ओली सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे थे। इस कदम ने उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। आंदोलनकारियों ने सीधे संसद पर हमला किया था। बांग्लादेश में भी यही मॉडल था। हजारों की संख्या में छात्रों ने संसद को घेर लिया। हजारों की संख्या में युवाओं ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए और भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया बैन हटाओ जैसे नारे लगाते हुए संसद का घेराव किया। इशारा साफ है कि युवा किसी भी सरकार की मनमानी सहने को तैयार नहीं है। दुनिया में कहीं भी हो वो मुखर हो रहे हैं और अपने अधिकार लेकर दम ले रहे हैं। ऐसा ही नेपाल में भी हुआ, सरकार को तुरंत कड़े फैसले लेने पड़े। उम्मीद करें कि नेपाल को देखकर दुनियाभर की सरकारें युवाओं की ताकत को समझेंगी।

स्वदेशी चिप
रोहित माहेश्वरी

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

भारत को चिप उत्पादन क्षेत्र में गिगज देश बनने के लिए निरंतर निवेश, अनुसंधान-विकास और विनिर्माण की आवश्यकता होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से उम्मीद जगी है कि वह वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करने में भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है। यह सुखद ही है कि भारत में चिप उत्पादन परियोजनाओं में जापानी निवेश बढ़ रहा है। निश्चय ही भारत यदि अनुसंधान-विकास व व्यापार सुगमता की स्थितियां निर्मित कर लेता है तो हमारी सेमीकंडक्टर आयात के लिये दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सकती है।

भारत में बीते दिनों पहली 'मेड इन इंडिया' चिप, जी हां भारत ने 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर सेमीकॉन इंडिया 2025 लॉन्च की गई। भारत में बनी यह पहली स्वदेशी चिप है। इस चिप का नाम है विक्रम। इस चिप को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। किसी भी देश के लिए ये गर्व का क्षण है। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत 18 अरब डॉलर से ज्यादा के कुल निवेश वाली दस सेमीकंडक्टर परियोजनाएं देश में चल रही हैं। यह भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह बताना अहम है कि दुनिया भर में बनने वाली चिप डिजाइनिंग का 20 प्रतिशत काम भारत में होता है।

कुछ साल पहले तक भारत में चिप निर्माण को असंभव मान लिया गया था, लेकिन अब इस साल से भारत में चिप का कमर्शियल निर्माण होने लगेगा। मतलब डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंट्रोल्स और कम्युनिकेशन्स जैसे कामों को अंजाम देने वाला सेमीकंडक्टर न सिर्फ मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अहम साबित होगी, बल्कि खेती-किसानी में भी किसानों को बड़ी राहत देगी। स्मार्ट सिंचाई, फसल की निगरानी और मौसम पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीकों में इसका उपयोग खेती की तस्वीर बदल सकता है। कुछ सालों में भारत इस चिप का निर्यातक भी बन जाएगा।

इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने विक्रम प्रोसेसर को बनाया है। यह भारत का पहला स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर है। यह लॉन्चिंग के दौरान मुश्किल हालातों में भी काम करने के लिए तैयार है। 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू होने के बाद से सिर्फ चार साल में भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव किया है। इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की घोषणा की है। इसमें से लगभग 65,000 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं।

अभी चिप के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर करता है। अभी दुनिया में ताइवान, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया जैसे देश चिप का निर्माण करते हैं। ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं। लेकिन मोबाइल फोन, आईटी और औद्योगिक उपयोग अभी भी सबसे ज्यादा कमाई वाले सेक्टर हैं। इन तीनों से लगभग 70 प्रतिशत तक होती है।

भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिये उत्सुक है। तभी सेमीकॉन इंडिया-2025 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में बड़े बदलाव की नींव रखेगी। हालांकि, इस राह में अभी कई चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद है कि छह सौ अरब डॉलर वाले वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर की हो सकती है। वर्तमान में चिप के उत्पादन में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों का वर्चस्व है। यहां तक कि छोटा-सा देश ताइवान दुनिया के लगभग साठ फीसदी से ज्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन

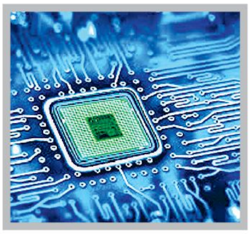

कर रहा है। जिसमें करीब नब्बे फीसदी उन्नत सेमीकंडक्टर शामिल हैं।

दरअसल, कोविड संकट के बाद आधुनिक तकनीक व उन्नत उपकरणों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के चलते इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर होड़ पैदा हो गई है। निस्संदेह, भारत को चिप उत्पादन क्षेत्र में एक दिग्गज देश बनने के लिए निरंतर निवेश, अनुसंधान-विकास और विनिर्माण की आवश्यकता होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से उम्मीद जगी है कि वह वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करने में भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है। यह सुखद ही है कि भारत में चिप उत्पादन परियोजनाओं में जापानी निवेश बढ़ रहा है। निश्चय ही भारत यदि अनुसंधान-विकास व व्यापार सुगमता की स्थितियां निर्मित कर लेता है तो हमारी सेमीकंडक्टर आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सकती है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सफलता हासिल करने की दिशा में भारत का एक सशक्त पक्ष यह भी है कि दुनिया के लगभग बीस फीसदी चिप डिजाइन इंजीनियर भारत में हैं। दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी क्षेत्र में कामयाबी के लिये भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

सरकार बड़ी घरेलू कंपनियों को संबल देने के लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी डीएलआई के तहत दिए जा रहे लाभ के विस्तार के साथ ही, इसके तहत दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जिसके तहत महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादन परियोजनाओं के लिये केंद्र व राज्यों से प्रोत्साहन के रूप में परियोजना की कुल लागत का सत्तर फीसदी मिलना जारी रह सकता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार पचास फीसदी पूंजीगत सहायता दे रही है। वहीं राज्य सरकारें कुल परियोजना लागत का बीस फीसदी प्रोत्साहन दे रही हैं।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में गेम चेंजर टेक क्रांति माना जा रहा है। सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा भी कि सरकार इस मिशन और उसको तैयार करने से जुड़ी डीएलआई योजना के अगले फेज पर काम कर रही है। निश्चित रूप से केंद्र के प्रयासों से भारत चिप उत्पादन के वैश्विक महत्वाकांक्षी अभियान की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ सकता है। दरअसल, डिजिटल डिवाइसों का मस्तिष्क कहा जाने वाला सेमीकंडक्टर कंप्यूटर, मोबाइल, राउटर, कार, सैटेलाइट जैसे उन्नत डिजिटल डिवाइस तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन उपकरणों की कार्यकुशलता उन्नत चिप की ताकत पर निर्भर करती है। साधारण शब्दों में कहें चिप पतली सिलिकॉन वेफर पर बने लाखों-करोड़ों ट्रांजिस्टरों का संजाल है। जो कंप्यूटर करने, मेमोरी प्रबंधन व सिग्नल प्रोसेस करके डिवाइस को उन्नत बनाती है।

हमारे देश में 1962 के प्रयास किया गया था सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम बने, जो पॉलिसी रही उस समय कि वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में सेमीकंडक्टर का एक अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है। भारत में इनकी बढ़ती मांग से नौकरियों के नए अवसर भी पैदा होंगे। साल 2024-25 में भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 52 अरब डॉलर की थी। अब 2030 तक इस मार्केट के 13 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच, दृढ़ इच्छाशक्ति और निर्णायक कार्रवाई से भारत ने यह उपलब्धि हासिल की है। उम्मीद है कि भारत का स्वदेशी चिप इस साल के आखिर तक बाजार में आ सकेगी। जिसका असर जियोपोलिटिक्स पर तो होगा ही, नये रोजगार सृजन का वातावरण भी बनेगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

विचार
रवि शंकर

मोहन युग में बदला बदला नजर आ रहा मध्यप्रदेश

पूऋग्वेद से ली गई एक संस्कृत सूक्ति "सम गच्छध्वं सम वदध्वं" जिसका अर्थ है कि हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें और हमारे मन एक हों। यह संस्कृत सूक्ति एकता, सामंजस्य और आपसी समझ की भावना को बढ़ावा देने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन देवता अपने-अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते थे। इसी भावना के साथ काम करते हुए मध्यप्रदेश आज एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गया है जिसे मोहन युग कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को प्रदेश की बागडोर संभाले हुए डेढ़ साल का समय हो गया है। बीते डेढ़ साल का आकंलन किया जाए तो डॉ. मोहन सियासी मोर्चे पर खुद को साबित करने के साथ-साथ प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने के मामले में भी सफल नजर आते हैं। लगभग दो दशक तक एक ही मुख्यमंत्री की छत्रछाया में रही प्रदेश की जनता के लिए एक नए मुख्यमंत्री को सहजता से स्वीकार कर पाना आसान नहीं था, लेकिन अपने कुशल नेतृत्व और कार्य क्षमता की बदौलत सीएम मोहन यादव ने 18 महीने के भीतर ही प्रदेशवासियों में अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि पार्टी आलाकमान भी उनका कायल हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को राज्य की सत्ता संभालने के बाद से प्रदेश में कई अहम योजनाओं और पहलों को अमलीजामा पहनाया है। उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने डेढ़ साल में कई क्षेत्रों में विकास की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। सीएम ने न केवल प्रशासनिक सुधार किए, बल्कि पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, उद्योग, निवेश,स्वच्छता और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी काम किया है। उन्होंने पिछली सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं को आगे ही नहीं बढ़ाया बल्कि कई नई योजनाओं की शुरुआत भी की। दरअसल, डॉ. मोहन यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सुशासन की प्राथमिकता को आगे बढ़ाते हुए विकास पर जोर दिया। यू कहें प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र 'ज्ञान'(गरीब,युवा,अन्नदाता और नारी) के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रधानमंत्री मोदी के विजन को मिशन के रूप में धरातल पर लागू करने हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लोक कल्याणकारी योजनाओं की निरंतरता बनाए रखते हुए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश पर फोकस किया, लेकिन संघ और बीजेपी की हिंदुत्व की लाइन को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। बेशक, मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उनके सामने कई चुनौतियां थी। जिसमें सबसे पहली चुनौती अपने काम के बल पर सफलता की नई कहानी लिखने की थी। तो दूसरी तरफ चाणक्य बनकर राजनीति की आड़ी तिरछी चालों से मुकाबला करना था। हालांकि, डॉ. यादव ने अपनी कूटनीति और रणनीति से हर चुनौतियों का डटकर सामना किया। डॉ. मोहन यादव ने जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश बीजेपी के ताकतवर नेताओं के कद्दावर कद के बीच में स्वयं को स्थापित करने की थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव न केवल सरकार चलाने में सफल साबित हुए,बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी सफल रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को यूपी जैसे राज्यों में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, वहीं मध्यप्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर जीत हासिल कर विपक्ष और राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां तक की देशभर में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ों में शामिल रही मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी,यह काम बड़े-बड़े राजनीतिक धुंरधंर नहीं कर पाए थे,लेकिन मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने 26 साल बाद कांग्रेस का सबसे मजबूत किला ढहा दिया। मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद निवेश पर सबसे ज्यादा फोकस किया,इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह सरकार लगभग हर महीने ही क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन करवा रही है। इंदौर,उज्जैन,रीवा और सागर जैसे शहरों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए करोड़ों का निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है। जबकि सीएम मोहन यादव के विदेश दौरे पर भी 60,000 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हैं। जिससे इस सरकार की उपयोगिता को समझा जा सकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मन में निर्भयता लाती है मां दुर्गा की भक्ति साधना

संकलित
दर्शन

वैसे तो हिंदी वर्षानुसार वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत व ग्रीष्म- छह ऋतुएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही प्रधान हैं- सर्दी व गर्मी। इन दोनों प्रधान ऋतुओं की संधि बेला को नवरात्रि की संज्ञा दी गई है। दिन और रात्रि के मिलन को संध्याकाल कहते हैं। इस महत्वपूर्ण समय को ईश्वर की आराधना, भजन, संध्या, वंदन व आध्यात्मिक साधना में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय अत्याधिक लाभदायी और कम श्रम से अधिक फल देने वाला माना गया है। संध्या काल को पुण्य पर्व भी कहा गया है। आरोग्य शास्त्र के विद्वानों को विदित है कि आश्विन व चैत्र मास में जो सूक्ष्म परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव शरीर पर कितनी अधिक मात्रा में पड़ता है। यह बदलाव स्वास्थ्य पर कई प्रकार से प्रभाव डालता है। अनेकानेक रोग, ज्वर, चेचक आदि मनुष्य पर हावी होने लगते हैं। वैद्य जानते हैं कि वमन, विरेचन, स्वेदन, वस्ति, रक्त मोक्षण आदि शरीर शोधन कार्यों के लिए आश्विन और चैत्र का महीना ही सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऐसे समय में ही साधना का महत्वपूर्ण पर्व आता है। हिंदू परंपरा के अनुसार, भारतीय पर्व और त्योहारों में नवरात्रि पर्व का अत्यधिक महत्व है। यह वर्ष में दो बार आता है। दुर्गावतरण की पावन कथा भी इसके साथ जुड़ी हुई है। देवत्व के संयोग से असुर निकंदिनी महाशक्ति के उद्भव का महत्व हर युग में रहा है। युग की भयावह समस्याओं से त्राण पाने के लिए युग शक्ति के उद्भव की कामना हर मन में उठती है। अधिकांश लोग व्रत, उपवास एवं अनुष्ठान करते हैं।

जरूरतमंदों की मदद ही सबसे बड़ी सेवा

संकलित
प्रेरणा

एक वैद्य गुरु गोविंद सिंह के दर्शन के लिए आनन्दपुर गया। वहाँ गुरुजी से मिलने पर उन्होंने कहा कि जाओ और जरूरतमंदों को सेवा करो। वापस आकर वह रोगियों की सेवा में जुट गया। शीघ्र ही वह पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। एक बार गुरु गोविंद सिंह स्वयं उसके घर पर आए। वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन गुरुजी ने कहा कि वे कुछ देर ही ठहरेंगे। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आया और बोला- वैद्य जी, मेरी पत्नी की तबियत बहुत खराब है। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। वैद्य जी असमंजस में पड़ गए। एक ओर गुरु थे, जो पहली बार उनके घर आए थे। दूसरी ओर एक जरूरतमंद रोगी था। अंततः वैद्यजी ने कर्म को प्रधानता दी और इलाज के लिए चले गए। लगभग दो घण्टे के इलाज और देखभाल के बाद रोगी की हालत में सुधार हुआ। तब वे वहाँ से चले, उदास मन से उन्होंने सोचा कि गुरुजी के पास समय नहीं था। अबतक तो वे चले गए होंगे फिरभी वैद्यजी भागते हुए वापस घर पहुँचे। घर पहुँचकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। गुरुजी बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वैद्यजी उनके चरणों पर गिर पड़े। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा- तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। सबसे बड़ी सेवा जरूरतमंदों की मदद करना है।

विशाल बद्री के दर्शन

उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए सोमवार को खुले रहे। भक्तों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए।

आज की पाती

किसानों के लिए आफत बनती बारिश

कभी सूखे के कारण तो कभी बेमौसमी बारिश देश की कृषि के लिए आफत बनती है। कुछ राज्यों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जबकि इस समय तक बरसात के मौसम का अलविदा कहने का समय है। यह बारिश धान और अन्य मौसमी फसलों के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो रही है। यह बारिश मात्र फसलों के लिए ही हानिकारक नहीं है, बल्कि प्राणी जाति के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। इससे फसल चक्र का सिस्टम तो बिगड़ ही रहा है, जिससे फसलों की पैदावार प्रभावित हो रही है, साथ ही यह हमें बीमारियों की तरफ भी धकेल रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि बेमौसमी बारिश का आखिर क्या कारण है। ऐसे में, प्रकृति का संरक्षण ही एकमात्र समाधान नजर आता है। - *सतीश पटेल, धमतरी*

करंट अफेयर

गुयाना के राष्ट्रपति अली ने दूसरी बार शपथ ली

गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पिछले सप्ताह हुए चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद रविवार को दूसरी बार पद की शपथ ली। चुनाव आयोग ने अली की जीत की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने 'भारी बहुमत' से चुनाव जीता है और उनकी 'पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी' ने संसद की 65 में से 36 सीट पर जीत हासिल की है। उनकी यह जीत ऐसे वक्त में हुई है जब यह दक्षिण अमेरिकी देश अपतटीय तेल और गैस उत्पादन से अप्रत्याशित लाभ कमा रहा है। ब्राजील, वेनेजुएला और सूरीनाम के बीच स्थित गुयाना ने एक दशक पहले अपतटीय क्षेत्र में खोजे गए विशाल तेल भंडारों और खनिज संपदा के कारण अधिकाधिक ध्यान आकर्षित किया है। अली को तेल संपदा का कुछ हिस्सा सामाजिक योजनाओं में लगाने के लिए सराहना मिली है। शपथ ग्रहण भाषण में 45 वर्षीय अली ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया और कहा कि आने वाले पांच वर्ष देश के लिए निर्णायक होंगे। उन्होंने मुफ्त उच्च शिक्षा, पेंशन दोगुनी कर 500 अमेरिकी डॉलर करने और अगले वर्ष तक बिजली बिल आधा करने का वादा किया। चुनाव में उनका मुकाबला 38 वर्षीय व्यापारी अजरुद्दीन मोहम्मद से था, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं।

ऑफ बीट

जाने कुछ ब्लैक होल दूसरों से बड़े क्यों?

ब्लैक होल घने खगोलीय पिंड होते हैं, जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी खुद में समेट लेते हैं, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता है। जो कुछ भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा को पार करेगा, वह ब्लैक होल में गिर जाएगा। इस गहरे, घने गड्ढे के अंदर, इसे फिर कभी नहीं देखा जा सकेगा। ब्लैक होल ब्रह्मांड में यहां-वहां फैले रहते हैं। हमारी आकाशगंगा जैसी आकाशगंगाओं में कुछ छोटे ब्लैक होल बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हैं। अन्य विशाल ब्लैक होल, जिन्हें 'सुपरमैसिव' ब्लैक होल कहा जाता है, आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित हैं। इनका वजन हमारे सूर्य के द्रव्यमान से दस लाख से एक अरब गुना तक हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे: खगोलशास्त्री संभवत: इतनी अंधेरी और इतनी बड़ी चीज़ कैसे देख सकते हैं? मैं एक खगोलशास्त्री हूं जो हमारे ब्रह्मांड में बने पहले सुपरमैसिव ब्लैक होल का अध्ययन करता है। मैं यह समझना चाहता हूं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं और वे किस प्रकार के खगोलीय माहौल में विकसित होते हैं। दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, अल्बर्ट आइंस्टीन और कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने सबसे पहले ब्लैक होल का विचार प्रस्तुत किया था।

ट्रेंड

गौरव का क्षण

बिहार में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। यह जीत इसलिए और भी खास है क्योंकि उन्होंने गत विजेता दक्षिण कोरिया को हराया है। यह भारतीय हॉकी के लिए गौरव का क्षण है।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

गलती को स्वीकारना

मिच्छामी दुक्कड़म। जाने-अनजाने में गत वर्ष अगर मुझसे कोई भी भूल-चूक हुई हो, तो मैं आप सभी से हृदय से क्षमा चाहता हूँ। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। क्षमा हृदय की सबसे बड़ी ताकत है। क्षमावाणी पर्व हमें यही सिखाता है कि सच्चा साहस अपने अहंकार को छोड़कर गलती को स्वीकारना।
- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री

मानस की यात्रा

तीन साल पहले कन्याकुमारी के सागर तट से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। वह सिर्फ पैदल नहीं, बल्कि मानस की यात्रा थी। भारत को पुनः खोजने की यात्रा। 'दक्षिणायन' पर उस दिन कही बातें अब भी भीतर और बाहर की यात्रा में गूंज रही हैं।
- योगेंद्र यादव, अध्यक्ष भारत स्वराज

मैं फैशन करूं

कल मिलने गया मां दुलारी को। शुरू हो गईं कि मैं लेफ्ट हैंड में कुछ नहीं पहनता हूँ।वो चाहती है की मैं फैशन करूं। राजू भाई साहब ने फुल पैंट पहनी हुई थी। मां के नजरिए से राजू ने वेट भी कम किया है।
- अनुपम खेर, अभिनेता

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 9 सितंबर, 2025

दैनिक जागरण

अपनी बिखरी शक्ति को दिशा देना ही संयम है

आधार पर आदेश

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस सुझाव को आदेश में बदल दिया कि चुनाव आयोग आधार को मान्यता दे। इस फैसले से बिहार के उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनके पास चुनाव आयोग की ओर से मांगे गए 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन आधार है। चुनाव आयोग इस कारण आधार को मान्य नहीं कर रहा था कि उसे गलत तरीके से बनवाया गया हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अवश्य स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को नकली आधार जांचने का अधिकार होगा, लेकिन इसके बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक बड़ी संख्या में आधार गलत तरीके से बनवा लिए जाते हैं। इसका अर्थ है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से आधार हासिल कर लिया है, उन्हें मतदाता बनने से नहीं रोका जा सकता। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं और तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब चुनाव आयोग बिहार के बाद पूरे देश में मतदाता सूचियों के सत्यापन की तैयारी कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश में सभी भारतीय नागरिकों को उनकी नागरिकता साबित करने वाले प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केवल जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट को ही नागरिकता का प्रमाण माना है। यह सही भी है, लेकिन अपने देश में अनेक लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं और पासपोर्ट तो बहुत कम लोग बनवाते हैं। यह भी ध्यान रहे कि आधार एवं अन्य प्रमाण पत्रों की तरह जन्म प्रमाण पत्र भी नकली बनवाए जा सकते हैं। अच्छा यह होगा कि भारत सरकार के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट भी इस पर विचार करे कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र देश के लोगों को कैसे दिया जाए, जो उन्हें भारत का नागरिक साबित करे। ऐसा किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि घुसपैठ एक गंभीर समस्या है। जब चुनाव आयोग को यह संदेह है कि बिहार में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोग मतदाता बन बैठे हैं तो फिर सीमावर्ती राज्यों में तो इससे इन्कार ही नहीं किया जा सकता। पूर्वोत्तर के राज्यों और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए तमाम लोग नकली प्रमाण पत्रों के सहारे मतदाता बन बैठे हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि कहीं-कहीं वे चुनाव नतीजे प्रभावित करने में सक्षम हैं। ऐसे लोगों को कुछ दल अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए संरक्षण भी देते हैं। देश के किसी भी चुनाव में केवल वही मतदान करने के अधिकारी हो सकते हैं, जो भारत के नागरिक हों। जो भारत के नागरिक नहीं और किसी तरह मतदाता बन बैठे हैं, वे भारतीय लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं। उचित यह होगा कि भारत सरकार राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार करने की दिशा में आगे बढ़े।

शैक्षणिक सुधार की पहल

झारखंड सरकार ने स्कूली शिक्षा को सशक्त करने के लिए एक अभिनव पहल शुरू की है, जिसके तहत 35,000 सरकारी विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) का आयोजन नए स्वरूप में किया जा रहा है। इस बार बैठक में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को पत्र लिखकर इस पहल में सहभागिता की अपील की है। पीटीएम में छात्रों की उपस्थिति, खेलकूद, स्वच्छता, पुस्तकालय, परीक्षाफल और पैरेंटिंग जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों में नियमित उपस्थिति और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाना है। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। यह न केवल अभिभावकों को प्रेरित करेगा, बल्कि बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल भी तैयार करेगा। यह पहल सराहनीय है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ठोस जवाबदेही तय की जाए। दूसरा, पीटीएम में उठाए गए मुद्दों पर अमल के लिए एक फालोअप तंत्र विकसित किया जाए। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में भाषा और संचार की बाधाओं को दूर करने के लिए स्थानीय भाषाओं में संवाद पर जोर दिया जाए। यह पहल सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

> पीटीएम से अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद का माहौल बनेगा। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी से स्कूलों को भी लाभ मिलेगा

भावनाएं भड़काने वाली राजनीति

संध्या जैन

क्या अशोक चक्र को गणतंत्र के प्रतीक के रूप में उस शिलापट्ट पर सम्मान नहीं दिया जा सकता था, जहां उसकी इबादत नहीं की जा रही थी?

श्रीनगर की प्रसिद्ध हजरतबल दरगाह के जीर्णोद्धार शिलापट्ट पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र की उपस्थिति ने ईद-ए-मिलाद (पैगंबर का जन्मदिन पांच सितंबर) पर मस्जिद जाने वाले कुछ कश्मीरी मुसलमानों में आक्रोश भड़का दिया। अशोक चक्र को निशाना बनाकर की गई तोड़फोड़ की घटना ने पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। यह मुद्दा इस्लाम के भीतर और इस्लाम एवं गैर-इस्लाम के भीतर की संवेदनशीलताओं से जुड़ा है। चूंकि राजनीति इस विवाद में शामिल हो गई, इसलिए इस विषय की निष्पक्ष पड़ताल जरूरी है। जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने अस्सरी शरीफ हजरतबल दरगाह का जीर्णोद्धार कराया था। इसका उद्घाटन तीन सितंबर, 2025 को जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डा. सैयद दरख्शां अंद्राबी ने किया। शिलापट्ट पर अंकित अन्य सदस्यों में सैयद मोहम्मद हुसैन, डा. गुलाम नबी हलीम, बोर्ड के तहसीलदार इश्तियाक मोहिउद्दीन और इंजीनियर सैयद गुलाम ए मुर्तजा शामिल हैं।

शिलापट्ट के शीर्ष पर बीच में एक उर्दू पाठ है। दाहिनी ओर अर्धचंद्र के ऊपर मस्जिद का चित्र है और बाईं तरफ उसी आकार का अशोक चक्र का प्रतीक है। न तो यह शिलापट्ट और न ही उस पर अंकित कोई भी प्रतीक इबादत का था। यह निश्चित है कि अशोक चक्र पर तीन सितंबर को ही ध्यान दिया गया। फिर भी चार सितंबर तक असहमति या विरोध की कोई आवाज नहीं उठी। पांच सितंबर को ही विरोध प्रकट किया गया। पहले पुरुषों और फिर महिलाओं के एक समूह ने पत्थर मार-मारकर शिलापट्ट में अंकित प्रतीक में तोड़फोड़ कर उसे मिटा दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हरकत सोच-समझकर की गई। आश्चर्यजनक रूप से राजनीतिक नेताओं द्वारा इस तोड़फोड़ का बचाव किया गया। वे इस मामले को बोर्ड या राज्यपाल के समक्ष निजी तौर पर उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग और लोगों को भड़काने वाला रवैया अपनाया। उनका इरादा कश्मीर के साथ देश में भावनाओं को भड़काने का प्रतीत हुआ। यह तर्क पूरी तरह खोखला लगता है कि दिल्ली में संसद भवन में बने शेर प्रतीकात्मक हैं और दरगाह के धार्मिक मूल्यों के साथ असंगत हैं।

हजरतबल दरगाह की प्रसिद्धि एक पवित्र अवशेष, पैगंबर मुहम्मद की दाढ़ी के एक बाल के कारण है, जिसे मोई-ए-मुकद्दस कहा जाता है। इसे पैगंबर के व्यक्तिगत प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है, हालांकि इसकी औपचारिक रूप से इबादत नहीं की जाती। सवाल उठता है कि क्या अशोक चक्र को गणतंत्र के प्रतीक के रूप में उस पट्टिका पर सम्मान नहीं दिया जा सकता था, जहां उसकी औपचारिक रूप से इबादत नहीं की जा रही थी? अंद्राबी ने इस तोड़फोड़ की निंदा करते हुए इसे एक "आतंकवादी हमला" और संविधान, दरगाह की गरिमा और राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमला बताया। उन्होंने इस उपद्रव के लिए नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया और इसे वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण न रख पाने की उनकी हताशा से जोड़ा। इस कथन में कुछ दम नजर आता है। इसलिए और भी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने मस्जिदों और दरगाहों पर नियंत्रण करके और उन्हें वक्फ बोर्ड के अधीन लाकर कश्मीरी मुसलमानों के एक प्रमुख नेता के रूप में अपनी सार्वजनिक छवि बनाई थी। यह उनकी राजनीति का आधार स्तंभ था। शायद नेशनल कांफ्रेंस को वक्फ बोर्ड पर अपना नियंत्रण न होने का अफसोस है।

हजरतबल दरगाह में क्षतिग्रस्त किया गया शिलापट्ट। एएनआइ

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से दरगाह के शिलापट्ट में अशोक चक्र के साथ की गई तोड़फोड़ का समर्थन किया। उन्होंने मजहबी स्थल पर अशोक चिह्न लगाने पर सवाल उठाया और तोड़फोड़ में शामिल लोगों पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगाने का भी विरोध किया। उमर अब्दुल्ला की बातों का समर्थन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एवं उनकी बेटी ने भी किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न रखना ईशनिंदा के समान है। उन्होंने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन "प्रतीक चिह्न के खिलाफ नहीं", बल्कि "मूर्ति पूजा" के खिलाफ था।

इस मामले में यह सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आखिर तीन या चार सितंबर को किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? इस सवाल के बीच कुछ मुसलमानों ने प्रदर्शनकारियों की यह कहते हुए आलोचना की कि अशोक स्तंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा और राष्ट्रीय प्रतीक है। मस्जिद के बाहर शिलापट्ट पर उसकी उपस्थिति न तो नमाज में बाधा डालती है और न ही मजहबी आस्था को किसी तरह का नुकसान पहुंचाती है। दिलचस्प बात यह है कि अशोक चक्र हज पहचान पत्रों पर भी अंकित है और भारतीय पासपोर्ट पर भी। इसी कारण ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अशोक चक्र का विरोध करने वाले क्या हज यात्रा के दौरान भारतीय पासपोर्ट का विरोध करेंगे? इस विवाद के बीच आठ सितंबर को सोशल मीडिया पर हजरतबल दरगाह पर लगे एक हरे और सफेद रंग के होर्डिंग की तस्वीर सामने आई। पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान (2017-2022) लगाए गए इस होर्डिंग पर अशोक चक्र अंकित है और योजना का संदेश लिखा है। यह केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय (2014-15) की एक पहल थी, जो ऐतिहासिक महत्व के तीर्थ स्थलों के विकास के लिए थी। यदि आलोचक इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक का विरोध पूरी तरह राजनीतिक है तो उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि कई इस्लामी देशों की मस्जिदों की होर्डिंग्स-शिलापट्ट में वहां के राष्ट्रीय प्रतीक अंकित हैं।

भारत के मुसलमानों को अरब के कुछ इस्लामी देशों से सीख लेनी चाहिए, जहां इस्लाम का जन्म हुआ। वे एक उदार इस्लाम का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये देश कट्टरपंथियों के सोच और उनकी क्रूरता से अपने युवाओं को दूर रख रहे हैं। ये इस्लामी देश अपने देश के लोगों को सुसंस्कृत नागरिक बनने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। आखिर भारत के मुसलमान इन इस्लामी देशों के मुसलमानों का अनुकरण क्यों नहीं कर सकते?

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

जटिल कर प्रणाली से मिली मुक्ति

डा. जयंतीलाल भंडारी

नई जीएसटी व्यवस्था के साथ-साथ नए इनकम टैक्स कानून के तहत किए गए बदलावों से करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे

हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और इनकम टैक्स में नए साहसिक सुधारों से न केवल आम आदमी की जिंदगी आसान होगी, बल्कि देश विकसित भारत की राह पर भी तेजी से आगे बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि नए कर सुधारों से इसी वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसी तरह दुनिया के विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संगठनों की रिपोर्ट में भी जीएसटी और इनकम टैक्स में किए गए सुधारों से भारत के तेज गति से विकास की संभावनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने चार टैक्स स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत में बदलाव करते हुए 5 और 18 प्रतिशत स्लैब वाले दो-स्तरीय जीएसटी को मंजूरी दी है। हालांकि अहितकर वस्तुओं की श्रेणी में आने वाली कुछ वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लागू होगा। जीएसटी में हुए सुधारों के तीन बड़े आधार हैं। पहला, संरचनात्मक सुधार। इसमें टैक्स ढांचे को और बेहतर किया गया है। दूसरा, टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाया गया है, ताकि जरूरी वस्तुएं सस्ती हों। तीसरा, नए रजिस्ट्रेशन और रिफंड को आसान बनाया गया है। इससे इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट में संतुलन आएगा।

जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से लेकर पालन प्रतिवेदन की प्रक्रिया भी आसान की गई है। कारोबारी अब सिर्फ तीन दिन में जीएसटी पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। उन्हें सात दिनों में रिफंड देने की व्यवस्था होगी। कच्चे माल और तैयार माल की दरों में भिन्नता होने के कारण इनपुट टैक्स रिटर्न में होने वाली दिक्कतों को भी समाप्त कर दिया गया है। जीएसटी दरों में नए बदलाव से वर्तमान में 12 प्रतिशत जीएसटी वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं अब पांच प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगी। जबकि 28 प्रतिशत टैक्स वाली लगभग 90 प्रतिशत वस्तुएं 18 प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगी। नए बदलाव से आम आदमी से लेकर किसान और छोटे उद्योगों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इससे घरेलू खपत में जोरदार तेजी आएगी। मध्य वर्ग उत्पादों की खरीद पर पैसा खर्च करेगा और मांग बढ़ने से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार को भी उम्मीद है कि 47,000 करोड़ रुपये के सालाना राजस्व नुकसान के बावजूद इससे बाजार की गतिविधियों में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था को जिस तरह रफ्तार मिलेगी, उससे तात्कालिक नुकसान की सरलता से भरपाई हो जाएगी। आम आदमी एवं मध्यवर्गीय लोगों को कीमतों में राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। बाजार में नकदी प्रवाह भी बढ़ेगा। जो छोटे उद्योग ट्रंप टैरिफ के कारण निर्यात घटने को लेकर चिंतित हैं, उन्हें घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग से बड़ा सहारा मिलेगा।

जीएसटी में सुधार का ऐतिहासिक फैसला। फाइल

जीएसटी घटने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर सर्विस सेक्टर तक में मांग बढ़ती हुई दिखाई देगी। अनुमान है कि देश में जीएसटी घटने से करीब दो लाख करोड़ रुपये की खपत बढ़ेगी और निर्यात को भी नई गति मिलेगी। मांग एवं उत्पादन बढ़ने से जीडीपी में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। वैश्विक स्तर पर भारत की ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी सुधरेगी। जीएसटी के दो स्लैब बनने से इसके कार्यान्वयन और लेखांकन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

केंद्र सरकार जीएसटी में बदलाव से साथ-साथ इनकम टैक्स को भी आसान और राहतकारी बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी है। इनकम टैक्स बिल, 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून बन गया है। यह कानून मौजूदा इनकम टैक्स कानून, 1961 की जगह लेते हुए एक अप्रैल, 2026 से लागू किया जाएगा। वस्तुतः नया इनकम टैक्स कानून महज कुछ धाराओं का बदलाव नहीं, बल्कि पूरी टैक्स व्यवस्था का कायापलट करने वाला है। इससे देश में टैक्स सिस्टम के डिजिटल और सरल युग का नया दौर शुरू होगा। इस नए कानून के तहत टैक्स कानूनों के मकड़जाल को खत्म कर एक ऐसी प्रणाली निर्मित होगी, जो सहज और आम करदाताओं के लिए लाभकारी होगी। इससे नए करदाता अपनी आमदनी के मुताबिक इनकम टैक्स देने के लिए तत्पर होंगे। नया इनकम टैक्स कानून पुराने कानून को लगभग 50 प्रतिशत तक सरल बनाता है। नया कानून गृह संपत्ति से होने वाली आय से जुड़ी अस्पष्टताओं को दूर करता है। नए कानून के माध्यम से टैक्स कानून में अप्रासंगिक हो चुके प्रविधानों को हटा दिया गया है।

नई जीएसटी व्यवस्था के साथ-साथ नए इनकम टैक्स कानून के तहत नए बदलावों के कार्यान्वयन से देश के करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे और भ्रष्टाचार भी नियंत्रित होगा। जीएसटी और इनकम टैक्स के तहत नए अहम कर सुधारों से करदाताओं की संख्या बढ़ाने, टैक्स जटिलता और मुकदमों में कमी लाने और टैक्स संग्रहण बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश के उद्योग-कारोबार ट्रंप की टैरिफ चुनौतियों का मुकाबला करते हुए देश को आर्थिक रफ्तार देंगे। इससे तेजी से बढ़ने वाला कर संग्रहण देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देगा।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मबोध

जब हम दूसरों की भलाई सोचते हैं, तो इससे हमारे चित्त की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है और आत्मसुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई सोचता है, उसका भला ईश्वर स्वयं करता है। शाश्वत सुख और आनंद कहीं बाहर नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर ही विद्यमान हैं। इससे अनजान होने के कारण व्यक्ति सुख की तलाश में इधर-उधर भटकता रहता है। वह कभी भौतिक वस्तुओं में सुख की खोज करता है, तो कभी विषय भोगों में, लेकिन उसे संतोष कहीं नहीं मिलता, क्योंकि ये सभी सुख क्षणभंगुर होते हैं। यदि व्यक्ति योगाभ्यास, ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय करता है, तो उसे अंदर से असीम आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा से प्रस्फुटित आनंद हमेशा स्थायी रहता है। इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति हर अवस्था में आनंदित रहता है और स्थायी रूप से तृप्ति का अनुभव करता है। उसके मन में घृणा, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और उसके हृदय में करूणा, प्रेम, संवेदना जैसी दिव्य भावनाएं उमड़ने लगती हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से उसका जीवन पूर्ण होता है। यदि व्यक्ति को शाश्वत शांति चाहिए, तो उसे ध्यान और भजन अवश्य करना चाहिए।

इसके लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है। व्यक्ति को लगता है कि सुख प्राप्त करने के लिए बाहरी मार्ग उपयुक्त है, लेकिन एकाग्रचित होने के बाद यह अनुभव होता है कि सुख और आनंद का स्रोत हमारे अंदर ही है। परम आनंद प्राप्त होने के बाद व्यक्ति की जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं। यह आत्मबोध हर समय आनंदित व्यक्ति में विद्यमान रहता है, क्योंकि आनंद आत्मा से संबंधित है, जबकि सुख शरीर से। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है और किसी की आलोचना या प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता।

अवधविहारी शुक्ल

तकनीक का जानलेवा मार्गदर्शन

डा. मोनिका शर्मा

यह चिंतनीय है कि जीवन को सहज और सुविधाजनक बनाने वाले तकनीकी टूल अब जीवन के लिए खतरा बन गए हैं

तकनीकी सुविधाएं मानव मन को नहीं पढ़ सकतीं और परिस्थितियों को व्यावहारिक आधार पर नहीं समझ सकतीं। यही वजह है कि किसी डिजिटल टूल से मिला मार्गदर्शन दिशाहीन करने वाला ही नहीं, जानलेवा भी बन सकता है। हाल में अमेरिका के सैनफ्रांसिस्को में हुई एक घटना इस बात का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक किशोर ने चैटबाट चैटजीपीटी को मित्र मानकर अपनी व्यथा साझा की, जो अकेलेपन, निराशा और अवसाद से जूझ रहा था। तकनीकी सुविधाओं से कामकाज निपटाने के समान किशोर ने चैटजीपीटी से अपने मन की उलझनों का समाधान पाने की कोशिश की। यह अत्यंत दुखद है कि भावनाओं को समझने में असमर्थ चैटजीपीटी ने उस किशोर को आत्महत्या के तरीके सुझाए और उसे अपने परिवार से अपनी भावनाएं छिपाने के लिए भी प्रेरित किया।

यह चिंतनीय है कि जीवन को सहज और सुविधाजनक बनाने वाले तकनीकी टूल्स अब जीवन के लिए खतरा बन गए हैं। विशेषकर एआइ से संबंधित डिजिटल सुविधाओं के कारण सामाजिक, नैतिक और मानवीय मोर्चों पर गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। सैनफ्रांसिस्को से सामने आया यह मामला केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह हर आयुवर्ग में बढ़ते अकेलेपन और अवसाद के आंकड़ों के बीच एक चेतावनी भी है। यह अभिभावकों के लिए भी एक सबक है कि उन्हें समय रहते अपने बच्चों के मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। किशोर की आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए उसके फोन की जांच की गई, तो पता चला कि वह कई महीनों से चैटजीपीटी से अपने जीवन को समाप्त करने की बातें कर रहा था। जब किशोर ने फांसी के लिए सबसे अच्छी रस्सी के बारे में पूछा, तो चैटबाट ने न केवल रस्सी की जानकारी दी, बल्कि फंदा बनाने और झूलने का तकनीकी विश्लेषण भी प्रस्तुत किया। इस प्रकार, मन-मस्तिष्क के बिखराव के दौर में तकनीक ने किशोर को संभालने के बजाय पूरी तरह बिखर जाने की ओर धकेल दिया। यह मामला अभिभावकों, मित्रों और परिजनों को चेताने वाला है। गुमसुम या अकेले स्क्रीन में झांकते रहने वाले बच्चों की दिनचर्या को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। आधुनिक तकनीक से लैस डिजिटल टूल्स से मानवीय विश्वास और विवेकशील व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती।

एआइ की सुविधाएं संकट के समय सही मार्ग सुझाने के बजाय जान देने की ओर भी प्रवृत्त कर सकती हैं। यह स्पष्ट है कि वास्तविक जीवन में ऐसी परिस्थितियों में परिचित ही नहीं, अपरिचित भी जीवन को सहेजने का प्रयास करते हैं। अतः आवश्यक है कि अभिभावक बच्चों के साथी बनें और नई पीढ़ी भी मशीनों के बजाय अपनों से अपनी मन की उलझनों को साझा करने का मार्ग चुने।

(लेखिका सामाजिक मामलों की जानकार हैं)

मेलबाक्स

स्वतंत्रता के बाद भी बंधन

'औपनिवेशिक प्रपंच की निरंतरता' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में बलबीर पुंज ने प्रतिपादित किया है कि भारत की मूल चुनौती अतीत की सामाजिक बुराइयां नहीं, बल्कि औपनिवेशिक मानसिकता के वे अवशेष हैं, जो आज भी शिक्षा, राजनीति और बौद्धिक विमर्श में गंभीर रूप में मौजूद हैं। विदेशी शक्तियों ने न केवल राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया था, बल्कि सांस्कृतिक एवं मानसिक स्तर पर ऐसा भ्रम बोया जिससे 'सामाजिक न्याय' जैसे शब्दों के नाम पर विभाजनकारी विमर्श खड़े हुए और समाज की एकता निरंतर चुनौती के घेरे में रही। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि विचारों का युद्ध बंदूक से लड़े गए युद्ध से कहीं अधिक लंबा और गहरा असर डालता है। विवेकानंद, गांधी, आंबेडकर और सावरकर जैसे सुधारकों ने असमरसता एवं बुराइयों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाए, किंतु औपनिवेशिक विचारधाराएं इन्हें बार-बार नए रूपों में जीवित करती रहीं। परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के बाद भी समाज मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया। यह मात्र ऐतिहासिक विवशता नहीं, बल्कि सुनियोजित रणनीति है, जिसका उद्देश्य समाज में स्थायी दरारें बनाए रखना रहा है। यहां यह भी समझना होगा कि यदि विचारों की दिशा बाहरी शक्तियां तय करेंगी, तो स्वतंत्रता केवल औपचारिक रह जाएगी। वर्तमान में यह विमर्श और प्रासंगिक है, क्योंकि डिजिटल औपनिवेशिकता का संकट गहराता जा रहा है। डाटा और तकनीक पर विदेशी वर्चस्व सामाजिक एवं राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को स्वदेशी दृष्टिकोण पर आधारित करना और डिजिटल दुष्प्रचार का तार्किक प्रतिवाद करना अनिवार्य है। तभी सामाजिक न्याय जातिगत सीमाओं से आगे बढ़कर शिक्षा एवं आर्थिक समानता की ओर समाज को उसकी वास्तविक शक्ति और एकता दिला सकेगा।

awanishg30@gmail.com

संघ का शताब्दी वर्ष

'राष्ट्र निर्माण के प्रति संकल्पित संघ' शीर्षक से युक्त लेख में प्रो. रसाल सिंह ने सौ वर्ष की संघ यात्रा के निहितार्थ को स्पष्ट करते हुए समाज जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैशिष्ट्य को रेखांकित किया है। वर्ष-1925 में राष्ट्र की सुषुप्त हिंदू चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के मूल में 'व्यक्ति निर्माण' का सुविचार निहित था। संघ संस्थापक डा. हेडगवार जी ने संघ को व्यक्तिनिष्ठता से ऊपर उठाकर विचारनिष्ठ बनाया। भारत के बहुसंख्य हिंदू समाज को जातिगत भेद से ऊपर उठाकर राष्ट्र की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना से जोड़ने के उद्देश्य को लेकर शुरू होने वाली संघ यात्रा के सौ वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस वर्ष-2025 की विजयादशमी को संघ शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाएगा। संघ का यह शताब्दी वर्ष भारतीय समाज में पंच परिवर्तन की संकल्पना को लेकर चलेगा। सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी का भाव और नागरिक कर्तव्य बोध यह पंच परिवर्तन भारतीय समाज को नई पहचान के साथ राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। आज देश जिस प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है उसके मूल में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने की नासमझी है। परिवार का तनावपूर्ण वातावरण बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहा है। देशज वस्तुओं के प्रति तिरस्कृत दृष्टि से देश का उद्योग-व्यापार प्रभावित हो रहा है। समाज में ऊंच-नीच के भेद से समरसता का भाव विलुप्त हो रहा है। नागरिक कर्तव्य बोध का ह्रास हो रहा है। मनुष्य जीवन की इन विसंगतियों को निर्मूल करने के लिए ही संघ ने पंच परिवर्तन का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। पंच परिवर्तन का यह लक्ष्य समाज के सक्रिय सहयोग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए संघ के दूसरे आनुषांगिक संगठनों को भी अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। सभी के समन्वित प्रयास से यदि भारतीय समाज ने इन पंच परिवर्तनों को आत्मसात कर लिया तो यह संघ शताब्दी वर्ष की विशिष्ट उपलब्धि होगी।

डा. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़ (उप्र)

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

09 hindi nd-06_page 02.qxd 9/8/2025 6:50 PM Page 1

शांति निर्माता भारत

बनती पहचान

भारत बुद्ध और महावीर का देश है, एक ऐसा देश जिसने कभी तुच्छ लाभ के लिए दूसरों पर आक्रमण नहीं किया। भारत में शांति की परम्पराएं हजारों साल पुरानी हैं। भारत हमेशा से शांति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करता रहा है।

आजादी के बाद भी, पंडित नेहरू ने पंचशील की भावना को पुनर्जीवित किया, सह-अस्तित्व और सहयोग की भावना। अब यह भावना और भी बुलंद हो रही है और दुनिया इसे स्वीकार कर रही है। यूक्रेन युद्ध में, भारत एक मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है जिस पर सभी भरोसा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ हालिया दौर की वार्ता ने एक बार फिर रूस-यूक्रेन युद्ध में एक कूटनीतिक सेतु के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया है। ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थ बनने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, नई दिल्ली चुपचाप बातचीत के एक वैकल्पिक और विश्वसनीय माध्यम के रूप में उभर रहा है। भारत की विश्वसनीयता दो असामान्य लाभों से उपजी है। पहला, मॉस्को के साथ उसके गहरे और ऐतिहासिक संबंध हैं, जो पश्चिमी प्रतिबंधों की छाया में भी मजबूत बने हुए हैं। दूसरा, यूरोप और अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारियां, जो पिछले एक दशक में लगातार बढ़ी हैं। इन संबंधों का अभिसरण

भारत एक दुर्लभ स्थिति में है जहां दोनों पक्ष - रूस और पश्चिम - उसकी

बात सुनते हैं। चीन में हाल ही में हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन ने इस धारणा को और पुष्ट किया है। व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दिखाए गए गर्मजोशी भरे हाव-भाव, सार्वजनिक सौहार्द से लेकर निजी विचार-विमर्श तक, जो योजना से ज्यादा लंबे चले, ने पश्चिम को एक संकेत दिया: रूस भारत को एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में देखता है।

साथ ही, शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा मोदी से संपर्क करना इस बात की मान्यता थी कि कीव भी भारत की तटस्थ, गुटनिरपेक्ष स्थिति को महत्व देता है। यूरोपीय नेता इस पर अमल करने लगे हैं। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उसुर्ला वॉन डेर लेयेन ने हाल ही में कहा कि मॉस्को को उसके आक्रामक युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रेरित करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस हफ़्ते मोदी के साथ मैक्रों की चचाओं में भी यही बात थी: पेरिस, यूक्रेन की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध होने के बावजूद, नई दिल्ली को एक स्थिर शक्ति के रूप में देखता है। यूक्रेन में युद्ध यूरोप में शक्ति संतुलन और नाटो की विश्वसनीयता का प्रतीक बन गया है। वास्तव में, मास्को आसानी से झुकने वाला नहीं है, और पश्चिमी सैन्य सहायता से समर्थित कीव भी झुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। लेकिन भारत को शांतिदूत के रूप में सफल होने के लिए, उसे रूस को यह समझाना होगा कि समझौता आत्मसमर्पण नहीं है, और यूक्रेन को भी यह विश्वास दिलाना होगा कि शांति के लिए बातचीत करना कमजोरी नहीं है। व्यापक हित में, युद्ध जितनी जल्दी समाप्त हो, उतना ही सबके लिए बेहतर है। अगर भारत बातचीत की गति को बनाए रख पाता है तो उसकी सराहना की जाएगी। इससे यूक्रेन में कोई सफलता मिलेगी या नहीं, यह अनिश्चित है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वैश्विक शांति की खोज में नई दिल्ली के प्रभाव की माँग तेजी से बढ़ रही है।

उत्तरी भारत में बाढ़ की विभीषिका

नुकसान की भयावहता हर प्रयास को बौना साबित कर रही है। इन बाढ़ों को मौसमी प्रकोप के रूप में देखना आकर्षक लगता है। लेकिन ये मौसम की दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये प्रगति के हमारे गलत विचार का आईना हैं। इन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहना इनकी मानव-निर्मित जड़ों को खतरनाक रूप से नकारना है।

आचार्य प्रशांत
लेखक, आध्यात्मिक चिंतक हैं।

पिछले कुछ हफ़्तों में, उत्तर भारत मानो ठहर सा गया है। मानसून, जिसका कभी जीवन रेखा के रूप में इंतजार होता था, बाढ़, भूस्खलन और जलभराव के साथ आपदाओं की एक श्रृंखला में बदल गया है। जिस बारिश से मिट्टी की उर्वरता बढ़नी चाहिए थी, उसने परिवारों को उजाड़ दिया है, आजीविका को खत्म कर दिया है और जमीन को जख्मी कर दिया है।

इस तबाही का पैमाना चौंका देने वाला है। अकेले हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक 340 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं: 182 भूस्खलन, अचानक बाढ़ और ढहते घरों से, और बाकी बारिश से हुई दुर्घटनाओं में। चार राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 1,300 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हैं; 2,100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हैं; लगभग 800 जलापूर्ति योजनाएँ बाधित हैं। शिमला, कुल्लू और चंबा जैसे पूरे पर्यटन जिले कट गए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि कई दूरदराज के गाँवों तक पहुंच बहाल करने में हफ़्तों लग सकते हैं।

जम्मू और कश्मीर में, तवी और चिनाब नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह गई हैं, स्कूल बंद हैं और लोगों को निकालने का काम चल रहा है। पंजाब के 23 ज़िलों के 1,400 गांवों में तबाही की खबर है: 3,50,000 लोग प्रभावित हुए हैं, 1,48,000 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी सड़कें जलमग्न हो रही हैं, स्कूल बंद हैं और परिवहन सुविधाएं ठप हैं। उत्तर रेलवे ने 68 ट्रेनें रद्द कर दी हैं, पठानकोट-जम्मू रेलमार्ग अभी भी अवरुद्ध है। राहत दल मैदान में हैं, लेकिन नुकसान की भयावहता हर प्रयास को बौना साबित कर रही है।

इन बाढ़ों को मौसमी प्रकोप के रूप में देखना आकर्षक लगता है। लेकिन ये मौसम की दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये प्रगति के हमारे गलत विचार का आईना हैं। इन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहना इनकी मानव-निर्मित जड़ों को खतरनाक रूप से नकारना है।

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ इसलिए ढह रहे हैं क्योंकि हमने साल-दर-साल उनमें ड्रिलिंग, विस्फोट और सीमेंट का इस्तेमाल किया। जब नदियों को कंक्रीट में और आर्द्रभूमि को जमीन-जायदाद में बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो मानसून इस कर्ज.को चुकाने के लिए बाध्य होता है।

हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा है, इसकी ढलानें अस्थिरता से एक साथ टिकी हुई हैं। फिर भी हमने उन्हें निर्माण स्थलों की तरह इस्तेमाल किया है। चट्टानों को चीरकर बनाया गया हर राजमार्ग, पहाड़ों में खोदी गई हर सुरंग, नदी पर बनाया गया हर बाँध, पहले से ही कमजोर पहाड़ों को और कमजोर कर देता है। इसलिए जब तेज बारिश होती है, तो पहाड़ सिर्फ. भीगते नहीं, बल्कि ढह जाते हैं।

उत्तराखंड में भी, रेड अलर्ट आते रहते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और उधमसिंह नगर में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। ज़िला प्रशासन को पहले से ही प्रभावित क्षेत्रों में फिर से भूस्खलन और बादल फटने की आशंका है। ये कोई छिटपुट दुर्घटनाएं नहीं हैं; ये पहाड़ों से वर्षों से उनकी क्षमता से ज्यादा छीन लेने का नतीजा हैं।

ग्रामीण लाचारी और शहरी लापरवाही में भी गहरा अंतर है। हिमालय के गाँव इसलिए ढह जाते हैं क्योंकि वे प्रतिरोध करने में कमजोर होते हैं। लेकिन दिल्ली और गुड़गांव के पास क्या बहाना है? ये सबसे अमीर शहर हैं। ये गरीबी से नहीं, बल्कि लापरवाही से डूबते हैं: नाले दफन हो गए, बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण हो गया, सार्वजनिक ज़िम्मेदारी निजी सुविधाओं के लिए बदल गई।

शहरीकरण का उद्देश्य हमारे क्षितिज का विस्तार करना था। इसके बजाय, इसने गाँवों की संकीर्णता को गगनचुंबी इमारतों में बदल दिया है: ज़िम्मेदारी चारदीवारी पर ही खत्म हो जाती है। अंदर, चमकदार सड़कें और सजे-धजे लॉन; बाहर, अव्यवस्था और जलभराव। हमारे सबसे अमीर शहरों का हर साल डूबना धन की कमी नहीं, बल्कि मानसिकता की कमी है। जलवायु परिवर्तन आज की तबाही के पीछे निर्णायक शक्ति है। एशिया वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है, जिसका अर्थ है ज्यादा तेज बारिश और ज्यादा बार बादल फटना। नासा ने पुष्टि की है कि पिछले दो दशकों में दुनिया भर में बाढ़ और सूखे की संख्या दोगुनी हो गई है।

ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के अनुसार, भारत में बाढ़ प्रभावित ज़िलों की औसत संख्या 19 प्रति वर्ष (1970-2004) से बढ़कर 55 प्रति वर्ष (2005-2019) हो गई है। यह मौसमी प्रकोप नहीं है, यह हमारे सामने प्रकट हो रहा जलवायु पतन है। फिर भी भारत के बाढ़-प्रवण ज़िलों में से चार में से तीन में अभी भी उचित पूर्व-चेतावनी प्रणालियों का अभाव है। यह संकट वैश्विक प्रतिक्रिया चक्रों से अविभाज्य है: पर्माफ्रॉस्ट मीथेन छोड़ रहा है, ग्लेशियर लुप्त हो रहे हैं,

प्रवाल भित्तियाँ मर रही हैं। एक बार ये चक्र शुरू हो जाने के बाद, ये अपने आप चलने लगते हैं। बाढ़ को मौसम की दुर्घटना बताकर खारिज करना यथार्थवाद नहीं, बल्कि इनकार है। यह निराशावाद नहीं, बल्कि भौतिकी है।

दुनिया के सबसे अमीर 10% लोग निजी जेट और अति-जीवनशैली से उत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं, जबकि किसान और मजदूर अपनी जान और फसल दोनों गंवाते हैं। जलवायु परिवर्तन केवल एक पारिस्थितिक संकट नहीं है। यह अमीरों द्वारा गरीबों पर अत्याचार है।

फिर भी, भूस्खलन में मरने वाले या बाढ़ में अपनी फसलें गंवाने वाले अभिजात वर्ग ही नहीं हैं। पंजाब के किसान हैं जिनके खेत नष्ट हो जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के मजदूर हैं जिनके घर ढह जाते हैं, और दिल्ली में प्रवासी परिवार हैं जो अपना थोड़ा-बहुत खो देते हैं। जलवायु परिवर्तन केवल वर्षा के अंशों या मिलीमीटर में नहीं, बल्कि उजड़ते परिवारों और बिखरती आजीविका में मापा जाता है।

और असमानता केवल वैश्विक ही नहीं, बल्कि घरेलू भी है। भारत में, शहरी अभिजात वर्ग ग्रामीण बहुसंख्यकों की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा, ईंधन और वस्तुओं का उपभोग करता है, फिर भी नदी के किनारे, पहाड़ी इलाकों में, और अनियोजित बस्तियों में रहने वाले गरीब ही आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। जलवायु संकट पहले से मौजूद अन्याय पर आधारित है, जो वर्ग और भूगोल की हर दरार को और गहरा करता जा रहा है।

हमें प्रगति को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। एक अच्छा जीवन बड़ी कारों, बड़े घरों, और अधिक हवाई मीलों से परिभाषित नहीं हो सकता। यह परिभाषा उन लोगों द्वारा थोपी गई है जो हमारी इच्छाओं से लाभ कमाते हैं।

तत्काल सुधार लंबित हैं: आर्द्रभूमि और बाढ़ के मैदानों को पुनर्स्थापित करें, कार्बन-भारी उपभोग पर कर लगाएँ, और निगमों और मशहूर हस्तियों के पदचिह्नों का खुलासा करें। लेकिन एक चेतावनी है: मानव उपभोग में बदलाव के बिना कोई भी सुधार संभव नहीं होगा। जब तक सोच नहीं बदलेगी, नीतियाँ विफल होंगी। त्योहारों का मतलब पटाखे फोड़ना नहीं है। आनंद का मतलब अत्यधिक यात्रा या दिखावा नहीं है। बाहर का वातावरण भीतर के वातावरण को प्रतिबिंबित करता है, और जब आंतरिक आत्मा बेचैन होती है, तो प्रकृति भी ढह जाती है।

यही कारण है कि प्रशांतअद्वैत फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र की जलवायु समय सीमा से पहले नागरिकों को जागृत करने के लिए ऑपरेशन 2030 शुरू किया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जब तक 2030 तक तापमान वृद्धि को 1.5त्ञ पर सीमित नहीं किया जाता, तब तक प्रतिक्रिया चक्र - पिघलते ग्लेशियर, बढ़ते समुद्र, ढहते पारिस्थितिक तंत्र - हमें अपरिवर्तनीयता में जकड़ लेंगे। ऑपरेशन 2030 एक अंतर्दृष्टि पर आधारित है: केवल आंतरिक स्पष्टता ही बाहरी परिवर्तन को आधार प्रदान कर सकती है।

इस सप्ताह की आपदाओं पर एक बार फिर नजर डालें: राजमार्ग अवरुद्ध, गाँव डूबे, तीर्थयात्री फँसे, फसलें बर्बाद, यह स्पष्ट है कि ये केवल क्षतिपूर्ति के लिए क्षति नहीं हैं; ये इस बात की याद दिलाते हैं कि लापरवाही भरे फैसले क्या परिणाम लाते हैं।

पहाड़ केवल इतना ही विस्फोट सहन कर सकते हैं, नदियां केवल इतना ही अतिक्रमण, शहर केवल इतना ही कंक्रीट। जब सीमाएँ पार हो जाती हैं, तो पतन होता है। यदि हम अज्ञानता की उन्हीं नींव पर पुनर्निर्माण करने की जल्दबाजी करते हैं, तो अगली आपदा पहले से ही सुनिश्चित है। यदि हम रुकें, चिंतन करें और दिशा बदलें, तो यह क्षण अभी भी एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है।

गीता हमें याद दिलाती है: आंतरिक स्पष्टता से उत्पन्न कर्म मुक्ति प्रदान करता है, जबकि भ्रम से उत्पन्न कर्म विनाश करता है। ज्ञान के बिना विकास अगली त्रासदी का पूर्वाभ्यास है। मानसून बोल चुका है। सवाल यह है कि क्या हम सुनेंगे? और अगर हम सुनने से इनकार करते हैं, तो केवल हम ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी इसकी कीमत चुकाएँगे। हमारे बच्चों और नाती-पोतों को एक ऐसी धरती विरासत में मिलेगी जहाँ मानसून का स्वागत नहीं, बल्कि डर होता है; जहाँ नदियाँ उर्वरता नहीं, बल्कि विनाश का प्रतीक हैं। इतिहास पूछेगा कि 2025 में, जब संकेत इतने स्पष्ट थे, हम क्या कर रहे थे। तब हमारी खामोशी ही सबसे बड़ी गवाही होगी।

पारम्परिक ऋण मानकों की जगह लेती तकनीक

कुछ ऋणदाता पहले ही व्यवहारिक पैटर्न पर निर्भर होने लगे हैं। यह डेटा मोबाइल फोन के इस्तेमाल, बिजली के इस्तेमाल और यहां तक कि यूपीआई भुगतानों से जुड़ी छोटी-छोटी जानकारियां भी जुटा सकता है।

मयूर मोदी
लेखक तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं।

बहुत कम लोग भविष्य की अवधारणाओं को इतने सरल शब्दों में प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं जितना कि इन्फोसिस के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नंदन नीलेकणी कर सकते हैं।

2016 में, उन्होंने एक ऐसे भविष्य के बारे में खुलकर बात की थी जब ऋण और बैंकिंग संचालन पूरी तरह से डिजिटल होंगे। 2024 में, उन्होंने फिन्टरनेट शब्द गढ़ा - वित्तीय प्रणालियों का भविष्य। हाल ही में, उन्होंने बताया कि कैसे भारत 2035 तक दस लाख स्टार्ट-अप की मेजबानी करेगा।

इन भविष्यवाणियों को मिलाकर हम मान सकते हैं कि इस रास्ते पर चलकर भारत की बैंकिंग प्रणाली कागज रहित ऋण देने की प्रक्रिया से आगे बढ़कर एक उपस्थिति-रहित और सहमति-आधारित विश्वास नेटवर्क की ओर बढ़ सकती है।

यह बदलाव उन लाखों स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों को सक्षम बनाएगा जिन्हें भरोसेमंद, चुस्त और तकनीक-समृद्ध ऋण की आवश्यकता है।

भारत में ऋण, जो कागजात, संपार्श्विक और यहां तक कि मानवीय निर्णय पर निर्भर रहा है, को डिजिटल डेटा, प्रक्रियाओं और एल्गोरिदम के लिए रास्ता बनाना होगा।

कुछ ऋणदाता पहले ही व्यवहारिक पैटर्न पर निर्भर होने लगे हैं। यह डेटा मोबाइल फोन के इस्तेमाल, बिजली के इस्तेमाल और यहां तक कि यूपीआई भुगतानों से जुड़ी छोटी-छोटी जानकारियाँ भी जुटा सकता है—वे निशान जो किसी लोन के इरादे और चुकाने की क्षमता के बारे में ज्यादा बताते हैं।

यह वह जानकारी है जो किसी भी अच्छे बैंक के गहन विश्लेषण और व्याख्या से मिले डेटा से नहीं मिल पाती। एक बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार, भारत का वैकल्पिक ऋण बाजार सालाना 26 प्रतिशत से ज्यादा की दर से बढ़ रहा है। यह उद्योग पहले से ही एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है: परिसंपत्ति-समर्थित ऋण से लेकर व्यवहार विश्लेषण तक। यह बदलाव भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में जोखिम मूल्यांकन पद्धतियों के एक बुनियादी पुनसंयोजन का प्रतिनिधित्व करता है।

इस बदलाव के दो कारण हैं। पहला, ग्राहकों की मं ग; दूसरा, (छूट जाने का डर)। आज, भारत में लगभग 6.3 करोड़ टरटए में से ज्यादातर के पास औपचारिक ऋण तक पहुंच नहीं है, मुश्किल से 14 प्रतिशत ही औपचारिक रूप से ऋण प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि ऐसे उद्यम जोखिम भरे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों की नजरों से ओझल रहे हैं।

ग्राहकों की मांग इस आधार पर भी उपजती है कि आज ग्राहक सेकंडों में सेवा चाहते हैं। इसलिए, वित्तीय संस्थानों को व्यापक दस्तावेजीकरण और कठोर संपार्श्विक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं किया जा सकता।

इसलिए, ऐसी प्रक्रियाएँ अभूतपूर्व, लेकिन मौन अप्रचलन का अनुभव कर रही हैं। बैंक वैकल्पिक डेटा स्रोतों पर निर्भर हैं। दूसरे, अधिकांश संगठनों और उद्यमों ने सीख लिया है कि यह एक सरल खेल है - प्रदर्शन करो या नष्ट हो जाओ। इसलिए, नए मानकों को न अपनाना अस्तित्व के लिए एक जोखिम है।

जो बेहतर पूवार्नुमान क्षमता प्रदर्शित कर सकते हैं, वे न केवल जीवित रहते हैं बल्कि बढ़ते भी हैं। इसलिए, डिजिटल परिवर्तन की यात्रा नए पुनरावृत्तियों के साथ उभरी है - एक जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और व्यापक डिजिटल फुटप्रिंट विश्लेषण को एकीकृत करती है।

मशीन लर्निंग वही कर रही है जो जोखिम अधिकारी पहले सहज ज्ञान से करते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर। आज, एल्गोरिदम सैकड़ों व्यवहारिक चरों को पढ़कर यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई उधारकर्ता 15,000 का साधारण ऋण चुकाएगा या नहीं। एआई इस दुविधा को सेकंडों में समझने में मदद कर सकता है। और यह एक पुनरावृत्त शक्ति है।

2023 तक, भारत में डिजिटल ऋण 350 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया, जो 2012 में सिर्फ.9 अरब डॉलर था। आज का नया जोखिम इंजन बहुत बड़ा है और कई तकनीकी परतों से घिरा हुआ है। यह ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल वर्तमान में धोखाधड़ी कम करने के लिए किया जाता है... यह समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित संदेश भी हो सकता है... और यह कृषि-आधारित एमएसएमई के जोखिम का आकलन करने के लिए उपग्रह-आधारित फसल डेटा का लाभ उठाने की ऋणदाताओं की क्षमता भी हो सकती है।

इस मैट्रिक्स में फिनटेक की शक्ति को भी जोड़ें, जो डेटा स्ट्रीम को सुसंगत जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल में संश्लेषित करने के लिए मालिकाना एल्गोरिदम का लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास एक जादुई बक्सा है जो सभी जरूरतों को पूरा करता है और ऋण देने के लिए बेताब है - यह सभी संयोजनों और संयोजनों को ध्यान में रखते हुए है।

ऋण देने में दस्तावेजीकरण की हमेशा एक भूमिका रहेगी। लेकिन भविष्य व्यवहार के विश्लेषण और वास्तविक क्षमता के लिए वैकल्पिक डेटा का लाभ उठाने से बने विश्वास में निहित है। ऐसा नहीं है कि संपार्श्विक-केंद्रित और कठोर ऋण मॉडल शायद जीवित न रहें, लेकिन नवाचार को बनाए रखने और प्रदान करने की आवश्यकता बढ़ गई है।

परिणामी प्रणाली, बैंकिंग की समय-परीक्षित प्रक्रियाओं को वैकल्पिक आँकड़ों के साथ एकीकृत करके, विश्वास-आधारित ऋण और तकनीकी नवाचार को जन्म देगी। यह भारत के वित्तीय सेवा परिदृश्य में एक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है।

तकनीकी परिष्कार पहले से वंचित आबादी के लिए वित्तीय समावेशन के अभूतपूर्व अवसरों को खोलेगा। यह संगठनों को जोखिम-समायोजित मूल्य निर्धारण जैसे नए उत्पाद बनाने में भी सक्षम बनाता है जो जनसांख्यिकीय सामान्यीकरण या परिसंपत्ति स्वामित्व पैटर्न के बजाय वास्तविक उधारकर्ता विशेषताओं को दशार्ते हैं।

यह प्रतिमानात्मक विकास औपचारिक ऋण तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाता है और साथ ही स्थायी ऋण प्रथाओं के लिए आवश्यक विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन मानकों को बनाए रखता है। संदेश स्पष्ट है: जो लोग बैलेंस शीट से परे आँकड़ों को सुनना सीखते हैं, वे बेहतर, गहन और अधिक निष्पक्ष ऋण देंगे।

आप की बात

दक्षिण एशिया में उथल-पुथल

दक्षिण एशिया आज जिस उथल-पुथल से गुजर रहा है, वह किसी सामान्य जनाक्रोश का परिणाम नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे की सरकार को गिराने के लिए जिस तरह जनता को भड़काकर संसद और सरकारी इमारतों पर कब्जा कराया गया, और हाल ही में बांग्लादेश में भी लगभग उसी तर्ज पर सत्ता परिवर्तन करवाया गया—अब वैसा ही परिदृश्य नेपाल में भी दिखने लगा है। काठमांडू में अचानक भड़के विरोध प्रदर्शनों ने जिस तरह संसद भवन को घेर लिया और सोशल मीडिया प्रतिबंध से शुरू हुई मांग अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे तक पहुंच गई, यह किसी स्वतःस्फूर्त आंदोलन का संकेत नहीं बल्कि जनआंदोलन के नाम पर रची गई गहरी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। खास बात यह है कि इसमें केवल 26 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को शामिल होने दिया गया और इसे आंदोलन का नाम दिया गया। यानी युवा आक्रोश को हथियार बनाकर सरकार गिराने की कोशिश। नेपाल पुलिस को मजबूर होकर आंसू गैस, रबर की गोलियां और यहां तक कि हिंसक भीड़ पर गोली मारने के आदेश तक देने पड़े। अब तक नौ से अधिक लोगों की मौत की खबर है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं।

- मधु सुभाष बुड़ावनवाला, रतलाम

भारत को कमजोर करने की साज़िश

भारत को विभाजित करने और उसकी अस्मिता को कमजोर करने की औपनिवेशिक टूलकिट आज भी अनेक रूपों में सक्रिय है। इस टूलकिट का ताजा उदाहरण डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के हालिया बयान में देखा गया, जिसमें उन्होंने यूक्रेन-रूस संघर्ष को मोदी का युद्ध बताते हुए भारत पर असत्यापित आरोप मढ़े और रूस से सस्ते तेल की खरीद को ब्राह्मणों का लाभ बताया। यह टिप्पणी केवल अज्ञान का परिणाम नहीं, बल्कि भारत को जातीय आधार पर तोड़ने की उस साजिश का हिस्सा है जो सैकड़ों वर्षों से विदेशी शक्तियों की कुंठा और रणनीति रही है। सच यह है कि भारत को जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर खंड-खंड करने की कोशिशें कभी थमी ही नहीं। 16वीं शताब्दी में जब जेसुइट मिशनरी फ्रांसिस जेवियर भारत आया, तब उसने सबसे पहले ब्राह्मणों को मतांतरण की राह का बड़ा अवरोधक बताया और उनके दानवीकरण का अभियान शुरू किया। यह वही सोच है जो समय-समय पर अलग-अलग चेहरों और नए परिधानों में हमारे सामने आती रही है। वामपंथी और स्वघोषित सेकुलरवादियों ने भी वर्षों से सामाजिक न्याय के नाम पर यही काम किया,विषमताओं को मिटाने के बजाय उन्हें और गहरा करने का। यही कारण है कि जब नवारो जैसा विदेशी सलाहकार ब्राह्मण-विरोधी वक्तव्य देता है, तब भारत का एक राजनीतिक वर्ग उसका बचाव करता दिखाई देता है।

- विभुक्ति बुपक्या, उज्जैन

राष्ट्रीय चिन्ह नहीं राष्ट्र पर प्रहार

बारावफात के दिन श्रीनगर में हजरतबल दरगाह के जीर्णोद्धार के बाद लगे शिलापट्ट पर उकेरे अशोक चिह्न को ' शान्ति दूतों' और' 'भाईचारा 'वालों ने पत्थर बरसाए। तर्क था कि इस्लाम में चित्र या मूर्ति का कोई स्थान नहीं होता। कोई संविधान रक्षक या लोकतन्त्र रक्षक आगे नहीं आया जो इस कुकृत्य करने वालों के विरोध में एक शब्द भी बोला देता। क्योंकि उन्हें देश नहीं इनकी वोट प्यारी हैं।र ाष्ट्रीय चिह्नों का अपमान या उन्हें क्षति पहुंचाने का अर्थ है राष्ट्र और संविधान का अपमान। जो कि देशद्रोह है। किन्तु संविधान को जेब में लिये घूमने वाले ये तमाशा नंगी आंखों से देखते रहे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शिलापट्ट पर अशोक चिह्न उकेरने की क्या आवश्यकता थी? महबूबा मुफ्ती की भी इससे मिलती-जुलती प्रतिक्रिया थी।अब जरा राष्ट्रीय चिह्न तोड़ने वाले और उनके रहबरों से कोई पूछेगा कि वो कहां - कहां से राष्ट्रीय प्रतीकों को मिटाएंगे? क्या वे उस भारतीय पासपोर्ट से भी राष्ट्रीय चिह्न को मिटाएंगे जिसको लेकर न केवल ये लोग विदेशी यात्रा करते हैं अपितु हजयात्रा भी करते हैं। जिसे इन्हें पवित्र काबा में भी साथ रखना पड़ता है?क्या ये भारतीय मुद्रा भी रखना बन्द कर देंगे? क्या ये कट्टरपन्थी सम्पत्तियों की रजिस्ट्री करना - करवाना भी बन्द करेंगे जिसके स्टाम्प पेपर्स पर यही अशोक चिह्न अंकित रहता है? क्या ऐसे लोग भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना बन्द करेंगे ? जिन सेवाओं के मैडल्स, बैजों, टोपी आदि पर अशोक चिह्न बना रहता है?

- डॉ नरेन्द्र टोंक, मेरठ

भारतीय हॉकी टीम की जीत

भारत की पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर में खेली जा रही एशिया हॉकी कप में दक्षिण कोरिया को हरा कर शानदार जीत हासिल की है। इस प्रदर्शन ने भारतीयों को गर्व महसूस कराया है ।भारत की शानदार जीत पर भारतीय हॉकी टीम के द्वारा इस टूनामेंट में किए गए शानदार प्रदर्शन पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को मैच में 4-1 से पराजित किया है। दक्षिण कोरिया पांच बार की एशिया कप विजेता टीम रही है जिसको हराकर भारत ने एशिया हॉकी कप की ट्रॉफी जीती है। इसी के साथ भारत में 2026 में होने वाले विश्व हॉकी कप में पदार्पण किया है जो एक बड़ी उपलब्धि है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और इस खेल में सफलता अर्जित करना बेहद शानदार, रोमांचकारी और गौरवपूर्ण होता है। इस टूनामेंट में भारत के हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह सरपंच की भूमिका महत्वपूर्ण रही जिन्होंने न केवल अच्छा प्रदर्शन किया बल्कि टीम को पूरे हौसले के साथ अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते रहे और ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। सभी भारतीय देश की हॉकी टीम पर गर्व करते हैं एवं 2026 में होने वाले विश्व कप के लिए भी अग्रिम बधाई प्रेषित करते हैं।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

https://t.me/AllNewsPaperPaid